बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 148

कर मांगने में जल्दबाजी

सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की नामी कंपनी इन्फोसिस को कर विभाग की तरफ से प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद बाजार एवं अन्यत्र असंतोष दिख रहा है। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इन्फोसिस पर भारत एवं विदेश में उसके कार्यालयों के बीच हुए लेन-देन से संबंधित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की देनदारी बनती है। इन्फोसिस इस लेन-देन की व्याख्या स्वयं को उपलब्ध कराई सेवा के रूप में कर रही है परंतु, कर विभाग का तर्क है कि विदेश में कंपनी के कार्यालय या सहायक इकाइयां स्वतंत्र हैं, इसलिए कंपनी को उसे कर चुकाना चाहिए। कर विभाग के इस दावे पर स्थिति साफ नहीं है और उलझन बनी हुई है, जिससे बाजार में चिंता और बढ़ गई है। राज्य प्राधिकरण (कर्नाटक) ने भी नोटिस जारी किया था परंतु, अब उसने इसे वापस ले लिया है। कुछ पुराने कर, जिन्हें अब चुकाने के लिए कहा जा रहा है, वे समय से परे (टाइम बार्ड) हो सकते हैं या जल्द इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यह दावा जुलाई में निर्गत एक परिपत्र में दिए गए एक प्रावधान से निष्प्रभावी हो भी सकता है और नहीं भी। अन्य आईटी कंपनियां, जिनकी विदेश में इकाइयां हैं, उनके समक्ष भी यह कर मांग रखी जा सकती है या नहीं भी रखी जा सकती है। यह भी संभव है कि उन्हें जुलाई में निर्गत परिपत्र से सुरक्षा मिल जाए या फिर न मिले। विदेश में सहायक इकाइयां या शाखा कार्यालय रखने वाली विमानन कंपनियों से भी ऐसी मांग की जा सकती है और नहीं भी।

कर दावों पर जिस तरह उलझन की स्थिति बनी है सरकार को इससे निश्चित तौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। यह संभव है कि सरकार ने कानून में वर्णित विभिन्न समय सीमा का पालन करने की हड़बड़ी में इन्फोसिस को 32,400 करोड़ रुपये कर चुकाने के लिए कहा है। सरकार ने कर के रूप में इन्फोसिस से जितनी रकम मांगी है वह कंपनी के मुनाफे के आंकड़े के बराबर नजर आ रही है। यह कानून की मर्यादा का उल्लंघन और व्यावहारिक रूप से करदाता के लिए अवमानना है। सरकार को कर मांगने से पहले सोच-विचार करना चाहिए था और समग्र कारोबारी मानकों के संदर्भ में निर्णय लेना था। परंतु, ऐसा नहीं हुआ और एक समय सीमा का पालन करने के लिए उसने आनन-फानन में फैसला ले लिया गया। संभव है कि सरकार ने सोचा होगा कि कंपनी से कर मांगने के बाद जांच-पड़ताल की जाएगी और कुछ अनियमितता दिखेगी तो वह नोटिस वापस ले लेगी। यह रवैया स्वीकार्य नहीं है और उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जो कानून की गलत व्याख्या कर नोटिस भेजते हैं।

पिछले दशक में हुए कर सुधार की मूल भावना अधिक पारदर्शिता एवं सटीक अनुमान पर आधारित है। ये दोनों बातें यह व्यावहारिक रूप में भी दिखनी चाहिए। आनन-फानन में भेजे गए ऐसे कर नोटिस इस मूल भावना के बिल्कुल उलट हैं और बाजार व्यवस्था में उलझन की स्थिति खड़ी करते हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी का सामान्य कारोबारी व्यवहार उचित रूप में कराधान के दायरे में लाया जाता है तो खुली चर्चा के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। परंतु, अचानक एवं पिछली तारीख से इसे लागू करना उचित नहीं माना जा सकता। यहां स्थिति कुछ इस तरह है कि एक बड़ी कंपनी एक विशेष आचरण के साथ कई वर्षों से कर चुकाती आ रही है और फिर अचानक कर विभाग को याद आता है कि कर चुकाने का तरीका या आधार ठीक नहीं है। उसके बाद सरकार तपाक से कर भुगतान की अंतिम तारीख से ठीक पहले कर नोटिस थमाती है। सरकार का यह रवैया अचरज भरा है। केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही है कि लोगों एवं कंपनियों में कर का डर दूर किया जा रहा है परंतु, वास्तविकता यह है कि कर अधिकारियों की तरफ से उठाया गया ऐसा प्रत्येक कदम (भले ही बाद में वापस क्यों न ले लिया जाए) इस बात की ओर इशारा करता है कि कर संग्रह तंत्र के संचालन पर नीति निर्धारकों का कम या बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। जब तक जीएसटी प्रणाली में सुधार एवं इसे सरल नहीं बनाया जाएगा और कर विभाग की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी तब तक निवेशक भारत में कारोबार करने से कतराएंगे।

वैश्विक व्यापार के रुझान और बजट में किए गए उपाय

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अधिक खुली व्यापार नीति अपनाने की दिशा में किए गए उपायों को और भी व्यापक एवं समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता बता रही हैं अमिता बत्रा

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के इस्तेमाल से जुड़े नियम सरल बनाए गए हैं, जो व्यापार नीति के लिहाज से सकारात्मक उपाय हैं। जरूरी यह है कि इस निरंतरता को बनाए रखा जाए और वादे के मुताबिक अगले छह महीने में शुल्कों की समीक्षा की जाए तथा सर्वाधिक तरजीही देशों (एमएफएन) के शुल्कों में कमी आए। विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर यह बात विशेष रूप से लागू होनी चाहिए। इससे वैश्विक व्यापार में होने वाले सूक्ष्म बदलावों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास या अंकटाड की जुलाई 2024 की रिपोर्ट और विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार के उभरते रुझानों का उल्लेख किया गया है। इनमें कुछ रुझानों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सबसे प्रमुख रुझान यह है कि कई बाधाओं एवं उतार-चढ़ाव के बाद भी वैश्विक व्यापार डगमगाता नहीं दिखा है। कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास संघर्ष, राजनीति से प्रेरित व्यापारिक पहल जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन ऐक्ट (आईआरए) एवं कार्बन कर (सीबीएएम) और अमेरिका तथा चीन की बीच तकनीक में तीखी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद दुनिया में व्यापारिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। उक्त बातों से व्यापार की गति निस्संदेह प्रभावित हुई मगर अल्प अवधि के लिए ही इनका असर दिखा। कोविड महामारी फैलने के तत्काल बाद 2020 में तेज गिरावट दिखी किंतु 2021 में वैश्विक व्यापार की गति फिर तेज हो गई और 2022 में इसमें शानदार तेजी दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से 2023 के शुरू में फिर इसमें गिरावट आई मगर अंतिम तिमाही में व्यापार वृद्धि फिर तेज हो गई, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में यह दर अलग-अलग रही। 2024 की पहली तिमाही में वस्तु एवं सेवा दोनों स्तरों पर व्यापार के रुझान सकारात्मक रहे हैं। इस तरह 2023 की दूसरी छमाही से सुधार का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के रुझानों में नरमी और इसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय में बढ़ोतरी और विनिर्मित वस्तुओं की मांग में तेजी से अगले वर्ष भी वृद्धि का यह सिलसिला जारी रहेगा। किंतु सेवाओं में व्यापार की वृद्धि दर ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद थमने के संकेत मिल रहे हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण बदलाव यह है कि वृहद तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) के अंतर्गत होने वाला व्यापार इसके (पीटीए) दायरे से बाहर होने वाले व्यापार की तुलना में अधिक टिकाऊ रहा है। पिछले वर्ष व्यापार में नरमी के बाद अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते, यूरोपीय संघ के देशों और कुछ हद तक क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी में शामिल सदस्य देशों के बीच व्यापार का प्रदर्शन बेहतर रहा। पूर्व में हुए अध्ययनों में भी कोविड महामारी के दौरान ऐसे ही रुझान दिखाए थे। अधिक आर्थिक एकीकरण, कम व्यापार लागत और नियामकीय एवं निवेश तंत्रों में मेल-जोल एक सघन उत्पादन तंत्र तैयार करते हैं। ये तंत्र व्यापार अस्थिरता के समय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ढांचा एवं मजबूती प्रदान करते हैं।

तीसरा रुझान वैश्विक व्यापार, मित्र देशों के बीच व्यापार, व्यापार के केंद्रीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के बढ़ते आकार पर भू-राजनीतिक कारकों के प्रभाव से संबंधित है। यह रुझान 2022 और 2023 से दिख रहा है परंतु इस रुझान के नरम पड़ने के भी कुछ संकेत मिलने लगे हैं। इसके बावजूद वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को नया रूप मिलने से एशिया और लैटिन अमेरिका में तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन श्रृंखलाओं के एकीकरण के मौके भी मिल रहे हैं। देशों के बीच राजनीतिक नजदीकी भी व्यापार की दशा-दिशा तय कर रही है। इससे वैश्विक स्तर पर व्यापार में एक-दूसरे पर निर्भरता भी राजनीतिक समीकरणों के अनुसार बदल रही है किंतु यह बदलाव अब तक बहुत बड़ा नहीं रहा है। सकल द्विपक्षीय के रुझान बताते हैं कि व्यापार में चीन पर अमेरिका की और अमेरिका पर चीन की निर्भरता घटी है मगर यह कमी बहुत मामूली है। चीन पर जिन देशों की व्यापार निर्भरता बढ़ी है उनमें ब्राजील, वियतनाम और भारत शामिल हैं। भू-राजनीतिक उठापटक का सबसे बड़ा असर यह दिख रहा है कि यूरोपीय संघ पर रूस की व्यापार निर्भरता कम हुई है। यूरोपीय संघ और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार और यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों को देखते इस बदलाव को समझना मुश्किल नहीं है। चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है।

चौथी अहम बात यह है कि क्षेत्रवार रुझान परंपरागत क्षेत्रों जैसे मशीनरी एवं परिवहन ने अपनी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और व्यापार गतिशीलता बरकरार रखी है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक एवं उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में मांग बढ़ी है किंतु इनमें व्यापार एवं औद्योगिक हस्तक्षेप भी हुआ है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ता अधिक होने के कारण प्रतिस्पर्द्धा के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि बैटरी उत्पादन में कुछ आपूर्तिकर्ताओं का ही दबदबा बना हुआ है। क्षेत्रों के भीतर बदलाव की यह प्रक्रिया अभी जारी है और भू-राजनीतिक स्तर पर जारी अनिश्चितता और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में बिखराव से यह प्रक्रिया और बढ़ने की संभावना है।

इस रुझानों को देखते हुए भारत को व्यापार नीति से जुड़े कुछ विशेष कदम उठाने से इन अवसरों का लाभ मिल सकता है। पहली बात, विनिर्माण क्षेत्र में आयात शुल्कों को आसियान जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आयात शुल्कों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से बदला जाए। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले छह महीने का समय रखना चाहिए। आयात शुल्क कम रहने से निर्यात के मामले में होड़ करने में मदद मिलेगी। निर्यात के मोर्चे पर ताकत हासिल करके ही विनिर्माण में प्रतिस्पर्द्धी देशों को टक्कर दी जा सकती है।

दूसरी बात, शुल्क कम करने की समय सीमा पहले से ही तय कर देने पर भारत की व्यापार नीति का संकेत भी अभी से मिल जाएगा और निर्यात पर केंद्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अग्रणी कंपनियों से एफडीआई आकर्षित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कंपनियां लंबे समय से विकसित देशों में जमी हुई हैं। उनकी निर्माण एवं नवाचार की क्षमताओं से तकनीक के अंतरण एवं प्रसार में मदद मिलेगी, जिससे विनिर्माण में हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी।

तीसरी बात, वृहद व्यापार समझौतों के अंतर्गत होने वाला व्यापार संकट के समय अधिक टिकाऊ होता है। इसे ध्यान में रखते हुए एफटीए में अधिक से अधिक प्रावधानों को शामिल करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। किंतु एफटीए का स्वरूप एवं बातचीत की रणनीति संदर्भ को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उत्तर अमेरिका में क्षेत्रीय व्यापार समूह और यूरोपीय संघ दुनिया के अन्य देशों के व्यापारिक हितों को दरकिनार कर पक्षपात एवं भेदभाव की नीति अपनाते हुए अपने क्षेत्र के भीतर ही व्यापार कर रहे हैं। भारत को अपनी व्यापार नीति का स्वरूप इसे देखते हुए ही तैयार करना चाहिए।

उत्तर अमेरिका में अमेरिका द्वारा तैयार आईआरए पूरी तरह से बहिष्कारवादी व्यापार नीति है, जिसका मकसद अपने क्षेत्र के भीतर ही व्यापार एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा अपने एफटीए साझेदार के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। भारत ने अमेरिका के साथ एफटीए नहीं किया है और वर्तमान सरकार एवं अमेरिका में मौजूदा प्रशासन दोनों ने ही अपनी व्यापार नीतियों के रुख में बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं।

यूरोपीय संघ ने सीबीएएम लागू किया है और दावा कर रहा है कि यह 'वैश्विक व्यापार के लिए हितकारी' होगा। मगर यह व्यवस्था यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार को बढ़ावा देगी और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनुपालन का खर्च बढ़ा देगी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन सहित दूसरे देश सीबीएएम अपनाएंगे। इसकी तुलना में आसियान के साथ बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार व्यवस्था का पालन करते हुए व्यापार गतिशीलता एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देने के अवसर मिलते हैं। लिहाजा भारत में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अधिक खुली व्यापार नीति की तरफ बढ़ाए गए उपायों को आने वाले वर्ष में व्यापक तथा गहन बनाया जाना चाहिए।

(लेखिका सीएसईपी में वरिष्ठ फेलो हैं)

नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद नहीं

बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) ने 1 अगस्त को मुख्य उधारी दर 25 आधार अंक घटाकर 5 प्रतिशत कर दी। मार्च 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद पहली बार बीओई ने ब्याज दर घटाई है। बीओई के इस कदम से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दर 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया। फेडरल रिजर्व के इस कदम का अंदाजा सबको था, मगर ये संकेत भी मिले हैं कि सितंबर में ब्याज दर घटाई जा सकती है। भविष्य के लिए अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। किंतु अब तक मुद्रास्फीति को काबू करने पर जोर देने वाली नीति में पहली बार रोजगार सृजन पर भी ध्यान देने की बात कही गई। अब महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों पर क्या निर्णय लेगा? मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक आम चुनाव के ठीक बाद जून में हुई थी।

रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश बजट से अवश्य खुश होना चाहिए क्योंकि इसमें सरकार राजकोषीय घाटा सीमित रखने के लक्ष्य पर टिकी रही है। बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट के 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे भी अच्छी बात यह रही कि सरकार ने अंतरिम बजट में तय पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की है। वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा कम होकर 4.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के अनुमान में कमी के बाद अनुमानित सकल और शुद्ध बाजार उधारी भी मामूली घटने का अनुमान है।

मॉनसून की प्रगति भी अच्छी बात रही है। किंतु खुदरा मुद्रास्फीति चिंता का विषय रही है। मई तक लगातार तीन महीने कम रहने के बाद खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 5.08 प्रतिशत पर पहुंच गई। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति ने मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन प्रमुख मुद्रास्फीति (खाद्य एवं तेल के अलावा मुद्रास्फीति) 2012 की आधार वर्ष श्रृंखला के आधार पर 3.1 प्रतिशत के सबसे कम स्तर पर रही।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़ों और मॉनसून में विलंब से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है मगर बारिश के रफ्तार पकड़ने के साथ ही हालात सुधर जाएंगे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक से क्या उम्मीद की जा सकती है? जून में केंद्रीय बैंक ने लगातार आठवीं बार नीतिगत दर बिना किसी बदलाव के 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखी।

जून में मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर का अनुमान भी अप्रैल में व्यक्त 7 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया गया था। मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है मगर इसमें 2 प्रतिशत कमीबेशी की गुंजाइश भी छोड़ दी गई है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है और आधार प्रभाव के कारण यह सिलसिला इसी महीने शुरू हो जाएगा किंतु रिजर्व बैंक इससे अपनी नजरें बचाकर नीतिगत दर घटाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। वास्तव में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के संकल्प पर जोर देने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं।

इस बीच जुलाई में रिजर्व बैंक के बुलेटिन में दो दिलचस्प बातों ने विश्लेषकों को उत्साहित कर दिया। इस बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लिखे अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है कि मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत पर ही समेटने पर पूरा ध्यान है। इस अध्याय में कहा गया है, 'मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत स्तर पर पहुंचने और वहां ठहरने के बाद ही मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव पर विचार किया जाएगा। इसके बजाय जोखिम संतुलन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम भविष्य में मौद्रिक नीति का रुख तय करने में मददगार होंगे।'

बुलेटिन के एक अन्य आलेख में स्वाभाविक या तटस्थ ब्याज दर के स्तर की चर्चा की गई। वित्त वर्ष 2024 के लिए तटस्थ दर का अनुमान 1.4 से 1.9 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के 0.8 से 1.0 प्रतिशत के पिछले अनुमान से अधिक है।

मान लें कि अगले एक साल के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर 4.5 प्रतिशत रहती है तो 1.4 से 1.9 प्रतिशत की तटस्थ दर पर नीतिगत दर 5.9 प्रतिशत से 6.4 प्रतिशत के बीच रहनी चाहिए। यह 6.5 प्रतिशत की वर्तमान दर से बहुत कम नहीं है। लिहाजा फिलहाल ब्याज दर में कटौती की संभावना बनती नहीं दिख रही मगर कई लोगों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक 'तटस्थ' रुख जरूर अपनाएगा।

दिसंबर में नई मौद्रिक नीति समिति के साथ ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। मौजूदा समिति अक्टूबर में दोबारा गठित होगी, जिसमें तीन नए बाहरी सदस्य होंगे। बॉन्ड यील्ड में कमी के बाद बाजार की अपेक्षा का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बॉन्ड पर यील्ड और कीमत दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तथाकथित लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो से जुड़े नियमों में संशोधन के बाद बॉन्ड की मांग बढ़ रही है। लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो से अभिप्राय आसानी से कारोबार करने वाली परिसंपत्तियों (सरकारी प्रतिभूतियों) से है। जमा रकम की अचानक निकासी की स्थिति में बैंकों को अगले 30 दिनों के लिए पर्याप्त रकम बरकरार रखनी पड़ती है। संशोधित दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2026 से लागू होंगे। इस बीच, फेडरल रिजर्व के सकारात्मक रुख और जुलाई में अमेरिका में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड शुक्रवार को फिसल गई, जिससे वैश्विक शेयर बाजार में तहलका मच गया।

क्या इससे एमपीसी के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा? एक कारोबारी अखबार को हाल में दिए एक साक्षात्कार में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का ध्यान मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत के भीतर रखने पर है।

हालांकि मौजूदा नीतिगत दर के साथ भी वृद्धि दर तेज है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने के बाद रिजर्व बैंक को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 7.2 प्रतिशत दर से वृद्धि करेगी। पहली तिमाही में यह 7.4 प्रतिशत रह सकती है। आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहने पर अब मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है यानी आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति नियंत्रित करना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर तटस्थ दर को भी बहुत अधिक अहमियत देते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने तटस्थ दर को अव्यावहारिक करार दिया है। अगस्त में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद नहीं है मगर रुख बदल सकता है। अगर रुख नहीं बदला तो नीतिगत समीक्षा का नजरिया सकारात्मक रह सकता है।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

बांग्लादेश में अस्थिरता

बांग्लादेश में तख्तापलट और अस्थिरता के समाचारों से भारत में चिंता स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्ता छोड़ कर भारत में पलायन, सेना द्वारा सत्ता पर अधिकार, बांग्लादेश में सत्तापलट में सेना, चीन और पाकिस्तान के हाथ होने की आशंका और आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण 15 वर्षों तक सत्तासीन और जनवरी 2024 में ही लोकतांत्रिक चुनावों में विजय के बाद भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने की मजबूरी कुल मिलाकर किसी गहरे षड्यंत्र के संकेत देते हैं। केवल छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन का यह स्वरूप संभव नहीं है, जबकि बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को काफी कम कर दिया था। एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के पीछे सरकार की 15 वर्षों की राजनीतिक स्थिरता थी। यह ध्यान देने की बात है कि पिछले 2 वर्षों में भारत के दो पड़ोसी इस्लामिक देश

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उग्र भीड़ ने पीएम आवास पर कब्जा कर तोड़फोड़ की

मालदीव में चीन का वर्चस्व स्थापित हो गया है और पाकिस्तान की सत्ता असलियत में चीन के इशारे पर चलती है। नेपाल और भूटान पर भी चीन आखें गड़ाए बैठा रहता है। इसलिए बांग्लादेश की सत्ता में भारत का हस्तक्षेप कहने वालों को वस्तुस्थिति ईमानदारी से समझनी चाहिए। अभी की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है और यह तख्तापलट से उपजी अराजकता दीर्घकालिक है क्योंकि शेख हसीना के परिवार ने उनके राजनीति से हटने की बात कही है। सत्ता में सेना के वर्चस्व की यदि कुछ समय यही स्थिति रही तो बांग्लादेश में राजनीतिक शून्यता भी उत्पन्न हो सकती है जो बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसी आर्थिक बदहाली और गुलामी दे सकती है। भारत को सभी पक्षों पर सतर्क रहना होगा और बांग्लादेश में स्थिरता के प्रयासों से जुड़े रहना होगा।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इंटर्नशिप अच्छी किंतु नौकरी की गारंटी भी हो

बजट में पेश की गई इंटर्नशिप योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों को चुना जाएगा और जिनके द्वारा एक करोड़ युवाओं को योग्यतानुसार इंटर्नशिप दी जाएगी। इसमें प्रशिक्षु को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यहां तक तो ठीक है, किंतु इसके बाद प्रशिक्षु को नौकरी की गारंटी होना चाहिए या फिर उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि वह प्रशिक्षु इंटर्नशिप के बाद घर पर खाली ना बैठे।

बी एल शर्मा, उज्जैन

कौशल विकास के साथ रोजगार सृजन भी

नई इंटर्नशिप योजना से प्रतिवर्ष लाखों युवाओं को रोजगार के साथ-साथ इंटर्नशिप के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना से युवाओं में कौशल विकास और रोजगार सृजन के साथ ही एआई, वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने की दिशा में काम होगा। 12वीं के बाद युवाओं में पढ़ाई के प्रति अनिश्चितता का भाव रहता था कि आगे की पढ़ाई के लिए क्या किया जाए? अब सरकार और देश की शीर्ष 500 कंपनियां मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन होगा।

संजय डागा, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली कटोनिवेरे ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।' मुर्मू ने फिजी के एक हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां मौजूद विद्यार्थियों से बातचीत भी की।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Machine Translated by Google

THE HINDU

आशा से निराशा तक

सत्ता में बने रहने के कारण हसीना में तानाशाही प्रवृत्ति विकसित हो गई

ढाका से नाटकीय ढंग से भागने के बाद, भीड़ द्वारा की गई आगजनी से कुछ ही क्षण पहले बबरता के बाद, अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस बात पर विचार करने का समय मिलेगा कि आखिर इस अप्रत्याशित परिणाम की वजह क्या थी। बांग्लादेश के युवाओं की उम्मीद, लोकतंत्र की लड़ाई और बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाली प्रधानमंत्री सुश्री हसीना कभी बांग्लादेश की युवा पीढ़ी की उम्मीद थीं।

हसीना को आखिरकार छात्रों की सबसे बड़ी विरोधी के रूप में देखा गया, जिन्हें पिछले दो महीनों के विरोध प्रदर्शनों में 300 से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि 2009 में आतंकवादी शिविरों पर कार्रवाई, अपराधियों को भारत को सौंपने और कट्टरपंथ के खिलाफ उनके अभियान के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी, सुश्री हसीना को हाल ही में अपने विरोधियों पर उन्हीं कठोर तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए अधिक बदनाम किया गया। जुलाई में शुरू हुए कोटा को लेकर छात्रों का विरोध शायद आखिरी तिनका था; पिछले एक दशक से गुस्सा बढ़ रहा था, जिसमें वोटों में धांधली और मीडिया को दबाने के आरोप और नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने के आरोप शामिल थे। जनवरी में चौथी बार चुनाव जीतने के बाद भी, सुश्री हसीना ने उसी रास्ते पर चलना जारी रखा, नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस के खिलाफ मामले दर्ज किए और उन्हें जेल भेजा, जिन्हें अब अंतरिम सरकार का मुखिया माना जा रहा है। उनके कार्यों और असहमति के लिए कोई जगह न देने से उनकी विरासत धूमिल हो गई है, जो उनके लिए सबसे प्रिय है - उनके पिता, बांग्लादेश के बहुत प्रिय संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की, जिनकी मूर्तियाँ अब मलबे के बीच खड़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरमपंथी भीड़ हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, और संभवतः पाकिस्तान और अमेरिका में तत्वों का प्रोत्साहन भी था, दोनों के ही अवामी लीग सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे।

अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसमें इस्लामवादी समूहों की अंतर्निहित संलिप्तता है, जो उस धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर सकती है जिसे सुश्री हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान स्थापित करने का प्रयास किया था।

भारत के लिए, इनमें से प्रत्येक परिणाम आत्मनिरीक्षण का कारण होना चाहिए। नई दिल्ली न केवल बांग्लादेशी विपक्षी सदस्यों के खिलाफ सुश्री हसीना की कार्रवाइयों में शामिल थी, बल्कि उन्हें इसके परिणामों के बारे में सलाह देने में भी विफल रही। वह उनसे संवाद करने में भी विफल रही, जिससे ढाका की सड़कों पर भी सद्भावना खो गई।

मोदी सरकार द्वारा सुश्री हसीना को दिए गए पूर्ण समर्थन ने उन्हें बिना किसी आलोचना के समर्थन देने का भी मौका दिया, जिससे उन्हें नागरिकता (संशोधन) अधिनियम जैसे अलोकप्रिय निर्णयों को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुश्री हसीना की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करते हुए, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने हमेशा भारत के हितों को बरकरार रखा है, सरकार को अगली सरकार के साथ बातचीत करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए एक अधिक समावेशी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण संक्रमण में सहायता करने के लिए काम करना चाहिए।

राष्ट्र को स्वस्थ करना

हैरिस का दौड़ में देर से शामिल होना उन्हें नुकसान की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाता है

संभवतः सबसे अप्रत्याशित अमेरिका के हालिया इतिहास में कथानक का मोड़ मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन के नवंबर चुनाव की दौड़ से पीछे हटने के रूप में चल रही राजनीति के चलते, अगले चार वर्षों के लिए राजनीति के कम विषाक्त और अधिक दयालु पै-रेडिगम के निर्माण की उम्मीद उनके उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर आ गई है। मिश्रित भारतीय और जमैकन विरासत की सुश्री हैरिस को औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी गई है, जो रिपब्लिकन चैलेंजर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनौती देंगी, क्योंकि उन्होंने इस महीने के अंत में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से ठीक पहले पार्टी प्रतिनिधियों से बहुमत से अधिक वोट हासिल किए हैं। अब, सुश्री हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त की है, जो रिपब्लिकन चैलेंजर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनौती देंगी।

हैरिस अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से संबंधित अभियान गतिविधियों, सम्मेलन के दृश्य, उसके बाद होने वाली राष्ट्रपति पद की बहसों और मतदाताओं का मन अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन सामग्री के निरंतर निर्माण सहित, अंतिम चरण की ओर तेजी से दौड़ रही हैं। उनकी रणनीति काम करती दिख रही है - मिनेसोटा के प्रगतिशील गवर्नर टिम वाल्ज़ को अपने साथी के रूप में चुनकर, उन्होंने रिपब्लिकन जिलों को डेमोक्रेटिक बनाने की प्रतिष्ठा वाले एक नेता के साथ भागीदारी की है। हालाँकि श्री बिडेन महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में अनुमोदन सर्वेक्षणों में श्री ट्रम्प से कुछ अंकों से पीछे थे, सुश्री हैरिस ने न केवल प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अद्यतन समायोजित औसत के आधार पर 1.9% के अंतर से डेमोक्रेट की ओर तराजू को झुका दिया है, बल्कि उन्होंने जुलाई में $310 मिलियन की भारी राशि जुटाकर वित्तीय दृष्टि से भी अपनी साख साबित की है, जिसमें दौड़ में प्रवेश करने के बाद पहले सप्ताह में $200 मिलियन शामिल हैं।

उनके देर से प्रवेश से लाभ और जोखिम दोनों ही हैं। एक ओर, ट्रम्प अभियान को श्री बिडेन को निशाना बनाने, विशेष रूप से उनकी उम्र को उजागर करने, और अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन, और आव्रजन के संबंध में कथित विफलताओं के लिए उनके प्रशासन को दोषी ठहराने के लिए महीनों और उससे भी अधिक डॉलर खर्च करने के बाद, उन पर अपनी आलोचना को फिर से केंद्रित करना पड़ा है। अब, श्री ट्रम्प नाम-पुकारने और जाति-भेद के एक घटिया अंदाज में सुश्री हैरिस की नस्लीय पहचान पर अभद्र शब्दों में विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विडंबना यह है कि यह सुश्री हैरिस को उच्च स्थान देता है, जिससे उन्हें संभावित रूप से एक व्यापक राजनीतिक जाल बिछाने और अधिक समावेशी नीति एजेंडा बनाने की जगह मिलती है जो जाति की राजनीति से ऊपर उठ सकती है, उनकी पार्टी के उदारवादी आधार और मूल्यों को फिर से जीवंत कर सकती है, और उन्हें श्री हैरिस के वैकल्पिक उम्मीदवार से कहीं अधिक के रूप में देखा जा सकता है।

ट्रम्प। वास्तविकता यह है कि यह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व भी है जो अगले राष्ट्रपति के तहत वाशिंगटन से लाभान्वित होगा, जो मूल लोकतांत्रिक मूल्यों पर अडिग रहेगा और दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों में शांति के लिए वास्तव में काम करेगा, सबसे तात्कालिक रूप से पश्चिम एशिया में फैल रहे गाजा में संघर्ष और यूक्रेन में रूस की आक्रामकता के संदर्भ में।

30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास जारी

सी भारत की विकास गाथा पर की गई टिप्पणियों में अक्सर समय से पहले विजयोन्माद की झलक मिलती है। हमारी 7% से अधिक जीडीपी विकास दर और भारत जैसे तथ्य आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा 21वीं सदी 'भारत की सदी' होगी जैसी भविष्यवाणियों को पुष्ट करने के लिए ये बातें दोहराई जाती हैं।

ऐसा माना जाता है कि भारत के मामले में आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य है। हमें याद रखना चाहिए कि कई देश पहले भी इस मोड़ पर रहे हैं, जहाँ आज भारत खड़ा है। हालाँकि, अधिकांश देश अंतिम मील तक पहुँचने और विकसित राष्ट्रों के रूप में उभरने में विफल रहे हैं। भारत को इस तरह के भाग्य से बचने और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए, जैसा कि सरकार ने परिकल्पित किया है, हमें निजी क्षेत्र का उपयोग करने वाली उदार आर्थिक नीतियों पर आधारित तेज़ आर्थिक विकास को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रयास में, कई लोग भारत की आय असमानता की निंदा करना जारी रखेंगे। हमें ऐसी आलोचनाओं से प्रभावित या अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए।

राहुल अहलूवालिया

फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक

आर्थिक

विकास (एफईडी), एक गैर-लाभकारी संगठन है जो केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करता है

सरकारों को आगे बढ़ाना

आर्थिक विकास

हर्षित रखेजा

प्रबंधक,
फाउंडेशन में संचार

आर्थिक

विकास

भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी की क्षमता तथ्य यह है कि: गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार के लिए आर्थिक विकास सबसे प्रभावी साधन है। स्वतंत्रता से लेकर 1991 तक, गरीबी कम करने पर जोर देने वाली समाजवादी नीतियों के बावजूद भारत की गरीबी दर लगभग 50% पर रही।

हालांकि, उदारीकरण के वर्ष 1991 से 2011 के बीच गरीबी दर लगभग 20% तक गिर गई। इस अवधि के दौरान भारत की वृद्धि ने 35 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला।

क्या भारत आज 1991 से पहले की तुलना में अधिक असमान है?
शायद, हालांकि डेटा गिनी गुणांक में बहुत अधिक बदलाव नहीं दिखाता है। लेकिन क्या पहले से कहीं ज़्यादा भारतीय बेहतर हैं, खासकर पिरामिड के निचले हिस्से में रहने वाले लोग? हाँ। किसी भी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित करते हैं - संपत्ति सृजन आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है और उद्यमिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। यह एक ऐसा माध्यम भी है जो सभी के जीवन को बेहतर बनाता है। हमें बाद वाले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अब जबकि हमने असमानता के बारे में नकारात्मक बातें करने वालों को कुछ हद तक संतुष्ट कर दिया है, तो आइए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें - जो कम उत्साहवर्धक और अधिक गंभीर हैं।

1990 के दशक के आर्थिक सुधारों से आसान लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत के 2000-10 के उच्च-विकास वर्षों का नेतृत्व आईटी सेवाओं में उछाल ने किया था, जिसने एक मजबूत मध्यम वर्ग को जन्म दिया। हालाँकि, हमारी 46% श्रम शक्ति कृषि में बनी हुई है, जो कम उत्पादकता और अल्प-रोज़गार की विशेषता है, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18% का योगदान देती है। तेजी से विकास करने वाले देशों में देखी गई प्रवृत्ति के साथ एक और असंगति भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) है - केवल 37%।

यह आंकड़ा भी जितना बताता है उससे कहीं ज़्यादा छुपाता है, क्योंकि 2019 में यह 26% था और कोविड-19 के बाद, कई महिलाएँ फिर से खेतिहर मज़दूर के तौर पर काम करने लगी हैं। इसकी तुलना चीन, वियतनाम और जापान के FLFPR से करें, जो सभी 60%-70% के बीच है, और हम ठीक-ठीक जानते हैं कि हमें कहाँ होना चाहिए।

भारत को उदार नीतियों का उपयोग करते हुए तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें निजी क्षेत्र का उपयोग हो; आय असमानता की आलोचना से इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए

तो फिर, हम इस अपार क्षमता को कैसे उजागर करें?
भारत की कामकाजी आयु की आबादी - जिसकी संख्या 950 मिलियन है, जिनमें से केवल आधे ही रोजगार में हैं - और रोजगार समानता सुनिश्चित करते हैं? कम कौशल, रोजगार-गहन विनिर्माण जिसमें निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वह है दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान और वियतनाम को 'एशियाई टाइगर्स' कहा जाने लगा, जिन्होंने 1960-90 के बीच नियमित रूप से दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की। तेजी से निर्यात-उन्मुख औद्योगीकरण पर केंद्रित उनकी आर्थिक नीति का विशेष ब्रांड इस समझ पर आधारित था कि बढ़ते निर्यात के लिए अपने लाभों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जबकि अन्य क्षेत्रों में आयात के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। कुल मिलाकर, विकास के लिए खुलेपन की आवश्यकता है, जैसा कि भारत के लिए था - 1990 और 2013 के बीच, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात 1990 में 7% से बढ़कर 2013 में 25% हो गया। आज, जबकि भारत वैश्विक निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने और अपने निर्यात को और बढ़ाने के लिए चीन+1 क्षण का लाभ उठाने की कोशिश करता है, हमें आयात के लिए बड़ी तारी दीवारें खड़ी करने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए।

मध्यम आय का जाल उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की हमारी उम्मीद में, हम अत्यधिक लाड़-प्यार से भरे और अकुशल निर्माताओं को जन्म देने का जोखिम उठाते हैं। आयात शुल्क के लालच का भी विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भारतीय निर्माताओं को नुकसान होगा, जैसे कि एक मोबाइल फोन निर्माता जिसे चीन से पुर्जे आयात करने पड़ते हैं। शुल्क कृत्रिम रूप से उनके तैयार फोन के लिए आवश्यक कई पुर्जों की कीमतों में वृद्धि करेंगे, जिससे अंततः डाउनस्ट्रीम भारतीय निर्यात की कीमतें बढ़ेंगी। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे भारत को दूर रहना चाहिए, खासकर जब मध्यम आय का जाल सामने आ रहा है।

1960 में 101 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से केवल वर्ष 2018 तक 23 देशों ने उच्च आय का दर्जा प्राप्त कर लिया था, जो भारत के लिए चुनौती की एक कठोर चेतावनी है, क्योंकि भारत अभी भी निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है, जिसे अगले दशक के प्रारम्भ तक मध्यम आय की स्थिति में पहुंचना होगा, तथा फिर उससे भी आगे बढ़ना होगा।

कई कारण हैं जिनके कारण देश मध्यम आय के जाल में फंस जाते हैं - इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्थाएं निचले क्षेत्रों में अपनी बढ़त खो रही हैं और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अधिक समृद्ध देशों के साथ पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं रह गई हैं।

भारत की समस्या अनोखी है: हम अपने अधिशेष श्रम का लाभ उठाकर निम्न-स्तरीय क्षेत्रों में विकास करने में असमर्थ रहे हैं। आईटी बूम ने हमें विकास के लिए एक वैकल्पिक मार्ग दिया, लेकिन वहां सीमित गुंजाइश है। यह नुकसानदेह है क्योंकि विनिर्माण में मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना निम्न-तकनीकी विनिर्माण की नींव पर बना है - प्रबंधकों और श्रमिकों का पारिस्थितिकी तंत्र जो पैमाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए काम पूरा करते हैं, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ बनते हैं। यहां तक कि सरकारी अधिकारी जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरल, निम्न-तकनीकी विनिर्माण को विकसित करने में मदद की है, उन्हें बाद में अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना आसान लगेगा।

भारत के सामाजिक क्षेत्र और नागरिक समाज को ऐसे अभियानों को देखना चाहिए जो कारखानों (निम्न-तकनीकी विनिर्माण के केंद्र) को पसीने की दुकान के रूप में चित्रित करते हैं, तथा इस संबंध में उनकी कार्य स्थितियों और कम वेतन की निंदा करते हैं। बहुत कम मार्जिन पर काम करने वाले नियोक्ताओं को कर्मचारी कल्याण पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर करने से विनिर्माण नौकरियों की गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं होगा, जितना कि उन लोगों के लिए ऐसी नौकरियों के पूरी तरह से खत्म हो जाने का परिणाम होगा जिनके पास कृषि कार्य के अलावा रोजगार के बहुत कम विकल्प हैं।

मध्यम आय के जाल से बचने के लिए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जो निजी उद्यम को पनपने दे, सरकार या फैक्ट्री नौकरियों की धारणा के बिना, रास्ते में बाधा बने - न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। भारतीय राज्य को इस दशक भर के वादे को ईमानदारी से पूरा करना जारी रखना चाहिए, जिसका अर्थ है कि 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ाने के लिए सुधारों को रोकना नहीं चाहिए।

क्लस्टर-आधारित औद्योगिक मॉडल सरकार को भारत के अब तक के जर्जर बुनियादी ढांचे को सुधारने में अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों को दोगुना करना चाहिए, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण करना चाहिए जो चीन और वियतनाम के समान हों, जिनमें प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे और सहायक पारिस्थितिकी तंत्रों की भरमार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन के लिए, जो नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों को आकर्षित करेंगे।

आज, भारतीय राज्यों को बिजली, रसद और वित्त पोषण के लिए लागत संबंधी अक्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में कम श्रम उत्पादकता और अनुपालन का बोझ भी है, जो नए खिलाड़ियों को प्रवेश करने और मौजूदा खिलाड़ियों को विस्तार करने से रोकता है।

कई देशों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; इसलिए, औद्योगिक विकास का क्लस्टर-आधारित मॉडल, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में कड़े नियमों में ढील दी जाती है, विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करता है।

समय की कमी नहीं है; सरकार को निजी क्षेत्र की ताकत और सुधारों के प्रति अपनी रुचि का लाभ उठाते हुए कम कौशल वाले विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और परिधान जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि इस अवसर को अनेक भारतीयों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

यहां अंतर-राज्यीय प्रवास और शहरीकरण महत्वपूर्ण कारक होंगे, साथ ही एफएलएफपीआर और कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट भी महत्वपूर्ण कारक होंगे, जिससे यह आकलन किया जा सकेगा कि क्या हम 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सही रास्ते पर हैं।

नीति में एक वाक्य अक्सर दोहराया जाता है भारत के बारे में लोगों की धारणा है कि "यह एक ऐसा देश है, जिसमें मुंह में पानी लाने वाले अवसर और आंखें नम करने वाली चुनौतियां हैं।" हमें लगता है कि यहां की चुनौतियां सबसे रोमांचक अवसर हैं। विकास की इन बाधाओं को तोड़ने का इनाम समृद्धि का एक अप्रतिबंधित मार्ग होगा, जब तक कि हम अपने भाग्य से मिलने का मौका न पा लें। यह समय विश्वगुरु की तरह आगे की सोच रखने वाले और महत्वाकांक्षी होने का है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अमेरिका में निरंकुश प्रवृत्तियों की ओर बदलाव

एस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, वाशिंगटन ने अपनी विदेश नीति को लोकतंत्रों और सरकारों के बीच नैतिक संघर्ष के रूप में परिभाषित किया है।

तानाशाही, हालांकि यह परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में और उसके खिलाफ़ खड़े लोगों के लिए लचीली और संशोधित साबित हुई। लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच का अंतर अब अमेरिका के भीतर राजनीतिक रुझानों के कारण और भी धुंधला हो गया है।

एक अलग स्थिति व्याप्त है अतीत में, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की राजनीति में नीति और सिद्धांत पर मतभेद शामिल थे, जब राष्ट्रपति और कांग्रेस लाभ के लिए संघर्ष करते थे और कार्यकारी अधिकार की सीमाओं पर बातचीत की जाती थी। गंभीर असहमतियों के बावजूद, लोकतांत्रिक शासन के अनुरूप शिष्टाचार और सहनशीलता के मानदंड प्रबल रहे।

अब वह स्थिति नहीं रही।
रिपब्लिकन पार्टी पर हावी होने वाला गुट, शायद बहुमत, नेतृत्व के एक मजबूत दृष्टिकोण को अपनाता है जो पारंपरिक लोकतांत्रिक मानदंडों से परे काम करता है। यह अब अमेरिकी राजनीति में केंद्र-मंच है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई, 2024 के फैसले से समर्थन मिला है, जिसने पूर्व अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यह इच्छा है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने के उनके प्रयासों पर मुकदमा न चलाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी
राष्ट्रपति को मुख्य सामाजिक कृत्यों के लिए अभियोजन से पूर्ण छूट प्राप्त है और मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने छह रूढ़िवादी न्यायाधीशों के बहुमत के निर्णय का सारांश इस प्रकार दिया; "हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अलग-अलग शक्तियों के हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत, राष्ट्रपति की शक्ति की प्रकृति की आवश्यकता है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक कृत्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से कुछ छूट प्राप्त हो। कम से कम राष्ट्रपति द्वारा अपनी मुख्य संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, यह छूट पूर्ण होनी चाहिए। जहाँ तक उनके शेष सामाजिक कार्यों का सवाल है, वे भी छूट के हकदार हैं।"

कृष्णन श्रीनिवासन

एक पूर्व विदेशी सचिव

लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच का अंतर समाज के भीतर राजनीतिक रुझानों के कारण धुंधला होता जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर हैं, लेकिन 1970 के दशक से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जब वाटरगेट के बाद बढ़ते कार्यकारी अधिकार और सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई थी।

तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रपति को उन्मुक्ति प्रदान करने से अमेरिकी लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा।

न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमोर ने कहा, "राष्ट्रपति की कार्रवाई की वह श्रेणी जिसे गैर-सामाजिक माना जा सकता है, वह बहुत छोटी हो जाएगी।"

परिवर्तन के चरण आधुनिक युग में अमेरिकी राष्ट्रपति पद परिवर्तन के दौर से गुजरा है, जिनमें से प्रत्येक में सत्ता का नाटकीय विस्तार शामिल है। पहला थियोडोर रूजवेल्ट और वुडरो विल्सन के तहत प्रशासनिक राज्य का उदय था, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, लिंडन जॉनसन और रिचर्ड निक्सन के तहत आकार और लागत में बढ़ गया, जब द्विदलीय मूल्यों ने सरकारी हस्तक्षेप के दायरे को व्यापक बना दिया और सामाजिक समस्याओं और सामाजिक कल्याण को संबोधित करने के लिए एक जटिल नौकरशाही उत्पन्न की। इस प्रशासनिक राज्य ने, अपने संसाधनों और एजेंसियों के साथ, दोनों दलों के राष्ट्रपतियों को सार्वजनिक नीति को निर्देशित करने और अपनी विरासत का निर्माण करने में सक्षम बनाया। उन्हें प्रशासन को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीकृत तंत्र का निर्माण हुआ जो राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय में निहित है।

दक्षिणपंथी विचारधारा ने लगातार बढ़ते प्रशासनिक राज्य को असंवैधानिक, समाजवादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी के रूप में देखना शुरू कर दिया। दक्षिणी राज्यों में रिपब्लिकन की बढ़ती ताकत और इवेंजेलिकल्स द्वारा राजनीतिक सक्रियता के साथ, रूढ़िवादी आंदोलन ने इस विश्वास को जन्म दिया कि इसका उत्तर एक ऐसे नेता में निहित है जो शीर्ष-से-नीचे की शक्ति का उपयोग करता है और उन कानूनों के प्रति अलग दृष्टिकोण रखता है जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को बाधित करते हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पैट्रियट एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ निरंकुशता की बात कही गई थी

शक्तियों का विस्तार किया, प्रशासन की निगरानी क्षमताओं का विस्तार किया, तथा वैधानिक कानून के विपरीत कैदियों को यातना देने की अनुमति दी।

रिपब्लिकन रूढ़िवाद की लोकलुभावन प्रवृत्ति कम शिक्षित, ब्लू-कॉलर, श्वेत, ग्रामीण, धार्मिक आबादी के बीच केंद्रित है, जो वैश्वीकरण से वंचित हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खतरे में हैं, और शिकायत और गुस्से से प्रेरित हैं। वे एक ऐसे नेता की तलाश करते हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर हमला करे, इसकी प्रक्रियाओं को खत्म करे और उनकी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करे। डेमोक्रेट्स को राजनीतिक विरोधियों के बजाय उनके दुश्मन के रूप में देखा जाता है, यह मुकाबला लोगों को बड़ी सरकार और भ्रष्ट और अवैध वाशिंगटन प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़ा करता है।

डोनाल्ड ट्रंप में नई सामान्यता ,
लोकलुभावन लोगों को अपना स्वाभाविक नेता मिल गया। जिस क्षण से उन्होंने राष्ट्रपति पद की तलाश करने के अपने इरादे की घोषणा की, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की कानूनी सीमाओं का उन्हें कोई खास उपयोग नहीं है। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री ट्रंप ने दो-पक्षीय राजनीति के मानदंडों और संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसका चरमोत्कर्ष 2020 के चुनाव में उनकी हार के तुरंत बाद हुआ, जब एक मजबूत राष्ट्रपति पद के सत्तावादी कार्यों को लागू करने के बावजूद, उन्हें जो बिडेन की चुनावी जीत को रद्द करने से रोक दिया गया।

लोकलुभावन अतिवाद राजनीतिक दक्षिणपंथ का नया सामान्य रूप है जिसने रिपब्लिकन पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया है। यह पार्टी को प्रशासनिक राज्य के प्रति घृणा से भर देता है और अपनी शिकायतों के लिए रामबाण के रूप में एक मजबूत राष्ट्रपति को गले लगाता है, जिससे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को खतरा होता है। इसे श्री ट्रम्प ने 26 जुलाई को फ्लोरिडा जैसे समर्थकों के लिए अस्पष्ट लेकिन अशुभ घोषणाओं के माध्यम से खुद ही पुष्ट किया है - "आपको फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे इतना ठीक कर देंगे कि आपको मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।" जब तक आने वाले वर्षों में ऐसी भावनाओं को कम नहीं किया जाता है, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है

संपादक के नाम चिठी

बांग्लादेश में अचानक और चौंकाने वाला परिवर्तन तथा यह निश्चितता कि बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना द्वारा खाली किए गए स्थान पर कब्जा कर लेंगी, ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से भारत के लिए अधिक शत्रुतापूर्ण पड़ोस के निर्माण की ओर ले जाएंगी।

घटनाक्रम से उत्पन्न खतरे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ। मौजूदा स्थिति भारत की विदेश नीति के लिए एक अग्निपरीक्षा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश इतिहास और भूगोल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

एस. शेषाद्रि, चेन्नई

एक बार फिर यह हो गया है यह स्पष्ट है कि निरंकुशता और तानाशाही हमेशा कायम नहीं रह सकती। यह भी स्पष्ट है कि आम आदमी की आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता।

बालगोपाल गोपीनाथ, कीरिक्कड़, अलाप्पुझा, केरल

एक ऐसा बांग्लादेश जो कट्टरपंथियों और उग्रवादियों के हाथों में है और पाकिस्तानी प्रभाव भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह भारत की एक बड़ी विफलता है कि उसने सुश्री हसीना के खिलाफ मजबूत धाराओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया।

जहां तक भारत के सहयोगियों का प्रश्न है, पड़ोस-प्रथम नीति विफल हो गई है।

ए. थिरुग्नानासांबंथम, कोयंबटूर

दावा और हकीकत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का दावा कि चेन्नई में बारिश का पानी जमा नहीं हुआ है ("स्टालिन ने कहा, उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाने का समय अभी नहीं आया है", 6 अगस्त) हंसी का पात्र बन गया है। एक रिपोर्ट के साथ दी गई तस्वीर, "थोड़े अंतराल के बाद, तूफान फिर से चेन्नई में लौट आया है उत्तर तमिलनाडु" (चेन्नई, पृष्ठ 4, अगस्त 6), हजारों शब्द कहता है। यह देखना चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री के विपरीत दावे के बावजूद पानी स्थिर है, जबकि पूर्वोत्तर मानसून आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं।

वी. मंजूनाथ, चेन्नई

संपादकीय

"प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष अक्सर भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से होते हैं।" -रॉबर्ट कैगन

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हाल ही में दुनिया भर के शेयर बाजारों में जिस तरह से उथल-पुथल दिखाई दी और भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों को करीब पंद्रह लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, उससे अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई दुनिया अमेरिकी मंदी का शिकार होने वाली है?

मंदी आने को है?

अमेरिका में मंदी और ईरान-इस्राइल के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच हाल ही में दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल-पुथल देखी गई, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों को एक ही सत्र में करीब पंद्रह लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, उससे अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका में मंदी आने वाली है। यह भी देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी मंदी की आशंका का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार के कमजोर परिदृश्य और जापान में ब्याज दर बढ़ाए जाने से येन में कैरी ट्रेड के बंद होने से भी अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों-नैस्डैक, एसएंडपी 500 और डॉउजोंस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों और भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों-सेंसेक्स और निफ्टी50 में भी घबराहट देखी गई। दरअसल, अमेरिका में बेरोजगारी दर के पिछले तीन साल के उच्चतम स्तर पर रहने की वजह से मंदी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम कहते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगातार दो तिमाहियों तक नकारात्मक रहता है, तो उसे मंदी का सामना करना पड़ता है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ढाई फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ी है। लिहाजा अमेरिका में मंदी के संकेत बेशक दिख रहे हों, पर वहां मंदी आ चुकी है, यह कहना अतिशय ही होगा। भारत में बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बीस लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा घटा है, जो चिंताजनक है। मगर राहत की बात है कि यह गिरावट जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई बाजारों और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम रही। उल्लेखनीय है कि 2008 की अमेरिकी मंदी, जिससे पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई थी, के समय भी भारत काफी हद तक अप्रभावित रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार पर निर्भर करता है। यही वजह है कि वैश्विक झटकों का भारत पर उतना असर नहीं पड़ता। चूंकि केंद्र सरकार सतत रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, ऐसे में रोजगार का बढ़ना तय है। भारतीय शेयर बाजार इन सबसे कुछ दबाव में आने के बावजूद मजबूत बने हुए हैं, तो यह अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर आश्वस्त ही करता है। लेकिन बाजार की अनिश्चितताओं को मापने वाले सूचकांक इंडिया वीआइएक्स के 42 फीसदी बढ़ने से अनेक वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। ऐसे में, देखना होगा कि आगामी दिनों में बाजार कैसा प्रदर्शन करते हैं।

जीवन धारा

निकोला टेस्ला

हम सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी हम अविभाज्य संबंधों के साथ आकाश में तारों की तरह एक साथ बंधे हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं।

अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं

***आज** दुनिया के सबसे सभ्य देश अपनी आय का अधिकतम हिस्सा युद्ध पर और न्यूनतम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। युद्ध के मैदान में मरने के बजाय अज्ञानता के विरुद्ध लड़ना अधिक गौरवपूर्ण होगा। इसके लिए एक नई दुनिया का जन्म होना चाहिए। एक ऐसी दुनिया, जो मानवता द्वारा किए गए बलिदानों को उचित ठहराएगी। यह नई दुनिया ऐसी दुनिया होनी चाहिए, जिसमें ताकतवर द्वारा कमजोरों का शोषण न हो, बुराई द्वारा अच्छे लोगों का शोषण न हो, जहां अमीरों की हिंसा से गरीबों का अपमान न हो, जहां बुद्धि, विज्ञान और कला के उत्पाद समाज की बेहतरी और जीवन को सुंदर बनाने के काम आएं, न कि व्यक्तियों द्वारा धन कमाने के लिए।*

यह नई दुनिया शोषितों और अपमानित लोगों की दुनिया नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र लोगों और स्वतंत्र राष्ट्रों की दुनिया होगी। जब हम मनुष्य की बात करते हैं, तो हमारे पास समग्र रूप से मानवता की अवधारणा होती है, और उसके आंदोलन की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने से पहले हमें इसे एक भौतिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या आज कोई इस बात पर संदेह कर सकता है कि लाखों प्रकार के व्यक्ति एक इकाई का निर्माण करते हैं? यद्यपि हम सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी हम अविभाज्य संबंधों के साथ आकाश में तारों की तरह एक साथ बंधे हुए हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। सदियों से धर्म की अत्यंत बुद्धिमानी भरी शिक्षाओं में इस विचार की घोषणा की गई है, शायद केवल मनुष्यों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक गहन सत्य के रूप में। सभी धर्म के लोग इसे अलग-अलग तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, हम सब एक हैं। हालांकि, आध्यात्मिक प्रमाण ही एकमात्र ऐसे प्रमाण नहीं हैं, जिन्हें हम इस विचार के समर्थन में प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञान भी अलग-अलग व्यक्तियों की इस संबद्धता को पहचानता है, हालांकि बिल्कुल उसी अर्थ में नहीं, जिस तरह से यह स्वीकार करता है कि एक नक्षत्र के सूर्य, ग्रह और चंद्रमा एक शरीर हैं। यदि हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचना होगा। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन होते हैं कि वे अपने भीतर क्या चल रहा है, उससे पूरी तरह बेखबर हो जाते हैं। लेकिन बचपन से ही हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें शुरू में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारे भविष्य के लिए यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह काम आता है, क्योंकि इससे हमें जीवन के संरक्षण में आत्मनिरीक्षण के अमूल्य मूल्य की सराहना करने के साथ ही जीवन में उपलब्धि का एक साधन भी मिलता है। जीवन में उपलब्धि पाने के लिए हमें अकेले रहना होगा, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं।

अब कट्टरपंथियों के हवाले

बांग्लादेश में अगर लोग शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ रहे हैं और खुद को मुक्ति योद्धाओं से अलग देखते हुए अराजकता फैला रहे हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि कौन-सी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं। ऐसे में भारत को अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है।

इसी महीने 15 अगस्त को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके बीस करीबी रिश्तेदारों की हत्या की 49वीं वर्षगांठ है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग ने उस दिन 'राष्ट्रीय शोक दिवस' मनाना तय किया था। लेकिन बाद में 'सूचित' किया गया कि वह 'कार्यक्रम अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया' है। ढाका में अचानक हुए सियासी बदलाव को बताने के लिए इससे ज्यादा मार्मिक और कुछ नहीं हो सकता।

हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाना, 1971 में मुक्ति युद्ध से जन्मे बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए सबसे नया सियासी घटनाक्रम है। 53 वर्ष पहले मुजीब के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी परिणति एक और सैन्य तख्तापलट के रूप में हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा उस सैन्य जनरल ने किया है, जो शेख हसीना का दूर का रिश्तेदार है, और जिस पर वह भरोसा करती थीं। 15 वर्षों तक सैन्य शासन के बाद, जिसे शेख हसीना ने आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता से रोका था, बांग्लादेश अब फिर सेना के अधीन है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले सैन्य तख्तापलट की तरह सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने अंतरिम सरकार का वादा किया है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इसमें उनकी या सेना की कोई भूमिका होगी या नहीं। मगर इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि फैसले कौन लेगा। उन्होंने 'न्याय' का भी वादा किया है। सबसे पहले रिहा होने वालों में शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया भी हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। पिछली सदी के अंत में खालिदा जिया और उनके इस्लामी सहयोगी पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए भी चिंता का कारण बन गए थे, जब बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था। ये ताकतें भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है, वह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्या बांग्लादेश फिर से आतंकवादियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा? शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षित बनाने में भारी योगदान दिया। बांग्लादेश की धरती से संचालित होने वाले आतंकी शिविरों को उखाड़ फेंका गया। भारत को अब फिर से बांग्लादेश द्वारा कबायली चरमपंथ को बढ़ावा दिए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब नगा, उल्फा एवं अन्य चरमपंथी गुटों के साथ केंद्र सरकार के शांति समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ढाका के उथल-पुथल में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा सामाजिक रूप से ताकतवर इस्लामी संगठनों के साथ पाकिस्तान-समर्थक जमात-ए-इस्लामी की संलिप्तता है, जिसे हसीना प्रतिबंधित करना चाहती थीं, लेकिन नहीं कर पाईं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कबायली आबादी के अलावा बढ़ते व्यवसायी वर्ग एवं मदरसों के माध्यम से इस उथल-पुथल को हवा दी। पाकिस्तान में 'मुजीब युग' के अंत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत पर अपने पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा पर निगरानी बढ़ाने का दबाव कई गुना बढ़ गया है।

भारत को कूटनीतिक विवादों को जन्म दिए बिना हसीना शासन के दौरान दी गई सभी आर्थिक मदद, व्यापार रियायतों और परियोजनाओं को संशोधित करना होगा। पाकिस्तान की तरह चीन भी ढाका में हुए बदलाव पर खुश है। बीजिंग इस बात से नाराज था कि हसीना ने भारत से ऐसी परियोजनाएं हासिल कीं, जिन्हें वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव फैलाने के लिए चाहता है। रिपोर्ट बताती हैं कि हसीना को चीनी नेतृत्व ने तवज्जो नहीं दिया था। आर्थिक रिश्तों और सीमा प्रबंधन के अलावा, जो किसी भी दो पड़ोसी देशों के लिए ज्यादा मायने रखता है, भारत को गंगा जल संधि पर कूटनीतिक विवाद के लिए तैयार रहना होगा, जिसका नवीनीकरण होना है। अतीत में खालिदा जिया सरकार ने 1990 के दशक में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया था। एक अन्य विवादास्पद मुद्दा तीस्ता जल बंटवारे और उसके बेसिन के विकास का है, जो उत्तर बंगाल में 23 किलोमीटर लंबे संकरे 'चिकेन नेक' के पास है।

भारत ने हसीना सरकार को आश्वस्त किया था कि वह चीन को इससे दूर रखेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का विरोध किया। ढाका की नई सरकार अब चीन को इसमें शामिल कर सकती है, जो धन और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए तैयार है। इससे भारत के क्षेत्रीय और नदी संबंधी हित खतरे में पड़ सकते हैं। इस्लामी और कबायली चरमपंथियों के अलावा, भारत को बांग्लादेश के हिंदू एवं बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए भी चिंता करनी होगी, जिनके ऊपर वहां अक्सर हमले होते रहते हैं। बांग्लादेश अब भारत को रेडिमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में विरोधी के रूप में देखेगा, जहां दोनों विश्व बाजार में एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। बांग्लादेश के साथ भारत 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सबसे लंबी सीमा है। इन सीमा रेखाओं से पशुओं, मनुष्यों और नशीले पदार्थ की तस्करी रिश्तों को खराब कर सकती है, जिसे अब तक दोनों पक्षों ने कम महत्व दिया था। बांग्लादेश अब गरीब नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति वाला मुल्क है और अब वह भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। विशेष समुदाय छोटे से बांग्लादेश के साथ सहानुभूति रख सकता है। कूटनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि लोगों के बीच आपसी संबंधों का एक नया युग शुरू होने वाला है।

हसीना के नेतृत्व में भारत ने 'पड़ोसी पहले' की अपनी नीति के तहत बांग्लादेश को दोस्ताना पड़ोसी बताया था। कूटनीतिक व सुरक्षा कारणों से भारत न तो अपने छोटे पड़ोसियों से लड़ सकता है और न ही उनकी अनदेखी कर सकता है। बांग्लादेश उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हो गया है, जो लगातार सत्ता परिवर्तन से गुजरते हैं, जैसे नेपाल, अशांत श्रीलंका और मालदीव, जहां सत्ता में परिवर्तन को इस आधार पर देखा जाता है कि कौन भारत समर्थक है और कौन चीन समर्थक। बांग्लादेश तख्तापलट इस क्षेत्र की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत की तरह पश्चिम को भी दक्षिण एशिया में बढ़ती चीनी भूमिका से निपटना होगा, क्योंकि चीन को 'रोकने' के लिए अमेरिका दक्षिण एशिया को एक 'धुरी' बनाना चाहता है।

निराशा का अंतिम रूप खुशी

सूत्र

अगर हमारे जीवन में निराशा आ जाए, तो याद रखें इसका आखिरी रूप खुशी ही होगी। हमें अतीत में देखना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी महान था, उसका अक्सर उपहास किया गया, उसकी निंदा की गई, उसका दमन किया गया, लेकिन वह संघर्ष से शक्तिशाली और अधिक विजयी होकर उभरा है।

दूसरा पहलू

मागरिट ए मुइर जहाज 1893 में एक तूफान के दौरान डूब गया था। वैज्ञानिकों को यह विस्कॉन्सिन बंदरगाह के मुहाने पर मिला है।

डूबने के 130 साल बाद मिला जहाज

मागरिट ए मुइर जहाज 30 सितंबर, 1893 को नमक लेकर मिशिगन झील से शिकागो के बंदरगाह की ओर जाते हुए मैकिनैक के संकीर्ण जलडमरूमध्य को पार कर गया था। जैसे ही चालक दल ने मिशिगन का चक्कर लगाया और दक्षिण की ओर बढ़ा, जहाज को 50 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे मुइर ने तेज हवाओं व ऊंची लहरों का सामना किया, जो जहाज के डेक को तोड़ गईं। कैप्टन डेविड क्लो और उनके चालक दल के छह सदस्य बमुश्किल जीवित बचे। मुइर में कैप्टन के वफादार कुत्ते की मौत हो गई। इससे दुखी 71 वर्षीय कैप्टन क्लो, जिनके पहले तीन जहाज डूबने से बच गए थे, ने जहाज नहीं चलाने की शपथ ली। साथ ही कहा कि उन्हें पानी पसंद नहीं। इस तरह मुइर 19वीं सदी में ग्रेट लेक्स के तूफानी पानी में फंसे अन्य हजारों जहाजों में शामिल हो गया। अब खो जाने के 130 साल बाद मुइर मिल गया है। 12 मई को विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन के तीन वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का उपयोग करके जहाज के अवशेष खोज लिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष और टीम के सदस्य ब्रेंडन बैलीद ने कहा कि मुइर की खोज पर जाने से पहले उन्होंने पुराने मानचित्रों और जहाजों के डूबने की समाचारपत्रों की खबरों के आधार पर पांच वर्ग मील का नक्शा तैयार किया था। इसके बाद वह और उनके साथी रॉबर्ट और केविन मई में एक दिन मुइर की खोज पर निकले। सूरज डूबने वाला था, लेकिन उनकी सोनार तकनीक झील के तल में मुइर का पता नहीं लगा सकी। वह अपना सामान समेटने वाले ही थे कि स्क्रीन पर एक बड़ी वस्तु रेंगती हुई दिखी। बैलीद ने कहा, 'उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह मुइर है।' इतिहासकारों के मुताबिक मुइर ग्रेट लेक्स के अवशेष वाले 8,000 जहाजों में से एक है। मुइर 130 फुट लंबा, तीन खंभों वाला स्कूनर था, जिसे अनाज व्यापार के लिए बनाया गया था। इसे 1872 में कैप्टन डेविड मुइर के लिए बनाया गया था, जिन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था। जहाज ने अपने 21 साल के सफर के दौरान सभी पांच महान (ग्रेट लेक्स) झीलों में माल पहुंचाया। कैप्टन क्लो ने अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मिलकर जहाज बनाए थे और दशकों तक उन्हें चलाया। बैलीद कहते हैं कि ऐसे जहाज बनाने के लिए अब 50 लोगों का दल लगेगा। बैलीद ने बताया कि जहाजों के अवशेषों से वह झीलों के किनारे लुप्त हुई संस्कृतियों की कहानी बताने के लिए करते हैं।

सारा रुबर्ग

मुइर में कैप्टन के वफादार कुत्ते की मौत हो गई। इससे दुखी कैप्टन क्लो, जिनके पहले तीन जहाज डूबने से बच गए थे, ने जहाज नहीं चलाने की शपथ ली।

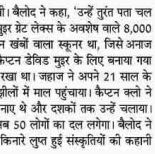

विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन के तीन वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का उपयोग कर जहाज के अवशेष खोज निकाले।

आंकड़े

बांग्लादेश सीमा

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमारेखा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पश्चिम बंगाल	2,216.7
त्रिपुरा	856.0
मेघालय	443.0
मिजोरम	318.0
असम	263.0

भारत के राज्यों से लगती बांग्लादेश की सीमारेखा के आंकड़े किमी में। स्रोत : MEA

आज हरियाली तीज है। मान्यता है कि श्रावणी शुक्ल पक्ष की तीज के दिन भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था।

पूरी हुई माता पार्वती की मनोकामना

एक बार महादेव ने देवी पार्वती को पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहा कि हे पार्वती! तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। एक बार नारद मुनि आपके पिता जी के पास पहुंचे और कहा, 'भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं'। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे अपना पति मान चुकी थीं।

शिव जी ने पार्वती को बताया, 'इससे बाद तुम अपनी सखी के कहने पर घने जंगल में एक गुफा में शिवलिंग बनाकर तप करने लगी थीं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर दर्शन देकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता जी से कहा कि, मैं आपके साथ तभी चलूंगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे।' शिव जी ने कहा, 'हे पार्वती तुम्हारे पिता और हठ के आगे पिता ने तुम्हारा विवाह मुझसे कराने की सहमति दे दी।' मान्यता है कि जो भी महिला हरियाली तीज पर विधि-विधान के साथ व्रत रखती है, तो उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित संकट दूर हो जाते हैं। इससे शिव-पार्वती प्रसन्न होते हैं।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

गीत सेठी विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियन बने

भारत में बिलियर्ड्स के खेल का जिक्र हो तो गीत सेठी की बात होना लाजिमी है। गीत श्रीराम सेठी ने 1985 में आज ही के दिन विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मार्लर को हराकर खिताबी जीत हासिल की थी। दोनों के बीच तकरीबन आठ घंटे तक चले इस मैच की चर्चा लंबे समय तक रही थी। 1606 में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का पहली बार मंचन किंग जेम्स प्रथम के लिए किया गया। 1753 में ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का निधन। 1944 में पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फुट लंबी, 8 फुट ऊंची और पांच टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण।

भुला दी गई नदियां मचा रहीं तबाही

वायनाड भूस्खलन में सबसे बड़ी भूमिका उन नदियों की है, जिनको गैर-जरूरी मानकर कभी इन्सान ने समाप्त करने का प्रयास किया था।

पंकज चतुर्वेदी

आपदा

वायनाड-नीलगिरी पर्वतमाला के ऊंचे पहाड़ों से होकर कभी एक नदी बहती थी। तेज गति वाली नदी गर्मी में उदास रहती थी, लेकिन बरसात के छह महीने तेज वेग में नीचे जाकर पश्चिमी घाट की नदियों में मिल जाती। सन 1876 में इंग्लिश और स्कॉटिश कॉफीटेप सोसायटी ने यहां के पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा क्यारियां बनाकर असम और चीन की चाय की संकर नस्ल की खेती शुरू की। वहां कई छोटी-छोटी जल सरिताएं थीं। अंग्रेज बागान मालिक ने उन सरिताओं पर मिट्टी डालवा दी और उस पर मजदूरों के लिए बस्ती बसा दी।

वायनाड में आई भयावह तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान वेल्लारीमाला पर्वतमाला के नीचे मुंदक्कई और चूरलमाला में हुआ है। असल में इन दोनों जगहों पर घर और इमारतें भूला दी गई नदी के ऊपर बने हुए थे। वेल्लारीमाला स्कूल की विशाल इमारत भी उस नदी के बहाव मार्ग पर बनी थी, जो कुछ साल पहले अपना रास्ता तो बदल चुकी थी, लेकिन शायद उसे भूली नहीं थी। विदित हो कि वेल्लारीमाला पर्वतमाला कोझिकोड जिले में थिरुवंबाडी पंचायत से वायनाड जिले में मेप्पाडी पंचायत तक फैली हुई है। वायनाड के ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर जब मलप्पुरम जिले की तरफ आते हैं, तो शायद दुनिया का एकमात्र सागवान की लकड़ी का संग्रहालय नीलांबूर में मिलता है। इस छोटे से कस्बे की सुंदरता और जैव विविधता जिस चलियार नदी के कारण है, वह इन्सानों की लाशों से पट गई। यह नदी वायनाड जिले में इलमपिलेरी पहाड़ियों से निकलती है। वायनाड से लगभग 90 किलोमीटर दूर इन्सानों के शव के टुकड़े मिलना बताते हैं कि वायनाड भूस्खलन से हुई तबाही में सबसे बड़ी भूमिका उन नदियों की है, जिनको गैर-जरूरी मानकर कभी इन्सान ने समाप्त करने का प्रयास किया था। विकास के नक्शे बनाने वाले यह भूल गए कि सभी नदियां जीवित जीव की तरह होती हैं और उनकी यादाश्त 200 साल की होती है। इस तबाही के मूल में वेल्लारीमाला पर्वतमाला का भूस्खलन है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन के साथ मानवीय दखल जिम्मेदार है, लेकिन मलबे के तेजी से बहने के पीछे लुप्त नदी का अचानक जीवंत होना भी बड़ा कारण है। वर्ष 2020 में केरल में घटित जलवायु परिवर्तन, खासकर तापमान में वृद्धि की घटनाओं को समूचे तंत्र ने नजरअंदाज किया। उस वर्ष केरल में भयंकर जल प्लावन के बाद जैव विविधता के लिए जगजाहिर वायनाड में अचानक केंचुए और कई प्रकृति प्रेमी कीट गायब हो गए थे। कई शोध बताते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी से पश्चिमी घाट के आसपास के इलाकों में अचानक भारी बरसात होगी ही और जब ऐसे में प्रकृति पर मानवीय दखल बढ़ा, जंगल कम होने से मिट्टी की पकड़ ढीली हुई, तो भारत के इतिहास के सर्वाधिक भयावह भूस्खलन में से एक वायनाड में घटित हो गया। वेल्लारीमाला पर्वतमाला घने जंगल और छोटी-बड़ी जलनिधियों से संपन्न ऊंट की पीठ के आकार की पर्वतमाला है। बार-बार इसे विशेष क्षेत्र घोषित कर सभी तरह के निर्माण रोकने की मांग होती रही, लेकिन पहाड़ खोद कर कोझिकोड राजमार्ग को चौड़ा करना जारी रहा। वेल्लारीमाला का भूस्खलन एक सैडल (ऊंची जमीन के दो क्षेत्रों के बीच एक निचला बिंदु) से उत्पन्न हुआ है। सैडल दो तरह से बन सकते हैं, या तो दरारों द्वारा या फिर कटाव से। आमतौर पर कटाव वाले सैडल चूना पत्थर में होते हैं, जो यहां है नहीं। स्पष्ट है कि वेल्लारीमाला का भूस्खलन दरारों के कारण हुआ था। जब इस तरह की दरारों में लंबे समय तक पानी जमा होता है और मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ती जाती है, तो यह अचानक फट पड़ता है। कोई 100 मीटर सीधी ऊंचाई से ढेर सारा मलबा नीचे आना और फिर उससे लुप्त हो गई नदी के बहाव का जुड़ जाना कल्पना से परे है कि मानव निर्मित कोई संरचना इस वेग में खड़ी रह सकती थी। फिर दो घंटे में 37 सेंटीमीटर बारिश का प्रकोप, तो था ही।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 175 (रजि.नं. 13045/59 आएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

संपादकीय

नई दिल्ली, बुधवार 7 अगस्त 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. माणाराम सुरजन

भारत के लिए संभल कर चलने का वक्त

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वहां के सियासी हालात और भारतीयों की सुरक्षा समेत कई जरूरी सवालों पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इसके अलावा विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने संसद में भी इस पर आधिकारिक बयान दिया। केंद्र सरकार के मुताबिक 5 अगस्त को शेख हसीना ने बेहद शार्ट नोटिस पर कुछ लम्हे के लिए भारत आने की अनुमति मांगी और इसके साथ ही बांग्लादेश प्रशासन ने फ्लाइट क्लियरेंस की अनुमति मांगी, जिसके बाद 5 तारीख की शाम को शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई। सरकार ने संसद में यह जानकारी भी दी कि वहां के अल्पसंख्यक समुदायों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर उसकी नजर है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यह जानकारी सामने आई है कि शेख हसीना के ब्रिटेन जाने पर भी संशय है, क्योंकि वहां की सरकार ने उन्हें किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना से कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी-कार्यवाही शुरू होती है तो ब्रिटेन उनका बचाव नहीं करेगा।

इन स्थितियों में शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत से ही संपर्क किया और वह भी काफी कम वक्त में, उससे जाहिर होता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने मजबूत रहे हैं। अब जो नयी सरकार गठित होगी, क्या उसके साथ भी भारत के संबंध सौहार्द्रपूर्ण और भरोसे के रहेंगे, इसे परखना होगा। क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश ही नहीं है, हमारी सीमाओं के साथ-साथ आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक हितों की भी साझेदारी है। जिन हालात में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के दो हिस्से कराकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, उस हार का स्वाद पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है और चीन ने भी भारत की सक्षमता को तब देख लिया था। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश को आधार बनाकर भारत में अपने गलत इरादों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, इस बारे में भारत को पहले से सचेत रहना होगा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार के पास बांग्लादेश के घटनाक्रम में किन्हीं बाहरी ताकतों की भूमिका के बारे में कोई जानकारी है, तो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सरकार के पास केवल पाकिस्तान के राजनयिक की बदली हुई डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) के बारे में जानकारी है जो विद्रोहियों को उनके समर्थन को दर्शाती है।

यह जानकारी छोटी सी है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। पाकिस्तान के राजनयिक अगर विद्रोहियों को समर्थन दे रहे हैं, तो जाहिर है कि बांग्लादेश की राजनैतिक अस्थिरता या वहां कठपुतली सरकार बनाने में बाहरी ताकतों की दिलचस्पी है। ये ताकतें कौन सी हैं, और इनका असल मकसद क्या है, इसे बेहद सावधानी के साथ विश्लेषित करने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश केवल मोहरा हो सकता है और निशाने पर कोई और हो सकता है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पिट्ठू सरकारों को बिठाने का सफल प्रयोग वैश्विक ताकतें पहले कर चुकी हैं, अरब बसंत जैसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जहां आंदोलन के प्रत्यक्ष कारण कुछ और होते हैं और छिपे हुए एजेंडे जब तक सामने आते हैं, तब तक देश बर्बाद हो चुके होते हैं। ऐसे आंदोलनों में धर्म और नस्ल के नाम पर अत्याचार सहउत्पाद की तरह आता है और लोगों का ध्यान उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। इस वक्त बांग्लादेश में भी यही सब हो रहा है। हिंदुओं पर मंडराता खतरा, मंदिरों पर हमला, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिनसे भारत में चिंता उपजना स्वाभाविक है। लेकिन क्या धर्म की आड़ में लोकतंत्र पर मंडराए खतरे से ध्यान भटकाया जा रहा है, यह भी समझना होगा।

शेख हसीना की चुनावों में जीत पर सवाल उठाना, उनकी नीतियों और फैसलों का विरोध करना, उनसे इस्तीफे की मांग करना, सब जायज़ रहता, अगर यह सब लोकतंत्र के दायरे में रहकर किया जाता। लेकिन शेख हसीना को जिन हालात में देश छोड़ने पर मजबूर किया गया और फिर बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा को प्रहार करके तोड़ा गया, वह असल में लोकतंत्र पर प्रहार था। आंदोलनकारियों ने जिस तरह शेख हसीना के आवास पर कब्जा किया और उनके निजी सामान का बेहूदा प्रदर्शन किया, वह उपद्रवियों और दंगाइयों का आचरण था, आंदोलनकारी इस तरह अपने लक्ष्य से नहीं भटकता करते हैं।

बांग्लादेश में लोकतंत्र का ढहना भारत के लिए किसी लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे पड़ोसी देशों में एक बांग्लादेश ही था, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। वहां की अंतरिम सरकार कितनी लोकतांत्रिक रहती है, यह तो आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नरेन्द्र मोदी की सरकार को हरेक कदम सावधानी से उठाना होगा और इसके लिए अगर विपक्षी दलों से सलाह-मशविरा किया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मंगलवार को जो सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सभी दलों ने सरकार से सहयोग ही किया है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं क्यों अनुपस्थित रहे। इसी तरह आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल करना सरकार ने क्यों जरूरी नहीं समझा, इसका तार्किक जवाब भी सरकार को देना चाहिए। क्योंकि यह वक्त क्षुद्र राजनीति का नहीं है।

दुश्मनी हसीना से है, हमसे नहीं

बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों में हमारा एकमात्र सच्चा मित्र शासन भी खत्म हो गया है। नया शासन अनिवार्यत: हमारा बैरी हो यह जरूरी नहीं है लेकिन राजनैतिक अस्थिरता, फौजी दखल और कई स्पष्ट भारत विरोधी राजनैतिक ताकतों के बीच किस किस्म का संतुलन बांग्लादेश में बनाता है और वह भारत से किस तरह का संबंध रखता है यह आने वाले वक्त में तय होगा। यह हमारी कूटनीति की परीक्षा भी है। मालदीव में एकदम भारत विरोधी शासन को बहुत जल्दी अपने रुख में 180 डिग्री का बदलाव करना पड़ा पर वह बहुत छोटा देश है और भारत पर उसकी निर्भरता कहीं अधिक है। नेपाल में भी ओली सरकार को नहीं पर खुद प्रधानमंत्री ओली और उनकी पार्टी का रुख चीन समर्थक है। पाकिस्तान की बात ही क्या है। श्रीलंका की सरकार भी भारत के बहुत पक्ष की नहीं है। अफगानिस्तान और चीन के अपने किस्से बहुत हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत चारों ओर से जिन देशों से घिरा है वहां की सरकारें भारत समर्थक नहीं हैं और इनसे रिश्ता रखते हुए भारत को फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे।

बांग्लादेश की सत्ता छोड़ने और देश छोड़ने को मजबूर हुईं शेख हसीना के साथ ऐसा नहीं था। उनके पंद्रह साल लंबे शासन में भारत बांग्लादेश की तरफ से काफी निश्चिंत रहा है। भारत के काफी उद्यमियों ने बांग्लादेश के सस्ते श्रम के लोभ में अपने उत्पादन का केंद्र वहां भी बना रखा था। चीन भी बांग्लादेश के समुद्री लोकेशन और सस्ते श्रम को लेकर उसके आसपास मंडराता रहा है। और जब एकतरफा बांग्लादेश चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को 300 में से 288 सीटों पर विजेता घोषित किया गया था तब उनकी सरकार को विश्वसनीयता का संकट था। उस समय भी चीन ने आगे बढ़कर उनका समर्थन किया था और उनकी सांस लौटी थी। लेकिन इसके बावजूद हसीना ने चीन के दबाव में तीस्ता को लेकर ऐसा समझौता नहीं किया जो भारत के हितों के खिलाफ होता। हसीना के शासन में पंद्रह साल में बांग्लादेश ने अच्छी आर्थिक तरक्की की थी और आज बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों पर दुनिया की नजर है। कई पैरामीटर पर बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। बाहर से काफी पूंजी बांग्लादेश में लगी है और हमारे हजारों बच्चों समेत इस पूरे क्षेत्र के बच्चे यहां के विश्वविद्यालयों और मेडिकल-इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।

अरविन्द मोहन

निश्चित रूप से बांग्लादेश में तख्तापलट का भारत पर असर होगा। हमारी सीमा ही चार हजार किलोमीटर से ज्यादा बड़ी है। फौजी और मजहबी रूप से ज्यादा कट्टर सत्ता होने से बांग्लादेश से घुसपैठ और शरणार्थियों का रेला आ सकता है। आंदोलन की सूत्रधार जमाते इस्लामी तो खुलेआम पाकिस्तान समर्थक है और वह बांग्लादेश बनने का विरोधी भी है। इस आंदोलन को भी आई एस आई के समर्थन की बात कही जा रही थी।

लेकिन इससे शेख हसीना के शासन के सारे पापों को भुलाया नहीं जा सकता। अभी के आंदोलन में ही चार सौ नौजवान सेना और पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। एक रात में ही 75 बच्चों के शव को चुपचाप दफनाया दिया गया था। विपक्ष की नेता खालिदा जिया जेल में बंद थीं तो लघु वित्त के अद्भुत प्रयोग के लिए नोबल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस भी जेल में थे। दूसरी ओर सरकारी बैंकों के भारी-भारी लोन का घोटाला करने वाले सरकार और शासन में प्रमुख बने बैठे थे। पिछला चुनाव भी लोकतंत्र का मजाक था और जिस आरक्षण को लेकर छात्रों, नौजवानों का आंदोलन जिस आरक्षण नीति को लेकर था उसमें सरकार और कोर्ट क्या खेल करते रहे यह समझना मुश्किल है। हसीना ने भी कभी आंदोलनकारियों से नहीं कहा कि वह अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। और जब आंदोलन उग्र हुआ तो उसे शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से निपटाने की जगह पहले अपने छात्र संगठन से हमले कराए गए और फिर कठोर पुलिस के तरीकों से दबाने का प्रयास अंतत: भारी पड़ा। और खुद उस सेना प्रमुख वकारुज़्जमां ने तख्ता पलट की है जिसे शेख हसीना ने डेढ़ महीने से भी कम समय पूर्व इस पद पर प्रमोट किया था। ऐसी गलती सत्ता के मद में होने से भी होती है।

लेकिन इस प्रकरण में भारत ने उनको अपने यहां आने दिया और सुरक्षित रखा यह बहुत ही उचित व्यवहार है। शेख मुजीबुर्रहमान और बांग्लादेश की आजादी के साथ हमारा क्या रिश्ता रहा है यह बताने की यह जगह नहीं है। लेकिन यह कहने में हर्ज नहीं है कि शेख हसीना के साथ हमारा ज्यादा गहरा नाता है। जब 1975 में सैनिक तख्तापलट में शेख मुजीबुर्रहमान के पूरे परिवार के लोगों को मार डाला गया था तब से भारत से उनका रिश्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही नहीं विपक्षी गांधी परिवार से भी उनके घरेलू रिश्ते हैं। अभी जब वे मोदी जी के शपथ ग्रहण में आई थीं तो सोनिया गांधी से मिलना न भूलीं। पर यह याद रखना जरूरी है कि वे सत्तर पार कर चुकी हैं। और मुल्क में उनकी पार्टी अवामी लीग अभी भले सबसे ताकतवर हों पर वे वापसी कर पाएंगी इसमें संदेह ही रहेगा। अभी वहां राजनैतिक रूप से क्या-क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना उचित न होगा क्योंकि सत्ता का स्वाद चख चुकी फौज बहुत जल्दी से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल करे यह होता नहीं है। दूसरे वहां की राजनीति में जो भी तत्व हसीना विरोधी हैं वे भारत विरोधी भी हैं। खालिदा जिया तो कब से घोषणा कर रही है कि अगर वे सत्ता में आईं तो भारत से हुए सारे समझौतों पर पुनर्विचार करेंगी। लेकिन वे भी हसीना की तरह उम्रदराज हैं और बहुत बीमार हैं।

निश्चित रूप से बांग्लादेश में तख्तापलट का भारत पर असर होगा। हमारी सीमा ही चार हजार किलोमीटर से ज्यादा बड़ी है। फौजी और मजहबी रूप से ज्यादा कट्टर सत्ता होने से बांग्लादेश से घुसपैठ और शरणार्थियों का रेला आ सकता है। आंदोलन की सूत्रधार जमाते इस्लामी तो खुलेआम पाकिस्तान समर्थक है और वह बांग्लादेश बनने का विरोधी भी है। इस आंदोलन को भी आई एस आई के समर्थन की बात कही जा रही थी और चीन जरूर कोशिश करेगा कि नई सरकार पर उसका प्रभाव ज्यादा रहे। फौज और जुनूनी मजहबी जमात से संबंध निभाना आसान नहीं होगा। हां, यह याद करना लाभदायक है कि इन सबका विरोध शेख हसीना से था, भारत से नहीं और बांग्लादेश की हाल की खुशहाली उनको भी भायी होगी। सो वे सत्ता बदलकर वे हर चीज बदलने नहीं जाएंगे। स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। पर अगले कुछ दिन बहुत नाजुक हैं भारत को गंभीरता से हर चीज पर गौर करके ही कदम उठाना चाहिए।

अहं और प्रजातंत्र विरोधी रवैया शेख हसीना के अध:पतन के लिए जिम्मेदार

बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी सरकार के अध:पतन के बाद शायद दुनिया में एकमात्र धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक देश का पतन हो गया है। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के निर्माता थे। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि नागरिकों के लिए धर्म से ज्यादा महत्व भाषा का है। जब पाकिस्तान के अधिनायकशाही शासकों ने बांग्लादेश पर उर्दू को लादने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया था और यह कहा था कि बांग्ला भाषा ही हमारी मातृभाषा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के चुनाव में मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला था। इसके बावजूद पाकिस्तान के शासकों ने उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस सबका बांग्लादेश के नागरिकों ने जबरदस्त विरोध किया और उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया।

इस बीच मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश का शासन दक्षिणपंथी इस्लामी ताकतों के हाथ में आ गया। परंतु कुछ समय के बाद मुजीबुर रहमान की आवामी लीग फिर सत्ता में आ गई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनीं। उनके शासनकाल में बांग्लादेश ने काफी प्रगति की। वहां की आर्थिक व्यवस्था में भारी सुधार हुआ। आर्थिक प्रगति के साथ ही शेख हसीना ने वहां अनेक संवैधानिक सुधार किए। इन सुधारों के जरिये उन्होंने बांग्लादेश को एक पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को जिनमें हिन्दू भी शामिल थे, पूरी सुरक्षा दी और दक्षिणपंथियों को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया।

एल.एस. हरदेनिया

भारत से भी बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो गये। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा अपनी राजनीति करती थी उसमें कुछ हद तक ब्रेक लग गया और नरेन्द्र मोदी ने भी बांग्लादेश से अपने संबंध सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु धीरे-धीरे शेख हसीना को सत्ता का नशा चढ़ने लगा। वहां उन्होंने अपने विरोधियों पर जबरदस्त ज्यादतियां कीं।

भारत से भी बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो गये। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा अपनी राजनीति करती थी उसमें कुछ हद तक ब्रेक लग गया और नरेन्द्र मोदी ने भी बांग्लादेश से अपने संबंध सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु धीरे-धीरे शेख हसीना को सत्ता का नशा चढ़ने लगा। वहां उन्होंने अपने विरोधियों पर जबरदस्त ज्यादतियां कीं। यहां तक कि उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी की नेता खालिदा जिया को जेल में डाल दिया। उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने में तरह-तरह की बाधाएं उत्पन्न कीं और स्थिति इतनी खराब हो गई कि खालिदा जिया की पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में भाग लेने से भी मना कर दिया।

इसी तरह वहां की एक और पार्टी जमाते इस्लामी को उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जबकि जमात का बांग्लादेश में प्रभाव था। उन्होंने हर तरह से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया। नतीजे में उनकी लोकप्रियता घटती गई और एक मौका ऐसा आया कि लगभग पूरा बांग्लादेश उनके विरूद्ध हो गया। जब उन्होंने उनके विरोधियों को आतंकवादी कहा और उन्हें रजाकार भी निरूपित किया, इससे पूरे बांग्लादेश में आक्रोश फैल गया। फिर इन्होंने एक और गलत फैसला किया कि उन लोगों को जो 1971 के पाकिस्तान विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे उनको नौकरी देने का फैसला किया। नौकरी प्राथमिकता पर दी जाने लगी और सरकारी नौकरियों में उन्हें 30 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इसका जबरदस्त विरोध बांग्लादेश में हुआ और इस विरोध ने शेख हसीना का व्यक्तिगत रूप ले लिया और मांग उठने लगी कि शेख हसीना इस्तीफा दो और बांग्लादेश छोड़ो। विरोध इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को रात के अंधेरे में हैलिकाप्टर से अपनी बहन के साथ, कुल दो सूटकेस और अपनी काम की चीजों के साथ, बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। वहां की फौज ने उनको बांग्लादेश छोड़ने में मदद की। फौज ने उनकी मदद इसलिए की कि यदि वे बांग्लादेश से नहीं भागतीं तो शायद उनकी हत्या कर दी जाती। उन्होंने भारत में शरण ली और भारत सरकार ने उनके हवाईजहाज को फौजी हवाई अड्डे में उतरने की इजाज़त दी और उन्हें अस्थायी शरण दी। भारत पहुंचने के बाद हमारे सुरक्षा सलाहकार उनसे मिले और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया।

अब वे तय कर रही हैं कि वे किस देश में शरण लें। उनकी सरकार के पतन से हमारे सामने बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश सही मायनों में हमारा मित्र देश है। वहां जो स्थिति बनी है उसका चीन और पाकिस्तान पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। इन दोनों देशों की नीति का विरोध करना हमारे लिए कठिन हो जायेगा। शेख हसीना के पुत्र ने भी घोषणा कर दी है कि उनकी राजनीति समाप्त हो गई है और वे शायद ही बांग्लादेश जायेंगी। उनका अध:पतन इस बात का प्रतीक है कि भले ही आप धर्मनिरपेक्ष हों परंतु यदि आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं तो आपकी धर्मनिरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं होता।

शेख हसीना की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता इस हद तक थी कि जिन रवीन्द्रनाथ टैगोर के गीत को हमने अपना राष्ट्रगान बनाया था, उन्हीं रवीन्द्रनाथ टैगौर के गीत को उन्होंने भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया था। इसके साथ ही साड़ी यदि कहीं सबसे ज्यादा पहनी जाती थी तो प्राय: बांग्लादेश में। वे स्वयं हमेशा साड़ी पहनती थीं। वहां के रहन-सहन से उन्होंने हमेशा यह बताने की कोशिश की कि वे भारत की सच्ची मित्र हैं। परंतु उनके सत्ता के घमंड के सामने यह सब नहीं टिक सका और उन्हें अत्यधिक शर्मनाक स्थिति में अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा और अपने पिता की धरोहर को खोना पड़ा।

यहां यह बताना उचित होगा कि जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई तो उस समय उनके परिवार में जितने लोग थे सबकी हत्या कर दी गई थी। परंतु शेख हसीना इसलिए बच गई थीं कि वे उस समय जर्मनी में थीं। उसके बाद उन्होंने लम्बे समय तक अपने पिता के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया परंतु वे बाद में भटक गईं हम भारतवासियों को इसका हमेशा दुख रहेगा।

ललित सुरजन की कलम से

संशयग्रस्त भारत और ओलंपिक

'एक खिलाड़ी को पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन मिले यह तो ठीक है, लेकिन अगर वह विज्ञापन से मिलने वाले करोड़ों रुपए की चकाचौंध में खो जाएं तो फिर उसका एकाग्रचित्त होकर खेल पाना मुश्किल हो जाता है। हाल के वर्षों में कुछ नए खिलाड़ियों ने जो बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कीं उनकी चमक कम पड़ जाने का कारण शायद यही है। एक बार-बार कही गई बात मुझे भी दोहराना चाहिए। हमारे खेल संगठनों पर अधिकतर राजनेता व अधिकारी कब्जा करके बैठे हैं। तर्क दिया जाता है कि यह उनका जनतांत्रिक अधिकार है। यह भी कहा जाता है कि उनके रहने से सुविधाएं हासिल हो जाती हैं। ये दोनों तर्क गलत हैं। राजनेता और अधिकारी दोनों के पास बहुत काम है। उनका प्रमुख काम न्यायसंगत नीति बनाना और उसे ईमानदारी से लागू करना है। अगर वे खेल संगठन में हैं तो उनसे अपने पद का दुरुपयोग करने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। दूसरे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ये प्रभावशाली लोग खेल संगठनों का उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं। इन्हें खिलाड़ियों से वास्तव में कोई लेना-देना नहीं होता। सच तो यह है कि अपने देश में खेल संस्कृति का विकास ही नहीं हुआ है।'

(देशबन्धु में 25 अगस्त 2016 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/08/blog-post_24.html

पावन प्रसंग

उभरती युवाशक्ति

युवा-साहस, शौर्य, संवेदना एवं शक्ति का प्रज्वलित प्रतीक है। युवा ऊर्जा का संघनित एवं में घनीभूत पुंज है। संवेदना और साहस की सघनता में ही युवाशक्ति प्रज्वलित होती है। जहां भाव छलकते हों, साहस मचलता हो, वहीं यौवन के अंगारे शक्ति की धधकती ज्वालाओं में बदलने के लिए तत्पर हैं।

विपरीतताएं इसे प्रेरित करती हैं, विषमताओं से है इसे उत्साह मिलता है। समस्याओं के संवेदन इसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। काम की कुटिल व्यूहरचनाओं की छुअन से युवाओं की यह ऊर्जा और अधिक उफनती है और तब तक नहीं थमती, जब तक कि यह उ इन्हें पूरी तरह से छिन्न-भिन्न न कर दे।

देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। अपने देश में 18-23 आयु वर्ग के करीब 15 करोड़ युवा हैं। केवल यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हम देश के सबसे बड़े जनसांख्यिकी वर्ग की जरूरतों पर ध्यान दें, बल्कि यह भी बहुत जरूरी है कि हम उन्हें रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल करें, ताकि देश के विकास के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो सके।

हमें देश के अलग-अलग भागों और विभिन्न वर्गों से भारत के भविष्य को नया आकार देने के लिए युवाओं को एकजुट करना चाहिए। इनमें किसानों से लेकर उद्योगपति और देश के शीर्ष संस्थानों के छात्र भी शामिल होने चाहिए।

युवाओं की यह नवीनतम पहल आकांक्षाओं से सराबोर युवाओं को नया आधार उपलब्ध कराएगी। युवाओं की ऊर्जा एवं उचित मार्गदर्शन बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिवेश और जन आकांक्षाओं के साथ बदलनी भी चाहिए। अतीत में अपनी जड़ों को मजबूती से जमाए हुए यह बदलती सोच परिवर्तन को आत्मसात् करती है - और इस प्रकार भारत के अतीत को इसके चमकदार भविष्य से जोड़ती है।

नए भारत की आवाज पुरानी नहीं हो सकती है। आखिरकार भारत की औसत आयु महज 24 साल है। हमें भारत के युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को सँवारने में सहायता प्रदान करनी ही चाहिए। हमें युवाओं की आकांक्षा के आधार पर उनके लिए भारत निर्माण करना है। युवा वर्ग तब तक विकास नहीं कर सकता, जब तक हम उसकी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे।

इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि हम युवा भागीदारी के बिना एक स्थायी तंत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चुनाव में किसी मसीहा को नहीं चुना जाता है, जो हमारी तरक्की के वादे करता हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, जिसके पास देश को बदलने की दृष्टि और क्षमता हो और जिसके पास ऐसे विचार हों, जो देश को नई दिशा में ले जा सकें।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे और व्यापक कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें ऐसी योजनाएँ और नीतियाँ तैयार करनी चाहिए, जिनसे सरकार आखिरी व्यक्ति की आवाज भी न सुन सके। लोकतंत्र को आम जन तक ले जाने का परिणाम है सुशासन। इसी से सभी नागरिक गरिमा के साथ जीवन जी सकते हैं और यह सुनिश्चित हो सकता है कि उनकी आवाज सुनी गई।

अखण्ड ज्योति

आपके पत्र

रोज़गार के कारण पलायन की मजबूरी

हमारा देश जिन बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रहा है उसमें रोज़गार एक प्रमुख मुद्दा है। विशेषकर हमारा ग्रामीण इलाका इससे बहुत अधिक प्रभावित है जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण शहरों, महानगरों और औद्योगिक इलाकों की ओर पलायन करने को मजबूर होता है। परिवार के लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए लोग अपने गांव से निकल कर दूसरे शहरों और राज्यों का रुख करते हैं। जहां वह खेतों, फैक्ट्रियों और दिहाड़ी मज़दूर के रूप में 16 से 17 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं जिसके बाद भी वह मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रूपए महीना कमा पाते हैं। पलायन का आंकड़ा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जहां प्रति वर्ष लाखों लोग रोज़गार की खातिर गांव छोड़कर कभी अकेले तो कभी परिवार के साथ दिल्ली, नोएडा, पंजाब, हरियाणा, सूरत, मुंबई और कोलकाता का रुख करते हैं। गांव में रोज़गार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से पलायन करना इनकी मज़बूरी हो जाती है।

गांव में राशन डीलर का काम करने वाले 47 वर्षीय पंकज के अनुसार '350 परिवारों में लगभग एक हज़ार लोगों के नाम राशन में दर्ज हैं लेकिन इनमें से अधिकतर परिवारों के पुरुष गांव से बाहर रहते हैं.' वह बताते हैं कि इनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बाहर जाने से पहले पंचायत में पलायन करने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इसकी वजह से जहां इनकी सटीक संख्या दर्ज नहीं है, वहीं इनके साथ होने वाले किसी दुर्घटना पर इन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। पंकज बताते हैं कि राज्य सरकार के नियमानुसार यदि कोई व्यक्ति कमाने के लिए राज्य से बाहर जाता है तो उसे अपना नाम पंचायत के पलायन सूची में दर्ज करानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसे अथवा उसके परिवार को उचित मुआवज़ा मिल सके। लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग ऐसा नहीं करते। वह कहते हैं कि इसके लिए गांव-गांव में प्रचार करने की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

दरअसल देश में रोजगार एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी? इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार की काफी कमी है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों से लोगों की एक बड़ी संख्या पलायन करती है हालांकि वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते समय केंद्र सरकार ने सभी सेक्टरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी खास फोकस किया है। इसमें मनरेगा समेत रोजगार के कई क्षेत्रों में बजट आवंटन को बढ़ाया भी गया है। ग्रामीण विकास विभाग का बजट गत वर्ष के संशोधित अनुमान 1.71 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.77 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) का बजट वर्ष 2023-24 के 60 हजार करोड़ की तुलना में 2024-25 में बढ़ा कर 86 हजार करोड़ रुपए किया गया है। वहीं रोजगार के क्षेत्र में भी इस बार के बजट में विशेष फोकस किया गया है जिसमें स्किल डेवलपमेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इससे पलायन की समस्या का हल हो जाएगा? वास्तव में, हमारे देश में चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों न हो, कौशल की कमी नहीं है। ज़रूरत ऐसी योजना बनाने की है जिससे उस कौशल को पलायन की जगह गांव में ही रहकर रोज़गार का अवसर मिले क्योंकि दो वक्त की रोटी की खातिर पलायन विकल्प नहीं मज़बूरी होती है।

लक्ष्मी देवी, गया बिहार

https://t.me/AllNewsPaperPdf

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोनः 011-23718195,23357784, फैक्सः 011-43581404, नोएडा कार्यालयः फोनः 0120-4114404 फैक्सः 0120-4273770

ई-मेलः deshbandhudelhi@gmail.com वेबः www.deshbandhu.co.in

दैनिक
जलते दीप

जोधपुर, बुधवार 7 अगस्त 2024

हसीना का निष्कासन

भले ही प्रथम दृष्टया, बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन की वजह आरक्षण विरोधी आंदोलन से उपजा आक्रोश बताया जा रहा हो, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह बनना बड़ा कारण रहा। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश को हल्के में लिया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि, पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। दरअसल, महज सात माह पहले हुए आम चुनावों के बाद से ही देश में जनाक्रोश धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। दक्षिणपंथी रुझान वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। हालांकि,शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। वास्तव में शेख हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। हालांकि, लगातार चौथी बार सरकार बनाने वाली शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, फलत- बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार ढंग से संभाल नहीं पायी। आंदोलनकारियों से निबटने के लिये की गई सख्ती से आंदोलन लगातार उग्र होता गया। जिसका विपक्षी राजनीतिक दलों ने भरपूर लाभ उठाया। हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने हसीना सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोल दिया। जनाक्रोश के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। निस्संदेह, सत्ता से चिपके रहने के लिये किए जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जनाक्रोश के चरम के रूप में सामने आती है। यह घटनाक्रम श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शन की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतरकर विदेश भागने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान अपने हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध थे, लेकिन हालिया उथल-पुथल को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। पाकिस्तान परस्त बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की आसन्न वापसी से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सावधान रहने की जरूरत होगी।

सुनिश्चित हो परीक्षाओं की शुचिता

प्रश्नपत्र लीक होने के सिलसिले को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ आठ राज्य सरकारों ने भी इससे संबंधित कानून बनाए हैं। हाल में बिहार सरकार ने भी बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक पारित किया है। यह सराहनीय और समयानुकूल है। सामान्य और भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या देशव्यापी है। यह जरूरी था कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इसे रोकने की दिशा में ठोस कदम उठातीं। भर्ती परीक्षाओं के अलावा सामान्य परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस काम होना चाहिए, तभी नए कानून कारगर हो पाएंगे। यह संयोग नहीं है कि नीट में प्रश्नपत्र लीक के केंद्र हजारीबाग और पटना रहे। बिहार के प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में भी दस साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इससे कानून का उल्लंघन करने वालों में अधिक भय पैदा होगा। इससे पहले बिहार में 1981 में नकल विरोधी कानून बना था। उसके तहत छह महीने की जेल और दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान था। वह कानून तनिक भी करगर साबित नहीं हुआ। बिहार ने जो नया कानून बनाया है, उसके तहत दायर मुकदमों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। पुराने कानून में ऐसा प्रविधान नहीं था। बिहार सरकार पेपरलीक कांड की जांच बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से करा सकेगी। बिहार का यह कानून जिन संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा, उनमें बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग शामिल हैं। यह सब ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि क्या स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं को कदाचारमुक्त किए बिना भर्ती परीक्षाओं में जारी कदाचार को पूर्णतः रोका जा सकता है? यह सवाल बिहार के सामने ही नहीं, सभी राज्यों के समक्ष है। आखिर आज देश के कितने राज्यों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-परीक्षा हो पा रही है? शिक्षा-परीक्षा को सुधारे बिना भर्ती परीक्षाओं के लिए कितने सुशिक्षित उम्मीदवार मिल पाएंगे? इसलिए अगले कदम के तहत राज्य सरकारों को वहां जारी गंदगी की भी सफाई के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। इस दिशा में अब तक जो भी कदम उठाए गए, वे विफल ही रहे हैं। समय-समय पर अनेक राज्यों में सच्ची परीक्षा और सच्ची पढ़ाई की कोशिशें हुईं, लेकिन निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें विफल कर दिया। वे तत्व आज भी कमजोर नहीं हुए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सरकारें हर स्तर की परीक्षाओं को कदाचार से मुक्ति के लिए अपनी कठोर इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करें। उत्तर भारत के कई राज्यों और खासकर बिहार की शिक्षा-परीक्षा में गिरावट की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1995 तक बिहार में उसकी हालत ऐसी दयनीय हो चुकी थी कि कई राज्य सरकारों ने बिहार इंटर काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को मानने से ही इन्कार कर दिया था। कई मामलों में जाली अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी जारी होने लगे थे। उस स्थिति से ऊबकर पटना हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त कदाचारमुक्त परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके चलते 1996 में बिहार में मैट्रिक और इंटर की कदाचारमुक्त परीक्षाएं हुईं। 1996 की इंटर साइंस की परीक्षा में सिर्फ 15 प्रतिशत परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो सके थे। पटना जिले में मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ 16 प्रतिशत परीक्षार्थी ही सफल हो सके। कमोबेश ऐसा ही परिणाम अन्य जिलों में रहा। नतीजतन कॉलेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों का अकाल सा हो गया। शिक्षा माफिया के पांव उखाड़ना इतना आसान काम नहीं था।

प्रसंगतः अपना अपना स्वभाव

एक बार एक भला आदमी नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा एक बिज्छू पानी में गिर गया है। भले आदमी ने जल्दी से बिज्छू को हाथ में उठा लिया। बिज्छू ने उस भले आदमी को डंक मार दिया। बेचारे भले आदमी का हाथ काँपा और बिज्छू पानी में गिर गया। भले आदमी ने बिज्छू को डूबने से बचाने के लिए दुबारा उठा लिया। बिज्छू ने दुबारा उस भले आदमी को डंक मार दिया। भले आदमी का हाथ दुबारा काँपा और बिज्छू पानी में गिर गया। भले आदमी ने बिज्छू को डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर उठा लिया। वहाँ एक लड़का उस आदमी का बार-बार बिज्छू को पानी से निकालना और बार-बार बिज्छू का डंक मारना देख रहा था। उसने आदमी से कहा, धआपको यह बिज्छू बार-बार डंक मार रहा है फिर भी आप उसे डूबने से क्यों बचाना चाहते हैं?' भले आदमी ने कहा, धबात यह है बेटा कि बिज्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब बिज्छू एक कीडा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोडता तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोडूँ?' मनुष्य को कभी भी अपना अज्छा स्वभाव नहीं भूलना चाहिए।

आरक्षण के स्वरूप में बदलाव जरूरी

यदि गीता भारत की आत्मा है, तो जाति इसका अभिशाप है। जो व्यवस्था सहस्राब्दियों पहले पेशेवर पहचान के रूप से प्रारंभ हुई, वह कालांतर में भ्रष्ट होकर चुनाव जीतने का एक पैंतरा बन गयी। जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। भारतीय राजनीति को यथास्थिति पसंद है और इसे बदलाव से परहेज है। किसी दल ने उस प्रावधान में फेर-बदल नहीं किया है। उन्होंने जाति प्रथा को अपने चुनावी घोषणापत्र के लिए आरक्षित रखा है। आरक्षण का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद की पहली वंचित पीढ़ी के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। लेकिन वह अब तीसरी पीढ़ी का एक विशेषाधिकार बन गया है।

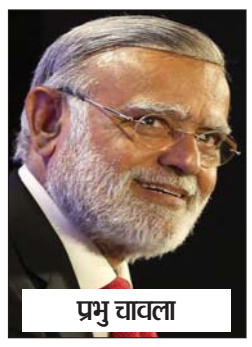
प्रभु चावला

सहस्राब्दियों से जाति भारतीय मानस में पत्थर की तरह ठोस पैठ बना चुकी है। विडंबना ही है कि लोकतंत्र बनने के बाद भी भारत में भेदभाव की विरासत जारी रही। सामाजिक ढांचे को सिर के बल खड़ा कर दिया गया, पर जाति आधारित परिवारवाद भी बिना चुनौती के फलता-फूलता रहा। राजनीति एवं नौकरशाही में धनी एवं ताकतवर वंशगत विरासत इस व्यवस्था को पोषित करती रही है। पर बीते सप्ताह आया सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस व्यवस्था को पटरी से उतार सकता है।

संसद, चुनाव एवं संस्थानों में जाति पर चल रहे वर्तमान शोर ने शीर्षस्थ न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने उद्वेलित कर दिया। न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में चार न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि जातिगत आरक्षण मेधा से संबंधित है, न कि नौकरशाही या धन तंत्र से। न्यायाधीश गवई ने लिखा है कि सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए, जिससे उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाया जा सके। इसी उपाय से संविधान में निहित समानता को सही अर्थों में साकार किया जा सकता है। उन्होंने पूछा है कि क्या एक बड़े अधिकारी की संतान को पंचायत या जिला परिषद के विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे के समकक्ष रखा जा सकता है।

यदि गीता भारत की आत्मा है, तो जाति इसका अभिशाप है। जो व्यवस्था सहस्राब्दियों पहले पेशेवर पहचान के रूप से प्रारंभ हुई, वह कालांतर में भ्रष्ट होकर चुनाव जीतने का एक पैंतरा बन गयी। जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। भारतीय राजनीति को यथास्थिति पसंद है और इसे बदलाव से परहेज है। किसी दल ने उस प्रावधान में फेर-बदल नहीं किया है। उन्होंने जाति प्रथा को अपने चुनावी घोषणापत्र के लिए आरक्षित रखा है। आरक्षण का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद की पहली वंचित पीढ़ी के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। लेकिन वह अब तीसरी पीढ़ी का एक विशेषाधिकार बन गया है।

आरक्षण का आशय समानता लाने का एक माध्यम बनना था। अब यह सामाजिक अभिजन के अल्पाधिकार और एकाधिकार का युग्म बन गया है। सत्ता पर अपने हिस्से के नियंत्रण से दलित एवं पिछड़े शाहों ने एक विशिष्ट सुरक्षा घेरा बना लिया है, जिसमें निचले पायदान पर खड़े लोगों का प्रवेश वर्जित है। जब सत्ता ने अपने लाभ को सर्वोच्च बना लिया है, तो नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का हस्तक्षेप हुआ है। न्यायाधीश गवई ने रेखांकित किया है कि विषमता और सामाजिक भेदभाव, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक व्याप्त हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर आते-आते कम होने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अच्छे संस्थानों के छात्र तथा पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र को एक ही श्रेणी में रखना संविधान के समता के सिद्धांत को भुला देना है।

न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण को पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी तक सीमित रखा जाना चाहिए तथा अगर एक पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठाकर उच्च हैसियत पा ली है, तो तार्किक रूप से अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि इस न्यायिक रुख को केंद्र और राज्य स्वीकार कर लेते हैं, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसने इस व्यवस्था का लाभ पहले उठा लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनिंदा जातियों के आरक्षण के लाभ में बदलाव कर इसे समावेशी बना दिया है तथा अब आरक्षण के दायरे में ऐसी उप-जातियां आ सकेंगी, जो पीछे रह गयी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए वे लोग योग्य नहीं हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक है। इसमें विसंगति यह है कि कृषि आय को कुल आय में नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे में जमीन वाले पिछड़े वर्ग के परिवार आरक्षण का लाभ उठाते हैं।

राजनेता न्यायिक सलाह को नहीं सुनेंगे। चूंकि आरक्षण का श्रेणीकरण विधायिका के तहत है, इसलिए ऐसी संभावना बहुत ही कम है कि नेताओं और अफसरों का गठजोड़ न्यायपूर्ण स्थिति के लिए प्रयासरत होगा। ग्रामीण भारत अभी भी अंधेरे में है, जहां तमाम अपराध होते रहते हैं। बीते तीन दशकों में राजनीति, नौकरशाही और कारोबार वंशानुगत संस्थान बन गये हैं। जातिगत आरक्षण का दुरुपयोग जाति नेताओं ने भी खूब किया है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि हर चौथे सदस्य ने अपनी सीट अपने माता-पिता से पायी है। बीते दो दशकों में आये कम से कम 20 प्रतिशत अधिकारी उसी पृष्ठभूमि से आये हैं। हाल में गरीब पृष्ठभूमि से आये कुछ युवाओं ने जगह बनायी है, पर अच्छी शिक्षा और कौशल विकास तक वंचित वर्गों के अधिकतर लोगों की पहुंच नहीं है, जो उच्च जाति के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह वरिष्ठ सरकारी नौकरियों को एक परिवार के एक सदस्य तक सीमित करना चाहते थे, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। उनका मानना था कि चयन व्यवस्था प्रभावशाली के पक्ष में है।

उस दौर में सत्ता के गलियारों में यह चुटकुला आम था कि वरिष्ठ अधिकारियों के संतानें संघ लोक सेवा आयोग की ऐसी समितियों के समक्ष साक्षात्कार देती हैं, जिनके सदस्य उनके 'अंकल और आंटी' होते हैं। एक समय तो लगभग 20 आइएएस अधिकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख सचिव के करीबी रिश्तेदार थे। वीपी सिंह का मानना था कि सेवाओं में वंशगत एकाधिकार जारी नहीं रहना चाहिए। वे मंडल कमीशन रिपोर्ट को परे रखने के लिए भी राजी थे, अगर सभी दल 'एक परिवार, एक पद' सिद्धांत पर सहमत होते। सामाजिक न्याय के उनके सूत्र पर खामोशी रही क्योंकि पार्टियां अपने वंश, वर्ग एवं जाति के समीकरण को बचाने के लिए एकजुट हो गयी थीं। सिंह ने इसका जवाब जाति की बड़ी आग लगाकर दिया, जिसकी चपेट में पूरा देश आ गया।

स्वामी विवेकानंद ने 1900 में ओकलैंड में कहा था कि पुत्र द्वारा हमेशा पिता के कारोबार का अनुगमन करने के कारण जाति व्यवस्था का विकास हुआ। सवा सौ साल बाद भी ताकतवर पिता अपने वर्ग और जाति के मशाल को अपनी संतानों को थमा रहे हैं। इस स्थिति के बदलने के आसार दूर-दूर तक नजर नहीं आते। **(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर है)**

https://t.me/AllNewsPaperPdf

वायनाड की तबाही अक्षम्य राजनीतिक अपराध का परिणाम

- के रवींद्रन

वायनाड के भूस्खलन के संदर्भ में, असली सवाल यह है कि क्या नवीनतम मसौदा अधिसूचना से सार्थक बदलाव आयेगा या यह केवल एक और रणनीति के रूप में ही काम करेगा। वायनाड में देखी गई तबाही एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि पर्यावरण क्षरण के व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है या अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।

वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन, जिसमें बस्तियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, के बाद पश्चिमी घाट के लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव क्षेत्र (ईएसए) के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नयी मसौदा अधिसूचना जारी करने के निर्णय को इस क्षेत्र की पुरानी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति एक रणनीतिक, सुविचारित दृष्टिकोण के बजाय एक जल्दबाजी में लिया गया कदम ही माना जा सकता है।

पश्चिमी घाट, जो एक एक जैव विविधता हॉटस्पॉट और एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र है, लंबे समय से विकास संबंधी दबाव और अधकचरे संरक्षण प्रयासों दोनों के निशाने पर रहा है। घाट पिछले कई वर्षों से कई पर्यावरणीय चर्चाओं और कानूनी संशोधनों का विषय रहे हैं। यहां तक कि जुलाई 2022 में जारी नवीनतम मसौदा इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास और संरक्षण के बीच जटिल संतुलन को संबोधित करने के उद्देश्य से अधिसूचनाओं की लंबी श्रृंखला में एक और पुनरावृत्ति को चिह्नित करता है।

विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों से निपटने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे यह सुनिश्चित करना था कि गांव के नाम और ईएसए सीमाओं से संबंधित विसंगतियों को ठीक किया जाये। इन उपायों के बावजूद, लगातार संशोधनों से वास्तविक परिवर्तनों के बजाय ठहराव और सतही सुधारों की एक बड़ी, अधिक परेशान करने वाली प्रवृत्ति ही देखी गई। समस्या की जड़ पर्यावरणीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक गतिशीलता के व्यापक संदर्भ में निहित है।

पश्चिमी घाट की अधिसूचना की चल रही गाथा की असलियत का पता 2011 में गाडगिल समिति की सिफारिशों से लगाया जा सकता है। प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल के नेतृत्व में, समिति ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के उद्देश्य से उपायों का एक व्यापक और कठोर सेट प्रस्तावित किया था। गाडगिल रिपोर्ट ने क्षेत्र की भेद्यता को उजागर किया और एक मजबूत सुरक्षात्मक ढांचे की वकालत की। पश्चिमी घाट के इसकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। इस ढांचे का उद्देश्य सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ प्रकार के विकास को प्रतिबंधित करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।

हालांकि, गाडगिल समिति की सिफारिशों को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष रूप से केरल से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राज्यों की आपत्तियां मुख्य रूप से संभावित आर्थिक प्रभावों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली विकास गतिविधियों में संभावित कटौती की चिंताओं से प्रेरित थीं। इस प्रतिरोध के पीछे राजनीतिक गणना स्पष्ट थी - स्थानीय आबादी की मांगों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की आर्थिक अनिवार्यताओं के विरुद्ध पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करना जिसका मुख्य उद्देश्य था।

इस प्रतिरोध की परिणति के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक दूसरी समिति के गठन में हुई, जिसने 2013 में एक संशोधित रिपोर्ट तैयार की। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने कई मूल सिफारिशों को कमजोर कर दिया, कई प्रतिबंधों में ढील दी और प्रस्तावित ईएसए की सीमा को कम कर दिया। इस समझौते को कई लोगों ने संरक्षण पर एक सैद्धांतिक रुख के बजाय राजनीतिक दबाव के आगे झुकना माना। बाद के संशोधन मूल मुद्दों को हल करने में विफल रहे और कई मामलों में, मूल सिफारिशों की अखंडता से समझौता किया।

आज की स्थिति के अनुसार, पश्चिमी घाट को ईएसए के रूप में अधिसूचित करना एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। नवीनतम मसौदा, जो जाहिर तौर पर वायनाड भूस्खलन की प्रतिक्रिया है, एक गहरी समस्या को संबोधित करने के लिए एक सतही प्रयास को दर्शाता है। भूस्खलन स्वयं इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले व्यापक पर्यावरणीय संकट के लक्षण हैं - वनों की कटाई, असंवहनीय कृषि पद्धतियों और अनियंत्रित शहरीकरण से संकट और भी बढ़ गया है। केवल एक नया मसौदा अधिसूचना जारी करने से इन अंतर्निहित मुद्दों का समाधान नहीं होता है। इसके बजाय, इसे एक प्रदर्शनकारी इशारे के रूप में देखे जाने का जोखिम है जो पर्यावरण शासन में प्रणालीगत विफलताओं को संबोधित करने में विफल रहता है।

गाडगिल समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में अनिच्छा के दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अतिक्रमण और अनियमित निर्माण सहित अवैध गतिविधियां संवेदनशील क्षेत्रों में बेरोकटोक जारी रहीं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा उल्लंघनकर्ताओं को दिया गया संरक्षण, जो अक्सर चुनावी लाभ और आर्थिक प्रोत्साहन से प्रेरित होता है, ने वास्तविक संरक्षण प्रयासों को कमजोर कर दिया है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि माधव गाडगिल जैसे पर्यावरणविद, जो मजबूत सुरक्षात्मक उपायों की वकालत करते हैं, अक्सर यथास्थिति से लाभ उठाने वालों द्वारा बदनाम किये जाते हैं और उन्हें बाधा डालने वाले या यहां तक कि %पारिस्थितिकी आतंकवादी' करार दिया जाता है।

वायनाड के भूस्खलन के संदर्भ में, असली सवाल यह है कि क्या नवीनतम मसौदा अधिसूचना से सार्थक बदलाव आयेगा या यह केवल एक और रणनीति के रूप में ही काम करेगा। वायनाड में देखी गई तबाही एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि पर्यावरण क्षरण के व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है या अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। मसौदा अधिसूचनाएं जारी करने का बार-बार चक्र, उसके बाद संशोधन और रुकावट, पर्यावरण क्षरण को संबोधित करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। पश्चिमी घाट को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय संकटों के असली कारणों की पहचान करना आवश्यक है।

पश्चिमी घाट में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के तरीके में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। अल्पकालिक राजनीतिक और आर्थिक लाभों के बजाय वैज्ञानिक साक्ष्य और दीर्घकालिक स्थिरता द्वारा निर्देशित, विकास संबंधी आवश्यकताओं को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इन उपायों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ पर्यावरणीय मानकों को बनाये रखने और उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने की वास्तविक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए।

पश्चिमी घाट के मुद्दों को केवल प्रशासनिक इशारों से हल नहीं किया जा सकता। एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व का सम्मान करता हो और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को शामिल करते हुए संरक्षण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हो। तभी हम आगे की आपदाओं को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें।

सम्पादकीय

डेरिवेटिव कारोबार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था पर असर

आधुनिक एवं सक्षम बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य में होने वाले बदलाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच मिलने वाले संकेतों से मांग एवं आपूर्ति के मोर्चों पर हरकत होने लगती है। ये उतार-चढ़ाव दीर्घ अवधि में असहज एवं नुकसानदेह हो सकते हैं। मगर वित्तीय डेरिवेटिव बाजार ऐसे माध्यम तैयार करते हैं जिनका सहारा लेकर कुछ निश्चित भुगतान करने के बदले लघु एवं मध्यम अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल असर से बचा जा सकता है। वित्तीय डेरिवेटिव के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर, अधिक परिपक्व एवं लेनदेन के लिहाज से आसान बाजार तैयार करने की प्रक्रिया बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना के संग-संग चलती है। पिछली एक पीढ़ी के दौरान इन मोर्चों पर प्रगति हुई है, यह अलग बात है कि इस पर काफी अधिक खर्च आया है। इसमें कोई शक नहीं कि निवेशकों को गुमराह कर की जाने वाली कुछ डेरिवेटिव योजनाओं की बिक्री रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं मगर बाकी के लिए बुनियादी हालात बदलना अधिक खर्चीला साबित होगा। भारत में समाजवादी व्यवस्था में सरकार ने कई वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित की थीं। कभी-कभी तो कानून में नियत मूल्य की परिभाषा भी तय की गई और इसका उल्लंघन करने पर कड़े दंड के प्रावधान किए गए। अन्य अवसरों पर कानून के माध्यम से यह तय कर दिया कि कौन लेनदेन कर सकता है (मसलन केवल बैंक एवं प्राइमरी डीलर को अनुमति मिली) और लेनदेन कहां हो सकते हैं (उदाहरण के लिए केवल कृषि उत्पाद विपणन समिति में)।

इन कायदों का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था नियंत्रित करने के लिए कई नियम-कायदे तैयार कर डाले थे, जिनका इस्तेमाल कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नजर एवं नियंत्रण रखने (जैसे निर्यात एवं आयात पर प्रतिबंध के माध्यम, नियमन के स्तर पर बदलाव आदि से) के लिए किया गया था। एक बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरह के लोगों की अलग-अलग गतिविधियां आपूर्ति एवं मांग निर्धारित करती हैं। आपूर्ति एवं मांग पर नियंत्रण का असर सीधे कीमतों पर पड़ता है। समाजवादी व्यवस्था से संपन्नता की तरफ कदम बढ़ाते हुए हम एक ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं जिसमें कीमतें पहले सरकार के नियंत्रण में रहती हैं मगर बाद में ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहती हैं। सुधार का वास्तविक अर्थ मात्रा एवं कीमतों पर लगी पाबंदी हटाना है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मांग एवं कीमतों में बदलाव होते रहते हैं। कीमतों में उतार-चढ़ाव अच्छी बात होती है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था को संकेत भेजते हैं जिससे बाजार में बेहतर तालमेल स्थापित हो पाता है। जब रुपये में अवमूल्यन होता है तो आयात अधिक महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है और भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियां विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार परिस्थितियां जब स्वतः बदलती हैं तो इससे आर्थिक संपन्नता को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोग यह चाह रखते हैं कि उनका आने वाला कल भी उनके आज की तरह हो।

निरंकुशता के कारण हसीना का निष्कासन

जब-जब जिन-जिन देशों में जनता की आवाज को दबाया गया, एक विस्कोटक स्थिति बनी, क्रांति का शंखनाद हुआ। मान्य सिद्धान्त है कि आदर्श ऊपर से आते हैं, क्रांति नीचे से होती है। बांग्लादेश में क्रांति एवं विद्रोह का कारण भी यही स्थिति बना कि ऊपर से आदर्श की स्थितियों पर धुंधलका छाने लगा तो ₹ ांति नीचे से होने लगी, बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसने लगा, आगजनी, तोड़फोड, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गये, सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश एवं जनता के विद्रोह को हल्के में लिया। वास्तव में हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव एवं घाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

ललित गर्ग

बांग्लादेश में जनभावना को दबाने एवं अनसूना करने से पनपे विद्रोह, आक्रोश एवं विरोध की निष्पत्ति है शेख हसीना सरकार का पतन। लम्बे समय से चला आ रहा आरक्षण विरोधी आंदोलन का आक्रोश उग्रतम होता गया, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह एवं निरंकुश बनना बड़ा कारण रहा। जनभावनाओं को कुचला जाना एवं अनसूना करने के कारण ही हसीना आनन-फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा। उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे बगावती प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। बांग्लादेश बेहाल हो गया, हिंसक एवं अराजक घटनाएं कहर बन कर हसीना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा रही थी। जैसी आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप के श्रीलंका, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति भारत सरकार को सतर्क एवं सावधान रहने के साथ अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। निश्चित ही पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि, शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक एवं असंगत आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, फलतः बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार ढंग से संभाल नहीं पायी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया। जनाक्रोश के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। निस्संदेह, सत्ता से चिपके रहने के लिये किए जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जनाक्रोश एवं जनान्दोलन के चरम के रूप में सामने आता ही है। ताजा घटनाक्रम एवं हिंसक आंधी श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शन की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतरकर विदेश भागने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान अपने हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना होगा। नयी व्यवस्था एवं सोच में व्यापक सकाकरात्मक परिवर्तन हो, विदेशी ताकतों विशेषतः पाकिस्तान की कठपूतली बनने से बचना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध थे, भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी, सहयोगी और दुख के दिनों का साथी रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त जर्मनी में थी। इसलिए जिंदा बच गई थी। तब तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन को भारत बुलाया था एवं संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन हालिया उथल-पुथल को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। पाकिस्तान परस्त बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की आसन्न वापसी भारत के लिये सावधान होकर अग्र-स्थितियों पर गंभीरता से ध्यान देने की है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

वृष
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मिथुन
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

कर्क
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

सिंह
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

कन्या
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

तुला
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

वृश्चिक
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

धनु
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

मकर
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

मीन
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

शख्सियत

यदि आसानी से हम जीत गए तो कोई जरूरी नहीं तालियों की गडगड़ाहट सुनने को मिले ,लेकिन यदि संघर्ष के साथ हार भी गए तो सारी बजने वाली तालियां तुम्हारें ही हिस्से की ही होंगी ये तय है ......

पवन जैन (चौधरी)
(युवा समाजसेवी व उद्योगपति)

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत हैं युवा उद्योगपति व समाजसेवी पवन जैन (चौधरी) अपने पिता पारस मल जी जैन के पदचिन्हों पर चल कर समाज को नई दिशाए दिखाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। 4अप्रेल सन् 1967 में बड़ौदाकान, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पवन जैन का आज तक का जीवन संघर्ष से जुडा हुआ है। कक्षा 6 तक की शिक्षा गांव में प्राप्त की साथ में अपने दादाजी के साथ उनके कार्य में हाथ बटाया। पिताजी सरकारी नौकरी में अजमेर से ट्रांसफर होकर 1978 में अलवर आए तभी आगे की शिक्षा अलवर में ग्रेजुएशन तक रही । इनकी शुरू से तमन्ना रही कि नौकरी नहीं करनी अपना ही कोई व्यापार करना है जिसके लिए पढ़ाई के साथ साथ किताबो की जिल्द चढ़ाने, कुर्सी की केनिंग करना,टाइपिंग के साथ-साथ कपड़े की दुकान पर नौकरी की ओर बाद में कपड़े का ही अपनी कर्म भूमि मानकर उसमे ही अपना भाग्य आजमाना शुरू किया और 1991 में बहुत कम पूंजी से न्यास कॉम्प्लेक्स हॉप सर्कस पर अपना स्वयं का कपड़े का छोटे से स्तर से थोक व्यापार शुरू किया । अपनी मेहनत और लगन से छोटे भाई मुकेश को भी साथ लेकर प्रभु के आशीर्वाद से सन 2000 तक जिले में एक अच्छे थोक वस्त्र व्यापारी की पहचान बनाई। सियाराम के मिस्टेयर ब्रांड का लगातार 18-20 साल से राजस्थान में सेल में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। साथ में भीलवाड़ा और मुंबई की 12-15 कंपनियों की एजेंसी लेकर कार्य कर अपना एक नाम कायम किया। इसी बीच एक दम नए व्यापार कंट्रेक्सन लाइन में भाग्य अजमाने के लिए 2019-20 में अलवर के खेरली कस्बे में जाकर 24 एकड़ की एक आवासीय कॉलोनी नवकार वाटिका डवलप करने का बीड़ा उठाया और प्रति दिन 200 किलोमीटर का अप डाउन कर आज उसमे सभी सुविधाओं युक्त 80 से 90 परिवार रह रहे है आगे काम जारी है। 1995 में वस्त्र व्यापार समिति के सहमंत्री पद से अपनी समाज सेवा की शुरुआत की उसके पश्चात लंबे समय तक मंत्री-अध्यक्ष थोक वस्त्र व्यापार समिति, महामंत्री अलवर जिला वस्त्र व्यापार,फाउंडर मंत्री संयुक्त व्यापार महासंघ आदि विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने व्यापारी भाईयो के हकों के लिए कार्य किया और एक जुझारू इंसान के रूप में पहचान बनाई । समाज सेवा में लाइंस क्लब अलवर के विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्ष 2000 में रीजन चेयर मैन पद पर रहते हुए बेस्ट रीजन चेयर मेन का अवॉर्ड मिला एलाइंस क्लब में रहते हुए बहुत से कैंप आयोजित किए अपने पैतृक गांव में 6-7 वर्ष लगातार आई कैंप लगा हजारों ग्रामीण वासियों के नि:शुल्क शिविर लगा पीड़ित मानव की सेवा कर पुण्य एकत्रित किया बाद में सरकार द्वारा ग्रामीण शिविर बंद करने पर वहां से अलवर जिला अस्पताल में नेत्र आपरेशन कराए । इसी कड़ी में 1992 से अब तक 71 बार अपना रक्तदान कर अपना कर्तव्य निर्वहन किया । बेजुबानों के दर्द को समझते हुए ढहरा मोड़ नदबई में जैन गोशाला के फाउंडर मेंबर के रूप में पूर्ण समर्पण से कार्यरत । यहीं नहीं पवन जैन साधु संतों की सेवा में भी अग्रणी हैं। कभी 200 रुपए की नोकरी करने वाला व्यक्ति 200 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है जिसे भी वो अपना नही केवल प्रभु का एवम गुरुओं का आशीर्वाद मानते है। अंतिम इच्छा सिर्फ एक है, तन- मन-धन सभी से सेवा की लेकिन अंत में मरणोपरांत अपना सम्पूर्ण शरीर भी किसी पीड़ित मानव की सेवा में काम आ सके इसलिए दान देने हेतु परिवार की सहमति की इच्छा। दैनिक बढ़ता राजस्थान टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिन्द

आज का इतिहास

7 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- प्रसिद्ध न्यूटन ने 1668 में ट्रिनीटी कॉलेज कैंब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल किया।
- ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना 1753 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई।
- उचित वक्ता 1880 को पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया।
- रूस ने 1914 में पूर्वी परूसिया पर हमला किया।
- 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और पांच टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण 1944 में हुआ।
- मुंबई नगर निगम को 1947 में बिजली और परिवहन व्यस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई।
- अमेरिका ने 1957 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
- लैंसिंग, मिशिगन में 1966 को नस्लभेदी दंगे भडके।
- गीत सेठी 1985 में विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने।
- अमेरिका ने 1990 में सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की शुरूआत की।
- इजरायल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा 1994 में शुरु हुई।
- अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता 1996 को चला।
- केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर 1998 में आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु।
- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने 1999 में एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की।
- रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा 2000 में एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार।

विशेष आलेख

मनु भाकर क्यों बन गयीं सभी खिलाड़ियों के लिए आदर्श

आर.के.सिन्हा।

निशानेबाज मनु भाकर को अब सारा देश जानता है। पेरिस ओलंपिक खेलों में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी चौथे स्थान पर रहीं। उनके पेरिस ओलंपिक खेलों में अभूतपूर्व प्रदर्शन से सारा देश प्रसन्न है। मनु भाकर सिर्फ अचूक निशानची ही नहीं हैं। वो तो देश के अधिकतर खिलाड़ियों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी हमेशा भरपूर ध्यान दिया। हरियाणा के झज्जर शहर की रहने वाली मनु भाकर ने 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 90 पर्सेंट से अधिक अंक अर्जित किए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्लाय के लेडी श्रीराम कॉलेज (एलएसआर) से पालिटीकल साईंस आनर्स की डिग्री भी ली। एल0 एस0 आर0 देश का चोटी का महिला कॉलेज माना जाता है। नोबल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की शिखर नेता आंग सान सू ची यू ने 1964 में इसी लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मुन भाकर का लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ना इस बात की गवाही है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी हमेशा फोकस रखा।

इधर बीते कुछ सालों से हमारे अपने देश के बहुत सारे नामवर खिलाड़ियों ने स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं मानी जा सकती। आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों न हो जाएं, पर आप बेहतर इंसान और नागरिक तो ढंग से पढ़-लिखकर ही बनते हैं। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी, क्रिकेटर अजीत वाडेकर और सुनील गावस्कर उन खेलों की दुनिया के शिखर नाम रहे हैं, जिन्होंने खेल के मैदान में जौहर दिखाते हुए अपनी पढ़ाई को नजरअंजाद नहीं किया। चुन्नी गोस्वामी और अजीत वाडेकर तो स्टेट बैंक में अहम पदों पर इसलिए पहुंचे , क्योंकि ; इनके पास सही डिग्रियां थीं। सुनील गावस्कर बीते पांच दशकों से सक्रिय हैं। पहले क्रिकेटर के रूप में और बाद के दशकों में बतौर लेखक और कमेंटेटर के। उनके पास क्रिकेट की गहरी समझ के अलावा शब्दों का भंडार भी है। वैसे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के आधार पर नौकरी तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल ही जाती हैं। माफ करें, कई कथित खिलाड़ियों को जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर भी नौकरियां मिलती रही हैं। यह भी सबको पता है।

सारी दुनिया ने मनु भाकर को बीत दिनों मीडिया को इंटरव्यू देते हुए देखा। इतनी छोटी सी उम्र में वह कितने धीर-गंभीर अंदाज में अपनी बात रखती है। वह गीता का उदाहरण देते हुए सफलता के मर्म को समझाती है। मनु भाकर हिन्दी और अंग्रेजी में पूरे विश्वास के साथ सवालों के जवाब देती है। यही सही शिक्षा सिखाती भी है। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अधिकतर खिलाड़ियों को देख लें। जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर जैसे मशहूर खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में भले ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हों, पर वे जब बोलते हैं तो सच में बहुत अफसोस होता है कि बेहतर शिक्षा ना मिलने के कारण वे अपने व्यक्तित्व निर्माण में कितना पिछड़ गए। वे इंटरव्यू देते वक्त पूरी तरह से सड़क छाप ही लगते हैं। बेशक,शिक्षा ही जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। एक सफल जीवन में सार्थक शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा जीवन का आधार है, और शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, सही गलत में अंतर कर पाता है। शिक्षा और संस्कार एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके संस्कार सही है तो आपकी शिक्षा भी सही दिशा में जाएगी। मनु भाकर और दूसरे खिलाड़ियों के कोचों का दायित्व है कि वे युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाएं, ताकि आने वाला कल अच्छा हो।

उन्हें शिक्षा के महत्व की जानकारी दें। मनु भाकर के अलावा भी हमारे यहां बहुत सारे खिलाड़ी साबित करते रहे हैं कि खेलों में सफलता के साथ-साथ पढ़ाई करना भी संभव है। यह सट है कि पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए बहुत समर्पण और मेहनत चाहिए। इसके अलावा, व्यक्ति को अपने खेल के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तमाम कठिनाइयों और संघर्षों के बीच, अधिकांश एथलीटों के लिए पढ़ाई पीछे छूट जाती है। पर इस तरह के खिलाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, जिन्होंने अपने खेल और पढ़ाई के बीच सही संतुलन बनाया और दोनों क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। ये व्यक्ति बौद्धिक और शारीरिक शक्ति का शानदार उदाहरण हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के हाल तक कोच रहे राहुल द्रविड़ को दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सभी प्रारूपों में 23,000 से अधिक रन हैं। राहुल द्रविड़ ने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री भी हासिल की है, जिसे उन्होंने बैंगलोर के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से प्राप्त किया। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने से पहले, वह एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। कर्नाटक और भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के साथी

अनिल कुंबले ने सभी प्रारूपों में 900 से अधिक विकेट लिए हैं और टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच भी रहे हैं। उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की बात कर लेते हैं।

विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं। वह पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं और उन्हें शतरंज के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जा सकता है। शतरंज के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों ने उनकी शिक्षा को बाधित नहीं किया। उनके पास चेन्नई के लोयोला कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। यह हरेक इंसान को समझन होगा कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्यों इतना महत्व है और हर व्यक्ति को शिक्षित होना क्यों जरूरी है? सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षित लोग अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा, शिक्षा हमें समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। शिक्षित लोग अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। मनु भाकर यह साबित करती है कि हरेक इंसान के लिए शिक्षा कितनी अहमियत रखती है।

निरंकुशता के कारण हसीना का निष्कासन

-ललित गर्ग

बांग्लादेश में जनभावना को दबाने एवं अनसूना करने से पनपे विद्रोह, आक्रोश एवं विरोध की निष्पत्ति है शेख हसीना सरकार का पतन। लम्बे समय से चला आ रहा आरक्षण विरोधी आंदोलन का आक्रोश उग्रतम होता गया, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह एवं निरंकुश बनना बड़ा कारण रहा। जनभावनाओं को कुचला जाना एवं अनसूना करने के कारण ही हसीना आनन-फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा। उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे बगावती प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। बांग्लादेश बेहाल हो गया, हिंसक एवं अराजक घटनाएं कहर बन कर हसीना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा रही थी। जैसी आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप के श्रीलंका, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति भारत सरकार को सतर्क एवं सावधान रहने के साथ अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

जब-जब जिन-जिन देशों में जनता की आवाज को दबाया गया, एक विस्कोटक स्थिति बनी, क्रांति का शंखनाद हुआ। मान्य सिद्धान्त है कि आदर्श ऊपर से आते हैं, क्रांति नीचे से होती है। बांग्लादेश में क्रांति एवं विद्रोह का कारण भी यही स्थिति बना कि ऊपर से आदर्श की स्थितियों पर धुंधलका छाने लगा तो क्रांति नीचे से होने लगी, बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसने लगा, आगजनी, तोड़फोड, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गये, सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश एवं जनता के विद्रोह को हल्के में लिया। वास्तव में हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव एवं घाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। निश्चित ही पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया। लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।

हालांकि, शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक एवं असंगत आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, फलतः बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार ढंग से संभाल नहीं पायी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया। जनाक्रोश के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ह्यबंगबंधुह्न शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। निस्संदेह, सत्ता से चिपके रहने के लिये किए जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जनाक्रोश एवं जनान्दोलन के चरम के रूप में सामने आता ही है।

ताजा घटनाक्रम एवं हिंसक आंधी श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शन की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतरकर विदेश भागने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान अपने हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना होगा। नयी व्यवस्था एवं सोच में व्यापक सकाकरात्मक परिवर्तन हो, विदेशी ताकतों विशेषतः पाकिस्तान की कठपूतली बनने से बचना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध थे, भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी, सहयोगी और दुख के दिनों का साथी रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त जर्मनी में थी। इसलिए जिंदा बच गई थी। तब तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन को भारत बुलाया था एवं संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन हालिया उथल-पुथल को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। पाकिस्तान परस्त बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की आसन्न वापसी भारत के लिये सावधान होकर अग्र-स्थितियों पर गंभीरता से ध्यान देने की है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना का विरोध कर रहे छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के नाम का समर्थन किया है। शेख हसीना और यूनुस का आपस में बहुत तनाव रहता था। अब यूनुस से उम्मीद की जा रही है कि वह देश को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। भारत पडोसी देश के नाते बांग्लादेश में स्थिरता, शांति एवं सौहार्दपूर्ण स्थितियों की कामना करता है।

भारत- बांग्लादेश, अब दोनों देशों के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा?

अशोक भाटिया

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल तख्ता पलट तक पहुंच गया है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आकर शरण लेनी पड़ी है। वहीं, बांग्लादेश में बवाल चरम पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हालात और सुरक्षा की समीक्षा के लिए बैठक कर चुके हैं। इन सबके बीच आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध? कैसे पड़ी थी इसकी नींव? और दोनों देश एक-दूसरे से क्या खरीदते-बेचते हैं और अब क्या दोनों देशों के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा?

पहले भारत-बांग्लादेश ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इसकी नींव साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के साथ ही पड़ गई थी। पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की बांग्ला भाषी जनता को राहत दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम यहां तक कह सकते हैं कि भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद आज बांग्लादेश का अस्तित्व भी नहीं होता। आज भारत ने बांग्लादेश में तखता पलट के बाद फिलहाल आवागमन से जुड़ी सभी सेवाएं रोक दी हैं। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तीस्ता सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए बातचीत चल रही है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी हुई थी। चीन की इस प्रोजेक्ट पर बुरी नजर है क्योंकि अब पीएम शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं।

फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज के मुखिया डॉ. संदीप त्रिपाठी का मानना है कि भारत के लिए यह कठिन समय है। शेख हसीना युग के समापन के बाद बांग्लादेश में अब वह सब कुछ होगा, जो चीन-पाकिस्तान चाहेंगे। आर्थिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या रेल प्रोजेक्ट या विकास की अन्य योजनाएं, भारत का अब वह प्रभाव नहीं रहेगा। भारत को चौकन्ना रहना होगा। बिजनेस की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी।

डॉ. त्रिपाठी के मुताबिक 34 फीसदी कॉटन का आयात भारत बांग्लादेश से करता है। शेख हसीना के राज में साल 2009 से अब तक जो कुछ भी सकारात्मक चीजें हुई हैं, वह सब रुक सकती हैं। उधर, शेख हसीना का इस्तीफा हुआ, उन्होंने देश छोड़ा और बांग्लादेश खालिदा जिया की रिहाई के आदेश राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने कर दिए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश की स्थिति काबू में नहीं है। अभी बांग्लादेश में सेना का शासन है। वहां की हालात तेजी से बदल रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश की हालत का असर पड़ सकता है। डाबर से लेकर ट्रेंट तक कई भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश में बाजार या सप्लाई चेन कंपोनेंट के रूप में भागीदारी है। दरअसल, उच्च गुणवत्ता के रेडीमेड गारमेंट तैयार करने के लिए बांग्लादेश जाना जाता है। सस्ती लेबर और कच्चे माल की बांग्लादेश में पर्याप्त उपलब्धता है। इसलिए वहां तैयार होने वाले कपड़ों की फिनिशिंग और गुणवत्ता दुनिया में बेहतर मानी जाती है। इसलिए कई नामी कंपनियों के कपड़े बांग्लादेश में ही बनते हैं। भारत के भी तमाम बड़े ब्रांड बांग्लादेश में कपड़े तैयार कराते हैं या फिर वहां से कच्चा माल उठाकर लाते हैं और फिर उसे तैयार कराते हैं। हाई क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट को तैयार करने के लिए बांग्लादेश फेमस है। यहां पर सस्ते दामों पर मजदूर और कच्चा माल मिल जाता है। इसीलिए यहां पर तैयार होने वाले कपड़ों की फिनिशिंग और क्वालिटी दुनिया में काफी अच्छी मानी जाती है। भारत के बड़े-बड़े ब्रांड या तो बांग्लादेश में कपड़े तैयार करवाते हैं या फिर वहां से कच्चा माल वहां से मंगवाते हैं और फिर उसे अपने ही देश में तैयार करवाते हैं।

कपड़ों के अलावा भारत बांग्लादेश से मसाले, जूट, प्राकृतिक रबर, खाद्य तेल, सब्जी तेल, व समुद्री उत्पाद का आयात करता है। जबकि भारत से 6052 कमोडिटी का निर्यात करता है। इसमें चावल, रुई, पेट्रोलियम उत्पाद, सूती कपड़ा, गेहूं और गेहूं से बने उत्पाद, मसाले, सब्जी, चीनी, फल, खाद्य तेल व अन्य उत्पाद शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 1220 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है।

व्यापारियों का कहना है कि, हिंसा के बाद से कुछ उत्पादों के आयात और निर्यात में असर दिख रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में फैक्ट्रियों व मंडियों से कंटेनर डिपो (बंदरगाह) माल पहुंचाने में परेशानी हो है। उसी तरह से जो माल यहां से भेजा (निर्यात) जा रहा है, उसका उठान भी पूरी मात्रा में नहीं हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो कुछ उत्पादों की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है।

इसके पहले भी बांग्लादेश में सैन्य शासन आया था। सैन्य शासन आते ही भारत के अहसान भुलाकर सीमा विवाद, विद्रोह और पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी शासकों ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी थी। हालांकि, साल 1996 में शेख हसीना की सरकार बनी तो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया। इससे दोनों देशों के संबंधों में फिर से सुधार आना शुरू हुआ। वैसे भी भारत की नीति है कि पड़ोसी पहले। अपनी इसी नीति पर चलते हुए भारत ने साल 2010 के बाद से बांग्लादेश को सात बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता कर्ज के रूप में प्रदान की है। दोनों देशों ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते के साथ ही पानी के बंटवारे और समुद्री सीमा विवाद को भी हल करने में सफलता हासिल कर ली।

भारत और बांग्लादेश लगातार ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते रहे हैं। पिछले दशक में भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था जो साल 2021-2022 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, साल 2022-23 में कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इनके बीच व्यापार में गिरावट देखने को मिली।

साल 2021-22 में भारत ने 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चावल और 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चीनी और 43 करोड़ डॉलर से ज्यादा के दूसरे अनाजों का निर्यात किया था। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को हरी सब्जियों, फलों के साथ ही मसालों और खाद्य तेल का निर्यात भी किया जाता रहा है इसके अलावा हाल के सालों में बांग्लादेश जेनरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मुख्य निर्यातक बन रहा था। भारत भी बांग्लादेश से फार्मास्यूटिकल उत्पादों और इससे जुड़े कच्चे माल का आयात करता है। भारत मसाले और समुद्री उत्पाद जैसे मछली आदि भी बांग्लादेश से मंगाता है।

बांग्लादेश से भारत केवल कपड़ों के माल का ही आयात नहीं करता है। बल्कि जूट, रबर, खाद्य तेल और सब्जी तेल का भी आयात करता है। वहीं भारत भी काफी कुछ निर्यात करता है। इसमें चावल, रुई, सूती कपड़ा, गेंहू और गेंहू से बने प्रोडक्ट, मसाले, सब्जी, चीनी, फल और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 1220 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। बात करें बांग्लादेश से भारत आने वाले सामानों की तो फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में 1154 सामानों का आयात किया गया। यह करीब 2.02 अरब डॉलर का था। वहीं, इससे पिछले फाइनेंसियल ईयर में यह आंकड़ा महज 1.97 अरब डॉलर ही था।

VIP लगेज निर्माता कंपनी का बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी लगभग 30 से 35% क्षमता यहां से आती है। ऐसे में इस क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर हो सकता है।मैरिको इंटरनेशनल मार्केट का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो कुल रेवेन्यू का एक चौथाई से अधिक हिस्सा है। मैरिको के अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू का लगभग 44% बांग्लादेश से आता है। डाबर, जीसीपीएल और ब्रिटानिया एक बडी एफएमसीजी कंपनी है। यहां से कंपनी का 5 प्रतिशत से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। ऐसे में इन कंपनियों के रेवेन्?यू पर भी असर हो सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज ऑपरेटर के बांग्लादेश में 28 स्टोर हैं, जो इसकी कंसॉलिडेटेड सेल का लगभग 1% है। ऐसे में यह बिजनेस भी प्रभावित होगा। बांग्लादेश टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट के लिए सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के साथ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यहां से बड़ा बिजनेस टाटा ग्रुप को मिलता है। कपड़े से लेकर कार और अन्य बिजनेस के लिए अच्?छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका असर अब कंपनियों के मुनाफे पर दिखाई दे सकता है।

बांग्लादेश में संकट के बीच एशिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बांग्लादेश में ऑफिस 7 अगस्त तक बंद कर दिया है। छक्ह ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, ‘बांग्लादेश में मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के कारण एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का ऑफिस 05 अगस्त 2024 से 07 अगस्त 2024 तक की अवधि के दौरान बंद रहेगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच में मजबूत संबंधों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने भारतीय रुपये में ट्रेड शुरू करने का एक अहम कदम उठाया था। भारत में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था और 22 जून को पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान कई सारे समझौतों पर भी मुहर लगाई गई थी। इसमें दोनों देशों के बीच में रुपयों में व्यापार करना भी शामिल था।

बांग्लादेश में चीन और आईएसआई ने मिलकर जो साजिश रची थी, वह सफल हो गयी है

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया और कई मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से अपने घर में नजरबंद खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी आ गया। यदि आप बांग्लादेश में हाल में घटी सारी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि यह सब कुछ तय पटकथा के हिसाब से हुआ है। इसलिए शेख हसीना सरकार का जाना और खालिदा जिया का कैद से बाहर आना भारत के लिए चिंताजनक खबर है। पहले ही डुरंड लाइन के नाम से मशहूर भारत और अफगानिस्तान सीमा तथा पाकिस्तान व चीन से लगती सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर भी सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण हो गये हैं। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटा है यदि उसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि हमें घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जो प्रयास लंबे अर्से से कर रहे थे उसमें वह कुछ हद तक कामयाब हो गये हैं।

दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करता और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता हिंदुस्तान हमारे दुश्मनों को नहीं भा रहा है। इसलिए भारत में अशांति फैलाने के लिए तमाम प्रयास किये जाते हैं। दुश्मनों को लगता है कि भारत ने आतंक और उग्रवाद पर काबू पाने में जो सफलता पाई है कैसे उसे विफल करा जाये। इसके लिए वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और सीधी लड़ाई से बचते हुए दायें या बायें से वार करना चाहते हैं।

दुश्मन को जम्मू-कश्मीर की शांति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति नहीं भा रही है। दुश्मनों ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंक और उग्रवाद को हवा देने के लिए तथा भारत को इस दंश से जूझने के लिए जो कड़ी मेहतन की थी उस पर पिछले दस सालों में पानी फेर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी कमांडरों और अलगाववादियों का सफाया हो चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भी अपेक्षाकृत शांत हो गया है। वहां के कई उग्रवादी संगठन सरकार से समझौता कर मुख्यधारा के जीवन में लौट आये हैं। उग्रवादी और आतंकी संगठनों को मिलने वाली टैरर फंडिंग पर भी रोक लग गयी है। जाहिर है यह सब पाकिस्तान और चीन को नहीं भा रहा था। खासतौर पर शेख हसीना के कार्यकाल में जिस तरह बांग्लादेश सरकार भारत को वरीयता देती थी उससे भी चीन नाखुश रहता था। ऐसे में चीन इस ताक में था कि कैसे इस स्थिति को बदला जाये। चीन को परेशान देख पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मदद के लिए प्रस्ताव रखा और फिर योजनाबद्ध तरीकों से चीजों को आगे बढ़ाया गया।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर (आईसीएस) को पाकिस्तान में काम कर रही कुछ चीनी कंपनियों की ओर से फंडिंग भी दी गयी थी। इन पैसों का इस्तेमाल बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जनभावनाएं भड़काने और छात्रों का आंदोलन खड़ा करने में किया गया था। बताया जा रहा है कि चीन और आईएसआई की मिलीभगत से यह तय किया गया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए कब क्या किया जाना है। इस्लामी छात्र शिबिर आईएसआई के बेहद नजदीकी माने जाने वाले देवबंदी आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) के साथ काम रहा था।

बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां लंबे समय से इस्लामी छात्र शिबिर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं क्योंकि उन्हें खबर लगी थी कि भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस्लामी छात्र शिबिर के कुछ सदस्यों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण भी दिलाया गया था। इस संबंध में कुछ वीडियो भी हाल के दिनों में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। बताया जा रहा है कि इन सबका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान के तालिबान जैसी सरकार बनाई जा सके। इस संबंध में आईएसआई ने पूरी मदद और समर्थन का भरोसा भी इस्लामी छात्र शिबिर को दिलाया था। यह सारे समूह चाहते थे कि दिन पर दिन जिस तरह भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। चीन भी देख रहा था कि जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विभिन्न मुद्दों पर चीन को वरीयता देने की बजाय भारत के साथ खड़ी हो जाती हैं उस स्थिति से तभी छुटकारा मिल सकता है जब बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बन जाये।

जहां तक बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की बात है तो उसने कभी भी भारत विरोधी रवैया अख्तियार करने का मौका नहीं गंवाया। बताया जा रहा है कि बीएनपी के कार्यकताओं ने इस्लामी छात्र शिबिर के साथ मिलकर सरकार विरोधी आंदोलन को हवा दी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। इसके अलावा, बांग्लादेश सेना जिस तरह कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकती दिख रही है और देश को अराजकतावादियों के हाथों में जाते देख रही है उससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

बहरहाल, भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले रोकने की दिशा में कदम उठाने के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष निगाह रखनी होगी। यहां किसी भी राज्य में सरकार विरोधी आंदोलन को अगर हवा दी जाती है तो उसे तत्काल थामना होगा। दरअसल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत ने शांति को स्थापित करने के लिए जो मेहनत की है उसको बाधित करने के लिए उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इसलिए बहुत सतर्क रहना होगा। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, नशीली दवाओं और मानव तस्करी पर लगाम लगाने और नकली मुद्रा से संबंधित मुद्दों के समाधान की दिशा में जो सफलता प्राप्त की है, उसे भी विफल करने के प्रयास किये जायेंगे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

प्रकृति की चेतावनियों को अनसुना करना ठीक नहीं

प्रकृति का अत्यधिक दोहन और छेड़छाड़ के दुष्परिणाम वायनाड, जोशी मठ और केदारघाटी के तौर पर हमारे समक्ष हैं। प्रकृति बार बार किसी ने किसी घटना या तरीके से पूरी मानव जाति को चेतावनी और संदेश दे रही है, और हम लगातार प्रकृति के संदेशों को अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं। 2013 में केदार घाटी में जो सैलाब आया और तबाही हुई अथवा उत्तरकाशी में भूकंप के बाद जो बाढ़ आई, हमने उन्हें ही प्रलय माना। विनाश और बबार्दी का दूसरा नाम प्रलय है।

अब केरल के वायनाड जिले में लगातार तीन भू-स्खलन आए और फिर सैलाब आया, गांव के गांव दफन हो गए, 400 से अधिक घर देखते ही देखते मलबा हो गए, करीब 387 मौतें हो चुकी हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, यह प्रलय नहीं है, तो और क्या है?

स्थावराणां हिमालयः, इस प्रसंग का उल्लेख श्रीमद्भागवत गीता के दसवें अध्याय के 25 वें श्लोक में हुआ है। इसमें श्रीकृष्ण ने कहा है कि मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। सुखमय जीवन के लिए वेदों में हिमालय की आराधना का उल्लेख भी हुआ है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमारसंभव में हिमालय को धरती का मानदंड तथा दुनिया की छत व आश्रय बताया था। अनादिकाल से पहाड़ आध्यात्मिक चेतना की पुण्यभूमि रहे हैं। प्रकृति के प्रबल उपासक रहे कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली, भक्ति व अनुसंधान का केंद्र पर्वतराज हिमालय ही रहा है। मगर बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं व अंधाधुंध निर्माण कार्य पहाड़ों की स्थिरता को चुनौती पेश कर रहे हैं।

16 जून 2013 को केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई। पांच मिनट में पूरी झील खाली हो गई। पानी इतनी तेजी से निकला कि केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिलीं। चारों तरफ तबाही और बबार्दी।

हजारों लोग मारे गए। हजारों का आज भी पता नहीं चला। नदियों का बढ़ा जलस्तर देख डर लग रहा था। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने 10 हजार से ज्यादा सैनिक और 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमान लगाए। वायुसेना के विमानों ने 2137 बार उड़ान भरी। 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। साल-दर-साल बीतते चले गए।

हादसे के निशान तो अब भी पहाड़ों की ढलानों पर दिखते हैं। केदारनाथ धाम जाने की दूरी भी बढ़ गई। क्योंकि रामबाड़ा कस्बा पूरी तरह से खत्म हो गया था। नया रास्ता बनाया गया। जो पुराने रास्ते से करीब तीन किलोमीटर ज्यादा है। पहले आप केदारनाथ घाटी के बाएं पहाड़ों पर चलते हुए मंदिर तक जाते थे अब रामबाड़ा से रास्ता दाहिनी ओर कट जाता है।

उत्तराखंड का शहर जोशीमठ धीरे-धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। 2023 में जोशीमठ से जुड़े समाचार देश दुनिया में छाये हुए थे। विशेषज्ञों

का कहना है कि वर्तमान संकट कई कारणों से उत्पन्न हुआ है, जिनमें वर्षों से चल रहा अनियोजित निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएं और उचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव शामिल है। 1976 में एक सरकारी रिपोर्ट में जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि ३मिट्टी की भार वहन क्षमता३ की जांच के बाद ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में उचित जल निकासी और सीवेज प्रणाली के निर्माण तथा कटाव को रोकने के लिए कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक लगाने का भी सुझाव दिया गया था। लेकिन विशेषज्ञों की हर हिदायत और चेतावनी को अनसुना किया गया।

वायनाड में जो कुछ हुआ, यह कुदरती मार नहीं, मानव-निर्मित घटना है, क्योंकि आदमी अपनी मौज मस्ती और ऐयाशी के लिए पहाड़ों को तोड़ रहा है। पहाड़ों की चोटियों पर भी इमारतें बनाई जा रही हैं। केरल की भौगोलिक स्थिति परंपरागत पहाड़ों से भिन्न है, लेकिन देश भर के 80-85 फीसदी भू-स्खलन केरल में ही आते हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक, 2015 से 2022 तक 3782 भूस्खलन आए। उनमें से करीब 60 फीसदी केरल में ही आए। मौजूदा हालात पर विशेषज्ञों का मानना है कि अरब सागर का तापमान बढ़ने से बेहद घने बादल बने और उसी से केरल में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई। वायनाड पहाड़ी जिला है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहां 2100 मीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। विशेषज्ञों की मानें तो, जलवायु-परिवर्तन ने भी बारिश की स्थिति और भूस्खलन की तीव्रता को बढ़ाया है। एक शोध में कहा गया है कि जो वायनाड साल भर बूंदाबांदी और मानसून की बारिश वाला ठंडा, नम वातावरण वाला इलाका होता था, जलवायु-परिवर्तन के कारण अब सूखा, गर्म, लेकिन मानसून के दौरान भारी, तीव्र बारिश वाला क्षेत्र बन गया है। इस बदलाव से भूस्खलन का जोखिम बढ़ा है। 2018 के मानसून में भी खूब बारिश हुई थी, तब करीब 400 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद केरल में भू-स्खलन वाला क्षेत्र बढ़ गया है। इस हादसे, संकट या घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

देश में हर राज्य में, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक भी सीखना चाहिए। विकास-कार्य जापान और ताइवान सरीखे देशों में भी हो रहे हैं। वहां भी पहाड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे हादसों से बचने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। वे दीवार पुश्ता लगाना हो अथवा पेड़-पौधों का रोपण या कुछ और बंदोबस्त करना हो, जापान इसमें अग्रणी रहा है। वहां के पहाड़ों को स्थिर बनाए रखने के लिए विशेष तरह की जालियां तक लगाई गई हैं। देश के उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध में ढलानों की कटाई के बाद बेहतर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ताइवान ने पहाड़ पर दबाव मापी यंत्र लगाकर एक भिन्न प्रयोग किया है। इससे यथासमय पता चल जाता है कि पहाड़ पर कितना दबाव है और वह लोगों को पहाड़ के दरकने को लेकर आगाह कर देता है। हमारे देश में जो निर्माण-कार्य बेलगाम और अनियोजित तरीके से किए जाते हैं। खनन तक धड़ल्ले से कराया जाता है। पहाड़ को काटते-तोड़ते रहेंगे, तो ऐसे प्रलय कैसे रोके जा सकते हैं? इस विषय पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। निस्संदेह, मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में ऐसी आपदाओं से बचाव की तैयारी करने और निपटने के लिये तंत्र को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के तौर-तरीकों पर भी युद्धस्तर पर काम किया जाए। इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में देश में आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रतिक्रियाशील तंत्र सक्रिय हुआ है और जान-माल की क्षति को कम करने में कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके साथ ही पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रभाव के बारे में विशेषज्ञों की चेतावनियों पर ध्यान देने की जरूरत है। जिसके लिये राज्य सरकारों की सक्रियता, उद्योगों की जवाबदेही और स्थानीय समुदायों की जागरूकता की जरूरत है। अपनी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की तुलना में देश कहीं ज्यादा तेजी से प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन देशों में भारत भी शामिल है जो अभी भी अपने देश में रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह जानकारी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स द्वारा वर्ष 2021 में किए एक अध्ययन में सामने आई है जोकि जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुआ है। वायनाड की त्रासदी का बड़ा सबक यह है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल के प्रति नये सिरे से प्रतिबद्ध होना होगा। केदारनाथ, जोशीमठ और वायनाड में प्रकृति के रौद्र रूप हम देख और भोग चुके हैं। इसलिए समय रहते प्रकृति की चेतावनियों और संदेशों को समझना होगा, अपितु आने वाले समय में प्रकृति का रौद्रता का आकार विशाल और भयानक हो सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

वक्फ बोर्ड की बेहिसाब ताकतें

केंद्र की एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर 'वक्फ बोर्ड' किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। वहीं अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति या संस्था के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरीफिकेशन कराया जाएगा। पूरे देश में वक्फ एक्ट के विरोध की वजह उसकी वो धारा है जिसे लोग संविधान विरोधी बता रहे हैं। दरअसल वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 'वक्फ' की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कोई भी मुसलमान अपनी जमीन, मकान या कोई भी कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। यही वक्फ प्रापर्टी बन जाती है। आगे वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल और मेंटिनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों की होती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया। 1995 में नए कानून से हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति मिली थी। दरअसल वक्फ बोर्ड को अभी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इस प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख उद्देश्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके द्वारा संपत्तियों के वर्गीकरण को नियंत्रित करना है। सरकार का कहना है कि संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर गलत दावा नहीं कर पाएगा इसलिए भविष्य में शायद ही जमीन विवाद से जुड़ा ऐसा कोई मामला सामने आएगा। आरोप है कि वक्फ बोर्ड गलत तरीकों से दूसरे की संपत्ति पर दावा जता देता है, ऐसे में जमीन के असली मालिक से सिर के ऊपर से छत हट जाती है और वो बेघर हो जाता है। कहा गया कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधनों की वजह से वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में भू-माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भूस्खलन रोकने के लिए जैव-विविधता का संरक्षण जरूरी !

भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी भूस्खलन की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि इन दिनों उत्तराखंड में तेज बारिश कहर बनकर टूट रही है। वहीं महाराष्ट्र,गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में भी तेज बारिश से संकट बना हुआ है। दिल्ली जैसे महानगर में भी बारिश एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

– सुनील कुमार महला

वर्तमान में मानसून का सीजन चल रहा है। मानसून के इस सीजन में कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है और इससे जहां एक ओर हमारे देश में अनेक स्थानों पर बाढ़ आ गई है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं घटित हो रही हैं। दरअसल आज हम प्रकृति के संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से बारिश भी बहुत अधिक होने लगी है तो कहीं पर सूखा भी पड़ने लगा है। बारिश शहरों व बड़े महानगरों से लेकर गांव गलियों तक के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रहा है। आज बढ़ती जनसंख्या के बीच हमारे शहर भी नियोजित ढंग से नहीं बसाये गये हैं और उसका खामियाजा हमें निचले इलाकों में पानी भरने, बाढ़ आने के रूप में देखने को मिल रहा है। हमारे देश में भूस्खलन की घटनाएं तो जैसे आम होने लगीं हैं, विशेषकर बारिश के सीजन में। कहना ग़लत नहीं होगा कि भूस्खलन का कारण कहीं न कहीं अधिक बारिश भी है। बारिश ही नहीं बर्फ पिघलने, जल स्तर में परिवर्तन, धारा कटाव, भूजल में परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियों, मानवीय गतिविधियों द्वारा गड़बड़ी, या इन कारकों के किसी भी संयोजन से ढलानों में भूस्खलन शुरू हो सकता है। जानकारी देना चाहूंगा कि भूकंप के झटके और अन्य कारक भी पानी के भीतर अनेक बार भूस्खलन को प्रेरित कर सकते हैं। हमारे देश भारत में भूस्खलन एक बहुत ही गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसके भयानक परिणाम होते हैं। भूस्खलन की घटनाएं खड़ी ढ़लान वाली भूमि, चट्टानों में जोड़ व दरारें होने, ढ़ीली मिट्टी (वृक्ष कटाई के कारण), चरागाहों के कम होने के कारण होती हैं। वनों में आग लगने(दावानल) से मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और वहां भूस्खलन की घटनाएं घटित होने लगतीं हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, कंक्रीट के जंगलों में बढ़ोतरी (निर्माण कार्य) से भी भूस्खलन होता है। वास्तव में देखा जाए तो भूस्खलन के प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारण हैं। एक ओर जहां भारी बारिश, भूकंप, मिट्टी का प्राकृतिक रूप से क्षरण, ज्वालामुखी विस्फोट भूस्खलन के प्राकृतिक कारण हैं वहीं दूसरी ओर खनन, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, वनों की कटाई मानवजनित कारणों में से एक हैं। इन दिनों हमारे देश में दक्षिण-पश्चिमी मानसून आसमानी आफत का रूप ले चुका है। बीते कुछ दिनों से दक्षिण से उत्तर भारत तक जहां देखो वहीं पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि हाल में ही केरल के वायनाड में तीव्र भू-स्खलन ने मुंडक्कई, चूरलमाला कस्बों का अस्तित्व तक ही मिटा दिया। भीषण त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे गए। पशुधन, जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।सच तो यह है कि विनाशकारी लैंडस्लाइड अब राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। केरल जैव विविधता की दृष्टि से भारत के संपन्न राज्यों में से एक है, ऐसे में केरल जैसे राज्य में लगातार भूस्खलन चिंता का विषय हैं। अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्र की हानि केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के दो महत्त्वपूर्ण कारण हैं। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें वायनाड भूस्खलन में व्यापक तबाही दिखाती हैं। सैटेलाइट द्वारा प्राप्त तस्वीर से पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि खिसक गई, जिससे राष्ट्रपति भवन के आकार से लगभग पांच गुना बड़ा भूस्खलन हुआ। पता चला है कि मलबा इरुवैफुझा नदी के किनारे लगभग 8 किलोमीटर तक बह गया, यह बहुत ही चिंताजनक है। जानकारी देना चाहूंगा कि इसरो द्वारा तैयार किए गए 2023 'लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया' ने वायनाड क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में रखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसरो के बीते वर्ष जारी भूस्खलन मानचित्र के मुताबिक, भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन-संभावित जिलों में से 10 केरल में ही थे, और वायनाड इनमें 13वें स्थान पर था। इसी में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी घाट का 90 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है।

गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में सर्दी अधिक कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, ऐसे में हम सभी को चेतने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में बारिश के असमान वितरण अर्थात अचानक भारी वर्षा में बढ़ोतरी होने से मानसूनी त्रासदियां बढ़ती जा रही हैं। अब समय आ गया है हम सभी मिल जुल कर जलवायु में हो रहे बदलाव पर कार्य करें अन्यथा हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी भूस्खलन की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि इन दिनों उत्तराखंड में तेज बारिश कहर बनकर टूट रही है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में भी तेज बारिश से संकट बना हुआ है। दिल्ली जैसे महानगर में भी बारिश एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र ने अभी तक राज्य की सड़कों पर ऐसे 132 भूस्खलन हॉटस्पॉट क्षेत्र चिह्नित किए हैं जिनमें वर्षाकाल के दौरान विशेष निगरानी की आवश्यकता है। पूर्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अध्ययन में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिले को भारत का सर्वाधिक भूस्खलन संवेदनशील जिला बताया गया था। यहां भूस्खलन घनत्व भी सबसे अधिक बताया गया था। किसे याद नहीं है कि वर्ष 2013 की आकस्मिक बाढ़ ने केदारनाथ धाम मंदिर वाले शहर को मलबे में बदल दिया था। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी उस विभीषिका निशान साफ दिखते हैं। बहरहाल, हमें इस बात का पता है कि पर्यावरण विदो ने पश्चिमी घाट को पर्यावरण के प्रति अतिसंवेदनशील बताया हुआ है और इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर रोक की सिफारिश भी की गई है। बावजूद इसके इन चेतावनियों को हम सभी नजरंदाज करते हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील होना होगा और प्रकृति के संकेतों को समय रहते समझना होगा। वास्तव में, हमें यह चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लायें और स्वयं भी पर्यावरण संरक्षण करें। आज संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमें यह चाहिए कि हम हमारे मौसम विज्ञान तंत्र को दुरुस्त करें और सटीक पूर्वानुमान लगाने की तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करें ताकि आपदाओं के जोखिमों से निपटा सकें। सरकारों को भी यह चाहिए कि सरकारें मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर वनारोपण को बढ़ावा देकर जैव-विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में काम करें। भूस्खलन रोकने के लिए भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में सतत वृद्धि करना, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ-साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियन्त्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियन्त्रण उपाय कार्यान्वित करना कुछ अन्य कारगर उपाय साबित हो सकते हैं। चरागाहों को भी बचाया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति का हर हाल में संरक्षण किया जाए, अन्यथा मानवजाति को गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

पर्यावरण व प्रकृति को असंतुलित करने का प्रयास खतरनाक

– डॉ. वीरेन्द्र भाटी मंगल

बरसात के मौसम में लाखों पौधे उत्साह व उमंग के साथ लगाये जाते है, लेकिन इन लाखों पौधों में से कितने पौधे पेड़ बन पाते है, यह विचारणीय प्रश्न है। सही मायने में पौधे लगाने से अधिक उनके संरक्षण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सचमुच! आज पेड़ लगाना आसान सी बात हो गई है। जन्मदिन, शादी सालगिरह, विवाह, पुण्यतिथि आदि अनेक विशेष अवसरों पर पेड़ लगाने की एक स्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश हो चुका है। लेकिन अब प्रश्न यह उभरता है कि आखिर लगाये जाने वाले पेड़ो का संरक्षण कितना हो रहा है? प्राय: यह देखा गया है कि पौधे लगाकर, फोटो खिचवानें के बाद पेड़ों के संरक्षण की ओर हमारा ध्यान बहुत कम ही जाता है, जबकि जरूरी है कि हम पेड़ लगाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण पर भी ध्यान दें तो प्रतिवर्ष लगाये जाने वाले पौधों को पेड़ बनते हुए देख सकते है। वर्तमान दौर में प्रबुद्धजन, आम व्यक्ति से लेकर खाश व्यक्ति तक पौधे लगाते है, जिसके संरक्षण व सुरक्षा का जिम्मा लेना जरूरी है। यह एक विशेष उदाहरण है। इस दौर में केवल पौधारोपण ही काफी नहीं है, बल्कि हमें पौधो के संरक्षण व सुरक्षा की जिम्मेदारी की निभानी होगी। सामाजिक संस्थाओं को पेड़ लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी का दायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। बढती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधन धीरे-धीरे कम होते जा रहे है जो चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। जल, जमीन व जंगल बचना जरूरी है, नहीं तो मानव जीवन पर संकट में आ सकता है। आज पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व स्तर पर फैल रही है। प्रकृति के असंतुलन के पीछे अति-दोहन ही है। पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षों का भण्डार होना जरूरी है। सही मायने में यह पृथ्वी का श्रृंगार भी है। पेड़ हमें प्राण वायु देते है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पेड़ों के महत्व का हमें अध्ययन के साथ बचपन से ही पढाया जाता है। पेड़ों पर पक्षियों का निवास होता है, जो प्रकृति के जरूरी है। इसी प्रकार जलवायु पर नियंत्रण, सुन्दरता व शोभा, इंधन, फल-फूल, बाढ़ पर नियंत्रण, इमारती लकड़ी का खजाना, पर्यावरण पर नियंत्रण, रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण, कृषि उपज में वृद्धि, पथिकों को छाया, बंजर भूमि में सुधार, पर्यटन, रोजगार, औषधियां, कच्चा माल, जलस्तर में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि आदि अनेक लाभ पेड़ों के माध्यम से हमें मिलता रहता है। इसलिए जीवन में एक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़-पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। पेड़ पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग छोटे-छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए पेड़-पौधों की कटाई कर देते हैं। इससे हमारा पर्यावरण प्रदुषित हो रहा है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण से मानव समाज में विभिन्न बिमारियां फैल रही हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों की कमी के कारण वातावरण में लगातार बढ़ गर्मी घातक होती जा रही है। बरसात कम होने का कारण भी पेड़ो की अंधाधुंध कटाई ही है। दुख तब होता है जब पर्यावरण व प्रकृति के इस सामंजस्य को असंतुलित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिकता व भौतिकता के नाम पर वृक्षों को बेवजह काटकर जंगलों को नष्ट कर और धन कमाने की अंधी-लालसा, विकास या अन्य बहानों के साथ जगंल को उजाड़ा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य वजह भी यही है कि हमने प्रकृति के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड प्रारम्भ कर दी है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन खतरे के कगार पर खड़ा है, अनेक बिमारियों के साथ हमारा मानसिक, सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति और प्रकृति द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के प्रति गंभीर बनें और पेड़ लगाने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बने। अभी भी समय है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए प्राथमिकता के साथ पेड़ लगाने एवं उनके संरक्षण के लिए लग जाना चाहिए। पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़-पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। पेड़ धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए पेड़ों का संरक्षण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लोग छोटे-छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए पेड़-पौधों की कटाई कर देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदुषित हो रहा है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण से अनेक बिमारियां फैल रही हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों की कमी के कारण वातावरण में लगातार गर्मी बढ़ रही है। इससे बरसात भी कम होने लगी है।

(लक्ष्मी विलास, करन्ट बालाजी कॉलोनी, मंगलपुरा-लाडनूं, राजस्थान)

कविता

आदिदेव महादेव

जटा विराज गंगधार शीश चंद्र सोहते।
निहारते स्वरूप तेज तीन लोक मोहते।।
विराजमान कंठ नाग है त्रिशूल हाथ में।
जहाँ-जहाँ चले शिवा सदैव बैल साथ में।।

लपेट बाघ छाल अंग भस्म देह साजते।
बढ़े महेश पाँव व्योम ताल ढोल बाजते।।
निमग्न भूतनाथ ध्यान बैठ मुक्ति धाम में।
शिवा धरा समीर अग्नि नीर आसमान में।।

शिवा प्रसन्न होय बेलपत्र दूध नीर से।
प्रसून भांग घी दही गुलाल औ अबीर से।।
नमः शिवाय जाप आठ याम सोमवार को।
करे पुकार दर्श देवता लगे कतार को।।

खुले त्रिनेत्र क्रोध ताप विश्व धूम्र सा जले।
कृपा करे महेश तो मनुष्य मोद में पले।।
करे प्रणाम भक्त नीलकंठ के स्वरूप को।
कृपालु तेजपुंज आदिदेवता अनूप को।।

प्रिया देवांगन 'प्रियू'

(राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़)

मनु ने लौटाया शूटिंग का स्वर्णिम दौर

– योगेश कुमार गोयल

पेरिस ओलंपिक के आठवें दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने की पक्की उम्मीदें लगाए बैठा था और ये उम्मीदें टिकी थी भारत की 'मिरेकल गर्ल' मनु भाकर पर। पूरी उम्मीद थी कि 'मिरेकल गर्ल' मनु भाकर ओलंपिक में अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी करते हुए इस स्पर्धा में भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में कामयाब हो सकती हैं लेकिन इस बार वह पदक जीतने से थोड़ा सा चूक गई और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 40 में से 28 शॉट्स लगाने के साथ चौथे स्थान पर रही और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने का उनका सपना भी अधूरा रह गया। दरअसल तीसरे और चौथे स्थान के शूटर के बराबर प्वाइंट थे। इसके बाद मनु और हंगरी की मेजर वेरोनिका के बीच शूटऑफ हुआ, जिसमें मनु केवल तीन निशाने ही लगा पाई जबकि हंगरी की शूटर ने चार बार टारगेट को हिट किया और उसी के साथ मनु पदक की रेस से बाहर हो गई। पेरिस ओलंपिक के आठवें दिन मनु का लक्ष्य ओलंपिक में एक नया इतिहास रचना था लेकिन वह पदक हासिल करने से मामूली सी पीछे रह गई। वूमेन्स 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में हार के बाद मनु का कहना था कि उनके ऊपर इस इवेंट को लेकर काफी दबाव था। हालांकि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मिली इस हार के बावजूद भारत की इस इकलौती निशानेबाज ने वो खुशियां और गर्व के पल देश को दिए हैं, जिसकी ओलंपिक शुरू होने के समय तक शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मनु ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में तीन अलग-अलग शूटिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और तीनों में ही उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया। 3 अगस्त को जब मनु वूमेन्स 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में खेलने उतरी तो हर नजर उन्हीं के प्रदर्शन पर केंद्रित थी। भले ही वह यह मुकाबला हार गई लेकिन कुल तीन शूटिंग स्पर्धाओं में से उन्होंने अपने जोश और जज्बे के साथ दो में कांस्य पदक जीतकर भारत में शूटिंग के सुनहरे दौर को वापस लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मनु की ही बदौलत भारत ने पहली बार शूटिंग में किसी एक ओलंपिक सीजन में तीन मेडल हासिल किए हैं। विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धाओं में अनेक पदक जीतने के बाद एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर मनु ने ऐसा अविस्मरणीय इतिहास रचा, जो उनके अलावा ओलंपिक के 124 वर्षों के इतिहास में अब तक भारत का कोई भी अन्य दएथलीट नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक में मनु ने जिस तरह का जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपने मैचों के दौरान जिस प्रकार का 'धाकड़' खेल दिखाया, उसी के कारण उन्हें अब मनु भाकर के साथ-साथ 'मनु धाकड़' भी कहा जाने लगा है।

मनु से पहले कोई भी पुरुष या महिला एथलीट एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने में सफल नहीं हुआ है। देश की आजादी से बहुत पहले ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 में आयोजित हुए ओलंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में कुल दो रजत पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था और उम्मीद थी कि मनु 124 साल पुराने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती हैं लेकिन 'मिरेकल गर्ल' मनु भाकर की ओलंपिक में ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि पहला कांस्य पदक जीतने के साथ ही वह ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई थी और उस पदक के साथ ही मनु ने शूटिंग में भारत के पदक के 12 वर्ष के सूखे को भी खत्म किया था। मनु से पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में एक-एक पदक जीते थे। ओलंपिक के 124 वर्ष के इतिहास में मनु से पहले भारत को शूटिंग में केवल 4 पदक ही नसीब हुए थे जबकि भारत केवल इसी ओलंपिक में मनु के दो पदकों सहित कुल 3 पदक जीत चुका है। शूटिंग में 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता था, उसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक भारत के नाम किया और 2012 के लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने रजत और गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में मनु ने अपना पहला पदक 28 जुलाई 2024 को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में जीता था। उस शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। उसके बाद 30 जुलाई को मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता और उस जीत के साथ ही वह एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर वह सुशील कुमार और पीवी सिंधु को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। दरअसल ओलंपिक इतिहास में मनु से पहले यही दो ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने एकल स्पर्धा में दो पदक जीते थे लेकिन उन्होंने अपने पदक एक ही ओलंपिक में नहीं बल्कि अलग-अलग ओलंपिक में जीते थे। सुशील कुमार ने 2008 और 2012 के ओलंपिक में कुश्ती में जबकि स्टार शटलर पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में एक-एक पदक जीते थे। बहरहाल, देश के लिए एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर पर पूरे देश को गर्व है। ओलंपिक में अपने धाकड़ प्रदर्शन से मनु ने 140 करोड़ भारतवासियों का दिल जीत लिया।

(लेखक 34 वर्षों से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हमारे देश के ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण हिस्सों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस दिवस का उद्देश्य न केवल हाथ बुनकर समुदाय का सम्मान करना है बल्कि इस क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी करना है। हथकरघा कला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व बहुत ज्यादा है। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

पांच हज़ार साल पुराना है भारत का हथकरघा उद्योग

– बाल मुकुन्द ओझा

भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसके इतिहास में गांधीजी के 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आन्दोलन के शुरुआत की घटना को जोडकर देखा गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कारीगरों के आत्मविश्वास या आय को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हथकरघा उत्पादों को अधिक से अधिक मान्यता प्रदान करना है। भारत में हथकरघा क्षेत्र समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा है। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन के समान शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य भारत के सामाजिक आर्थिक सुधार में हथकरघा के योगदान को स्पष्ट करना है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को काम के विकल्प के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, हालांकि कोरोन के कारण पिछले साल यह प्रभावित हुआ था, हालांकि इस बार कई जगहों पर इस तरह की कार्यशाल का आयोजन हो रहा है। भारत का हथकरघा उद्योग अत्यंत विशाल होने के साथ हजारों साल पुराना भी है। इसके सबूत आपको रामायण से लेकर महाभारत तक में मिल जाएंगे। कुछ साक्ष्य यह भी बताते हैं कि भारतीय हथकरघा उद्योग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। पिछले 5000 सालों से देश में हैंडलूम का इस्तेमाल कर खूबसूरत पहनावे डिज़ाइन किये जा रहे हैं। साथ ही भारत का कुछ बड़े देशों को हथकरघा कपड़ों के निर्यात का भी इतिहास रहा है। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं। हथकरघा हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है, जबकि हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हमारे देश के ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण हिस्सों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस दिवस का उद्देश्य न केवल हाथ बुनकर समुदाय का सम्मान करना है बल्कि इस क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी करना है। हथकरघा कला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व बहुत ज्यादा है। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र असंगठित आर्थिक गतिविधियों में आते हैं, इनसे लगभग 65 लाख दस्तकारों और बुनकरों को आजीविका प्राप्त होती है। इनमें देश भर में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत 25.46 लाख महिलाएं और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत 20 लाख महिलाएं शामिल हैं। भारत का हथकरघा क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जो देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। हथकरघा बुनाई की कला में पारंपरिक मूल्यों से जुड़ाव है और इसके प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विविधताएँ हैं। बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्कत, पटोला, तसर सिल्क, माहेश्वरी, मोइरांग फी, बालूचरी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ और तंगलिया जैसे कुछ विशिष्ट उत्पादों के नाम हैं जिनकी विशिष्ट बुनाई, डिजाइन और पारंपरिक रूपांकन दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करता है।

अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। ये समय आज़ादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। इस माह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। बल्कि ये हमारी आर्थिक आज़ादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। वस्त्र मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है। इस वर्चुअल भारतीय स्टोर के माध्यम से कारीगरों को कीमतों में हेरफेर करने वाले बिचौलियों के बिना उचित पारिश्रमिक मिलेगा। शहर में रहने वाले खरीददार सीधे शत-प्रतिशत प्रामाणिक और सर्वोत्तम हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकेंगे। भारतीय हस्तनिर्मित पोर्टल – वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों अन्य साजों सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके सभी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित हैं। ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। हम देश के उस क्षेत्र की विरासत से आपको रूबरू कराना चाहते है जो सीमावर्ती तो है ही साथ ही अकाल और सूखे की मार से पीड़ित होने के बावजूद अपनी हथकरघा की कला और संस्कृति को विपरीत स्थितियों में भी सहेजे हुए है। रेतीले धोरों से आच्छादित राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के निवासियों के पास हुनर तो है मगर हुनर के विकास की सुविधा नहीं थी। मालाणी के गौरव पदमश्री मगराज जैन ने गरीबी झेल रहे दलित, गरीब ,वंचित और महिलाओं के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया तो लता कच्छवाहा के रूप में उन्हें एक सहकर्मी का साथ मिला। मगराज जैन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने थार के हथकरघा लोककला और मेलों को पुनर्जीवित कर विश्वस्तरीय ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह करीब पांच हजार से अधिक युवक-युवतियों को हस्तशिल्प यथा कांच कशीदा एप्लीक, चर्म कार्य, रेडियो मरम्मत सहित चालीस से अधिक विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई और उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युवाओं की रोजी-रोटी का जरिया बन गया।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

संपादकीय

हसीना का निष्कासन

भले ही प्रथम दृष्टया, बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन की वजह आरक्षण विरोधी आंदोलन से उपजा आक्रोश बताया जा रहा हो, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह बनना बड़ा कारण रहा। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश को हल्के में लिया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि, पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। दरअसल, महज सात माह पहले हुए आम चुनावों के बाद से ही देश में जनाक्रोश धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। दक्षिणपंथी रुझान वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। हालांकि,शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। वास्तव में शेख हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। हालांकि, लगातार चौथी बार सरकार बनाने वाली शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, फलतः बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार ढंग से संभाल नहीं पायी। आंदोलनकारियों से निबटने के लिये की गई सख्ती से आंदोलन लगातार उग्र होता गया। जिसका विपक्षी राजनीतिक दलों ने भरपूर लाभ उठाया। हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने हसीना सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोल दिया। जनाक्रोश के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। निस्संदेह, सत्ता से चिपके रहने के लिये किए जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जनाक्रोश के चरम के रूप में सामने आती है। यह घटनाक्रम श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शन की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतरकर विदेश भागने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान अपने हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध थे, लेकिन हालिया उथल-पुथल को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।

परीक्षाओं के लिए जान पर खेलते बच्चे

लेकिन अन्य परीक्षाओं के साथ यूपीएससी की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। खास तौर से तब जब वे असफलता से जुड़ी हों। बहुत बार इस आशा में कि बच्चा बड़ा अफसर बन जाएगा, माता-पिता अपनी जमीन, खेत मकान सब कुछ बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, मगर जरूरी नहीं कि उनका बच्चा सफल ही हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक सफलता की आशा में पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है।

पिछले दिनों से दिल्ली के कोचिंग सेंटर चर्चा में हैं। बारिश के कारण एक बेसमेंट में पानी भर गया और तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उससे पहले यूपीएससी की ही तैयारी करने वाला एक बच्चा बारिश में करंट लगने से मर गया। हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में तमाम सपनों को लिए यहां आते हैं और जीवन के बहुमूल्य वर्ष लगा देते हैं।

कोचिंग सेंटर्स में देश भर से आए बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वे किन विकट परिस्थितियों में रहते हैं, इसे मीडिया ने बार-बार दिखाया और बताया है। कितनी कम जगह के लिए उन्हें भारी किराया देना पड़ता है। कैसा खाना मिलता है। मकान मालिक बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा लेते हैं। उस पर रात-दिन की मेहनत। लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होता, कोई नहीं जागता। न सरकार, न कोचिंग सेंटर्स के मालिक, न ही बच्चे, न बच्चों के माता-पिता। मीडिया भी। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स बड़े विज्ञापनदाता भी हैं। आखिर इनसे कौन दुश्मनी मोल लेकर अपनी आय का नुकसान करे। न ही सरकारी अधिकारियों को कभी इस बात का खयाल आता है कि वे उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। हां, जब दुर्घटना हो जाती है, तब जिम्मेदारी एक से दूसरे पर डाल दी जाती है।

फिल्म बारहवीं फेल में भी हम ये सब देख चुके हैं। यह फिल्म बहुत सफल भी हुई थी। बच्चे ही नहीं उनके माता-पिता चाहते हैं कि किसी तरह बच्चा आईएएस या, आईपीएस, अथवा अन्य सेवाओं में एक बार आ भर जाए तो न केवल उसकी जिंदगी बन जाए बल्कि माता-पिता की भी और दहेज भी मोटा मिले। एक बार एक खबर पढ़ी थी कि जो बच्चे आईएएस बन जाते हैं, उनका नाम लिस्ट में देखकर उनके घर में बड़ा वाहन रुपये लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। यूपीएससी का इम्तिहान देने के लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं जबकि चयन कुछ ही का होता है। एक सफल के पीछे हजारों असफल खड़े रहते हैं। कई-कई बार तो दशकों इसमें निकल जाते हैं, मगर सफलता के साथी सब हैं असफलता की कहानी कोई नहीं कहता। न ही उस संघर्ष और जी तोड़ मेहनत के बारे में बताया जाता है कि वर्षों तक अठारह-बीस घंटे मेहनत करने और सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया।

आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों की सफलता का प्रतिशत औरों से ज्यादा है, इसीलिए बच्चे दिल्ली आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे बिहार से आते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2002 से 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अठारह हजार, एक सौ चौहत्तर बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। मगर सफल सिर्फ दो हजार, दो सौ इकतालीस बच्चे ही हुए थे। सफलता का प्रतिशत इतना कम होने पर भी इस परीक्षा की तैयारी करने वाला हर बच्चा सोचता है कि वह अपने परिश्रम से जीत हासिल कर लेगा, पर ऐसा होता बहुत कम के साथ है।

यूपीएससी को कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अफसोस होता है कि बच्चों के परिजन, साथ में जहां रहकर ये तैयारी करते हैं वे सेंटर्स, न इनके स्वास्थ्य का खयाल रखते हैं न इनकी मामूली सुविधाओं का। ये पैसे बरसाने वाली मशीनें हैं, जो जितनी बड़ी संख्या में आएंगी लोगों की जेबें उतनी ही फूलती जाएंगी। तभी तो दिल्ली में कुल कोचिंग सेंटर्स की संख्या पांच सौ तिरासी है और सिर्फ सड़सठ के पास सुरक्षा मानकों को पूरे करने वाले प्रमाण पत्र हैं। आखिर बिना सुरक्षा मानक पूरे किए इन सेंटर्स को क्यों चलने दिया गया।

फिर कोचिंग सेंटर्स हमेशा अपनी सफलताओं को बहुत रंगीन बनाकर पेश करते हैं। बहुत से इसमें झूठ-सच का सहारा भी लेते हैं। इसमें एक उदाहरण देना काफी होगा। करीब सत्ताईस-अट्ठाईस साल पहले एक युवा का न केवल आईआईटी बल्कि देश के बहुत से इंजीनियरिंग संस्थानों में चुनाव हुआ था। जैसे ही रिजल्ट आया कोचिंग संस्थानों से फोन आने लगे कि वह युवा अपना फोटो उन्हें छापने की अनुमति दे। जिसमें वे कह सकें कि इस युवा ने इतनी सफलता इसलिए पाई कि अमुक संस्थान से ट्रेनिंग ली थी। वे इसके लिए बड़ी रकम देने को भी तैयार थे। जबकि इस युवा ने खुद ही पढ़ाई की थी। इस युवा ने कोचिंग संस्थान वालों से मना कर दिया। ऐसा आज भी होता है। कोचिंग संस्थान चाहे यूपीएससी के हों, इंजीनियरिंग के हों, अथवा मेडिकल या एमबीए के, अधिकांश की कहानी कमोबेश एक जैसी ही होती है। कोटा में भी यही हाल देखने को मिलता है। वहां तो और भी कम उम्र के बच्चे मेडिकल की तैयारी करने आते हैं। बहुत बार इतने निराश होते हैं कि जान दे देते हैं।

लेकिन अन्य परीक्षाओं के साथ यूपीएससी की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। खास तौर से तब जब वे असफलता से जुड़ी हों। बहुत बार इस आशा में कि बच्चा बड़ा अफसर बन जाएगा, माता-पिता अपनी जमीन, खेत मकान सब कुछ बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, मगर जरूरी नहीं कि उनका बच्चा सफल ही हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक सफलता की आशा में पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भारत में माता-पिता का ध्यान अक्सर सरकारी नौकरी पर रहता है। और यदि नौकरी सरकारी है और ऊपरी कमाई वाली भी है तो कहना ही क्या। क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन भर के लिए पक्की समझिए। इसीलिए विवाह के मामले में भी लोग उन लड़कों को पसंद करते हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है।

कई साल पहले यह लेखिका एक ऐसे दक्षिण भारतीय लड़के से मिली थी जो बहुत पढ़ा-लिखा था। अपने हुनर में माहिर था, मगर बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद उसकी शादी दो कारणों से नहीं हो रही थी, एक तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी और दूसरे वह विदेश में नौकरी नहीं करता था। दोनों में से एक भी बात होती तो शायद उसकी शादी समय पर हो गई होती। उत्तर भारत में भी ऐसी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते, इसका दुःख उन्हें जिंदगी भर सालता रहता है। अपने ही किसी साथी को बड़ा अफसर देख उनका दुःख और बढ़ जाता है। फिर जिस सपने को लेकर दिल्ली आए थे, वह पूरा नहीं हुआ तो वे अपने नाते-रिश्तेदारों, अड़ोसी-पड़ोसियों की नजर में गिर जाते हैं। तरह-तरह का अपमान झेलते हैं।

समाज में शक्ति और अधिकार के प्रति इतना सम्मान है कि बाकी मानवीय गुण पीछे छूट जाते हैं। इस मामले में महान लेखक जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त का ही पहला वाक्य याद आता है-अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।

आज का इतिहास

- प्रसिद्ध न्यूटन ने 1668 में ट्रिनीटी कॉलेज कैंब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल किया।
- ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना 1753 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई।
- उचित वक्ता 1880 को पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया।
- रूस ने 1914 में पूर्वी परूसिया पर हमला किया।
- 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और पांच टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण 1944 में हुआ।
- मुंबई नगर निगम को 1947 में बिजली और परिवहन व्यस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई।
- अमेरिका ने 1957 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
- लैंसिंग, मिशिगन में 1966 को नस्लभेदी दंगे भड़के।
- गीत सेठी 1985 में विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने।
- अमेरिका ने 1990 में सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की शुरूआत की।
- इजरायल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा 1994 में शुरु हुई।
- अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता 1996 को
- चला।
- केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर 1998 में आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु।
- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने 1999 में एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की।
- रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा 2000 में एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार।
- बगदाद में जार्डन दूतावास के बाहर 2003 में हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु।
- इस्रायल के वित्तमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2005 में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
- नाइजीरिया के ओकेन में चर्च में तीन बंदूकधारियों ने 2012 में हमला कर 19 लोगों की हत्या की।
- पाकिस्तान के कराची शहर में बाजार में 2013 को हुए बम विस्फोट में 11 लोगों की मौत।
- ईसवी को इटली के शायर और लेखक फ़्रैन्सिसको पेटर्क का जन्म 1304 में हुआ।
- प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 1871 को हुआ था।
- भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 को हुआ था।
- प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 को हुआ था।
- दक्षिण अफ्रीका की अभिनेत्री चार्लीज थेरोन का जन्म 1975 को हुआ था।
- रूस के लेखक थिएटर ड्रामों के निदेशक इस्टानिस्ला विस्की का निधन 1938 में हुआ।
- भारतीय लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निधन 1941 को हुआ था।
- चौथी लोकसभा के सदस्य पी. सी. अदिचन का निधन 1976 को हुआ था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीएम फसलों की मंजूरी को बने राष्ट्रीय नीति

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जेनेटेकली मोडिफ़ाइड यानी जीएम सरसों की भारत में व्यावसायिक खेती करने की सरकारी मंजूरी के खिलाफ याचिका पर खंडित फैसला दिया। जहां न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का आकलन था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी की 18 और 25 अक्तूबर, 2022 को सम्पन्न जिस बैठक में इसकी मंजूरी दी गई, वह दोषपूर्ण थी क्योंकि उसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति संजय करोल का मानना था कि जीईएसी के फैसले में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने जीएम सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ने की बात जरूर की। हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि केंद्र सरकार को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाएगा।

वैसे जीईएसी आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों के लिए देश की नियामक संस्था है। लेकिन दो जजों की पीठ ने निर्देश दिया कि चार माह के भीतर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जीएम फसल के सभी पक्षों के परामर्श से जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे जिनमें कृषि विशेषज्ञों, जैव प्रौद्योगिकीविदों, राज्य सरकारों और किसान प्रतिनिधियों सहित हितधारक शामिल हों। किसी से छुपा नहीं कि भारत में खाद्य तेल की जबरदस्त मांग है। साल 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद भारत को 141.93 लाख टन का आयात करना पड़ा। अनुमान है, अगले साल 2025 -26 में यह मांग 34 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। हमारे खाद्य तेल के बाजार में सरसों तेल की भागीदारी 40 फीसदी है। दावा किया गया कि यदि सरसों उत्पादन में जीएम बीज का इस्तेमाल करेंगे तो फसल 27 प्रतिशत अधिक होगी, जिससे तेल आयात खर्च कम होगा। हालांकि यह सोचने की बात है कि 1995

तक देश में खाद्य तेल की कमी नहीं थी। फिर बड़ी कंपनियां इस बाजार में आई। आयात कर कम किया गया और तेल का स्थानीय बाजार बैठ गया।

दावा यह भी है कि इस तरह के बीज से पारंपरिक किस्मों की तुलना में कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है और मुनाफा अधिक। लेकिन जीएम फसलों, खासकर कपास को लेकर हमारे अनुभव बताते हैं कि ऐसे बीजों के दूरगामी परिणाम खेती और पर्यावरण के लिए भयावह हैं। समझना होगा कि जीएम फसलों को उत्पाद के मूल जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है। आमतौर पर किसी अन्य जीव से आनुवंशिक सामग्री डाली जाती है जिससे उन्हें नए गुण दिए जा सकें जैसे अधिक उपज व पोषक तत्व, कम खरपतवार, कम रोग, कम पानी हो सकते हैं।

भारत में धारा सरसों हाइब्रिड-11 (डीएमएच-11) को देशी सरसों किस्म 'वरुणा' और यूरोपीय किस्म 'अर्ली हीरा-2' के संकरण से विकसित किया गया है। इसमें दो विदेशी जीन 'बार्नेज' और 'बार्स्टार' शामिल हैं, जिन्हें बैसिलस एमाइलोलिके फैसिएन्स नामक मृदा जीवाणु से पृथक किया गया है। दावा है कि इस बीज से उपज को 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है।

हमारे देश में अभी तक कानूनी रूप से केवल बीटी कपास एकमात्र जीएम स्वीकृत फसल है। बीते 17 सालों में कपास के बीज दावों पर खरे उतरे नहीं। बीटी बीज देशी बीज की तुलना में बहुत महंगा है और इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना ही पड़ा। फसल ज्यादा नहीं, लेकिन हर साल बीज खरीदना मजबूरी हो गई। विकसित देशों में भी ऐसे बीजों से उर्वर क्षमता व पौष्टिक तत्व कम हुए हैं।

बीटी कॉटन बीज बनाने वाली कंपनी मोनसेंटो ने 1996 में अपने देश अमेरिका में बोलगार्ड बीजों का इस्तेमाल शुरू करवाया था। इसके नतीजे निराशाजनक रहे। दुनियाभर में कहीं भी बीटी फसल को खाद्य पदार्थ के रूप में मंजूरी नहीं मिली है। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन के बीटी बीज कुछ खेतों में बोए जाते हैं, लेकिन इस उत्पाद को इंसान के खाने के रूप में इस्तेमाल पर पाबंदी है। यूरोप में भी इस पर सख्त पाबंदी है। ऐसे में भारत में सरसों तेल के लिए बीटी पर मंजूरी शक पैदा करती है।

जीएम बीजों से उत्पन्न सरसों के फूल मधुमक्खियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस तरह के बीजों से उत्पन्न सरसों के फूलों में मधुमक्खियों को परागण तो मिलेगा नहीं, उलटे कुछ जानलेवा कीटों की वे शिकार हो जाएंगी। इससे उनके खत्म होने की आशंका है। वहीं जीएम बीज हमारे पारंपरिक बीजों के अस्तित्व के लिए खतरा है और अब बदले हुए नाम से इन्हें बैंगन-टमाटर आदि के लिए पिछले रास्ते से घुसाया जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार कोई दो साल पहले जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नई फसल प्रजातियां विकसित करने के शोध को मंजूरी दे चुकी है। चालाकी से जेनेटिकली मोडिफाइड के नाम पर जीन एडिटिंग तकनीक शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैसे यूरोपीय यूनियन में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जीन एडिटिंग तकनीकी और जीएम फसल अलग नहीं। जाहिर है, अदालतें जब जीएम बीजों पर कोई फैसला देंगी तो जीनोम एडिटेड प्लांट्स के नाम से ये बीज बाजार में बिक रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित होने वाली कमेटी में इस नई तकनीक को यूरोपियन यूनियन की तरह जीएम ही मानना होगा।

मनु भाकर सभी खिलाड़ियों के लिए आदर्श

सारी दुनिया ने मनु भाकर को बीते दिनों मीडिया को इंटरव्यू देते हुए देखा। इतनी छोटी सी उम्र में वह कितने धीर-गंभीर अंदाज में अपनी बात रखती है। वह गीता का उदाहरण देते हुए सफलता के मर्म को समझाती है। मनु भाकर हिन्दी और अंग्रेजी में पूरे विश्वास के साथ सवालों के जवाब देती है।

निशानेबाज मनु भाकर को अब सारा देश जानता है। पेरिस ओलंपिक खेलों में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी चौथे स्थान पर रहीं। उनके पेरिस ओलंपिक खेलों में अभूतपूर्व प्रदर्शन से सारा देश प्रसन्न है। मनु भाकर सिर्फ अचूक निशानची ही नहीं हैं वो तो देश के अधिकतर खिलाड़ियों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी हमेशा भरपूर ध्यान दिया। हरियाणा के झज्जर शहर की रहने वाली मनु भाकर ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 90 पर्सेंट से अधिक अंक अर्जित किए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज (एलएसआर) से पालिटीकल साईंस आनर्स की डिग्री भी ली। एल.एस.आर. देश का चोटी का महिला कॉलेज माना जाता है। नोबल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की शिखर नेता आंग सान सू ची यू ने 1964 में इसी लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मुन भाकर का लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ना इस बात की गवाही है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी हमेशा फोकस रखा।

इधर बीते कुछ सालों से हमारे अपने देश के बहुत सारे नामवर खिलाड़ियों ने स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं मानी जा सकती। आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों न हो जाएं, पर आप बेहतर इंसान और नागरिक तो ढंग से पढ़-लिखकर ही बनते हैं। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी, क्रिकेटर अजीत वाडेकर और सुनील गावस्कर उन खेलों की दुनिया के शिखर नाम रहे हैं जिन्होंने खेल के मैदान में जौहर दिखाते हुए अपनी पढ़ाई को नजरंदाज नहीं किया। चुन्नी गोस्वामी और अजीत वाडेकर तो स्टेट बैंक में अहम पदों पर इसलिए पहुंचे क्योंकि इनके पास सही डिग्रियां थीं। सुनील गावस्कर बीते पांच दशकों से सक्रिय हैं। पहले क्रिकेटर के रूप में और बाद के दशकों में बतौर लेखक और कमेंटेटर के। उनके पास क्रिकेट की गहरी समझ के अलावा शब्दों का भंडार भी है। वैसे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के आधार पर नौकरी तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल ही जाती हैं। माफ करें, कई कथित खिलाड़ियों को जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर भी नौकरियां मिलती रही हैं। यह भी सबको पता है।

सारी दुनिया ने मनु भाकर को बीते दिनों मीडिया को इंटरव्यू देते हुए देखा। इतनी छोटी सी उम्र में वह कितने धीर-गंभीर अंदाज में अपनी बात रखती है। वह गीता का उदाहरण देते हुए सफलता के मर्म को समझाती है। मनु भाकर हिन्दी और अंग्रेजी में पूरे विश्वास के साथ सवालों के जवाब देती है। यही सही शिक्षा सिखाती भी है। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अधिकतर खिलाड़ियों को देख लें। जावेद मियांदाद, इंजमाम-उल-हक, शोएब अख्तर जैसे मशहूर खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में भले ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हों, पर वे जब बोलते हैं तो सच में बहुत अफसोस होता है कि बेहतर शिक्षा ना मिलने के कारण वे अपने व्यक्तित्व निर्माण में कितना पिछड़ गए। वे इंटरव्यू देते वक्त पूरी तरह से सड़कछाप ही लगते हैं।

बेशक, शिक्षा ही जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। एक सफल जीवन में सार्थक शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, सही, गलत में अंतर कर पाता है। शिक्षा और संस्कार एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके संस्कार सही हैं तो आपकी शिक्षा भी सही दिशा में जाएगी। मनु भाकर और दूसरे खिलाड़ियों के कोचों का दायित्व है कि वे युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाएं ताकि आने वाला कल अच्छा हो। उन्हें शिक्षा के महत्व की जानकारी दें।

ये मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा ?

अमेरिका एक ओर ईरान पर दबाव बना रहा है कि आग ज्यादा न भड़के लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने खुले रूप से कह भी दिया है कि यदि ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि वह सीधे तौर पर जंग में कूद सकता है। यहां यह जानना जरूरी है कि चीन की भूमिका क्या होगी।

वायनाड से लेकर हिमालय तक खौफ का आलम, इधर इजराइल-हमास युद्ध में ईरान और अमेरिका कूद गए तो ? मौत के तांडव से बहुत व्यथित हूं, वायनाड में भूस्खलन ने ढाई सौ से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इधर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ दरक रहे हैं और दिल दहल रहा है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन सारी घटनाओं के मूल में सरकारों की गंभीर लापरवाही है। मैं लापरवाही शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार को सब कुछ मालूम है फिर भी खतरनाक जोन में लोग बसे हुए हैं क्योंकि वे गरीब हैं। इन इलाकों में पेड़ काट कर खेत के मैदान तैयार किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना कर क्या इन लोगों को दूसरी जगह बसाना जरूरी नहीं है? जरूरी तो बहुत है लेकिन दुर्भाग्य से किसी को फिक्र कहां है? फिक्र तो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हमास और इजराइल की जंग में पिस रहे आम फिलिस्तीनियों की भी किसी को नहीं है। जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था तब पिछले साल अक्तूबर में इसी कॉलम में मैंने लिखा था कि जंग का सबसे बुरा खामियाजा आम फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ेगा और वही हो रहा है। गजा में करीब 40 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 85 हजार से ज्यादा घायल हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों का बुरा हाल है। इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अब आगे क्या? हनियेह की हत्या का मामला ईरान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, हनियेह ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे। इस समारोह में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे, शपथ के बाद हनियेह राष्ट्रपति से मिले और स्टेट गेस्ट होने के नाते ऐसे इलाके में रुके थे जहां के चप्पे-चप्पे पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का पहरा रहता है। इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई, इजराइल ने खुले तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन तोहमत उसी पर लग रही है, हनियेह पर इससे पहले चार हमले हो चुके थे और इजराइल ने खुद कहा था कि हनियेह के परिवार के दस लोगों को उसने मार गिराया है। हनियेह की हत्या के तत्काल बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हनियेह की मौत का बदला लेना ईरान का फर्ज है। एक इजराइली अखबार ने तो सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि खामेनेई ने इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया है। ईरान कोई कदम नहीं उठाता है तो उसकी कमजोरी मानी जाएगी और ईरान कमजोर नहीं दिखना चाहता।

अमेरिका एक ओर ईरान पर दबाव बना रहा है कि आग ज्यादा न भड़के लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने खुले रूप से कह भी दिया है कि यदि ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि वह सीधे तौर पर जंग में कूद सकता है। यहां यह जानना जरूरी है कि चीन की भूमिका क्या होगी। चीन ने अभी हाल ही में कहा है कि वह गाजा पट्टी में संहार को अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि चीन जुबानी जंग लड़ने में तो आगे रहेगा लेकिन मध्य पूर्व की इस आग में अपने हाथ नहीं जलाएगा। तो क्या वह आर्थिक रूप से हमास की मदद करेगा? ऐसा हो सकता है।

एक सवाल यह भी है कि सऊदी अरब की भूमिका क्या होगी? सऊदी अरब की हमेशा यह चाहत रही है कि वह मुस्लिम देशों का नेता भी बना रहे और अमेरिका व इजराइल से उसके संबंध भी अच्छे रहें। सऊदी-इजराइल के बीच शांति समझौता होने वाला भी था। इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अहम शांति समझौता लगभग होने ही वाला है जो अरब-इजराइल संघर्ष को खत्म करने और अन्य अरब मुल्कों के इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को बढ़ावा देगा। इससे फिलिस्तीनियों के साथ शांति की संभावनाएं बढ़ेंगी लेकिन इजराइल पर हमास के हमले ने सारी संभावनाएं खत्म कर दीं। हालांकि सऊदी अरब ने हमास से दूरी बना रखी है।

घर के मुखिया को सर्वप्रथम खुद नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसका प्रभाव लोगों पर होता है। कई बार घर के बड़े लोग सबके लिए नियम कानून बना देते हैं, लेकिन खुद उसपर अमल नहीं करते। ऐसे घर में खुशियों का वास ज्यादा दिन तक नहीं रहता। इसलिए हमेशा सदस्यों के साथ-साथ खुद भी नियमों का पालन करें और सबके लिए प्रेरणास्रोत बनें।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, बुधवार 07 अगस्त 2024
www.live7tv.com

केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्द्र बनाए रखना जरूरी

मनीषा प्रियम

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद का संघर्ष भारतीय राजनीति में नया नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादा उभर रहा है। हाल के दो मामलों में देखें, तो यह कुछ स्पष्ट होगा। 27 जुलाई को हुई नीति आयोग की बैठक में गैर- भाजपा शासित राज्यों के करीब दस मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। इंडिया गठबंधन से अलग होकर सं ममता बनर्जी जरूर इसमें शामिल हुई, लेकिन वह भी यह आरोप लगाकर बाहर निकल गईं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें नियमानुसार बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। साथ ही बारी से पहले बोलने के उनके आग्रह को भी स्वीकारा गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया। ममता के बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकलने का राजनीतिक नतीजा यह हुआ कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा सेट किया कि राज्यों के कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख प्रशासन के वह कैसे वाहक बनेंगे, इस पर कोई विशेष चर्चा जनता के बीच नहीं हुई। सिर्फ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मामले बनाम केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति ही सुर्खियां बनीं। दूसरा मामला, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए। इस बयान को भी ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वह बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। इससे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आग-बबूला हो सकते हैं। निशिकांत के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी सांसद के अलावा अन्य किसी जिम्मेदार पद पर नहीं हैं। लेकिन राजनीति में तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। विपक्ष पहले से ही इस बात को लेकर हमलावर है कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। इस बयान को आधार बनाकर विपक्षी नेता आगामी कुछ महीनों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की खबरें भी राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनती रही हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों के राज्यपालों से टकराव तो अदालतों तक पहुंच चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संसद में विपक्ष के मजबूत होने से संघवाद बनाम क्षेत्रवाद की लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा प्रभावशाली थी, तो दूसरी तरफ उसके विरोध में कई प्रांतों में क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए। यानी प्रतिस्पर्धा द्विदलीय न होकर भाजपा बनाम क्षेत्रवाद बन गई। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में द्रमुक ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच टकराव था। यहां तक कि राज्यपाल ने राज्य के संयुक्त विधानसभा सत्र की बैठक में अभिभाषण (जो राज्य सरकार द्वारा लिखित एवं अनुमोदित होता है) पढ़ने से इन्कार कर दिया था। ऐसा ही कुछ केरल में भी हुआ। यहां राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान एवं वामपंथी गठबंधन के मुख्यमंत्री पी विजयन के बीच सर्वाधिक मतभेद विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर हुआ। कहने का मतलब कि हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बहसबाजी हुई और राज्य सरकारों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कानूनी मसले थोड़े क्लिष्ट हैं, किंतु इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में यह लड़ाई राजनीतिक है। इस राजनीतिक दंगल का सबसे बड़ा प्रतिरूप पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा से जमकर लोहा ले रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़ी मुहिम चलाई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव अभियान की बागडोर अपने हाथों में रखी। लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला अस्मिता के नाम पर क्षेत्रवाद का झंडा बुलंद कर फिर से सत्ता में लौट आईं। अब तक माना जाता रहा है कि राज्यों के चुनाव में ही स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीयता हावी रही। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता ने स्पष्ट किया कि भारत राज्यों की संघीय व्यवस्था है। पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस न्यायालय के सहयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा पाए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह गुहार लगाई है कि विधानसभा द्वारा पारित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय से लटकाए रखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला भी अधर में लटका हुआ है। न्यायालय ने राज्यपाल कार्यालय और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। राज्यपाल इन आरोपों का खंडन करते हैं। कुल मिलाकर मामला भले ही न्यायालय में लड़ा जा रहा हो, पर यह वास्तव में केंद्र बनाम राज्य तथा संघवाद के ऊपर छिड़ी सघन राजनीतिक लड़ाई है। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) का बंटवारा किया गया है। फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच हितों और शक्तियों के उपयोग को लेकर समय-समय पर टकराव देखे जाते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गुलेल चलाने से संघीय प्रणाली नहीं बदलने वाली है। नीति आयोग की बैठक में गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों का हिस्सा न लेना, ममता बनर्जी का बैठक छोड़कर बाहर आना, निशिकांत दुबे के बयान को तूल देना यह सब राजनीतिक तिकड़मबाजी है। संघवाद बेहतर चले इसके लिए केंद्र तथा राज्यों में सौहार्द्र बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि शासन-प्रशासन सुचारू ढंग से चले।

युद्ध की आशंका

ईरान, हमास और हिजबुल्ला की इस्राइल से बदला लेने की घोषणाओं के बीच मध्य पूर्व टकराव के एक नए दौर के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। पहले हिजबुल्ला के मिलिटरी चीफ फुआद शुकर का लेबनान के बेरूत में इस्राइली कार्रवाई में मारा जाना और फिर हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या- इन दोनों घटनाओं ने अचानक इस क्षेत्र का तापमान काफी बढ़ा दिया है। आलम यह है कि कल तक शांति की जरूरत बता रही और इस दिशा में कोशिश कर रही शक्तियां भी फिलहाल संघर्ष के और तेज होने की आशंका के आगे लाचार दिख रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे तमाम देश अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील कर रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से दूर रहने और जो पहले से वहां हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा है। इस्राइल में रह रहे भारतीयों से भी सतर्क रहने और प्रोटोकॉल्स का पालन करने को कहा गया है। ईरान की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है और वह इस अधिकार का इस्तेमाल निश्चित रूप से करेगा। दूसरी ओर इस्राइल भी हमले की आशंकाओं को लगभग स्वीकार करते हुए इसका सामना करने की तैयारियों में लग गया है। वहां नागरिकों को बताया जा रहा है कि हमला होने की स्थिति में किन-किन स्थानों को बम शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई कितनी गंभीर होगी और इसके किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। याद किया जा सकता है कि इसी साल अप्रैल में भी ईरान ने इस्राइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। तब सीरिया के दमिश्क में इस्राइली कॉन्सुलेट पर हुई बमबारी का बदला लेने के लिए उसने इस्राइल पर 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइलें और 110 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी थीं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मामले को और बिगड़ने से बचा लिया गया था। क्या इस बार भी बात दोनों तरफ की सीमित और सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित रहेगी? सभी पक्षों के मूड को देखते हुए फिलहाल इस उम्मीद में ज्यादा दम नजर नहीं आता, लेकिन यह बात भी सही है कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों के प्रत्यक्ष और परोक्ष नतीजों से जूझती दुनिया ईरान-इस्राइल के बीच एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि अगर ऐसा कोई युद्ध हुआ तो वह दूर तक नहीं फैल जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि कूटनीति के सभी संभव दांव आजमाते हुए इस तनाव को यथासंभव कम नुकसान की कीमत पर निकल जाने दिया जाए।

बदलती जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित हों युवा

सुरेश सेठ

दुनिया तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कामकाज के तरीके तेजी से डिजिटल और स्वचालित हो रहे हैं। रोबोटिक शक्ति इसका आधार बन रही है। कृत्रिम मेधा भी मुख्य सहयोगी के रूप में उभर रही है। यानी भारत में उत्पादन, निवेश और खेती-किसानी के तरीके भी बदलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अगले दस सालों में कामकाज के घंटों और नौकरी करने के तौर-तरीकों में परिवर्तन आएगा। एआई और रोबोटिक्स के चलते स्थायी व्यवस्था की जगह गिग अर्थव्यवस्था सामने आएगी। इसमें जरूरत के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने का चलन बढ़ेगा। इसके साथ ही, काम के घंटे बदलने के कारण पारंपरिक नौकरियों की व्यवस्था के अतिरिक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर विभिन्न सेक्टरों-कंपनियों में एक साथ कई जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे। इसका असर डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में अभी से दिखने लगा है। आईटी एक्सपर्ट वर्क फ्रॉम होम करते हुए एक साथ कई कंपनियों का काम संभाल रहे हैं। पिछले दिनों एक प्रस्ताव सामने आया था कि काम के घंटे 10 से 14 कर दिए जाएं, क्योंकि आईटी क्रांति का सामना इसी तरह से किया जा सकेगा। बहरहाल, कामकाजी दुनिया की हकीकत बदल रही है। हाल के बजट में वित्तमंत्री ने भी जिन पांच क्षेत्रों में नौकरी की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया है, उसमें कृत्रिम मेधा और रोबोट्स की दुनिया के प्रयोग को नकारा नहीं है। भारत, जिसकी आबादी इस समय दुनिया में सबसे अधिक है, क्या वह कृत्रिम मेधा या रोबोट का उपयोग उसी तरह कर सकता है जैसे शक्ति-संपन्न पश्चिमी देश करते हैं, जहां आबादी की कमी है। बजट सत्र में वित्तमंत्री ने नई नौकरियों के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके द्वारा अगले पांच साल में 4.1 करोड़ नौजवानों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार की दुनिया में खुद को अनुकूलित कर सकें। देश में आज भी आधी आबादी से कम खेतीबाड़ी में लगी हुई है। प्रश्न है कि वहां से सकल घरेलू आय में केवल 15 प्रतिशत का योगदान ही क्यों मिल रहा है? आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, ऐसे बेरोजगार भी हैं जो पारंपरिक तरीके से अपनी पैतृक खेतीबाड़ी के धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन देश की निवल आय में उनका कोई योगदान नहीं है। इस अनुपयोगी युवा शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे वैकल्पिक धंधे में होना चाहिए जो उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही वहीं काम उपलब्ध करवा दे। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और फसलों को पूर्ण रूप से तैयार करके सीधे मंडी में बेचना भी एक समाधान हो सकता है। बजटीय घोषणाओं में अगले वर्ष अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाने का वादा है। इसके अंतर्गत इन सभी लोगों को काम मिलेगा। लघु-कुटीर उद्योगों की बातें तो होती हैं लेकिन लाल डोरा क्षेत्र में भी ग्रामीण युवा शक्ति के स्थान पर शहरी निवेशक ही प्रवेश करता नजर आता है। निस्संदेह, जब निजी क्षेत्र का विकास होगा और नये कारखाने खुलेंगे या फसलों पर आधारित छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो लोगों को स्वाभाविक रूप से रोजगार मिल जाएगा। सरकार द्वारा नौकरियां देने की क्षमता बहुत कम है। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का प्रतिशत 30 से अधिक नहीं रहा। आर्थिक प्रोत्साहन और नए निवेश के बावजूद देश अधिक से अधिक हर साल 70 लाख नौकरियां ही प्रदान कर पाएगा, जबकि देश के युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक करोड़ नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या निजी क्षेत्र, सरकार के सभी प्रोत्साहनों, सब्सिडियों, मुद्रा योजनाओं और लोन क्षमता बढ़ाने के बावजूद इस कसौटी पर पूरा उतर सकेगा? बेशक, इस बार के बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रति इकाई कर दी गई है। नया प्रशिक्षण प्राप्त करने की इंटर्नशिप पर सबसिडी भी दी जा रही है। लेकिन क्या इतना काफी है? देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को अभी भी उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। शिक्षा बजट में केवल सवा लाख करोड़ रुपये और सेहत पर केवल 89 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह युवा शक्ति को स्वस्थ-शिक्षित नागरिक बनाने हेतु काफी नहीं है। शिक्षाविदों के अनुसार, पुरानी शिक्षा पद्धति से निकले हुए 75 प्रतिशत ग्रेजुएट्स नई डिजिटल व्यवस्था में नौकरी के योग्य नहीं हैं। इसलिए, युवा शक्ति को अपनी डिग्री से कहीं नीचे के काम करने के लिए समझौता करना पड़ता है। देश में काम देने में असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन डिजिटलीकरण के साथ असंगठित क्षेत्र भी बिखरता नजर आ रहा है। जरूरी है कि बेरोजगारों के संघर्ष को बेहतर ढंग से समझा जाए और बदलते समय की मांगों के अनुसार युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके उसे सही दिशा में कार्यशील बनाया जाए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुक्खू के साहसिक फैसलों में सियासी दूरदृष्टि

ज्योति मल्होत्रा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अवश्य ही हिंदी अंचलों के रूपक राजा-रंक से बहुत अच्छी तरह वाफिक होंगे, यह द्योतक है उस बड़े अंतर का, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों और उन मां-बाप के औलादों के बीच है जिन्हें दो जून की रोटी जुटाने के लिए दिन-रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस साल मार्च महीने में शिमला की सीली सर्दी में -सार्वजनिक स्थानों पर और बंद कमरों में- राजनीतिक कानाफूसी जमकर चली होगी, विद्रोही और वफादार खेमों में एक जैसे संकेत देते हुए, जब कांग्रेस के अपने विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया और राज्य सरकार को लगभग तोड़ ही डाला था। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के दक्षिण भारतीय चतुर नेताओं के साहसिक प्रयासों से जमे घी को आग पकड़ने से पहले अलग किया जा सका। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे और रामपुर बुशहर के पूर्व राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र पहले तो इस इंतजार में रहे कि शायद कांग्रेस हाइकमान बगावत में उनका साथ देगा और सामान्य वर्ग से आते मुख्यमंत्री की जगह गद्दी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन सुक्खू भी अपना मास्टर कार्ड खेल गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पूर्व कंडक्टर के बेटे सुक्खू ने दिखा दिया कि वे पार्टी में सबसे निचले स्तर से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया, ठीक वैसे ही जैसे कि हाई कमान के गांधी परिवार के लोग करने पर जोर देते हैं। वे भाजपा के दिए लालचों में कभी नहीं फंसे। अंत में विक्रमादित्य सिंह डगमगाए तो लेकिन छह अन्य साथी कांग्रेसी एवं तीन आजाद विद्रोही विधायकों की तरह पार्टी नहीं छोड़ी, इन छह बागी कांग्रेसी विधायकों में चार उपचुनाव में हार गए। देखा जाये तो अब अवश्य ही वे विधायक किस्मत के फेर को कोस रहे होंगे। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की कंगना रनौत से भी हार गए, जो कि सुक्खू का अन्य मास्टर कार्ड रहा, जब उन्होंने अपने इस युवा और कुलीन साथी को उत्साहित करते हुए, आसमान छूने के लिए, चुनावी रण में उतार दिया। मार्च महीने के विद्रोह के बाद खाली हुई सीटों में एक पर अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को जितवा कर सुक्खू ने अपनी स्थिति आगे और मजबूत कर ली है। लेकिन यह राजनेता दूसरों के जैसा नहीं जो अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर बैठ जाए। जहां पड़ोसी राज्य पंजाब से अनेक मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से अपनी राजकोषीय स्थिति संभाले नहीं संभल रही, विशेषकर दशकों से दी जा रही मुफ्त की बिजली के चलते, वहीं हिमाचल के सुक्खू 2022 में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के अपने चुनावी वादे से पीछे हट गए हैं। हाल ही उन्होंने संपन्न वर्ग के लिए बिजली सब्सिडी खत्म करने की घोषणा की है। नए बिजली सुधार में कुछ शर्तें हैं, यह केवल उन पर लागू होगा जो आयकर चुकाने वाली श्रेणी में हैं, बाकियों के लिए भी मुफ्त की बिजली 300 से घटाकर 125 यूनिट कर दी गई है, पिछली भाजपा सरकार ने भी ठीक यही चुनावी वादा किया था। बिजली सब्सिडी केवल एक परिवार-एक मीटर के आधार पर ही मिलेगी। यह पंजाब की तरह नहीं, जहां अमीरों ने मुफ्त बिजली की ऊपरी सीमा 300 यूनिट के भीतर बनाए रखने को एक ही घर में कई-कई मीटर लगवा लिए और संबंधित अधिकारी इस मामले में खुद को असहाय बताते हैं। अब हिमाचल में सभी बिजली कनेक्शन आधार कार्ड या राशन कार्ड से जुड़े होने जरूरी हैं। जिन्होंने नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए बगैर मीटर लगा रखे हैं उन्हें पूरा भुगतान करना पड़ेगा। सुक्खू का यह कदम वह ध्यान नहीं खींच पाया जिसके वह हकदार हैं, लेकिन वे पूरी तरह इसके काबिल हैं। देशभर में बिजली जैसे लोकलुभावन विषय में सुधारक उपाय करने पर राजनेता विशेष रूप से कतराते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच तुलनात्मक अंतर विशेष रूप में काफी अधिक है। हिमाचल की कुल 77 लाख जनसंख्या पंजाब की 3.17 करोड़ के सामने बहुत कम है, अधिकांश इलाका भी उपजाऊ मैदानी न होकर पहाड़ी है, साथ ही भरपूर पानी और मुफ्त की बिजली डकारने वाली गेहूं-चावल जैसी फसलें उगाने पर निर्भरता भी बहुत कम है। सुक्खू चतुर हैं। अपने सूबे को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है, उन्हें मालूम है यदि हिमाचल प्रदेश बढ़िया कर दिखाएगा तो यह उनके खुद के लिए भी अच्छा होगा। अपनी आस्तीन और बाहर पल रहे सांपों का फन कुचलकर उन्होंने अपनी स्थिति सफलतापूर्वक मजबूत कर ली है। उल्लेखनीय है कि बीती फरवरी में राज्यसभा के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालने वालों को काला नाग कहा गया गया था। इस उपलब्धि ने उन्हें लोगों की जेब से पैसा निकलवाने वाले अति-संवेदनशील विषय को छूकर राजनीतिक जोखिम उठाने के काबिल बनाया है। सोशल मीडिया के इस युग में, जहां तारीफ हाथों-हाथ मिल जाती हैं, यह कृत्य काफी श्रेयस्कर है। केवल दक्षिण भारत के कुछ अमीर राज्य जैसे कि केरल और तमिलनाडु, इस विषय को छू पाएं हैं, वह भी काफी घबराहट के बाद। सुक्खू ने स्पष्ट रूप से उनका अनुसरण किया है। केरल ने नवम्बर, 2023 में मुफ्त बिजली को सीमित करते हुए केवल 30 यूनिट कर दिया था। तमिलनाडु में सिर्फ 100 यूनिटें मुफ्त हैं। सुक्खू ने कहा कि राज्य के सिर पर बहुत भारी कर्ज है, कुल ऋण 85000 करोड़ रुपये पार कर चुका है, केवल 2023-24 में ही राज्य बिजली बोर्ड का घाटा 1800 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य सरकार ने 950 करोड़ रुपये बतौर सहायता राशि भी दिये हैं। हालांकि नए सुधारक उपायों से केवल 200 करोड़ रुपये ही बचने की उम्मीद है। लेकिन फिर यह भी तो देखने लायक है कि कौन-कौन हैं जिनकी जेब से पैसा निकलेगा, तमाम मौजूदा और पूर्व मंत्री, सभी वर्तमान और पूर्व सांसद एवं विधायक, तमाम आईएएस एवं आईपीएस, राज्य-काडर के अफसर, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी और वे सब जो आयकर चुकाते हैं। इस विषय में सुक्खू स्पष्टतः न केवल उत्तर भारत के शेष मुख्यमंत्रियों के लिए बल्कि बाकी पूरे भारत के लिए भी एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भांति, जिन्होंने हालिया प्रस्तुत बजट में खाद्य, खाद और ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को 7.8 प्रतिशत घटाया है यानी 413,466 करोड़ रुपये से 381,175 करोड़ रुपये। सुक्खू उन राजनेताओं में से हैं जिन्हें यह समझ है कि राजकोषीय बही-खाते को संतुलित रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें मालूम है अगला चुनाव तीन साल बाद है, इसलिए नाखुशगवार फैसलों की चुभन से पहले पार पा लेना ज्यादा सही विचार है। कहा जा रहा है कि अगला नम्बर पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी का है, फिलहाल पूरे सूबे में पेयजल मुफ्त बराबर है, यहां तक कि महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा वाले फैसले पर भी पुनर्विचार हो सकता है। वे उन स्कूलों का भी विलय करने की सोच रहे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है यानी प्रत्येक कक्षा में पांच से कम छात्र। इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां अध्यापक कम हैं और इन फालतू भवनों का उपयोग पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। भले ही कथनी और करनी में अभी काफी अंतर है। लेकिन यदि सुक्खू अपने पहाड़ी सूबे की आर्थिकी में सुधार लाने में सफल रहते हैं तो वे उस समूह से अलग अपनी पहचान बना लेंगे जो स्थाई रूप से दिल्ली दरबार की जी-हजूरी करने में लगा रहता है ह्वऔर उन्हें यह करने से इंकार है। लेकिन अभी यह बताना जल्दबाजी होगी। यदि लक्षण वही रहे, जो दिखाई दे रहे हैं, तो सुखविंदर सुक्खू का सफर देखना रोचक रहेगा।

बांग्लादेश : विद्रोह या साजिश

भले ही प्रथम दृष्टया, बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन की वजह आरक्षण विरोधी आंदोलन से उपजा आक्रोश बताया जा रहा हो, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्याग कर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह बनना बड़ा कारण रहा। लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश को हल्के में लिया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर चीन के साथ मिलकर पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश का इस्तेमाल शेख हसीना को सत्ता से हटाने में कर लिया। इसमें पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने से इंकार नहीं किया जा सकता। चीन भारत को चौतरफा घेरने और हमारे पडोसी देशों में अपनी कठपुतली सरकार बैठाने के लिए तत्पर है। इस संकट को शह देने में और भी कई विदेशी ताकतें रही। महज सात माह पहले हुए आम चुनावों के बाद से ही देश में जनाक्रोश कोभड़काने की कोशिशें हो रही थी । दक्षिणपंथी रुझान वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। हालांकि,शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतरराष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। वास्तव में शेख हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। अंततः एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा।

पडोसी देश बांग्लादेश में सत्ता पलट क्यों ?

प्रेमकुमार मणि

पूर्वी पाकिस्तान में जमायते-इस्लाम और दूसरे कट्टरवादी मुस्लिम संगठन सीधे तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। बांग्लादेश निर्माण के बाद ये शीत-निष्क्रियता में चले गए। लेकिन 1975 में इन लोगों की एक बार फिर चली। 15 अगस्त को जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, शेख मुजीब के घर में सेना की एक टुकड़ी घुसी, उन्हें कब्जे में लिया और पत्नी व तीन पुत्रों सहित मार दिया। बस चार साल में बांग्लादेश फिर खून से रंग गया। तब से उस देश में लोकतंत्र और फौजी शासन का आना-जाना लगा रहता है। इधर पिछले पंद्रह वर्षों में शेख हसीना ने उसे आर्थिक और सामाजिक मामले में आर्डर में लाने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन आज उसका भी पटाक्षेप हो गया। एक बार फिर वहां फौजी शासन कायम हो गया है। भारत पर इसके प्रभाव कई रूप में पड़ेंगे। बंगलादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब हिन्दू है। भारत बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 14 और पूर्वी पाकिस्तान में 28 फीसद हिन्दू थे।

हमारे पड़ोसी बंगलादेश में राजनीतिक अराजकता इतनी हुई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को भाग कर भारत आना पड़ा। विद्रोह की खबरों के अनुसार सेना ने राजपाट संभाल लिया है। आंदोलनकारियों ने हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोलकर लूटपाट मचाई और सेना देखती रही। हिंसक झड़पों में कोई तीन सौ लोगों के मारे जाने की खबर है।

मतलब साफ है बंगला देश में लोकतंत्र एकबार फिर खत्म हुआ। कब बहाल होगा कोई नहीं जानता। उस देश पर नजर रखने वाले लोग जानते हैं कि शेख हसीना ने पिछले पंद्रह वर्षों में उस देश को आर्थिक-सामाजिक तौर पर काफी मजबूत किया था। वह समाजवादी रुझान की लोकतंत्रवादी रही हैं। उनका कट्टरवादी मुसलमानों से हमेशा विरोध रहा। कट्टरतावादी लोग उनके जानी दुश्मन थे। इन्हीं लोगों ने उनके पिता शेख मुजीब, उनकी माँ और तीन भाइयों का कत्ल 1975 में एक विद्रोह के तहत किया था।

एक नए देश के रूप में बंगलादेश का जन्म बड़े संघर्ष से हुआ। आज की पीढ़ी पता नहीं उस से कितना अवगत है। नयी पीढ़ी को यह सब जानना चाहिए। 1970 का दौर ख्याल कर सकता हूँ। अपने देश में कांग्रेस के भीतर संग्राम मचा हुआ था। पार्टी दो भागों में बंट गई थी। 1971 के मार्च में भारत में मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और इस में इंदिरा गांधी संसद में दो तिहाई स्थान ला कर सत्तासीन हुईं। लेकिन भारत से पहले 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। वहां की कुल 313 सीटों वाली संसद में शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी आवामी लीग को 167 सीटें मिलीं थीं. पूर्वी पाकिस्तान (आज के बांग्लादेश) की कुल 169 में से 167 सीटें। लेकिन याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने तय कर लिया कि शेख को सत्ता नहीं सौंपनी है। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। इसे पाकिस्तान की फौज ने दुश्मन देश की तरह निर्ममता से कुचलने की कोशिश की। लाखों बेकसूर लोगों को पाकिस्तानी फौज ने मार डाला। हजारों स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार उसी मुल्क की फौज ने किये। कोई एक करोड़ लोग भाग कर भारत आ गए और शरणार्थी बने। पूरा भारत शेख मुजीब के साथ था। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने दुनिया भर में घूम कर शेख मुजीब और पूर्वी पाकिस्तान की जनता का पक्ष रखा। पाकिस्तान अपने देश को बताना चाहता था कि शेख के पीछे भारत का समर्थन है और उस ने 3 दिसम्बर 1971 को भारत के पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर दिया। उसे भरोसा था कि उसके पीछे अमेरिका है। लेकिन इंदिरा गांधी की चतुराई भरी कूटनीति के सामने पाकिस्तान की एक न चली। अमेरिकी फौजी बेड़े की धमकी को अंगूठा दिखाते हुए भारतीय सेना ने बंगला देश को पाकिस्तान से मुक्त करा लिया। ढाका में लगभग एक लाख सशस्त्र पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन गया। भारत के दबाव में शेख मुजीब पाकिस्तान की जेल से रिहा किये गए। वह आजाद बंगलादेश के राष्ट्रपति बने।

पूर्वी पाकिस्तान में जमायते-इस्लाम और दूसरे कट्टरवादी मुस्लिम संगठन सीधे तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। बांग्लादेश निर्माण के बाद ये शीत-निष्क्रियता में चले गए। लेकिन 1975 में इन लोगों की एक बार फिर चली। 15 अगस्त को जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, शेख मुजीब के घर में सेना की एक टुकड़ी घुसी, उन्हें कब्जे में लिया और पत्नी व तीन पुत्रों सहित मार दिया। बस चार साल में बांग्लादेश फिर खून से रंग गया। तब से उस देश में लोकतंत्र और फौजी शासन का आना-जाना लगा रहता है। इधर पिछले पंद्रह वर्षों में शेख हसीना ने उसे आर्थिक और सामाजिक मामले में आर्डर में लाने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन आज उसका भी पटाक्षेप हो गया। एक बार फिर वहां फौजी शासन कायम हो गया है।

भारत पर इसके प्रभाव कई रूप में पड़ेंगे। बंगलादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब हिन्दू है। भारत बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 14 और पूर्वी पाकिस्तान में 28 फीसद हिन्दू थे। आज पाकिस्तान में लगभग 2 फीसद और बंगलादेश में 8 फीसद हिन्दू हैं। वह भी मुश्किल में हैं। हसीना पर एक आरोप यह भी है कि उन्होंने अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण सुनिश्चित किया है। वहाँ कुल मिला कर 80 फीसद आरक्षण लागू था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के वारिसों के लिए भी था। साफ है कि जमायते-इस्लाम के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वे तो तब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। बांग्लादेश में जो अभी राजनीति चल रही है उसके पीछे यही कोटा पॉलिटिक्स है। विद्रोह का रुझान यही स्पष्ट करता है कि कट्टरतावादी इस्लामी ताकतें वहाँ मजबूत हुई हैं। पिछले आम चुनाव के समय से ही यह स्पष्ट हो रहा था।

चिन्ता की बात यह है कि पाकिस्तान और बंगलादेश में कट्टर धार्मिकता का उभार भारत में भी इसे बल देगा। भारत में इसके उभार का मतलब होगा भाजपा का और अधिक उभार या उसकी मजबूती। भारत ने आर्थिक रूप में अपनी स्थिति कई कारणों से थोड़ी मजबूत कर ली है। पाकिस्तान, श्रीलंका में आर्थिक अराजकता की स्थिति है। बांग्लादेश में भी अब वही आर्थिक अफरातफरी होगी। नेपाल की स्थिति से सब वाकिफ हैं। जब भारत के चारों तरफ दैन्य होगा तब भारत में सम्पन्नता क्या संभव होगी ? कभी नहीं। इसलिए बांग्लादेश में आज जो हुआ है वह हमारे देश भारत के लिए भी एक सबक होना चाहिए। भारत सरकार को तो नजर रखनी ही चाहिए, हम भारतवासियों को भी चिन्ता करनी चाहिए। पड़ोस में आफत आई हो तो हम चैन से कैसे सो सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शेख हसीना : बांग्लादेश को पटरी पर लाईं लेकिन अहंकार ले डूबा

शंभूनाथ शुक्ल

मुगलों के समय हिंदुस्तान का सूबा-ए-बंगाल सबसे संपन्न सूबा था। दिल्ली को भी उसकी संपन्नता से रश्क था। बंगाल की इस संपन्नता का राज था उसके बुनकर। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय के पूर्व ढाका की मलमल के लिए मशहूर था, ढाका की मलमल की एक थान को अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता था। कई सौ वर्ष बाद बंगाल का एक हिस्सा, जो अब बांग्लादेश है, अपने वस्त्रों के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक जाना जाता है। वहां के बाजारों में मेल-फीमेल दोनों के रेडीमेड कपड़ों पर मेड इन बांग्ला देश स्पष्ट तौर पर दर्ज होता है और इन कपड़ों की वहां मांग भी खूब है। अभी दो दशक पहले तो जो बांग्लादेश अपनी भुखमरी और पलायन के लिए जाना जाता था, वह बांग्लादेश आज अपने वस्त्र उत्पादों के लिए अव्वल है। यकीनन यह सफलता शेख हसीना वाजेद की सेंटर टू लेफ्ट सरकार के खाते में दर्ज होगी ही।

पिछले 15 साल से बांग्लादेश की पीएम की जिम्मेदारी संभालने वाली शेख हसीना को लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो अपना देश छोड़ कर भाग निकलीं। उनके लिए सबसे मुफीद जगह भारत थी, इसलिए वे पहले भारत आईं और यहां से उनके इंग्लैंड जाने की उम्मीद थी। लेकिन इंग्लैंड के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने बांग्लादेश में चल रहे असंतोष के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए उनका लंदन जाना टल गया है।

वर्ष 2009 से 2024 तक वे लगातार प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने बिगड़े हुए बांग्लादेश में कई चीजों को पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बांग्लादेश की कट्टरता पर काबू किया और वहां से भारत की ओर पलायन कर रहे मजदूरों को अपने देश में रोजगार दिया। दुनिया भर में चावल निर्यात में बांग्लादेश की स्थिति मजबूत की और भारत से रिश्ते सुधारे। लेकिन 15 वर्षों के शासन से उनमें कुछ एरोगेंस आ गई थी। वे खुद को मसीहा से कमतर नहीं आंकती थीं। उनको लगता था, जो वे चाहेगी देश में वही होगा। अपने इस अहंकार के चलते शेख हसीना ने बांग्लादेश की अधिकांश प्रजा को असंतुष्ट कर दिया। नौकरियों और विश्वविद्यालय में आरक्षण रेवड़ियों की तरह बांटा। साथ ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के बच्चों तथा पोते-पोतियों को उन्होंने 30 प्रतिशत आरक्षण दिया। आज वहां 56 प्रतिशत आरक्षण है, यानी स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए कुल 44 फीसद सीटें बचती हैं। हर गली-मोहल्ले में अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां लगवाईं, सड़कों के नाम अपने परिवार के लोगों के नाम पर रखे।

एक तरह से उन्होंने बांग्लादेश को अपनी जागीर बना लिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी लोकप्रियता और सहिष्णुता के बावजूद बांग्लादेश में छात्र उनके विरुद्ध हो गए। छात्र उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए। अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सहिष्णुता से मुस्लिम कट्टरपंथी जमायत इस्लाम ऑफ बांग्लादेश वैसे ही उनसे खार खाए बैठा था। ऐसे समय में बांग्लादेश के आम चुनाव में उनकी धांधली और लगातार चौथी बार उनकी जीत से लोग और नाराज हो गए. नतीजा सामने है।

ढाका विश्वविद्यालय के छात्र आरक्षण के खिलाफ एकत्र हुए और धीरे-धीरे यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इन छात्रों के हौसलों को देख कर कट्टरपंथी तत्त्व और बांग्लादेश के प्रमुख विरोधी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) के समर्थक भी इस छात्र आंदोलन को बैक करने लगे। छात्रों का आंदोलन इतना तेज हो गया कि 5 अगस्त को दोपहर असंतुष्ट तत्त्वों ने उनका घर घेर लिया। शेख हसीना अपने आवास से ही हेलिकॉप्टर में बैठ कर भारत के लिए उड़ गईं। भारत उनका सबसे करीब का पड़ोसी है और भारत से उनके रिश्ते भी मधुर रहे हैं। उपद्रव कारियों ने न सिर्फ शेख हसीना के आवास पर कब्जा कर लिया बल्कि अपने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ दीं। बांग्लादेश के छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब अराजकता पर उतर आया है। इसके पीछे हसीना द्वारा जमायत इस्लाम के जमायत शिबिर पर 4 अगस्त को प्रतिबंध लगाना भी रहा। छात्रों को प्रतीत हुआ कि हसीना ने ऐसा छात्र एकता को तोड़ने के लिए किया है।

शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना और तत्काल भारत भाग आना बहुत चौंकाने वाली घटना है। भारत उन्हें बहुत दिनों तक शरण नहीं दे सकता। उसकी 4091 किमी की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है और सीमा से जुड़े पांच राज्यों में कभी भी कोई इधर से उधर आ-जा सकता है। भारत की सीमा सुरक्षा बल को इतनी लंबी सीमा पर चौकस रहना बहुत आसान नहीं है। इस सीमा के बीच में मैदान हैं। गारों और खासी हिल्स की पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। ब्रह्म पुत्र जैसी नदियां हैं, सुंदर बन का भयावह जंगली और दलदली इलाका है। सबसे बड़ी बात कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के रंग-रूप, कद-काठी तथा बोली-बानी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कौन व्यक्ति उधर का है या इधर का, यह तय करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है की बांग्लादेश की बगावत भारत को भी चौकन्ना करती है।

बांग्लादेश में विद्रोह, बगावत और हत्याकांड का इतिहास बहुत लंबा रहा है। बस शेख हसीना ने काफी समय से इसे रोके जरूर रखा है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश-पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बंगाली पहचान नष्ट करना और उन पर जबरन उर्दू थोपने के कारण यहां विद्रोह हुआ। शेख मुजीबुर्रहमान ने इसका नेतृत्व किया। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के लोग बंग बंधु बोलते थे। लंबे संघर्ष और पाकिस्तान की सेना के भीषण उत्पीड़न के बाद शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान की फौजों ने अवामी लीग के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुक्ति वाहिनी ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को सैन्य प्रशिक्षण दिया।

चिढ़ कर पाकिस्तान ने भारत से युद्ध शुरू कर दिया। चूंकि उस समय महाबली अमेरिका पाकिस्तान का मददगार था, इसलिए वह शेर बना हुआ था। वह शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य मदद के लिए नौसेना का सातवां बेड़ा भेजा तो तत्काल सोवियत संघ भारत की मदद के लिए आगे बढ़ा। आखिरकार, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फौजों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच कोई एक करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से भारत आ गए। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान के समर्थक तत्व बांग्लादेश में रहे। उनमें जमायत इस्लाम ऑफ बांग्लादेश प्रमुख है। यह संगठन बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का विरोधी था।

शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहते थे लेकिन जमायत के कट्टरपंथियों ने विरोध शुरू कर दिया। 1974 में बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ गई। इस आपदा में 28000 के करीब लोगों की जान गई। अफरा-तफरी के माहौल में प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने देश में आपातकाल लगा दिया। मगर राजनीतिक उथल-पुथल पर वे लगाम नहीं लगा पाए। 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान राष्ट्रपति बने पर इसी वर्ष अगस्त में वहां सेना ने शेख की सरकार का तख्तापलट कर दिया। शेख और उनकी पत्नी, बेटे सब मारे गए, सिर्फ दो बेटियां बचीं, जो उस समय विदेश में पढ़ रही थीं, शेख हसीना और उनकी छोटी बहन। सैनिक शासन के वक्त सारी लिबरल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लग गया। 1977 में जनरल जियाउर्रहमान राष्ट्रपति बने और बांग्लादेश एक इस्लामी राष्ट्र बन गया।

1979 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए और जनरल जियाउर्रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत में आ गई। लेकिन दो वर्ष बाद फिर विद्रोह हुआ और जनरल जियाउर्रहमान मारे गए तथा अब्दुल सत्तार देश के नए राष्ट्रपति बने। एक वर्ष के भीतर ही फिर सत्ता पलट हो गया। फिर से सैन्य शासन आ गया, जनरल इरशाद सत्ता में आ गए। राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म हो गई। जनरल इरशाद ने सभी स्कूल / कॉलेज में अरबी और कुरान की पढ़ाई की अनिवार्यता पर जोर दिया। छात्रों ने विद्रोह कर दिया तो इसके बदले इरशाद ने कुछ आजादी बहाल की। 1986 में संसद और राष्ट्रपति के पद के लिए हुए चुनाव में इरशाद फिर जीत गए। 1988 की बाढ़ से बांग्लादेश फिर तबाह हुआ, हजारों लोगों की जान गई। इरशाद को पद से हटना पड़ा।

1991 में इरशाद को जेल भेजा गया और जनरल जियाउर्रहमान की विधवा एवं बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनीं। राष्ट्रपति का पद बहुत सीमित अधिकारों वाला रह गया। इसी वर्ष बांग्ला देश में चक्रवाती तूफान आया जिसमें डेढ़ लाख के करीब लोग मारे गए। 1996 में अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना प्रधानमंत्री चुनी गईं। लेकिन इसी वर्ष फिर बाढ़ आ गई और देश भर में हड़तालों और आंदोलन का दौर शुरू हुआ। इसी बीच शेख मुजीब की हत्या में आरोपी 15 सैन्य अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 2001 के चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग चुनाव हार गई तथा कट्टरपंथियों की मदद से बीएनपी ने सरकार बनाई। खालिदा जिया फिर से प्रधानमंत्री बनीं। 2008 के चुनाव में अवामी लीग सत्ता में लौटी और 6 जनवरी 2009 को शेख हसीना प्रधानमंत्री बनीं। तब से लगातार सत्ता में रहीं।

5 अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद से बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख जनरल वकार ने देश की बागडोर संभाल ली है। उन्होंने फौरन बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया है। साल 2024 के चुनाव में शेख हसीना ने बांग्लादेश की परंपरा के विरुद्ध चुनाव काल में सर्वसम्मति से कोई नेशनल सरकार नहीं बनाई थी और खुद ही प्रधानमंत्री बनी रहीं। इसलिए विरोधी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद से आरक्षण नीति का पहले छात्रों ने विरोध किया तो उनके पीछे विरोधी दल कट्टरपंथी जमायत भी आ गए। बांग्लादेश में चल रही अराजकता को देख कर लगता है कि यही हाल रहा तो समृद्ध बांग्लादेश को चौपट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब सवाल यह है कि शेख हसीना का क्या होगा?

सुभाषित — *कोई इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। मनुष्यरूपी जीवनमें इच्छाओंका यह भिक्षापात्र कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें तलहटी नहीं है। इसमें कुछ भी डालो, यह खालीकी खाली रह जाती है।* ❐ ययाति

चिन्ताएं और चुनौतियां

बंगलादेशमें सोमवारको तख्तापलट और प्रधान मंत्री शेख हसीनाके इस्तीफे तथा देश छोड़नेके बाद स्थितियां अभी भयावह बनी हुई है। वहां हिंसा और उपद्रवकी घटनाएं थमी नहीं हैं, बल्कि उसमें और तेजी आ गयी है। सेना प्रमुख वकार-उज-जमांने सत्ताकी बागडोर अपने हाथमें ले ली है और उन्होंने अन्तरिम सरकार बनानेकी भी घोषणा कर दी है लेकिन आनेवाले दिनोंमें वहांके हालात कैसे होंगे, यह अभी पक्के तौरपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तख्तापलटकी घटनाके पीछे किसका हाथ है, यह तो जांचका विषय है लेकिन जो संकेत अभी मिले हैं, उसमें पाकिस्तानकी खुफिया एजेंसी आईएसआईका हाथ होनेकी आशंका जतायी गयी है और इसकी पूरी साजिश लन्दनमें रची गयी, जहां बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक प्रमुख खालिदा जियाके बेटे रहमानकी सांठगांठके भी सुबूत मिले हैं। परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरने मंगलवारको सर्वदलीय बैठकके बाद राज्यसभामें जो वक्तव्य दिया है, वह अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। उन्होंने कहा कि बंगलादेशमें जनवरी २०२४ में हुए चुनावके बाद ही माहौल बिगड़ने लगा। वहां हिंसाकी घटनाएं बढ़ीं। अल्पसंख्यकोंकी दुकानों और मन्दिरोंपर हमले हो रहे हैं। चार अगस्तको सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओंपर हमले हो रहे हैं। भारतीय दूतावास सक्रिय है। उम्मीद है कि वहांकी सरकार हमारे नागरिकोंको सुरक्षा मुहैया करायेगी। सर्वदलीय बैठकमें सभी दलोंने बंगलादेशके प्रकरणमें केन्द्र सरकारको पूरा समर्थन देनेका भरोसा दिलाया, जो स्वागतयोग्य है। बंगलादेशमें तख्तापलटसे भारतकी चिन्ताएं और चुनौतियां बढ़ गयी हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि नयी सरकारका रुख भारतके प्रति क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस्लामी कट्टरपंथियोंके सत्तामें लौटनेसे भारतकी चुनौतियां बढ़ेंगी। पाकिस्तान और चीन दोनों ही मौकेका लाभ उठानेकी फिराकमें हैं। बंगलादेशमें राजनीतिक अस्थिरतासे घुसपैठका खतरा बढ़ेगा। दोनों देशोंके बीच विश्वका पांचवां सबसे बड़ा बार्डर है, जो पांच राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरासे जुड़ा है। सीमापर आतंकी गतिविधियां, अवैध तस्करीके भी खतरे बढ़ेंगे। हिन्दू आबादीपर हमले बढ़ेंगे तो भारतका धर्मसंकट भी बढ़ेगा। द्विपक्षीय व्यापारपर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। बंगलादेशमें भारतने काफी निवेश किया है, इसका असर परियोजनाओंपर पड़ सकता है। चीन और पाकिस्तानाका हस्तक्षेप बढ़नेसे स्थितियां असहज हो जायंगी। भारतके लिए चुनौतियोंका सामना करना मुश्किल नहीं है लेकिन इसके लिए बहुआयामी ठोस रणनीति बनानी होगी।

कोचिंग संस्थानोंपर हो सख्ती

छात्रोंकी जानसे खिलवाड़ कर चलाये जा रहे कोचिंग संस्थानोंको लेकर सर्वोच्च न्यायालयने जो टिप्पणी की है, वह प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारके लिए सख्त सन्देश है। न्यायालयने कहा है कि देशके अलग-अलग स्थानोंसे पढ़नेके लिए आये छात्रोंके लिए कोचिंग सेण्टर मौतके चैम्बर बन गये हैं। दिल्लीके एक आईएएस कोचिंगके बेसमेण्टमें स्थित लाइब्रेरीमें पानी भरनेसे २७ जुलाईको तीन छात्रोंकी मौतके मामलेको सर्वोच्च न्यायालयका स्वत: संज्ञान लेना ही मामलेकी गम्भीरताको दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालयने कहा है कि यह आंख खोलनेवाली घटना है। किसी भी संस्थानको सुरक्षा मानदण्डोंका पालन किये बिना संचालित करनेकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोचिंग संस्थान आनलाइन काम कर सकते हैं जबतक कि सुरक्षा मानदण्डों और जीवनके लिए बुनियादी मानदण्डोंका पूरी तरहसे पालन न हो। इस सम्बन्धमें सर्वोच्च न्यायालयने केन्द्र और दिल्ली सरकारको नोटिस देकर प्रशासनिक और सरकारकी विफलताको उजागर किया है। देशकी राजधानी दिल्लीमें आईएएस बननेकी आकांक्षा लेकर आये तीन छात्रोंकी जिन हालातमें मौत हुई है, वह दुखद तो है, शर्मनाक भी है। इस दुखद घटनाको अंजाम देनेवाले हालात न तो नये हैं और न ही ऊपरसे लेकर नीचेतक सरकारी तंत्रका कोई भी हिस्सा इससे अनजान है। यह किसीसे छिपा नहीं है। इससे पहले भी दिल्लीके एक कोचिंग सेण्टरमें आग लगनेसे तमाम छात्रा घायल हुए थे। उस समय भी सुरक्षा और मानकोंको लेकर खूब हो-हल्ला हुआ था और तमाम दावे किये गये थे लेकिन नतीजा सिफर निकला। इसमें दो राय नहीं है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमें जबरदस्त खामियोंने ही कोचिंग संस्थानोंको शिक्षाके व्यावसायीकरण करनेकी छूट दी। ३० हजार करोड़ रुपयेसे अधिकके टर्न ओवरका व्यवसाय बन चुके देशभरकी कोचिंगसे सरकारको भी ५५१७ करोड़ रुपये जीएसटी मिलती है। ऐसेमें सरकार भी इनकी खामियोंको नजरअन्दाज कर कोचिंग संस्थानोंको शिक्षाके नामपर खुली लूटकी छूट दे रही है, जो देशके भविष्यके लिए उचित नहीं है।

लोक संवाद

देश सेवाका जज्बा

महोदय,-घरके बाहर किसीने आकर तीन बार भारत माताकी जय हो नारे लगाये तो स्वाभाविक तौरपर मैं चौंका। बाहर आया तो देखा तीन-चार युवक थे। फिर उनमेंसे एकको गौरसे देखा तो पहचान गया, वह गोपाल था। गोपाल मेरे दफ्तरमें था। लेकिन हुलिया एकदम बदला हुआ था, चोला-पायजामा और सिरपर टोपी। मुझे देखते ही उसने मेरी चरण कमलोंका स्पर्श किया और बोला, सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा, भाई गोपाल वह तो सदैव तुम्हारे साथ रहा है, जब तुम दफ्तरमें कामचोरी करते थे तब भी मेरा आशीर्वाद था तुम्हें। परन्तु तुमने अपना लिबास कब बदल लिया। मैं रिटायरमेंटके समय तो तुम्हें अच्छा-भला छोड़कर आया था। वह बोला, सर यह लिबास मैंने आज ही बदला है और आपको बताने आया हूं कि मैं चांदनी चौकसे एमएलएका चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे नेत्र खुलेके खुले रह गये और मैं बोला, चुनाव लेकिन चुनाव लड़ने जैसी बात तो तुमने पहले कभी बतायी नहीं थी। यह यकायक तुम्हें क्या हुआ है। मेरा मतलब तुमने नौकरी छोड़ दी है। वह बोला, हां साहब, मैं देश सेवा करना चाहता हूं। तबतक मैं थोड़ा सहज हो गया था, इसलिए बोला, वैरी गुड, देश सेवा भी बुरा धंधा नहीं है। इसमें हाथ डालोगे तो कुछ न कुछ बन भी जाओगे। लेकिन भाई इसमें तो पैसा बहुत चाहिए। पहले निवेश करो, तब रिटर्न सालोंमें मिलता है। गोपाल बोला, सर मैं वाकई देश सेवा करना चाहता हूं। अन्नाका भक्त हूं। उन्हींकी प्रेरणासे आज सब कुछ त्याग कर मैं मूल्योंकी राजनीति करना चाहता हूं। मैंने कहा, वही तो मैं कह रहा था, राजनीति बिना मूल्यके आज करेगा भी कौन। गोपालने मेरा छिपा व्यंग्य समझा नहीं और उत्साहसे बोला, सर बस यही समझिये। दरअसल मैं भ्रष्टाचार और महंगीके विरुद्ध आवाज उठाकर चुनाव जीतनेका दम भर रहा हूं। आप खुद देख रहे हैं, देशकी हालत क्या हो रही है। मैं बोला, गोपाल मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारे दोनों मुद्दे ज्वलंत हैं। इसमें गरीबी मिटाने जैसा तुर्रा और लगा लेते तो राह आसान हो जाती। मेरा मतलब भय, भ्रष्टाचार और भूख मिटानेसे है। गोपालके होंठ थोड़ा हंसे और वह बोला, सर भ्रष्टाचार और महंगी, दोनों ही मुद्दे गरीबके लिए हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। धंधेबाज राजनेता देशको लूट रहे हैं और भारत चमकाने और भारत निर्माणकी बातें कर रहे हैं। सर इन सबका पर्दाफाश होना ही चाहिए। मैंने देखा गोपालका चेहरा तो उसपर ईमानदारीका जोश और व्यवस्थासे लड़नेका जज्बा दिखाई दिया। मुझे गोपालके बीवी-बच्चोंका ख्याल आ गया कि यदि यह वाकई देख सेवा करने निकल गया तो वे क्या करेंगे। मैंने ही यही प्रश्न गोपालपर दागा तो उसने कहा, सर देश सेवा पहले है। बीवी-बच्चोंको पेंशन बहुत है। अब मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे लगा गोपाल १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलनका कोई फ्रीडम फाइटर है, जिसे अच्छा बननेका दौरा पड़ गया है। मैं बोला, गोपाल तुम स्वस्थ तो हो न। मेरा मतलब सोचने-समझनेकी तुम्हारी शक्ति कहीं लुप्त तो नहीं हो गयी। वह बोला, नहीं सर मैं पूरे होशो-हवासमें हूं। मैं देशको बदल डालूंगा। बहुत हो गया, धैर्य जवाब दे रहा है। ये मेरे साथी हैं। मैंने शेष तीनोंको देखा तो वे कुटिलतासे मंद मुस्कान बिखेर रहे थे। मैंने कहा, आप लोग गोपालकी बातोंसे सहमत हैं। उनमेंसे एक बोला, सर हम लोग वर्षोंसे मूल्योंकी राजनीति ही कर रहे हैं। जबतक इनके पास मूल्य हैं, हम लोग डटे रहेंगे। मैं समझ गया ये आजके राजनेता हैं, जो गोपालके रिटायरमेंटके बदले मिले पैसोंतकके साथी हैं। बादमें ये लोग गोपालको छोड़ देंगे। मैंने गोपालसे कहा, गोपाल एक बार और सोच लेते। चुनाव थोड़ा ठहर कर लड़ लेते। वह बोला, नहीं सर फिर देर हो जायगी। यह कहकर उसने तीन बार भारत माता की जय हो के नारेका उद्‌घोष किया और चला गया। मैंने मन ही मन कहा, बेचारा गोपाल। भगवान उसकी रक्षा करे। मैं भारी मनसे अंदर आ गया। बार-बार मेरी आंखोंमें गोपालका चेहरा घूम रहा था। उसकी देश सेवाके जज्बेको बार-बार नमस्कार। **-पूरन सरमा, वाया ईमेल।**

आक्रोशकी निष्पत्ति हसीनाका पतन

बंगलादेशमें जनभावनाको अनसूना करनेसे पनपे विद्रोह एवं आक्रोशकी निष्पत्ति है शेख हसीना सरकारका पतन। इस आक्रोशकी बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनावमें अनियमितताओंके बाद ही पड़ गयी थी। हालके दिनोंमें व्यापक पैमानेपर हुए हिंसक प्रदर्शनोंने शेख हसीनाको प्रधान मंत्री पद त्याग कर देश छोड़नेको मजबूर कर दिया।

❐ ललित गर्ग

पिछले करीब तीन सप्ताहमें हुई आरक्षण विरोधी हिंसामें तीन सौसे अधिक लोगोंकी जान चली गयी। दरअसल इस संकटकी मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्वका तानाशाह एवं निरंकुश बनना बड़ा कारण रहा। जनभावनाओंको कुचला जाना एवं अनसूना करनेके कारण ही हसीना आनन-फानन देश छोड़कर भारत आनेके लिए विवश होना पड़ा। उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गये थे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे बगावती प्रदर्शनकारियोंने उनके सरकारी आवासमें घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बंगलादेशके राष्ट्रपिता कहे जानेवाले शेख मुजीबकी प्रतिमाको क्षतिग्रस्त करनेके साथ उनके नामपर बने एक संग्रहालयको भी जला दिया। बंगलादेश बेहाल हो गया, हिंसक एवं अराजक घटनाएं कहर बनकर हसीनाके खिलाफ विद्रोहका बिगुल बजा रही थी। जैसी आशंका थी, शेख हसीनाके पलायन करते ही सेनाने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनानेकी घोषणा की। भारतीय उपमहाद्वीपके श्रीलंका, नेपालके बाद अब बंगलादेशमें उत्पन्न होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियोंके प्रति भारत सरकारको सतर्क एवं सावधान रहनेके साथ अपनी रणनीतिमें बदलाव करनेकी जरूरत है। जब-जब जिन-जिन देशोंमें जनताकी आवाजको दबाया गया, एक विस्फोटक स्थिति बनी। बंगलादेश हिंसाकी आगमें झुलसने लगा, हिंसक प्रदर्शनोंमें सैकड़ों लोग मारे गये, सरकारी सम्पत्तिका भारी नुकसान हुआ। वास्तवमें लगातार चार बार प्रधान मंत्री बननेवाली शेख हसीनाने जनाक्रोश एवं जनताके विद्रोहको हल्केमें लिया। वास्तवमें आरक्षण आन्दोलनको दबानेके लिए की गयी सख्तीने आगमें घीका काम किया जिससे बंगलादेशके जनमानसमें गहरेतक यह भाव एवं घाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओंके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

शेख हसीनाके खिलाफ उपजे आक्रोशके मूलमें तात्कालिक कारण आरक्षण ही रहा। दरअसल वर्ष १९७१ में बंगलादेशको पाकिस्तानके दमनकारी शासनसे आजादी दिलानेवाले स्वतंत्रता सेनानियोंकी तीसरी पीढ़ीके रिश्तेदारोंके लिए उच्च सरकारी पदोंवाली नौकरियोंमें तीस प्रतिशत आरक्षणका विरोध छात्रोंने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षणका लाभ उठा चुकी हैं, फलतः बेरोजगारोंको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्टने आरक्षणको घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस सन्देशको जनतामें सही ढंगसे नहीं पहुंचा सकी।

चूंकि शेख हसीनाने अपने लम्बे शासनकालमें बंगलादेशको स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ताको कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षणके खिलाफ छात्रोंकी ओरसे शुरू हुआ आन्दोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आन्दोलनको शीघ्र ही शेख हसीनाके सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संघटनोंने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तानकी कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आन्दोलन सत्तापरिवर्तनके हिंसक अभियानमें बदल गया। निश्चित ही पाकिस्तानपरस्त राजनीतिक दलोंने इस आक्रोशको अपने लिए सत्ताका रास्ता बनानेमें इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकटको शह देनेमें कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्तामें तो आयीं, लेकिन विपक्षी दल जनतामें यह सन्देश देनेमें कामयाब रहे कि चुनावोंमें धांधली हुई है। इस तरह चुनावोंके संदिग्ध तौर-तरीकोंने शेख हसीनाकी जीतको धूमिल कर दिया। जिसका अंतरराष्ट्रीय जगतमें भी अच्छा सन्देश नहीं गया। तभी पिछले महीनोंमें अपनी सरकारके लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीनाने भारत एवं चीनकी यात्रा की थी। हालांकि इस दौरान देशमें स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। बीजिंग और नयी दिल्लीके बीच संतुलन साधनेकी शेख हसीनाकी नीतिसे चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हालकी अपनी चीन यात्रा बीचमें छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीनने पाकिस्तानी तत्वोंके जरिये शेख हसीना विरोधी आन्दोलनको हवा दी। निश्चित ही शेख हसीनाकी छवि एक अधिनायकवादी शासककी बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निन्दा करनेमें मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियोंसे पहलेसे ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्रपर उसकी नसीहत सुननेको तैयार नहीं थीं। उनका सत्तासे बाहर होना भारतके लिए अच्छी खबर नहीं है, बंगलादेशमें एक अर्सेसे भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आन्दोलनके दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अब भी हिन्दुओं और उनके मंदिरोंके साथ भारतीय प्रतिष्ठानोंको निशाना बना रहे हैं। हालांकि शेख हसीनाके खिलाफ उपजे आक्रोशके मूलमें तात्कालिक कारण अतार्किक एवं असंगत आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल एवं उनके आनुशंगिक संघटन सरकारको उखाड़नेके लिए बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल वर्ष १९७१ में बंगलादेशको पाकिस्तानके दमनकारी शासनसे आजादी दिलानेवाले स्वतंत्रता सेनानियोंकी तीसरी पीढ़ीके रिश्तेदारोंके लिए उच्च सरकारी पदोंवाली नौकरियोंमें तीस प्रतिशत आरक्षणका विरोध छात्रोंने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षणका लाभ उठा चुकी हैं, फलत: बेरोजगारोंको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आन्दोलनको हसीना सरकार ढंगसे संभाल नहीं पायी। हालांकि सुप्रीम कोर्टने आरक्षणको घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस सन्देशको जनतामें सही ढंगसे नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओंकी गिरफ्तारीने आन्दोलनको उग्र बना दिया। जनाक्रोशके चरमका अन्दाजा इस बातसे लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ने मुक्ति आन्दोलनका नेतृत्व करनेवाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमानकी मूर्तितकको तोड़ दिया। निस्संदेह सत्तासे चिपके रहनेके लिए किये जानेवाले निरंकुश शासनकी परिणति जनाक्रोश एवं जनान्दोलनके चरमके रूपमें सामने आता ही है। ताजा घटनाक्रम एवं हिंसक आंधी श्रीलंकामें २०२२ के विरोध प्रदर्शनकी याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओंको सत्तासे उतरकर विदेश भागनेको मजबूर होना पड़ा था। हालांकि फिलहाल बंगलादेशमें सेनाने कमान अपने हाथमें ली है लेकिन आनेवाली सरकारको उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दोंका समाधान करना होगा। नयी व्यवस्था एवं सोचमें व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हो, विदेशी ताकतों विशेषत: पाकिस्तानकी कठपुतली बननेसे बचना होगा। हालांकि भारतके हसीना सरकारसे मधुर संबंध थे, भारत बंगलादेशका सबसे करीबी, सहयोगी और दुखके दिनोंका साथी रहा है। शेख हसीना बंगलादेशके बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमानकी बेटी हैं। १९७५ में परिवारके ज्यादातर सदस्योंके साथ एक सैन्य तख्तापलटमें उनकी मौत हो गयी थी। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त जर्मनीमें थी। तब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधीने शेख हसीना और उनकी बहनको भारत बुलाया था एवं संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन हालिया उथल-पुथलको देखते हुए हमें अपनी रणनीतिमें बदलाव करना होगा। पाकिस्तानपरस्त बीएनपी और जमात-ए-इस्लामीकी आसन्न वापसी भारतके लिए सावधान होकर अग्र-स्थितियोंपर गम्भीरतासे ध्यान देनेकी है। बंगलादेशके नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस देशके अंतरिम प्रधान मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीनाका विरोध कर रहे छात्रोंने मोहम्मद युनूसके नामका समर्थन किया है। शेख हसीना और युनूसका आपसमें बहुत तनाव रहता था। अब युनूससे उम्मीद की जा रही है कि वह देशको स्थिरताकी ओर ले जा सकते हैं। भारत पड़ोसी देशके नाते बंगलादेशमें स्थिरता, शांति एवं सौहार्दपूर्ण स्थितियोंकी कामना करता है।

मानव अंग तस्करी रोकनेकी चुनौतियां

भारतमें अवैध रूपसे घृणित और भयावह काले धंधोंमें मानव अंग तस्करीका धंधा भी एक है। कड़े कानून होनेके बावजूद भी इसे रोका नहीं जा सका है, क्योंकि यह डाक्टर, नर्स, दलाल, पुलिस और तस्कर गिरोहकी मिलीभगतसे होता है।

❐ अखिलेश आर्येन्दु

पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिसकी अपराध शाखाने अंतरराष्ट्रीय किडनी तस्कर गिरोहका भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिसकी अपराध शाखाने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालकी जानी-मानी किडनी प्रत्यरोपित करनेवाली सर्जन डा. डी. विजय राजकुमारी और रैकेटके सरगना समेत सात आरोपियोंको गिरफ्तार किया। इनमें सरगना समेत तीन आरोपी बंगलादेशके रहनेवाले हैं। यह रैकेट दिल्ली और ग्रेटर नोएडाके अस्पतालोंमें काला धंधा चला रहा था। ऐसा पहली बार नहीं है मानव अंगकी तस्करी गिरोहका भंडाफोड़ हुआ हो। इस गिरोहके पूछताछसे मालूम पड़ा कि १४ मामलोंको इसने अंजाम दिया था। यह काला धंधा पिछले छह महीनेसे चल रहा था, जिसमें करोड़ोंका वारा-न्यारा हुआ। जानकारीके मुताबिक २०१९ में कानपुरमें इसी तरहके गिरोह जो किडनीका तस्करी करता था, को अंगोंकी तस्करीको अंजाम देकर करोड़ों रुपये कमाता था, का भण्डा फोड़ उत्तर प्रदेश पुलिसकी अपराध शाखा पुलिसने किया था। महज दो घटनाएं मानव अंग तस्करीकी घटी हों ऐसा नहीं है। देशमें चोरी-छिपे, विश्वासघात कर और मजबूरीका फायदा उठाकर रोजाना पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं जो पुलिसके रिकार्डमें नहीं होती। ऐसी घटनाओंको रोकना शासनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारीके अनुसार भारतमें मानव अंगोंकी तस्करीका धंधा पिछले ३० सालोंसे ज्यादा तेजीसे आगे बढ़ा है। सवाल उठता है मानव तस्करी क्या है। कड़े कानूनके बावजूद क्या मानव अंगोंकी तस्करी की जा सकती है। अमेरिकाकी सरकारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विसके अनुसार मानव अंगोंकी तस्करी, आम तौरपर ऐसी आपराधिक गतिविधियोंको कहते हैं, जिसमें अवैध तरीकेसे किसी जिन्दा या मृत व्यक्तिसे अंग निकाला जाता है और फिर उसकी अवैध बिक्री और प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जानकारोंके मुताबिक कानूनी दायरेसे जब मानव अंगोंकी मांग पूरी नहीं होती तब मानव अंगोंकी तस्करीको बढ़ावा मिलता है, जिसमें आपराधिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। अविकसित देशोंमें मानव अंगोंकी तस्करी करना विकसित देशोंकी अपेक्षा ज्यादा आसान है। इसकी वजह जागरूकताकी कमीका होना है। विकासशील देशोंमें लोगोंमें जागरूकताकी बेहद कमी तो है ही, गरीबीकी वजहसे धनके लालचमें आकर गरीब व्यक्ति अंग तस्करोंके झांसेमें फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह, आईसीयूमें भर्ती व्यक्तिके पास उसका कोई अपना नहीं होता है, ऐसे नाजुक हालातमें भी बेईमान शल्य चिकित्सक याकृत या कोई अंग चुपचाप निकालकर बेच दे तो पता नहीं चलता है। इसलिए हर स्तरपर जागरूकताका होना बहुत जरूरी है। रिपोर्टका सच माने तो मानव अंग तस्करीका बाजार अरबोंमें चल रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हर साल कमसे कम २००० मामले मानव अंग तस्करीके चुपचाप चलते रहते हैं। गैर-सरकारी संघटन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटीके आंकलनके मुताबिक दुनियामें मानव तस्करीका बाजार ८४० मिलियन डालरसे १.७ ट्रिलियन डालरतकका है। जीएफआईके मुताबिक हर साल दुनियामें १२,००० से ज्यादा मानव अंगोंका गैर-कानूनी प्रत्यारोपण होता है और इनमेंसे ८००० किडनी होती है, इसके बाद हृदय, फेफड़े, याकृत और अग्न्याशय जैसे अति महत्वपूर्ण अंगोंका गैर-कानूनी ढंगसे प्रत्यारोपण होता है। भारत सहित दुनियाके तमाम विकसित और विकासशील देशोंमें गैर-कानूनी अंग प्रत्यारोपित किये जाते हैं जिसमें हजारोंकी तादादमें लोगोंकी जान चली जाती है। इनसानके जरिये किये जानेवाले काले धंधोंमें यह सबसे काला कहा जा सकता है, क्योंकि यह इनसानकी मजबूरी, विश्वासघात, ठगी और धनके लालचमें चोरी-छिपे चलाया जाता है। मानव अंगोंकी तस्करीमें आम तौरपर भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधिक समूहोंकी सांठ-गांठसे होता है। बिचौलियोंकी भूमिका इसमें खास होती है। मजबूर लोगोंको लालच देकर या बीमार व्यक्तिका गुप-चुप तरीकेसे इलाजके नामपर शरीरके उस अंगको निकाल लिया जाता है जिसके निकालनेके तत्काल बाद मौत नहीं होती। इसके बाद बिचौलियोंका खेल चलता है जो एक अंगका बीस लाखसे लेकर करोड़ोंतकका होता है। भारत और पड़ोसी देशोंमें मानव अंगोंकी तस्करीका नेटवर्क वर्षोंसे चल रहा है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश जैसे विकासशील देशोंमें मानव तस्करीका धंधा बहुत बड़ी तादादमें चलता है। अमेरिकाकी क्राग्रेसनल रिसर्च रिपोर्टके मुताबिक चीनमें अल्पसंख्यकोंके अंगोंकी तस्करीकी घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें विवादित जगह विस्थापित हुए लोगोंके बीच ज्यादा तेज हुई है। रिपोर्ट बताती है कि यहां जातीय अल्पसंख्यकोंको उनके अंगोंकी तस्करीके लिए मारा गया। भारतमें मानव तस्करीके खिलाफ सख्त नियम बनाये गये हैं बावजूद बहुत बड़े पैमानेपर चोरी-छिपे मानव अंगोंकी तस्करी होती है। अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञोंके मुताबिक कानूनके अनुसार अंग दानके लिए केन्द्र सरकारने कानून बनाये हैं। इन कानूनोंके मुताबिक अंग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंगकी जांचमें अंग प्रत्यारोपण किये जानेवाले मरीजके लिए अनुकूल होना चाहिए। यह बहुत नजदीकी रिश्तोंके लिए ही स्वीकार होता है। इसमें मां, बाप, भाई-बहनके रिश्तोंका पता चल जाता है। लेकिन धंधेमें शामिल लोग या गिरोह सैंपल या नमूना लगा देते हैं असल रिश्तेदारका, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर (लगाकर) अंग तस्करीवाला लगा देते हैं। यह अंग तस्करीका पहला पड़ाव जैसा है जो तस्कर डाक्टरों और अधिकारियोंसे मिलकर पूरा करते हैं। लेकिन यदि अस्पताल चाहें तो इस काले धंधेको रोका जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञोंका कहना है कि अंग दानकी सत्यताकी जांच करनेवाली कमेटी यदि सही तरीकेसे जांच करे तो धंधेबाजोंके गैर-कानूनी दस्तावेजोंको आसानीसे पुलिसकी गिरफ्तमें दिया जा सकता है। अच्छी तरहसे एचएनए टाइपिंगकी जांच करनेसे गैर-कानूनी कागजको बाहर किया जा सकता है। मतलब साफ है यदि जांच करनेवाले अधिकारी और डाक्टर चाहें तो मानव अंगोंकी तस्करीके धंधेको रोका जा सकता है। दरअसल मानव अंगोंकी तस्करी उन देशोंमें ज्यादा फूल-फल रही है जहां जिन्दगी बहुत सस्ती है। पुलिस, डाक्टर, अधिकारी और दलालोंके गठजोड़ आसनीसे हो जाया करते हैं। मानवीय संवेदनाएं टूट रही हैं और धन बटोरनेके चक्करमें लोगोंको सभी तरहकी विश्वासनीयताओंका गला घोटनेमें कोई डर नहीं लगता यानी कानूनका डर, आपसी रिश्तोंकी विश्वासनीयताका डर और समाजका डर खत्म होता जा रहा है। आंकड़ेके मुताबिक पिछले बीस सालोंमें विकसित और विकासशील देशोंमें मानव तस्करी तेजीसे बढ़ी है, लेकिन विकसित देशोंमें भी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं, जितनी विकासशील देशोंमें। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशोंमें आतंक या युद्धके हालात रहे वहां मानव तस्करी बड़े पैमानेपर हुई। आतंकवादी गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय तस्करों और नये-नये गिरोहोंके जरिये भी मानव तस्करी तेजीसे बढ़ी, खासकर २००५ से लेकर २०१५ तक। आज भी ये गिरोह सक्रिय हैं और बड़े पैमानेपर मानव अंगोंकी तस्करी कर धनकी उगाही करनेमें लगे हुए हैं। भारत सरकार मानव अंगोंकी तस्करी रोकनेमें लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, बावजूद मानव अंग तस्करीका काला धंधा धड़ल्लेसे चल रहा है। अपराध शाखाकी पुलिसके साथ आम आदमी यदि मानव तस्करीके प्रति संवेदनशील हो तो इस काले बाजारके काले धंधेको खत्म किया जा सकता है।

आत्मबोध

शिवोपासना

❐ यशपाल कुमार

महामुनि मृगश्रृंगके पौत्र श्री मार्कण्डेय जीने अपने पूज्य पिताको चिन्तित देखकर अत्यन्त विनम्रतासे कहा, आपकी चिन्ताका क्या कारण है? बेटा! महामहिम मृकण्डुने दुखी मनसे श्री मार्कण्डेय जीके मुखकी ओर देखते हुए अतिशय स्नेहसे बताया तुम्हारी माता मरुद्वतीको कोई सन्तान न होनेसे मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिवको प्रसन्न किया। आशुतोषने प्रकट होकर वर मांगनेके लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभसे याचना की, अबतक मुझे कोई सन्तान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। त्रिपुरारि बोले, मुने! तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं अद्‌भुत सोलह वर्षकी आयुका पुत्र चाहते हो या गुणहीन, दीर्घजीवी पुत्रकी कामना तुम्हें है? मैंने तुरन्त प्रभुके चरणोंमें निवेदन किया मैं मूर्ख, गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। अल्पायु ही सही, परन्तु मुझे अनुपम, गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही अभीष्ट है। भगवान शशांकशेखर तथास्तु कहकर अन्तर्ध्यान हो गये। भोलेनाथके वरदानसे तुमसे अद्‌भुत गुण विद्यमान है। कुछ रुककर कातर स्वरमें श्री मृकण्डुने कहा, अब तुम्हारा सोलहवां वर्ष समाप्त हो चला है। आप मेरे लिए चिन्ता न करें। श्री मार्कण्डेयजीने अत्यन्त गम्भीरतासे पिताको आश्वस्त करनेके लिए विनम्रताके साथ कहा, भगवान आशुतोष कल्याणस्वरूप एवं अभीष्ट फलदाता है। मैं उनके मंगलमय चरणोंका आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करूंगा। तदनन्तर श्री मार्कण्डेयजी माता-पिता चरणोंकी धूलि मस्तकपर लगाकर भगवान शंकरका स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर पहुंचे। उन्होंने अपने ही नामपर शिवलिंगकी स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़े ही श्रद्धा-भक्तिसे भगवान मृत्युंजयकी उपासना करने लगे। मृत्युके दिन श्री मार्कण्डेय जी अपने आराध्यकी पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गये। उनके कोमल कण्ठमें कठोर पाश पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा तो सम्मुख भयानक यमराज खड़े थे। मार्कण्डेयजीने निवेदन किया, महामते यमराज! आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अपने प्राणप्रिय मृत्युंजय स्तोत्रका पाठ कर लूं। यमराज किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता ब्रह्मन्। तुम्हारे लिए भी समय नहीं है-यमराजने कहा। यमराजने क्रोधित होकर मार्कण्डेय जीका प्राण हरण करनेके लिए पाश खींचना ही चाहा कि सहसा मार्कण्डेयके मुखसे स्वर निकला मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम्। उक्त शिवलिंगसे साक्षात् भूतभावन भगवान शंकरने प्रकट होकर अत्यन्त क्रोधसे यमराजके वक्षपर कठोर पदाघात किया था। यमराजकी दुर्दशा एवं अपने आराध्यका अनुपम रूप लावण्य देखकर श्री मार्कण्डेय जीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। हृदयसे भक्तिरसकी नवीप मन्दाकिसी वाणीद्वारा स्तुतिके रूपमें प्रवाहित होने लगी। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:। देवाधिदेव महादेवजीने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया।

मनुने लौटाया शूटिंगका स्वर्णिम दौर

❐ योगेश कुमार गोयल

भारतका प्रत्येक व्यक्ति ओलंपिकमें पहला स्वर्ण पदक जीतनेकी पक्की उम्मीदें लगाये बैठा था और ये उम्मीदें टिकी थी भारतकी मिरेकल गर्ल मनु भाकरपर। पूरी उम्मीद थी कि मिरेकल गर्ल मनु भाकर ओलंपिकमें अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी करते हुए इस स्पर्धामें भी भारतको स्वर्ण पदक दिलानेमें कामयाब हो सकती हैं लेकिन इस बार वह पदक जीतनेसे थोड़ा-सा चूक गयी और महिलाओंकी २५ मीटर पिस्टल स्पर्धाके फाइनलमें ४० मेंसे २८ शॉट्स लगानेके साथ चौथे स्थानपर रही और इसीके साथ पेरिस ओलंपिकमें मेडलकी हैट्रिक लगानेका उनका सपना भी अधूरा रह गया। दरअसल तीसरे और चौथे स्थानके शूटरके बराबर प्वाइंट थे। इसके बाद मनु और हंगरीकी मेजर वेरोनिकाके बीच शूटऑफ हुआ, जिसमें मनु केवल तीन निशाने ही लगा पायी जबकि हंगरीकी शूटरने चार बार टारगेटको हिट किया और उसीके साथ मनु पदककी रेससे बाहर हो गयी। वूमेन्स २५ मीटर पिस्टलके फाइनलमें हारके बाद मनुका कहना था कि उनके ऊपर इस इवेंटको लेकर काफी दबाव था। हालांकि २५ मीटर पिस्टल स्पर्धामें मिली इस हारके बावजूद भारतकी इस इकलौती निशानेबाजने वह खुशियां और गर्वके पल देशको दिये हैं, जिसकी ओलंपिक शुरू होनेके समयतक शायद किसीने कल्पना भी नहीं की थी। मनुने भारतके लिए पेरिस ओलंपिकमें तीन अलग-अलग शूटिंग स्पर्धाओंमें हिस्सा लिया और तीनोंमें ही उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शनसे अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भारतको गौरवान्वित किया। ३ अगस्तको जब मनु वूमेन्स २५ मीटर पिस्टलके फाइनलमें खेलने उतरी तो हर नजर उन्हींके प्रदर्शनपर केंद्रित थी। भले ही वह यह मुकाबला हार गयी लेकिन कुल तीन शूटिंग स्पर्धाओंमेंसे उन्होंने अपने जोश और जज्बेके साथ दोमें कांस्य पदक जीतकर भारतमें शूटिंगके सुनहरे दौरको वापस लानेमें बहुत बड़ी भूमिका निभायी है। मनुकी ही बदौलत भारतने पहली बार शूटिंगमें किसी एक ओलंपिक सीजनमें तीन मेडल हासिल किये हैं। विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धाओंमें अनेक पदक जीतनेके बाद एक ही ओलंपिकमें दो पदक जीतकर मनुने ऐसा अविस्मरणीय इतिहास रचा, जो उनके अलावा ओलंपिकके १२४ वर्षोंके इतिहासमें अबतक भारतका कोई भी अन्य एथलीट नहीं कर पाया। मनुसे पहले कोई भी पुरुष या महिला एथलीट एक ही ओलंपिकमें दो मेडल जीतनेमें सफल नहीं हुआ है। देशकी आजादीसे बहुत पहले ब्रिटिश मूलके भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्डने १९०० में आयोजित हुए ओलंपिकमें २०० मीटर फर्राटा और २०० मीटर बाधा दौड़में कुल दो रजत पदक जीतकर एक ही ओलंपिकमें दो मेडल जीतनेका रिकार्ड बनाया था और उम्मीद थी कि मनु १२४ साल पुराने उस रिकार्डको भी पीछे छोड़ सकती हैं लेकिन मिरेकल गर्ल मनु भाकरकी ओलंपिकमें ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी नहीं हो पायी। हालांकि पहला कांस्य पदक जीतनेके साथ ही वह ओलंपिकके इतिहासमें भारतके लिए निशानेबाजीमें पदक जीतनेवाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गयी थी और उस पदकके साथ ही मनुने शूटिंगमें भारतके पदकके १२ वर्षके सूखेको भी खत्म किया था। मनुसे पहले २०१२ के लंदन ओलंपिकमें गगन नारंग और विजय कुमारने शूटिंगमें एक-एक पदक जीते थे। ओलंपिकके १२४ वर्षके इतिहासमें मनुसे पहले भारतको शूटिंगमें केवल चार पदक ही नसीब हुए थे जबकि भारत केवल इसी ओलंपिकमें मनुके दो पदकों सहित कुल तीन पदक जीत चुका है। शूटिंगमें २००४ के एथेंस ओलंपिकमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ने रजत पदक जीता था, उसके बाद २००८ के बीजिंग ओलंपिकमें अभिनव बिंद्राने स्वर्ण पदक भारतके नाम किया और २०१२ के लंदन ओलंपिकमें विजय कुमारने रजत और गगन नारंगने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिकमें मनुने अपना पहला पदक २८ जुलाई २०२४ को दस मीटर एयर पिस्टल शूटिंगके महिला वर्गमें जीता था। उस शूटिंग स्पर्धामें कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिकमें पदक हासिल करनेवाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। उसके बाद ३० जुलाईको मनुने सरबजोत सिंहके साथ मिलकर दस मीटर एयर पिस्टलके मिक्स्ड टीम इवेंटमें कांस्य पदक जीता और उस जीतके साथ ही वह एक ही ओलंपिकमें दो पदक जीतनेवाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गयी थी। एक ही ओलंपिकमें दो पदक जीतकर वह सुशील कुमार और पीवी सिंधुको भी पीछे छोड़ चुकी हैं। फिलहाल देशके लिए एक ही ओलंपिकमें दो पदक जीतनेवाली मनु भाकरपर पूरे देशको गर्व है।

https://t.me/AIINewsPaperPaid

युवाओं को बेहतर भविष्य संजोने का मौका

कारगिल विजय दिवस पर छह राज्यों की भाजपा सरकार ने अग्निवीरों को तोहफा दिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों द्वारा यह जानकारी दी गई है। अग्निवीर जब सेना की अपनी सेवा के बाद वापस लौटेंगे तो उन्हें पुलिस और पीएसी में प्राथमिकतानुसार समायोजित किया जाएगा। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की ड्रीम योजनाओं में से है, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत 17 से 21 साल की आयु वाले युवाओं को भारतीय सेना में चार साल के लिए सेवा का अवसर दिया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में सैनिक स्तर पर भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को लागू किया गया है। आम चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस योजना को विशेष तौर से निशाने पर रखा था और इसे लगातार रद्द करने की मांग कर रहा है। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सत्ता में आने के बाद इसे बंद करने की बात करते हैं। हालांकि सरकार बार-बार इस योजना को लेकर दलील देती रही है कि कुछ राजनीतिक दल इस तरह की बातों से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए आरक्षण की इस घोषणा के पीछे यही दबाव माना जा रहा है। चूंकि ये अल्पकालिक सेवाएं हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि चार साल बाद ये सेवामुक्त अग्निवीर पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने इन्हें निश्चित आरक्षण देकर इस विवाद को संभालने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ समय पूर्व ही गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में दस फीसद पद आरक्षित करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही, अग्निवीरों में से पच्चीस प्रतिशत को पंद्रह सालों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान भी जोड़ा गया। देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी सरकार के लिए कड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरे, बहुत बड़ा वर्ग सेना में नियुक्ति को लेकर विशेष उत्सुक रहता है। उसे प्राप्त होने वाला यह मौका सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सेना में केवल चार वर्षों के सेवाकाल के उपरांत इन प्रशिक्षित युवाओं का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता।

निरंकुशता के कारण हसीना का निष्कासन

आरती कुमारी

बांग्लादेश में जनभावना को दबाने एवं अनसूना करने से पनपे विद्रोह, आक्रोश एवं विरोध की निष्पत्ति है शेख हसीना सरकार का पतन। लम्बे समय से चला आ रहा आरक्षण विरोधी आंदोलन का आक्रोश उग्रतम होता गया, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह एवं निरंकुश बनना बड़ा कारण रहा। जनभावनाओं को कुचला जाना एवं अनसूना करने के कारण ही हसीना आनन-फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा। उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे बगावती प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। बांग्लादेश बेहाल हो गया, हिंसक एवं अराजक घटनाएं कहर बन कर हसीना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा रही थी। जैसी आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप के श्रीलंका, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति भारत सरकार को सतर्क एवं सावधान रहने के साथ अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। जब-जब जिन-जिन देशों में जनता की आवाज को दबाया गया, एक विस्कोटक स्थिति बनी, क्रांति का शंखनाद हुआ। मान्य सिद्धान्त है कि आदर्श ऊपर से आते हैं, क्रांति नीचे से होती है। बांग्लादेश में क्रांति एवं विद्रोह का कारण भी यही स्थिति बना कि ऊपर से आदर्श की स्थितियों पर धुंधलका छाने लगा तो क्रांति नीचे से होने लगी, बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसने लगा, आगजनी, तोड़फोड, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गये, सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश एवं जनता के विद्रोह को हल्के में लिया। वास्तव में हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव एवं घाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। निश्चित ही पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि, शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक एवं असंगत आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया। उनका तर्क था कि उनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं, फलतः बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार ढंग से संभाल नहीं पायी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन सरकार इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया। जनाक्रोश के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तोड़ दिया। निस्संदेह, सत्ता से चिपके रहने के लिये किए जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जनाक्रोश एवं जनान्दोलन के चरम के रूप में सामने आता ही है। ताजा घटनाक्रम एवं हिंसक आंधी श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शन की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतरकर विदेश भागने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान अपने हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना होगा। नयी व्यवस्था एवं सोच में व्यापक सकाकरात्मक परिवर्तन हो, विदेशी ताकतों विशेषतः पाकिस्तान की कठपूतली बनने से बचना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध थे, भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी, सहयोगी और दुख के दिनों का साथी रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त जर्मनी में थी। इसलिए जिंदा बच गई थी। तब तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन को भारत बुलाया था एवं संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन हालिया उथल-पुथल को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। पाकिस्तान परस्त बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की आसन्न वापसी भारत के लिये सावधान होकर अग्र-स्थितियों पर गंभीरता से ध्यान देने की है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना का विरोध कर रहे छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के नाम का समर्थन किया है। शेख हसीना और यूनुस का आपस में बहुत तनाव रहता था। अब यूनुस से उम्मीद की जा रही है कि वह देश को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। भारत पडोसी देश के नाते बांग्लादेश में स्थिरता, शांति एवं सौहार्दपूर्ण स्थितियों की कामना करता है।

भारत- बांग्लादेश, अब दोनों देशों के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा?

अशोक भाटिया, मुंबई

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल तख्ता पलट तक पहुंच गया है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आकर शरण लेनी पड़ी है। वहीं, बांग्लादेश में बवाल चरम पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हालात और सुरक्षा की समीक्षा के लिए बैठक कर चुके हैं।इन सबके बीच आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध? कैसे पड़ी थी इसकी नींव और दोनों देश एक-दूसरे से क्या खरीदते-बेचते हैं?और अब अब दोनों देशों के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? पहले भारत-बांग्लादेश ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इसकी नींव साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के साथ ही पड़ गई थी। पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लदेश) की बांग्ला भाषी जनता को राहत दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम यहां तक कह सकते हैं कि भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद आज बांग्लादेश का अस्तित्व भी नहीं होता। आज भारत ने बांग्लादेश में तखता पलट के बाद फिलहाल आवागमन से जुड़ी सभी सेवाएं रोक दी हैं। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तीस्ता सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए बातचीत चल रही है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी हुई थी। चीन की इस प्रोजेक्ट पर बुरी नजर है क्योंकि अब पीएम शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। फोरम फ़ॉर ग्लोबल स्टडीज के मुखिया डॉ। संदीप त्रिपाठी का मानना है कि भारत के लिए यह कठिन समय है। शेख हसीना युग के समापन के बाद बांग्लादेश में अब वह सब कुछ होगा, जो चीन-पाकिस्तान चाहेंगे। आर्थिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या रेल प्रोजेक्ट या विकास की अन्य योजनाएं, भारत का अब वह प्रभाव नहीं रहेगा। भारत को चौकन्ना रहना होगा। बिजनेस की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी। डॉ। त्रिपाठी के मुताबिक 34 फीसदी कॉटन का आयात भारत बांग्लादेश से करता है। शेख हसीना के राज में साल 2009 से अब तक जो कुछ भी सकारात्मक चीजें हुई हैं, वह सब रुक सकती हैं। उधर, शेख हसीना का इस्तीफा हुआ, उन्होंने देश छोड़ा और खालिदा जिया की रिहाई के आदेश राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने कर दिए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश की स्थिति काबू में नहीं है। अभी बांग्लादेश में सेना का शासन है। वहां की हालत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश की हालत का असर पड़ सकता है। डाबर से लेकर ट्रेंट तक कई भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश में बाजार या सप्लाई चेन कंपोनेंट के रूप में भागीदारी है। दरअसल, उच्च गुणवत्ता के रेडीमेड गारमेंट तैयार करने के लिए बांग्लादेश जाना जाता है। सस्ती लेबर और कच्चे माल की बांग्लादेश में पर्याप्त उपलब्धता है। इसलिए वहां तैयार होने वाले कपड़ों की फिनिशिंग और गुणवत्ता दुनिया में बेहतर मानी जाती है। इसलिए कई नामी कंपनियों के कपड़े बांग्लादेश में ही बनते हैं। भारत के भी तमाम बड़े ब्रांड बांग्लादेश में कपड़े तैयार कराते हैं या फिर वहां से कच्चा माल उठाकर लाते हैं और फिर उसे तैयार कराते हैं। हाई क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट को तैयार करने के लिए बांग्लादेश फेमस है। यहां पर सस्ते दामों पर मजदूर और कच्चा माल मिल जाता है। इसीलिए यहां पर तैयार होने वाले कपड़ों की फिनिशिंग और क्वालिटी दुनिया में काफी अच्छी मानी जाती है। भारत के बड़े-बड़े ब्रांड या तो बांग्लादेश में कपड़े तैयार करवाते हैं या फिर वहां से कच्चा माल वहां से मंगवाते हैं और फिर उसे अपने ही देश में तैयार करवाते हैं। कपड़ों के अलावा भारत बांग्लादेश से मसाले, जूट,प्राकृतिक रबर, खाद्य तेल, सब्जी तेल, व समुद्री उत्पाद का आयात करता है। जबकि भारत भी 6052 कमोडिटी का निर्यात करता है। इसमें चावल, रुई, पेट्रोलियम उत्पाद, सूती कपड़ा, गेहूं और गेहूं से बने उत्पाद, मसाले, सब्जी, चीनी, फल, खाद्य तेल व अन्य उत्पाद शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 1220 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। व्यापारियों का कहना है कि, हिंसा के बाद से कुछ उत्पादों के आयात और निर्यात में असर दिख रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में फैक्ट्रियों व मंडियों से कंटेनर डिपो (बंदरगाह) माल पहुंचाने में परेशानी हो है। उसी तरह से जो माल यहां से भेजा (निर्यात) जा रहा है, उसका उठान भी पूरी मात्रा में नहीं हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो कुछ उत्पादों की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। इसके पहले भी बांग्लादेश में सैन्य शासन आया था । सैन्य शासन आते ही भारत के अहसान भुलाकर सीमा विवाद, विद्रोह और पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी शासकों ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी थी । हालांकि, साल 1996 में शेख हसीना की सरकार बनी तो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया। इससे दोनों देशों के संबंधों में फिर से सुधार आना शुरू हुआ।वैसे भी भारत की नीति है कि पड़ोसी पहले। अपनी इसी नीति पर चलते हुए भारत ने साल 2010 के बाद से बांग्लादेश को सात बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता कर्ज के रूप में प्रदान की है। दोनों देशों ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते के साथ ही पानी के बंटवारे और समुद्री सीमा विवाद को भी हल करने में सफलता हासिल कर ली। भारत और बांग्लादेश लगातार ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते रहे हैं। पिछले दशक में भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 10।8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था जो साल 2021-2022 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, साल 2022-23 में कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इनके बीच व्यापार में गिरावट देखने को मिली। साल 2021-22 में भारत ने 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चावल और 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चीनी और 43 करोड़ डॉलर से ज्यादा के दूसरे अनाजों का निर्यात किया था। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को हरी सब्जियों, फलों के साथ ही मसालों और खाद्य तेल का निर्यात भी किया जाता रहा है।इसके अलावा हाल के सालों में बांग्लादेश जेनरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मुख्य निर्यातक बन रहा था। भारत भी बांग्लादेश से फार्मास्यूटिकल उत्पादों और इससे जुड़े कच्चे माल का आयात करता है। भारत मसाले और समुद्री उत्पाद जैसे मछली आदि भी बांग्लादेश से मंगाता है। बांग्लादेश से भारत केवल कपड़ो के माल का ही आयात नहीं करता है बल्कि जूट, रबर, खाद्य तेल और सब्जी तेल का भी आयात करता है। वहीं भारत भी काफी कुछ निर्यात करता है। इसमें चावल, रुई, सूती कपड़ा, गेंहू और गेंहू से बने प्रोडक्ट, मसाले, सब्जी, चीनी, फल और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 1220 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। बात करें बांग्लादेश से भारत आने वाले सामानों की तो फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में 1154 सामानों का आयात किया गया। यह करीब 2।02 अरब डॉलर का था। वहीं, इससे पिछले फाइनेंसियल ईयर में यह आकड़ा महज 1।97 अरब डॉलर ही था। VIP लगेज निर्माता कंपनी का बांग्लादेश में 8 मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी लगभग 30 से 35% क्षमता यहां से आती है। ऐसे में इस क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर हो सकता है।मैरिको इंटरनेशनल मार्केट का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो कुल रेवेन्यू का एक चौथाई से अधिक हिस्सा है। मैरिको के अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू का लगभग 44% बांग्लादेश से आता है। डाबर, जीसीपीएल और ब्रिटानिया एक बडी एफएमसीजी कंपनी है। यहां से कंपनी का 5 प्रतिशत से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। ऐसे में इन कंपनियों के रेवेन्यू पर भी असर हो सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज ऑपरेटर के बांग्लादेश में 28 स्टोर हैं, जो इसकी कंसॉलिडेटेड सेल का लगभग 1% है। ऐसे में यह बिजनेस भी प्रभावित होगा। बांग्लादेश टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट के लिए सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के साथ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यहां से बड़ा बिजनेस टाटा ग्रुप को मिलता है। कपड़े से लेकर कार और अन्य बिजनेस के लिए अच्छा रेवेन्यू जरनेट होता है, जिसका असर अब कंपनियों के मुनाफे पर दिखाई दे सकता है। बांग्लादेश में संकट के बीच एशिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बांग्लादेश में ऑफिस 7 अगस्त तक बंद कर दिया है। LIC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "बांग्लादेश में मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के कारण एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का ऑफिस 05 अगस्त 2024 से 07 अगस्त 2024 तक की अवधि के दौरान बंद रहेगा।" भारत और बांग्लादेश के बीच में मजबूत संबंधों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने भारतीय रुपये में ट्रेड शुरू करने का एक अहम कदम उठाया था। भारत में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था और 22 जून को पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान कई सारे समझौतों पर भी मुहर लगाई गई थी। इसमें दोनों देशों के बीच में रुपयों में व्यापार करना भी शामिल था।

मेष राशि-आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। माता-पिता के साथ रिश्ते मधुर होंगे। पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता बरकरार रहेगी। आपको जीवनसाथी से पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकता है। आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है।

वृष राशि-आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। आप खुद को किसी रचनात्मक काम में लगायेंगे। आपके काम से अधिकारी वर्ग भी खुश होंगे। आज आपकी सलाह किसी जरूरतमंद के लिए कारगर साबित हो सकती है।

मिथुन राशि-आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुल सकते हैं। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा।

कर्क राशि-आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आज आपके सारे जरूरी कामकाज पूरे हो जायेंगे। पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आपका खर्च बढ़ सकता है। किसी को उधार पैसा देने में सोच-विचार करना बेहतर रहेगा। कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं।

सिंह राशि-आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज निकल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव होंगे।

कन्या राशि-आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। करियर को बढ़ाने के लिए आज आपको नये अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ डिनर करने जा सकते है। साथ ही रिश्तों में पॉजिटिविटी भी आयेगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। आज आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। भाई- बहनों से आपको पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रूके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा।

तुला राशि-आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आज आपका ध्यान अपने कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों का दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ सकता है। आपके पास कुछ नयी जिम्मेदारियां आ सकती है, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जायेगा।

वृश्चिक राशि-आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज जो भी काम आप शुरू करेंगे उसे समय से पूरा कर लेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकती है। लेन-देन के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवनसाथी की उपलब्धियों की सराहना करने से आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आयेगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई-लिखाई में सफलता मिल सकती है।

धनु राशि-आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। इस राशि के लोगों को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव मिलेगा। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी कामकाज से भी जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होंगे। किसी समारोह में आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा।

मकर राशि-आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ समय बिता सकते है, इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लानिंग आज बन सकता हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। किसी खास काम में आपको सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशि-आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किस्मत का पूरा-पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। कारोबारियों को लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं, तो वह आज पूरा हो जाएगा। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने का भाव आज आपके मन में आयेगा। आज आपका दांपत्य जीवन शानदार रहने वाला है।

मीन राशि-आज आपका दिन ठीक रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। काम पूरा करने के लिए शायद आपको पर्याप्त समय न मिल पाये। परेशान होने के बजाय धैर्य बनाये रखना चाहिए। वहीं किसी कार्य में कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। दिनभर की व्यस्तता के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

शब्द सामर्थ्य -141

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :
1. पानी, नीर, अंबु 2. आना-जाना, आवागमन 5. बहुत, बढ़िया 6. दूर रहने वाला (घटना) जो वर्तमान में न घट सके 8. अबोध, नासमझ, अनाड़ी 10. सब्जी, शाक 11. निशान, उद्देश्य, अनुमान योग्य वस्तु 12. नाखून 13. द्रव पदार्थ 15. सूनसान, जनविहीन स्थान 16. चटकीला, चमकीला, चटपटा, गौरिया 18. भगवान, खुदा 19. इन दिनों, वर्तमान दिनों में 20. अग्नि, पावक 21. अन्नकण, अनाज का टुकड़ा 22. टालमटोल, बहाने बाजी 24. भैया की पत्नी 25. पांच से छोटी एक विषम संस्था 26. हत्या, कत्ल.

ऊपर से नीचे
1. दुनिया, संसार, ठोस रूप में परिवर्तित करना 2. चमक, पानी 3. बाजीगर, जादू का खेल दिखाने वाला 4. एक पंजाबी प्रेमगीत, रांझा की प्रेमिका 5. मार-काट, खून-कत्ल 7. भूमि, जमीन, भू-भाग 9. बहुत बड़ा दानी, 10. संगीत के सुरों की संख्या 14. लचीला, लोचयुक्त 17. खिसकना, अपने स्थान से हटना, विचलित होना 19. प्रवेश करना, पधारना, आना 20. धूप-दीप से पूजा 22. इसी समय 23. गुस्सा, कहर.

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 140 का हल

स्वा	द		सा	म	ना		कै	दी
व		ख	ल	ना	य	क		बा
लं	प	ट		ना	क	क	ट	ना
बी		प				ड़ी		प
	अ	ट	प	टा			शा	न
स	ह		यो			र	ति	
ह	म		द	र	ब	द	र	
म	क	र		सी	ल			
त		क्षा		द	वा	खा	ना	

सूडोकु नवताल- 7150

★★★★★ कठिनतम

		4			9			
	2			8	4			
8						3		
							9	4
	3						7	
5	6							
		7						9
			2	5			8	
			6			2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7149 का हल

5	9	1	2	8	4	3	6	7
6	4	2	3	5	7	9	1	8
8	3	7	9	6	1	4	2	5
4	7	5	8	2	6	1	9	3
3	6	9	7	1	5	8	4	2
1	2	8	4	3	9	7	5	6
7	5	6	1	9	8	2	3	4
9	8	3	5	4	2	6	7	1
2	1	4	6	7	3	5	8	9

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 7 अगस्त 2024

भारत की चुनौतियां बढ़ीं

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन सत्ता परिवर्तन तक जा पहुंचा। अतीत यही बताता है कि बांग्लादेश का संकट केवल उसका नहीं होता। जब-जब वह मुसीबत में घिरा है, तो उसकी परछाई भारत तक भी आई है। सवाल है कि इस बार वह परछाई कैसी और कितनी बड़ी होगी?

दोस्त का खोना | बांग्लादेश में ऐसे समय बदलाव हो रहा है, जब एक और करीबी पड़ोसी मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में ठंडापन आया है। शेख हसीना की नीतियों में संतुलन था। घरेलू मोर्चे पर उनकी कार्यशैली को लेकर जो भी आलोचना रही हो, लेकिन विदेश मामलों में उन्होंने भारत, चीन और पश्चिम के बीच बैलेंस जरूर बनाए रखा था।

बांग्लादेश में अस्थिरता से संकट

व्यापार पर असर | दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है बांग्लादेश। कई प्रॉजेक्ट्स पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बेहद अहम है। साथ ही, इस पड़ोसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत ने बहुत निवेश किया है। हालात अधिक वक्त तक काबू से बाहर रहे तो इन सब पर असर पड़ सकता है।

सुरक्षा की चिंता | शेख हसीना का भारत के साथ भावनात्मक नाता भी है। इसी वजह से वह आतंकवाद और चीन से जुड़ी भारत की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझती थीं। उन्होंने अलगाववादी और कट्टरपंथी ताकतों पर काफी हद तक लगाम लगाकर रखी थी। भारत को सतर्क रहना होगा कि ये ताकतें कहीं फिर से सिर न उठाने लगें।

बॉर्डर का मसला | दोनों देश एक लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते ही जिस तरह भारत में बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई, उससे ही समझा जा सकता है कि वहां की घटनाएं हम पर किस तरह का असर डाल सकती हैं। भारत यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चीन के साथ अब एक और पड़ोसी से लगती सीमा पर उसके ज्यादा संसाधन खर्च हों।

चीन का काउंटर | छात्र आंदोलन जिस तरह से हिंसक होकर सत्ता परिवर्तन कराने वाली शक्ति में तब्दील हुआ, उससे कई संदेह पैदा होते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है? इस पूरे घटनाक्रम से अगर किसी का फायदा हो सकता है, तो वह है चीन, जो पड़ोसियों की अस्थिरता का फायदा उठाने से नहीं चूकता।

संबंध बनाए रखें | बांग्लादेशी सेना के प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। इस बीच, पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दिए गए हैं। खालिदा को चीन और पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। हालांकि बांग्लादेश में जो भी सरकार आती है, भारत को उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ाने चाहिए।

ऑफबीट

निगाहें नींद पर

सौरभ श्रीवास्तव

कुछ दिनों पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलिस (UCLA) के प्रफेसर विनय लाल का एक विडियो देखा। विडियो की शुरुआत में एंकर ने बताया कि डॉ. लाल कहते हैं कि पूंजीवाद, बाजार की नजर अब आपकी नींद पर है। वह चाहता है कि आप कम से कम सोएं और ज्यादा से ज्यादा काम करें वह भी कम पैसे में। यह चौकाने वाली बात है कि आखिर वह कौन सी ताकतें हैं, जो हमारी-आपकी आठ घंटे की नींद में से कुछ घंटे चाहती हैं?

शहरों में काम करने वाले ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि नींद पूरी नहीं होती। दिन में 10 से पांच की नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग रात 12 बजे तक सोशल मीडिया पर टंगे मिलेंगे, फिर सुबह छह बजे उठकर बच्चों को स्कूल भेजना और पूरे दिन की तैयारी करना। आठ घंटे की गहरी और लगातार नींद के लिए सामान्य तौर पर आपको 9 घंटे तो बिस्तर पर रहना ही होगा वह भी बिना किसी स्क्रीन के।

सारे प्रपंच को समझने के लिए सबसे पहले 'मी टाइम' में हो रहे खेल को समझते हैं। मी टाइम यानी वह समय जो आप नितांत अपने लिए रखते हैं। इस वक्त में आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद है। 'जो आपको पसंद है' इस पंक्ति को दोबारा पढ़िए। क्या वास्तव में आप वही कर रहे हैं, जो आपको पसंद है? सोचिए, स्मार्टफोन आने और इंटरनेट डेटा सस्ता होने से पहले आपको क्या पंसद था? बागवानी, खेलना, किताबे पढ़ना, टहलना, आर्ट बनना। क्या आप अब भी ये काम करते हैं? टका सा जवाब है कि दिनभर की भागदौड़ में वक्त ही नहीं मिलता। वीक ऑफ वाले दिन जरूर कुछ कर लेते हैं। बाकी दिन इस शौक का क्या करते हैं? शौक से जुड़े विडियो देखते हैं, नोट पर पढ़ते हैं। जानकारी बढ़ाते हैं ताकि शौक को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। कब? जब भी समय मिलता है। समय कब मिलता है? ज्यादातर रात में 'मी टाइम'। दिन की बढ़ती व्यस्तताओं के बीच अब मोटे तौर पर रात में सोने से पहले का आधे-एक घंटे का वक्त ही खाली बचता है। यह खाली वक्त कब एक से दो और दो से तीन घंटे का हो जाता है पता ही नहीं चलता। यानी मोबाइल फोन की स्क्रीन शौक के बारे में जानकारी देने के एवज में आपसे आपकी नींद ले रही है। विडियो देखने या ऑनलाइन पढ़ने के दौरान आप अपनी रुचि से जुड़े ढेरों विज्ञापन भी तो देखते हैं। कई बार विज्ञापनों के जरिए खरीदारी करने वाली साइटों पर चले जाते हैं कुछ खरीद भी लेते हैं या कार्ट में डाल लेते हैं। यही तो चाहता है बाजार आपसे, जब आप रिलैक्स हों तो वह आपके पास आए और चुपके से कान में फुसफुसा दे- यह सामान खरीद लो इससे जीवन आसान हो जाएगा और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। कम सोएंगे तो बेहतर उपभोक्ता बनेंगे। बोलिए बनेंगे ना?

एकदा

लिंकन ने की मदद

1863 की सर्दियों में अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक दिन वाइट हाउस में अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। वहां वह एक पत्र पढ़ रहे थे, जो उन्हें पंद्रह वर्षीय एक लड़की ग्रेस ग्रीनवुड बेडेल ने लिखा था। पत्र में ग्रेस ने लिखा था कि वह लिंकन को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना चाहती थी, लेकिन उसे यह जानकर निराशा हुई कि महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। लिंकन ने तुरंत ग्रेस को जवाब लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह उसकी भावनाओं को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। कुछ दिनों बाद लिंकन को पता चला कि ग्रेस का परिवार युद्ध के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ग्रेस की मां बीमार थीं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। लिंकन ने उनके इलाज के लिए अपने निजी चिकित्सक को ग्रेस के घर भेजा और इलाज का खर्च अपने वेतन से दिया। इस घटना के एक महीने बाद लिंकन वाइट हाउस के बाहर लॉन में टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि पंद्रह-सोलह साल की एक लड़की उनकी ओर दौड़ते हुए आ रही है। यह ग्रेस थी, जो अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति को धन्यवाद देने आई थी। ग्रेस ने लिंकन को गले लगा लिया और कहा, 'आपने मेरी मां को बचा लिया। मैं बड़ी होकर आप जैसी बनना चाहती हूं।' लिंकन मुस्कुराए और बोले, 'बेटी, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकती हो। तुम एक ऐसे अमेरिका का निर्माण कर सकती हो, जहां हर किसी की आवाज सुनी जाए।' ग्रेस बेडेल बाद में अमेरिका की एक प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता बनीं और उन्होंने महिलाओं के मतदान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। लिंकन से मिली प्रेरणा ने उन्हें यह साहस दिया।

Subrata Dhar

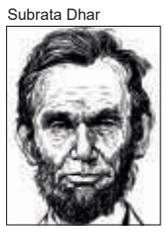

संकलन : देवेन्द्रराज सुथार

इस साल हुए चुनाव में धांधली की शिकायतें, कोरोना महामारी-यूक्रेन युद्ध से इकॉनमी पटरी से उतरी

हसीना को भारी पड़ा लोकतंत्र से खेलना

चंद्रभूषण

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है, लेकिन उनके देश पर मंडरा रही विपत्ति इससे जरा भी कम नहीं हुई है। बांग्लादेश अराजकता की गिरफ्त में है।

कुर्सी का मोह | शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी और भारत की पुरानी मित्र शेख हसीना ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के एक छोटे हिस्से को बाकी आबादी का शत्रु बना दिया। इसका नुकसान बांग्लादेश को लंबे समय तक झेलना पड़ेगा और सड़कों की बर्बरता हिंदू अल्पसंख्यकों समेत लाखों परिवारों का जीना मुहाल कर देगी।

आर्थिक कामयाबी | अवामी लीग की शीर्ष नेता के रूप में लगातार चौथा आम चुनाव जीतकर बतौर पीएम यह कार्यकाल शेख हसीना ने अभी कुल छह-सात महीने ही गुजारा था। सर्वशक्तिमानता का एक आभामंडल पंद्रह साल के शासन ने उनके इर्द-गिर्द रच डाला था। आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश को जो रफ्तार इस 76 वर्षीय राजनेता ने पकड़ाई थी, वह बांग्लादेश के लिए किसी सपने जैसी थी।

गरीबी घटी | सिले हुए सूती कपड़ों के निर्यात में बांग्लादेश देखते-देखते दुनिया का अग्रणी देश बन गया। बंदरगाह, रेलवे, सड़क और बिजली उत्पादन में भी वहां अंधाधुंध काम हुआ। ढाई करोड़ लोग इस दौरान वहां गरीबी रेखा से ऊपर गए। रोजगार के मामले में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का रेकॉर्ड 2019-20 के आंकड़ों में इतना अच्छा दिख रहा था कि भारतीय राजनीति में लंबे समय से बनी हुई 'अवैध बांग्लादेशियों की समस्या' अपने आप यहां के एजेंडे से बाहर हो गई। लेकिन बांग्लादेश में लोकतांत्रिक विपक्ष को हाशिये पर फेंका जा रहा था, जिसकी ताकतवर मुल्क अनदेखी करते रहे।

बड़ी जीत | सन 2018 में मुख्य विपक्षी दल BNP की नेता बेगम खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके थोड़े ही समय बाद हुए आम चुनाव में कुल 300 सीटों में अवामी लीग को 257 सीटें मिलीं, जबकि विपक्ष 26 सीटों पर सिमट गया।

महामारी की मार | लेकिन 2020 की शुरुआत में ही जब कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को गर्दन से पकड़ा तो बांग्लादेश के कल-पुर्जे बिखरने लगे। उसके कुल 55 अरब डॉलर के निर्यात में 85% हिस्सा सिले हुए सूती कपड़ों का था, जिस पर कोरोना के दौरान ही जोरदार धक्का लगा।

भारत का सहारा | शेख हसीना ने इस संकट का समाधान भारत से अपने गहरे रिश्तों में खोजने का प्रयास किया और अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए यहां से बड़े सरकारी कर्जे की व्यवस्था की। लेकिन कपड़ा उद्योग की हालत खराब बनी रही। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल, खाद्य तेलों और अनाज के महंगे आयात ने बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी।

बांग्लादेश में अराजकता
- हसीना ने देश की आर्थिक ताकत बढ़ाई
- लोकतंत्र और विपक्ष का दमन किया
- पिछले चुनाव में धांधली के आरोप लगे

चुनावी धांधली | 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनाव में शेख हसीना को पता था कि इसका स्वरूप उनके पिछले तीन चुनावों जैसा नहीं है। विपक्ष के 25 हजार (सरकारी आंकड़ा 11 हजार) नेता-कार्यकर्ता 2023 में हुए आंदोलनों के दौरान जेल में थे। उनकी ओर से चुनाव बॉयकॉट का नारा था। लेकिन लोग वोट देने आएं, इसके लिए अवामी लीग की ओर से यह बात फैलाई गई कि जो भी वोट नहीं डालेगा, उसे कार्ड पर मिलने वाली कोई भी सरकारी सहायता आगे नहीं मिल पाएगी।

खतरे की घंटी | इसके बावजूद वोटिंग बंद होने तक सिर्फ 28% वोट पड़ने की ही सूचना थी। बाद में चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना में खींचतान कर इसे 40% तक पहुंचाया गया। दिसंबर 2018 के चुनाव में 75% मतदान को देखते हुए इसे खतरे की घंटी माना जाना चाहिए था। हसीना ने शायद माना भी हो, लेकिन जवाब गलत खोजा।

आरक्षण पर बवाल | अभी वाले बवाल की शुरुआत जून में हुई, जब एक हाईकोर्ट ने 2018 में रद्द किए गए विवादास्पद कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। यह कोर्ट का फैसला था, जिससे सरकार हाथ खींच सकती थी। लेकिन शेख हसीना ने आंदोलन करने वाले छात्रों को रजाकार और आतंकवादी घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए आरक्षण को 7% पर ला दिया, लेकिन तब तक बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि मामला सरकार से माफी की मांग पर आ गया।

सांप्रदायिक रूप | अवामी लीग का छात्र संगठन और पार्टी कार्यकर्ता पुलिस और फौज के पीछे-पीछे उस आंदोलन से निपटते रहे, जो 5 अगस्त को पीएम का इस्तीफा मांगने के लिए 'ढाका कूच' का ऐलान कर चुका था। इस बिंदु तक पहुंचकर आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप भी धारण कर लिया, जो बांग्लादेश की स्थापना के बाद से ही पता नहीं क्यों वहां के हर बड़े जन-आंदोलन की नियति बन जाता है। इस तरह दो साल के अंदर दक्षिण एशिया में दूसरी बार, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भाग जाने की घटना सामने आई। अफसोस कि इस पलायन का दंड उन सेकुलर परिवारों और गिनती के बांग्लादेशी हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ज़िंदगी मिलेगी दोबारा

जाते-जाते भी कोई शख्स कई दूसरे लोगों को नया जीवन दे सकता है। यह कमाल है अंगदान का और इसलिए इसे महादान कहा गया है। नैशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) के जारी किए आंकड़ों से समझते हैं कि देश में ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की स्थिति क्या है...

18,378
ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए 2023 में। अमेरिका और चीन के बाद अंग प्रत्यारोपण में दूसरी पोजिशन है भारत की।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बढ़ता आंकड़ा 2018 में पहली बार 10 हजार पार और 2020 में कोरोना का रहा असर

वर्ष	ट्रांसप्लांट
2018	10,340
2019	12,666
2020	7,433
2021	12,259
2022	16,041

ट्रांसप्लांटेशन रेट में सुधार

13,426	4,491	221	197	27
किडनी	लिवर	हार्ट	लंग	पैनक्रियाज

मरने के बाद बांट रहे जीवन

2,935
अंग प्रत्यारोपण उन डोनर्स की वजह से हुए, जिन्होंने मौत के बाद अंगदान किया। पहली बार यह आंकड़ा हजार के पार पहुंचा है। 2013 में यह संख्या 837 थी।

1,099
अंगदान मौत के बाद देश में, 2023 में

लिविंग डोनर्स में महिलाओं का जोड़ नहीं

6 लिविंग डोनर्स महिलाएं थीं हर 10 अंगदान करने वालों में से

9,784 लिविंग डोनर्स महिलाएं रहीं 2023 में

5,651 लिविंग डोनर्स पुरुष थे पिछले साल

एक्सपर्ट राय

भारत में हर साल जितने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, उसकी तुलना में ऑर्गन डोनेट करने वाले बहुत ही कम हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जागरूकता बढ़ी है। फिर भी अभी बहुत प्रयास किए जाने हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस बारे में अभियान चलाए जाते हैं।

- डॉ. सुधीर सिंह, KGMU, लखनऊ

लेकिन, अब भी बहुत पीछे

मौत के बाद ऑर्गन डोनेशन को लेकर भारत में जागरूकता बढ़ रही है, पर हम टॉप 5 देशों के आसपास भी नहीं। प्रति 10 लाख आबादी पर मौत के बाद अंगदान में स्पेन सबसे आगे है...

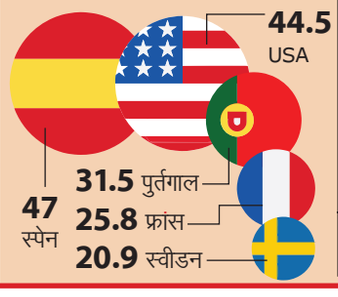

90%
अंगदान मौत के बाद सिर्फ पांच राज्यों से हुए। तेलंगाना सबसे आगे रहा।

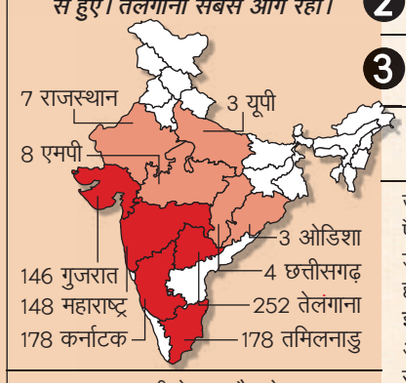

0.1% आबादी केवल मौत के बाद अंगदान करती है भारत में

विदेशियों को भा रहा भारत

10%
ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदेशी लोगों ने कराए। इनमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के मरीज ज्यादा थे। US और UK से भी कुछ मरीज थे।

1,851 विदेशी रहे अंग प्रत्यारोपण कराने वालों में

9 ऑर्गन डोनेशन मरे हुए लोगों की तरफ से हुए विदेशियों को

राज्यवार विदेशी ORGAN RECIPIENTS

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए सबसे ज्यादा विदेशी आए। बाकी राज्यों में संख्या बहुत कम रही, मसलन महाराष्ट्र में केवल 35, कर्नाटक में 15, गुजरात में 11, तमिलनाडु में 3 और मणिपुर में मात्र एक विदेशी का अंग प्रत्यारोपण हुआ।

संख्या	राज्य
1,445	दिल्ली
116	राजस्थान
88	पश्चिम बंगाल
76	उत्तर प्रदेश
61	तेलंगाना

भारत इसलिए खींच रहा विदेशियों को

1. पड़ोसी देशों के मुकाबले सुविधाएं ज्यादा हैं भारत में
2. विकसित देशों की तुलना में खर्च बहुत कम
3. मेडिकेयर में भारत की साख बेहतर हुई है

8 जिंदगियां बचा सकता है हर डोनर, 75 जीवन को बेहतर बना सकता है।

जीवित रहते एक किडनी, जबकि पैनक्रियाज और लिवर का कुछ हिस्सा डोनेट किया जा सकता है। मौत के बाद हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, इन्टेस्टाइन, स्किन और बोन टिशू, आई टिशू, हार्ट वॉल्व वगैरह डोनेट कर सकते हैं।

कंटेंटः शैलेंद्र पांडेय, ग्राफिक्सः अर्जुन सिंह

35 लाख लोगों को रोज़गार दे रहा हथकरघा

गिरिराज सिंह

स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक से हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर को याद करने और हमारी हथकरघा परंपरा का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मकसद है देश के हथकरघा कामगारों को सम्मानित करना और इस सेक्टर को प्रोत्साहित करना।

रोजगार का जरिया | हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है इससे। इसमें महिलाओं की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। इस तरह से यह क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण जरिया है। वस्त्र मंत्रालय ने देशभर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।

स्लो फैशन | पिछले कुछ वर्षों में हथकरघा क्षेत्र निरंतरता और स्लो फैशन के प्रतीक के रूप में उभरा है। आज मैं मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देना चाहता हूं, क्योंकि हम हथकरघा के पुनरुत्थान का जश्न मना रहे हैं। हथकरघा बुनाई एक विरासत वाली शिल्पकला है, जो निरंतर और नैतिक फैशन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है।

महिलाओं का योगदान | हथकरघा क्षेत्र sustainability को बढ़ावा देने के अलावा, महिलाओं और हाशिए पर पहुंच चुके समुदायों को सशक्त बनाने, उनके लिए आर्थिक संभावनाएं प्रदान करने और अपनी शिल्पकला पर उन्हें गर्व करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में कताई, रंगाई और बुनकर के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके बिना इस सेक्टर के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती।

समूह की ताकत | हथकरघा क्षेत्र में महिला-नेतृत्व वाली कई सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह हैं। ये संगठन न केवल प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि एक सहायता नेटवर्क भी प्रदान करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह एकजुट होकर अपने उत्पादों की बेहतर कीमत के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, बड़े बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं, उचित मजदूरी और कार्य करने संबंधी उचित परिस्थितियां की भी मांग कर सकते हैं।

AI Image

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

क्वॉलिटी पर फोकस | बुनाई कौशल, डिजाइन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों और पहल ने महिलाओं को अधिक सशक्त बनाया है। नई तकनीक सीखकर और आधुनिक डिजाइन एक्सप्लोर करके महिलाएं अधिक गुणवत्ता वाले प्रॉडक्ट तैयार कर सकती हैं। इससे बाजार में उनके उत्पाद की पैठ बनेगी।

वैल्यू एडिशन | एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग से पारंपरिक वस्त्रों में नई जान आती है। इससे ऐसे प्रॉडक्ट तैयार होते हैं, जिनकी मांग ज्यादा है। जरदोजी, कांथा या चिकनकारी जैसी कलाओं के माध्यम से कारीगर साधारण हथकरघा वस्त्रों को अद्वितीय टुकड़ों में बदल देते हैं। इससे सुंदरता के साथ कीमत भी बढ़ जाती है।

टेक्नॉलजी की मदद | हथकरघा उद्योग में टेक्नॉलजी और इनोवेशन के इस्तेमाल से बुनकरों का काम आसान हुआ है। यह प्रॉडक्शन बढ़ाने और इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हथकरघा बुनाई में शारीरिक ताकत कम लगती है। कंप्यूटर के जरिए डिजाइन बनाना आसान हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों ने बुनकरों को बड़े बाजार तक पहुंचा दिया है।

सम्मान का समय | राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मैं आपसे दो प्रतिज्ञा लेने का आग्रह करता हूं। पहली प्रतिज्ञा, हम सभी हथकरघा उत्पादों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, हथकरघा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। हर हथकरघा वस्तु अद्वितीय है, जिसे सावधानी और बारीकी से बुना जाता है, जो इसे बनाने वाले के समर्पण और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

सुख कहां छिपा है, बता गए बुद्ध, कबीर और ईसा

अमित वर्मा

हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की खोज करता है। इसकी वजह है कि दुख, अज्ञात डर और असंतोष मानव जीवन का एक अटल हिस्सा बन गया है। इनसे मुक्ति पाना कौन नहीं चाहता? लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि उस दुख की पहचान कैसे हो, उसके कारणों तक कैसे पहुंचा जाए? यह पता चल जाए तो उससे छुटकारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। इस दिशा में महान संतों और विचारकों ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है।

गौतम बुद्ध ने दुख की पहचान और मुक्ति के लिए 'चार आर्य सत्य' का सिद्धांत दिया। पहला सत्य, दुख एक वास्तविकता है जो जीवन के हर पहलू में मौजूद है। दूसरे सत्य के अनुसार, दुख का कारण अज्ञानता, लालच और क्रोध है। तीसरे सत्य के अनुसार, दुख की समाप्ति संभव है। चौथे सत्य के अनुसार, दुख से मुक्ति पाने के लिए ध्यान, सही आचरण और सही विचार आवश्यक है। अपने भीतर की इच्छाओं और असंतोष को समझकर हम उन्हें नियंत्रित करते हैं, और तब हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।

गुरु नानक देव जी ने ध्यान और भक्ति को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। उनका कहना है कि जब हम भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम में रम जाते हैं, तब संसार की अस्थायी समस्याओं से परे निकल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि आत्मा की शुद्धता और सचाई के माध्यम से हम दुख को पार कर सकते हैं। कबीर दास ने भी दुख की पहचान और मुक्ति के विषय में सरल, लेकिन गहन उपदेश दिए। उन्होंने जीवन की अस्थिरता और उतावलेपन की ओर ध्यान दिलाया। कबीर ने कहा है, 'साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।' इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को ऐसे सरल और स्वच्छ तरीके से जीना चाहिए जैसे कि सूप अच्छी चीजों को छांट कर निकाल देता है। कबीर ने यह भी कहा है कि जब हम अपने भीतर की बुराइयों और अशांति को समझकर त्याग देते हैं, तब हम शांति प्राप्त कर सकते हैं।

ईसा मसीह ने अपने उपदेशों में दुख की पहचान और उससे मुक्ति के लिए अपने आपको ठीक करने और प्रेम की जरूरत पर जोर दिया। दुख का मूल कारण मानव के भीतर का आत्मिक असंतोष और अन्याय है। ईसा मसीह ने कहा है, 'अपने पड़ोसी से प्यार करो, जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो। अगर हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाएंगे, तो आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।' दुख का सामना करने के लिए उन्होंने प्रार्थना और आत्म-निरीक्षण की जरूरत पर बल दिया।

इन चीजों को अपने मन में गुनें तो समझ आता है कि दुख की पहचान और उससे मुक्ति का मार्ग एक आत्मिक यात्रा है। जब हम अपने भीतर के दोषों, इच्छाओं और असंतोष को समझते हैं, और सचाई, प्रेम और ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, तब हम वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने मन और सोच की अस्थिरता का भी परिणाम है। इसलिए अगर हम वास्तव में दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के कारणों को समझना होगा। आत्मनिरीक्षण, करुणा और सचाई के पथ पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली ● बुधवार ● 7 अगस्त ● 2024
www.rashtriyasahara.com

भंवर में बांग्लादेश

बांग्लादेश में कुछ महीनों से आरक्षण को लेकर छात्रों का असंतोष इतना व्यापक हो गया कि 15 बरसों देश की सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा। अब बांग्लादेश में शासन सेना के हाथ में है। जनवरी, 2024 में हसीना ने लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल किया था लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टर मुस्लिम संगठन जमायते इस्लामी परोक्ष रूप से छात्र असंतोष को हवा दे रहे थे। जाहिर है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों से

हसीना सरकार को सख्ती से निपटना पड़ा। लेकिन यह सख्ती सरकार के लिए महंगी साबित हुई। जनाक्रोश बढ़ता गया और शेख हसीना के पसंदीदा सेना प्रमुख जनरल वकार-उजा-जमां भी उनकी सरकार को बचा नहीं पाए। हसीना सरकार के पतन से यह मिथक भी टूट गया कि देश का आर्थिक विकास शासनाध्यक्ष की सत्ता को स्थिरता प्रदान करता है। वस्तुतः हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश आर्थिक विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ लगा रहा था। करीब पचास वर्ष पूर्व जाने-माने अमेरिकी समाज विज्ञानी प्रो. हंटिगटन और नेल्स ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जो आज बांग्लादेश पर सही साबित हो रही है। इन विद्वानों का मत है कि विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक समानता एवं जनसहभागिता के मध्य संघर्ष होता है। सामाजिक-आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन कायम करने में हसीना विफल रहीं। विपक्षी दलों द्वारा आम चुनाव का बहिष्कार, छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन को बलपूर्वक दबाना आदि सरकार के दमनकारी कृत्यों के कारण हसीना का पंद्रह वर्षों का शासन अचानक धराशायी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जनता 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के पक्ष और विपक्ष में बंट गई। हसीना का प्रदर्शनकारियों को 'रजाकर' कहने ने आग में घी का काम किया। रजाकर उन्हें कहा जाता है जो मुक्ति संघर्ष के विरोध में थे। हसीना के कामकाज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन वह सेक्युलर नेता थीं। विडंबना है कि देश की नई पीढ़ी मुक्ति संघर्ष का अपमान कर रही है।

दिल्ली में फिर खींचतान

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उपराज्यपाल को एमसीडी में दस एल्डरमैन नामित करने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा वह (उपराज्यपाल) मंत्रीपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के दरम्यान तनावपूर्ण संबंधों पर असर डालने वाले फैसले में पीठ ने कहा कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम कानून उपराज्यपाल को निगम की विशेष जानकारी रखने वालों को नामित करने का विशेष अधिकार देता है। शक्ति संदर्भ में यह स्पष्ट है कि उपराज्यपाल को कानून के अनुसार काम करना होता है न कि मंत्रीपरिषद की सलाह के अनुसार। यह राज्यपाल का वैधानिक कर्त्तव्य है, न कि राज्य की कार्यकारी

शक्ति। एमसीडी में ढाई सौ निर्वाचित और दस नामित सदस्य हैं। दिसम्बर, 2022 में नगर निगम चुनाव में आप ने 134 वार्ड जीत कर भाजपा के पंद्रह साल के शासन को खत्म कर दिया था। आप के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। सिंह ने कहा कि यह चुनी गई सरकार पर एलजी के अधिकारों को तवज्जो देने वाला फैसला है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कहा उन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता विभिन्न मामलों में इस वक्त जेल में हैं जिससे सरकार के काम-काज में पहले ही खासी दिक्कत आ रही है। दूसरे जब से दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ आई है, तब से उसकी लगातार केंद्र और उपराज्यपाल से ठनी रहती है। दोनों कई बार पहले भी अदालत की शरण जा चुके हैं। यह कहना गलत नहीं है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को काम-काज की पूरी छूट होनी चाहिए। इसमें नियमों/कानून की अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसलिए लगातार विवाद उभरते रहते हैं जो लोकतंत्र के लिए चुनौती हैं। अधिकार क्षेत्र या विकास कार्यों को लेकर उठने वाले विवादों के निपटारे के लिए पारदर्शी नियम बनाए जाने की जरूरत है। सरकार को भी अपने फैसलों में एलजी के अधिकारों का अतिक्रमण करने से बचना सीखना होगा। दरअसल, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तभी से केंद्र और उसके बीच जब-तब मसले और मामले और विवाद उभरते रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों तरफ परस्पर विवेकपूर्ण रवैया अपनाया जाए।

हरियाली तीज/श्वेता गोयल

शिव-पार्वती को समर्पित पर्व

हिन्दू धर्म में 'तीज' पर्व का बहुत महत्त्व है, जो साल भर में तीन बार आता है। सबसे पहले आती है सावन के महीने में 'हरियाली तीज', उसके कुछ ही दिन बाद 'कजरी तीज' और फिर 'हरतालिका तीज'। तीनों ही तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं, और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। हर साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला हिन्दू महिलाओं का महत्त्वपूर्ण त्यौहार है 'हरियाली तीज', जिसका वर्णन सनातन शास्त्रों में भी मिलता है। यह शिव-पार्वती की पूजा के साथ महिलाओं के सजने-संवरने और खुशियां मनाने का पावन त्यौहार है।

हिन्दू धर्म में हरियाली तीज को महत्त्वपूर्ण व्रतों में से गिना जाता है। सनातन धर्म में हरियाली तीज का व्रत अपार भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन माता पार्वती को 107 जन्मों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि कई राज्यों में सुहागिन हिन्दू महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर हरियाली तीज मनाती हैं। तीज पर्व उस दिन की याद में मनाया जाता है, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, जिसके कारण पार्वती को 'तीज माता' के रूप में पूजा जाने लगा। हरियाली तीज में बरगद (वट) वृक्ष की परंपरा बहुत महत्त्वपूर्ण है, घरों में तथा वट वृक्ष की शाखाओं पर झूले डाले जाते हैं, जिन पर महिलाएं झूला झूलती हैं, नृत्य करती हैं और लोक गीत गाते हुए खुशियां मनाती हैं। हिन्दू पौराणिक कथाओं में वट वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है, जो ज्ञान का प्रतीक है और हरियाली तीज पर इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के दौरान महिलाएं कठोर निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को चंद्रमा की पूजा के साथ व्रत का समापन किया जाता है।

अनमोल वचन

जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है।
-गौतम बुद्ध

editpagesahara@gmail.com

कट्टरपंथियों की वापसी

बांग्लादेश

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

बांग्लादेश में राजनीति बंद, विरोध, गरीबी और आतंकवाद से बाहर निकल कर विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटते ही अब वह सफर थम जाने का अंदेशा है। बांग्लादेश की राजनीति में दूसरा बड़ा चेहरा खालिदा जिया हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की यह नेता अब ताकतवर होंगी। खालिदा को जहां कट्टरपंथी ताकतों का समर्थक माना जाता है वहीं हसीना उदार और भारत समर्थक मानी जाती हैं। बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में भारत समर्थन और भारत विरोध की शक्तियां समानांतर कार्य करती हैं। इस साल बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री हसीना ने सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो भारत के साथ सहयोग जारी रहेगा। यह भी स्पष्ट भी किया गया था कि भारत के साथ भूमि सीमाओं के सीमांकन और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने अपने क्षेत्र में उग्रवादियों, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों और अलगाववादी समूहों की उपस्थिति को रोकने के लिए दृढ़ता दिखाई और इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति की स्थापना में बड़ी मदद मिली।

खालिदा की राजनीति भारत के हितों पर चोट करने वाली और पाकिस्तान के ज्यादा करीब नजर आती है। करीब डेढ़ दशक पहले बीएनपी सरकार के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों को बड़ी मदद मिली। बीएनपी की जमात और इस्लामिक कट्टरपंथियों से पुरानी करीबी है। खालिदा की सहयोगी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी माना जाता है। जेआईबी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के गठबंधन का सदस्य रह चुकी है। 1971 में स्वतंत्रता युद्ध में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में यह बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुटकर एक सक्रिय दल के रूप में उभरा। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है, जिसने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान जैसे नारे गढ़े हैं। यह इस्लाम के कट्टर और रूढ़िवादी रूप को बांग्लादेश में लाना चाहता है। जमात-ए-इस्लामी का सहयोगी संगठन है हुजी। हरकत-उल-जिहाद-अल इस्लामी बांग्लादेश नामक यह आतंकी संगठन कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानता रहा है। इस संगठन की मांग है कि बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट में बदल दिया जाए। हुजी-बी का लक्ष्य बांग्लादेश में युद्ध छेड़कर और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की हत्या करके इस्लामी हुकूमत स्थापित करना है।

दो दशक पहले भारत के गृह मंत्रालय

ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसका शीर्षक था-पाकिस्तान के वैकल्पिक परोक्ष युद्ध का आधार। इसमें पाकिस्तान द्वारा अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए चलाए गए नये ऑपरेशन के बारे में उल्लेख था। इस दस्तावेज में खास तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान अपने भारत विरोधी अभियानों के लिए बांग्लादेश को एक नये आधार के रूप में विकसित कर रहा है। इस बात का भी खुलासा था कि पाकिस्तान ने लगभग 200 आतंकवादी प्रशिक्षण कैंपों को पहले ही अपने यहां से हटाकर बांग्लादेश में व्यवस्थित करवा चुका है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों के कारण हूजी को जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हूजी कार्यकर्ता कथित तौर पर भारत के पूर्वी गलियारे में अक्सर घुसपैठ करते हैं ताकि क्षेत्र के आतंकवादी और विध्वंसक संगठनों के साथ संपर्क बनाए रख सकें। हूजी को भारत में कई स्थानों पर आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। यह अलकायदा तथा तालिबान मिलिशिया से मजबूत संबंधों के बूते दक्षिण एशिया के कई देशों में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में मुजाहिदीन के साथ लड़ने के लिए बड़ी संख्या में मुजाहिदीन अफगानिस्तान गए थे। 1990 के दशक में बेगम खालिदा जिया के राजनीतिक दल बीएनपी शासन के दौरान इनमें से बड़ी संख्या में मुजाहिदीन बांग्लादेश लौट आए और अब देश में कट्टरपंथी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हूजी के असम से भी संबंध हैं। हूजी कथित तौर पर बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी इलाकों में स्थित उल्फा के कुछ शिविरों का प्रबंधन करता है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा पर स्थित हैं। बांग्लादेश में हुजी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी जैसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है। हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश अर्थात हूजी देवबंदी समूह है, जो पाकिस्तान स्थित हूजी से संबद्ध है और इसका गठन 17 बांग्लादेशी मुजाहिदीन द्वारा किया गया था। इनका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है।

करीब चार हजार किमी. लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा भौगोलिक और सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट रही है। इसका फायदा आईएसआई खूब उठाती है और कई इलाकों में भारत के विरुद्ध विद्रोही संगठनों को आश्रय और प्रशिक्षित करके भारत पर हमले करने के लिए प्रेरित करती है। जब से अवामी लीग की सरकार आई वह चरमपंथी संगठनों को दबाने की कोशिश कर रही थी और इसमें कुछ कामयाबी भी मिली थी। आम तौर पर बांग्लादेश में हिन्दुओं को अवामी लीग गठबंधन का समर्थक बताया जाता है, और इसी कारण अल्पसंख्यक हिन्दू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के निशाने पर होते हैं। बांग्लादेश में इस साल हुए आम चुनाव में अवामी लीग की जीत के बाद वहां जिस तरह से विपक्ष द्वारा इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया और उसे व्यापक समर्थन मिल रहा था, उससे देखते हुए कहा जा सकता है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। ये स्थितियां भारत के लिए आंतरिक और सीमाई सुरक्षा का संकट बढ़ा सकती हैं, और इससे सतर्क रहने की जरूरत है।

https://t.me/AIINewsPaper

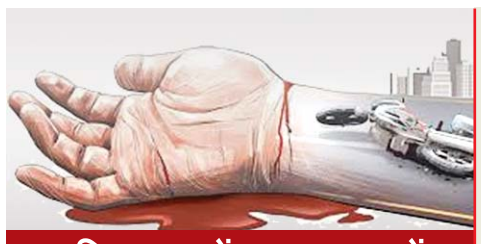

दुनिया भर में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 12 फीसद भारतीय

- दुनिया भर में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में करीब 12 फीसद भारतीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने 'वॉर्ल्ड रिपोर्ट' के हवाले से बताया है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 38.31 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है
- आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के. के. कपिला के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। सड़क हादसों में जानलेवा मामलों में करीब 31.4 फीसद लोगों की मौत मुख्य रूप से सिर में चोट लगने से होती हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

शेख हसीना ने कथित रूप से चुनाव में तिकड़मबाजी की और इस प्रकार वहां हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। तमाम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए यह संदेश है कि जनादेश का सम्मान हर सूरत में किया जाना जरूरी है। जय हिन्द।

सबा नकवी, लेखिका
@_sabanaqvi

जेनेटिक सरसों | पंकज चतुर्वेदी

अधर में लटका मसला

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जेनेटेकली मोडिफाइड अर्थात जीएम सरसों की भारत में व्यावसायिक खेती करने की सरकारी मंजूरी के खिलाफ याचिका पर खंडित फैसला दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना का आकलन था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) की 18-25 अक्टूबर, 2022 को संपन्न जिस बैठक में इसकी मंजूरी दी गई, वह दोषपूर्ण थी क्योंकि उस बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे। जस्टिस संजय करोल का मानना था कि जीईएसी के फैसले में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने जीएम सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ने की बात जरूर की। हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि केंद्र सरकार को आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार चाहिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाएगा। वैसे जीईएसी आनुवंशिक रूप से जीएम फसलों के लिए देश की नियामक संस्था है। लेकिन दो जजों की पीठ ने सुझाव दिया है कि चार महीने के भीतर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जीएम फसल के सभी पक्षों, जिनमें कृषि विशेषज्ञों, जैव प्रौद्योगिकीविद्, राज्य सरकारों और किसान प्रतिनिधियों सहित हितधारक शामिल हों, के परामर्श से जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे।

किसी से छुपा नहीं है कि भारत में खाद्य तेल की जबरदस्त मांग है लेकिन 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद भारत को 141.93 लाख टन का आयात करना पड़ा। अनुमान है कि 2025-26 में यह मांग 34 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। हमारे खाद्य तेल के बाजार में सरसों के तेल की भागीदारी कोई 40 फीसद है। ऐसा दावा किया गया कि यदि सरसों उत्पादन में जीएम बीज का इस्तेमाल करेंगे तो फसल 27 प्रतिशत अधिक होगी जिससे तेल की आयात का खर्च काम होगा। हालांकि यह तो सोचना होगा कि 1995 तक देश में खाद्य तेल की कोई कमी नहीं थी। फिर बड़ी कंपनियां इस बाजार में आईं। उधर आयात कर काम किया गया और तेल का स्थानीय बाजार बिल्कुल बैठ गया। दावा यह भी है कि इस तरह के बीज से पारंपरिक किस्मों की तुलना में कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, और मुनाफा अधिक। लेकिन जीएम फसलों खासकर कपास को लेकर हमारे

पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसे बीजों की दूरगामी परिणाम खेती और पर्यावरण, दोनों के लिए भयावह हैं। समझना होगा कि जीएम फसलों को उत्पाद के मूल जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है। इसके लिए आम तौर पर किसी अन्य जीव से आनुवंशिक सामग्री डाली जाती है जिससे उन्हें नये गुण दिए जा सकें। ये गुण अधिक उपज, खरपतवार कम करने, किसी कीट से लगने वाली बीमारी और कम पानी या फिर बेहतर पोषक तत्व आदि हो सकते हैं। देश में अभी तक कानूनी रूप से केवल बीटी कपास एकमात्र जीएम स्वीकृत फसल है। बीते 17 सालों में कपास की बीज दावों पर खरे उतरे नहीं। बीटी बीज देशी बीज की तुलना में बहुत महंगा है और दावे के विपरीत इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना ही पड़ा। फसल तो ज्यादा हुई नहीं, लेकिन अब हर साल बीज बाजार से खरीदने की मजबूरी हो गई। विकसित देश बानगी हैं कि इस तरह के बीजों से खेतों की उर्वर क्षमता कम हुई है। पौष्टिक तत्व भी कम हुए हैं।

दुनिया भर में कहीं भी बीटी फसल को खाद्य पदार्थ के रूप में मंजूरी नहीं मिली है। यूरोप में भी इस पर सख्त पाबंदी है। ऐसे में भारत में लोकप्रिय और आम आदमी के इस्तेमाल वाले सरसों के तेल के लिए बीटी पर मंजूरी संदेह पैदा करती है। समझना होगा कि इस तरह के बीजों से उत्पन्न सरसों के फूल मधुमक्खियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मधुमक्खियां शहद के लिए ज्यादातर रस सरसों के फूलों से ही प्राप्त करती हैं। सरसों की खेती में इस तरह के बीजों से उत्पन्न फूलों में मधुमक्खियों को परागण तो मिलेगा नहीं, उलटे कुछ जानलेवा कीट की वे शिकार हो जाएंगी।

समझ लें कि जीएम बीज हमारे पारंपरिक बीजों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं, और अब बदले हुए नाम से जीएम फसलों के लिए बैंगन-टमाटर आदि के लिए पिछले रास्ते से घुसाया जा रहा है। केंद्र सरकार कोई दो साल पहले जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नई फसल प्रजातियां विकसित करने के शोध को मंजूरी दे चुकी है। जीनोम एडिटेड प्लांट्स की एसडीएन-1 और एसडीएन-2 श्रेणियों के नियमन की समीक्षा (रेग्युलेटरी रिव्यू) के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) को 4 अक्तूबर, 2022 को अधिसूचित किया जा चुका है। इसमें बेहद चालाकी के साथ जीएम के नाम पर जीन एडिटिंग तकनीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे यूरोपीय यूनियन में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जीन एडिटिंग तकनीकी और जीएम फसल अलग नहीं हैं। जाहिर है कि अदालतें जब जीएम बीजों पर कोई फैसला देंगी तो उसी समय जीनोम एडिटेड प्लांट्स के नाम से ये बीज बाजार में घूम रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित होने वाली कमेटी में नई तकनीक को युरोपियन यूनियन की तरह जीएम मानना होगा।

भक्ति | सद्गुरु

अंग्रेजी में 'डिवोशन' (भक्ति) शब्द 'डिसोल्यूशन' शब्द से बना है जिसका अर्थ है: विसर्जन। जब हम भक्त कहते हैं, तो भक्त का अपना कोई मकसद नहीं होता। उसका एकमात्र मकसद उस चीज में विसर्जित हो जाना होता है जिसकी वह भक्ति कर रहा है, बस। वह अच्छी तरह से रहने के बारे में नहीं सोच रहा है। धनी होने के बारे में भी नहीं सोच रहा है।

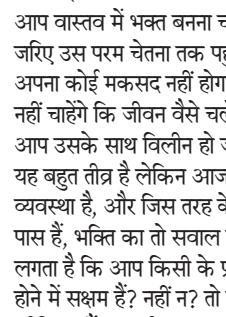

स्वर्ग जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा है। मान लीजिए वह भगवान शिव का भक्त है। इसका मतलब है कि बस शिव में ही विलीन हो जाना चाहता है, शिव में ही समाप्त हो जाना चाहता है। बस यही है, जो वह जानता है। क्या आप ऐसे हैं? आपके लिए तो भक्ति एक मुद्रा यानी 'करेंसी' की तरह है। भक्ति आसान जीवन जीने के लिए एक मुद्रा की तरह है। इस दुनिया में होने वाली प्रार्थनाओं को देखिए। निन्यानवे फीसद प्रार्थनाओं में क्या होता है? मुझे यह दे दो, वह दे दो। मुझे बचा लो, रक्षा करो। यह भक्ति नहीं है, सौदा है। आप एक मूर्खतापूर्ण सौदा करने की कोशिश में लगे हैं। तो अगर आप वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं, और भक्ति के जरिए उस परम चेतना तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका अपना कोई मकसद नहीं होगा, कोई एजेंडा नहीं होगा। आप नहीं चाहेंगे कि जीवन वैसे चले जैसा आप चाहते हैं। आप उसके साथ विलीन हो जाना चाहेंगे, बस। अगर आप ऐसे हैं तो भक्ति आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है। अगर आप वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं, और भक्ति के जरिए उस परम चेतना तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका अपना कोई मकसद नहीं होगा, एजेंडा नहीं होगा। आप नहीं चाहेंगे कि जीवन वैसे चले जैसा आप चाहते हैं। आप उसके साथ विलीन हो जाना चाहेंगे, बस। वास्तव में यह बहुत तीव्र है लेकिन आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, और जिस तरह के तार्किक दिमाग लोगों के पास हैं, भक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने में सक्षम हैं? नहीं न? तो इस बारे में बात मत कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपमें भक्ति का अंश बिल्कुल है ही नहीं। आपके भीतर जितनी भक्ति है उससे हो सकता है कुछ मकसद हल हो जाए, लेकिन यह आपको उस परम अवस्था तक नहीं पहुंचा सकती।

रीडर्स मेल

बांग्लादेश में तख्तापलट

बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। तीखे विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। यह भारत से अधिक हो गई है। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,250.18 डॉलर थी। आईएमएफ के अनुसार, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,621 अमेरिकी डॉलर है जबकि भारत की 2,612 अमेरिकी डॉलर है। फिर भी क्यों बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं? बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़क चुकी है। यह घटनाक्रम उन लोगों के लिए सबक है, जो लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं। बैक डोर से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी, भूख और अत्याचार की मार झेल रहे अवाम की ताकत को झेलना नामुमकिन है। तानाशाही की उमर बहुत छोटी होती है। तानाशाही नहीं चलेगी...नहीं चलेगी, क्योंकि जब लोकतंत्र उलट, तब तख्ता पलट।

सूर्यदीप कुशवाहा, ईमेल से

गूगल को एकाधिकारवादी बताया

टेक दिग्गज शीर्ष स्थान में बने रहने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं, जिसे निष्पक्ष व्यवहार तो नहीं ही कहा जाएगा। तभी तो अमेरिकी न्यायाधीश अमित मेहता ने सर्च एंटी ट्रस्ट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 'गूगल को एकाधिकारवादी' कंपनी की उपाधि दी है। एक संघीय न्यायाधीश ने निर्धारित किया है कि सर्च और टेक्स्ट विज्ञापन बाजारों में गूगल का अवैध एकाधिकार है। यह निर्णय तकनीकी उद्योग विनियमन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है, जो दशकों में किसी तकनीकी दिग्गज के खिलाफ पहला एकाधिकार-विरोधी निर्णय है। 2020 में शुरू किए गए इस ऐतिहासिक मामले में तर्क दिया गया कि गूगल ने प्रवेश में बाधाएं पैदा करके और एक आत्मनिर्भर फीडबैक लूप को बढ़ावा देकर सर्च मार्केट में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि गूगल की प्रथाओं ने शेरमेन अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन किया जो एकाधिकारवादी कार्यों को प्रतिबंधित करती है। अब देखें इस नवीनतम फैसले के बाद गूगल सुधरता है कि और अधिक एकाधिकारवादी बन जाता है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

कमल राष्ट्रीय भावना का प्रतीक

कमल सनातन और सनातन से उपजी हर आस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना के प्रतीकों में से एक है। ज्ञान, शक्ति, अर्थ, तीनों की देवियों, त्रिदेवों, बौद्धों, जैनों, सिखों से यह कमल किसी न किसी प्रतीक रूप में आवश्यक रूप से जुड़ा है। साथ ही यह राष्ट्रीय पुष्प के रूप में संविधान में भी स्वीकृत है। इस कमल को कौरव प्रयुक्त चक्रव्यूह के शातिरों से जोड़कर नेता प्रतिपक्ष मोदी विरोध में इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि सनातनी परंपरा और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सीधे आघात कर रहे हैं। कहीं यह दांव उल्टा न पड़ जाए? नेता प्रतिपक्ष के मार्क्सवादी विचारों वाली इन आलोचनाओं ने इतना अवश्य किया है कि रामायण, महाभारत, गीता समेत पुराणों को सुर्खियों में लाकर नई पीढ़ी को इसे नये सिरे से पढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उनके कहे का असर प्रतिगामी न होने पाए।

मनोज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, उप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्त्तव्य ● समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 355 | आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

विफल होता चीता प्रोजैक्ट

भारत में चीता प्रोजैक्ट को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी के पांच शावकों में से एक शावक की मौत हो गई। जांच के बाद पाया गया कि चीता शावक की रीढ़ की हड्डी में फैक्चर था। 10 मार्च को गामिनी ने पांच शावकों को जन्म दिया था तब केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने काफी खुशी जाहिर की थी। शावकों के जन्म के बाद 4 जून को भीषण गर्मी की वजह से एक शावक की मौत हो गई थी। अब दूसरे शावक की मौत के साथ ही कूनो नेशनल पार्क में अभी तक कुल 12 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 चीते और 5 शावक शामिल हैं। मादा चीता गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क को प्रोजैक्ट चीता के लिए चुना गया था और यहां विदेश से चीते लाकर छोड़े गए थे। शावकों की लगातार मौत के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या भारत का चीता प्रोजैक्ट असफलता की ओर बढ़ रहा है या फिर यह जमीनी हकीकत से दूर है। देखा जाए तो प्रोजैक्ट चीता के मिलेजुले परिणाम ही सामने आए हैं। भारत में चीता वापसी की परियोजना सितम्बर 2022 में शुरू की गई थी। 1952 में देश को चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीतों को विशेष विमान से नामीबिया से भारत लाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितम्बर, 2022 को कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीतों को छोड़ा था लेकिन प्रोजैक्ट चीता को शायद किसी की नजर लग गई। वर्ष 2023 में जुलाई तक 4 महीनों के भीतर 8 चीते चल बसे और लगातार हो रही चीतों की मौत चिंता का विषय बन गई है। प्रोजैक्ट के दूसरे चरण 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया लेकिन संक्रमण के कारण एक के बाद एक चीतों की मौत होती गई। हालांकि पार्क में 13 व्यस्क चीते और 12 शावक स्वस्थ और सामान्य हैं लेकिन चिंताएं अभी बनी हुई हैं। ऐसे में पर्यावरणविद प्रोजैक्ट चीता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे लापरवाही बता रहे हैं तो अनेक लोग इसे कूनो नेशनल पार्क इनके लिए उपयुक्त स्थान ही नहीं माने रहे।

> **चीतों की मौत का कारण बीमारी, संक्रमण, किडनी संक्रमण आदि रहे। सबसे बड़ा कारण गर्मी को भी माना गया जिससे चीतों की देखभाल में मुख्य चुनौती आई। भारत में गर्मी और मानसून के मौसम में चीतों ने अपने शरीर पर मोटी फर विकसित कर ली थी। अधिक उमस और तेज तापमान में चीते परेशान होकर पेड़ों के तनों या जमीन पर अपनी गर्दन रगड़ते थे, जिनसे उनकी खाल फट जाती थी और उन्हें विषाणु संक्रमण हो जाता था। कुछ चीतों की मौत आपस में हिंसक हो जाने के कारण हुई। दरअसल चीते भारत की जलवायु के अनुरूप खुद को ढाल ही नहीं पाए। चीतों की गर्दन में लगाए गए रेडियो कॉलर भी संक्रमण का कारण बने।**

कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए उपयुक्त जगह है या नहीं? इस पर बात करते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि कूनो के अलावा राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी चीतों के लिए वैकल्पिक आवास हो सकता है लेकिन जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते। लगातार हो रही मौतों के बारे में विशेषज्ञों का भी कहना यह है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 12 चीतों को भारत को देने के लिए 7 महीने का समय लगा लिया। इस दौरान चीतों को वहां भी कैद में रखा गया था, जब इन्हें भारत लाया गया तो दोबारा दो महीने के लिए कैद में रखा गया। इस तरह कुल 9 महीने उन्हें कैद में रहना पड़ा। इस कारण उनका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा।

चीतों की मौत का कारण बीमारी, संक्रमण, किडनी संक्रमण आदि रहे। सबसे बड़ा कारण गर्मी को भी माना गया जिससे चीतों की देखभाल में मुख्य चुनौती आई। भारत में गर्मी और मानसून के मौसम में चीतों ने अपने शरीर पर मोटी फर विकसित कर ली थी। अधिक उमस और तेज तापमान में चीते परेशान होकर पेड़ों के तनों या जमीन पर अपनी गर्दन रगड़ते थे, जिनसे उनकी खाल फट जाती थी और उन्हें विषाणु संक्रमण हो जाता था। कुछ चीतों की मौत आपस में हिंसक हो जाने के कारण हुई। दरअसल चीते भारत की जलवायु के अनुरूप खुद को ढाल ही नहीं पाए। चीतों की गर्दन में लगाए गए रेडियो कॉलर भी संक्रमण का कारण बने। चीतों को दवा देने के लिए भगाने, पकड़ने और बाड़ों में वापस लाने से तनाव और मौत का जोखिम भी कम नहीं है।

चीतों को धरती पर सबसे तेज रफ्तार जानवर माना जाता है। महज 3 सैकेंड के अंदर ये जीरो से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। चीते विशाल इलाके में रहना पसंद करते हैं। एक चीते की औसत रेंज लगभग 100 किलोमीटर होती है। उन्हें बाड़े से छोड़ने पर वे दूर तक निकल जाते हैं। यही वजह है कि मार्च में जब नामीबिया से लाए गए दो चीते आशा और पवन को जंगल में छोड़ा गया था तब वो नेशनल पार्क से बाहर चले गए थे। बाद में आशा को कूनो के विजयपुर रेंज से पकड़ा गया। पवन यूपी बॉर्डर पर शिवपुरी और झांसी के बीच मिला था। एक ये बात भी निकलकर आई कि भारत में अभी कोई चीता एक्सपर्ट नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी जो अधिकारी चीतों की देखभाल कर रहे हैं वे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि सरकार को भी अंदाजा है कि कूनो इन चीतों के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन ये सवाल भी है कि भारत में चीता प्रोजैक्ट कितना सफल रहा, इसका जवाब ढूंढने में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय को चीतों की जान बचाने के लिए उनके अनुकूल जगह ढूंढकर व्यवस्था करनी होगी और भारत के मौसम के अनुकूल उन्हें ढालने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे, अन्यथा चीता फिर भारत में विलुप्त हो जाएगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

एक साथ स्वतंत्र हुए दो देशों की...

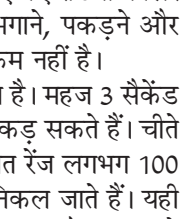
गीता पाढा

जहां आज भी भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का गुणगान है,
वहीं पड़ोसी मुल्कों में तख्तापलट को लेकर घमासान है,
एक साथ स्वतंत्र हुए दो देशों की विश्व में अलग-अलग पहचान है,
एक देश जाना जाता है मैत्री-भाव और बंधुत्व के लिए,
तो दूसरा बंटवारे और दहशतगर्दों को पनाह देने वाला स्थान है...!!

चंबा में भारी बारिश और तूफान

चंबा, (आईएएनएस): चंबा के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में सोमवार रात हुई बारिश और तूफान के कारण बड़े-बड़े पेड़ गिर गए। सर्किट हाउस के पास कई बड़े-छोटे पेड़ गिरने से बिजली की तारें और खंभे भी टूट गए। इससे सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। आपको बता दें कि यह मुख्य सड़क पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और डलहौजी की जीवन रेखा है।

इस बारे में नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला उन्होंने तुरंत मजदूरों को भेजकर पेड़ों को काटकर सड़क से हटा दिया और जल्द ही यह सड़क वाहनों के लिए खोल दी जाएगी। पिछले दिनों चंबा में भूस्खलन की चपेट में आकर मणिमहेश की यात्रा पर गए पांच श्रद्धालु घायल हो गये। उन्हें स्थानीय अस्पताल भेजा गया।

वक्फ बोर्ड नहीं घपला बोर्ड है यह !

फिरोज बख्त अहमद

आजकल वक्फ बोर्ड की खूब चर्चा है कि सरकार अब इस पर संशोधन लाने वाली है और इसकी जमीन कब्जाने की अपार शक्ति को नकेल डालने वाली है। इसको लेकर इंडी घटक के नेताओं ने अपना वही पुराना हिंदू-मुस्लिम खटराग गाना शुरू कर दिया है कि यह मुस्लिम विरोध में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 'वक्फ' अरबी भाषा के 'वकुफा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है 'ठहरना'। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट-जायदाद को जन-कल्याण के लिए समर्पित करना अर्थात बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मस्जिदों, मदरसों, शैक्षिक संस्थानों आदि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दान।

इस संशोधन से मुस्लिम समाज को बहुत सी ऐसी संपत्ति पुन: वापस मिल सकती है कि जिससे वे अपने जरूरतमंद बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग, देश-विदेश में शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और मुस्लिम विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं का गुज़ारा भत्ता दे सकते हैं। इससे वक्फ बोर्ड की उस प्रकार की दादागीरी भी समाप्त होगी जैसे चैन्नई में एक पूरे गांव को ही वहां के वक्फ बोर्ड ने अपनी बपौती बना दिया है, या एक ऐसे 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर पर कब्जे का दावा ठोक दिया है कि वह वक्फ जायदाद है, जबकि उस समय न तो इस्लाम आया था न ही वक्फ बोर्ड था।

इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है जो कुरान की सूरत 26, आयत 19 और सूरत 3, आयात 86 में दिया गया है कि जब तक धनाढ्य व्यक्ति इसे इस राह में नहीं लगाएंगे, अल्लाह उनसे खुश नहीं होगा। यही कारण है कि भारत में लगभग हजार साल से सुल्तान, बादशाह, नवाब व धनी मुस्लिम निर्धन लोगों के लिए जमीन व धन के रूप में दान करते चले आए हैं। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, ये चल-अचल दोनों तरह की हो सकती है। यह दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। पूर्ण भारत में नौ लाख एकड़ से भी ऊपर वक्फ संपत्ति है। वक्फ में भी दो प्रकार की संपत्ति होती है। प्रथम तो 'वक्फ अल्लाह' अर्थात अल्लाह के नाम में गरीबों हेतु और 'वक्फ-अल-औलाद' अर्थात औलाद के लिए वक्फ। वक्फ के पास काफी संपत्ति है, जिसका रखरखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए तो निर्धनों का बड़ा भला हो सकता है। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ हैं। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल हैं जो वास्तव में हो नहीं रहा।

वास्तव में इतनी अधिक भूमि होने के बावजूद मुस्लिम समाज को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है कि जब से वक्फ बोर्डों की भारत में स्थापना हुई है, तब से ही इनके पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने इसकी जमीनों को बेईमानी करके कौड़ियों के मोल बेचते रहे। उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी का जो 4535 मीटर में बना मकान, मुंबई की महंगी अल्टमाउंट रोड पर है, 2003 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मात्र 21.05 करोड़ में दे दिया, जिसकी असल कीमत उस समय 600 करोड़ थी। इसी प्रकार से बेंगलुरु में 'विंडसर मैनर' नामक एमजी रोड पर बने पांच सितारा होटल का किराया मात्र 12,000 रुपए जाता है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू आज 1100 करोड़ रुपए है।

पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध मुग़ल काल के बाज़ार, चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद के चारों ओर सैंकड़ों दुकानें हैं, जिनमें से हर दुकान 20-30 करोड़ से कम क़ीमत की नहीं है, मगर उनके किराए, कस्टोडियन के समय से 50, 100, 500 रुपए आदि दिए जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अफसरों ने पगड़ी के नाम में करोड़ों रुपए से अपनी जेबें भरी हैं और भर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 77 प्रतिशत ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर अख़बारों के दफ्तर, लुटियंस दिल्ली के मंत्रियों, सांसदों आदि के बंगले आदि शामिल हैं। इन सभी पर सरकार द्वारा क़ब्जे कर लिए गए और कोई देखने वाला नहीं, सिवाय एक सामाजिक कार्यकर्ता, अत्यब सिद्दीकी के, जिन्होंने उच्च न्यायालय की जनहित याचिका पर क़ौमी स्कूल, सराय खलील में न्यायमूर्ति गीता मित्तल के आदेश पर 4000 मीटर जमीन ओल्ड स्लॉटर हाउस, ईदगाह के पास वक्फ बोर्ड से दिलाई थी, जिस पर केजरीवाल दिल्ली सरकार का कब्ज़ा हो गया है।

अजमेर में तो दरगाह हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती (र.) के पूरे बाज़ार की मिल्कियत दरगाह ख्वाजा साहेब एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड की है। एक उदाहरण है, 'जन्नत निशान' होटल का, जिसको मार्केट रेट के अनुसार इस बहुमंजिला होटल का किराया कम से कम चार लाख रुपए महीना देना चाहिए, मात्र 11000 रुपए दे रहा है। इसमें सरकार द्वारा बनाई गई दरगाह कमेटी के सदस्य पैसा खाकर औने-पौने दामों पर किराया, पगड़ी आदि बांध देते हैं। यही हाल पूरे भारत का है। इस संशोधन में सरकार को देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की अधीकृत जमीन को छुड़ा कर पुराने वक्फ बोर्ड को समाप्त कर ईमानदार अफसरों का नया वक्फ बोर्ड स्थापित करें ताकि गरीब मुसलमानों को लाभ हो।

कोचिंग सेंटर हादसे होने ही नहीं चाहिए

राजेश माहेश्वरी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली और भारत सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना एक आंख खोलने वाली घटना है। किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये जगहें (कोचिंग सेंटर) मौत के चैंबर बन गए हैं। कोचिंग संस्थान ऑनलाइन काम कर सकते हैं जब तक कि सुरक्षा मानदंडों और जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूरी तरह से पालन न हो। दिल्ली के राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जो युवा सुनहरे भविष्य के लिए दिल्ली गये थे, उन्हें क्या पता था कि भ्रष्ट व्यवस्था और लालची व्यवस्थापकों की मिलीभगत उनकी जान ले लेगी।

तीन युवा छात्रों की पानी के तेज बहाव में, एक इमारत के बेसमेंट में फंस कर, मौत हो गई। यह आपदा या हादसा नहीं, हत्याकांड है। उस इमारत में आईएएस की कोचिंग देने वाला प्रख्यात केंद्र चलता है, जिसके बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं और युवा छात्रों को आकर्षित करते रहे हैं। यह केंद्र कोचिंग देने की फीस लाखों में लेता है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उस इमारत के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कानूनन अवैध है। जो छात्र बच गए हैं, उनकी नियति ही ऐसी थी, अलबत्ता पानी का बहाव किसी बाढ़ से कम नहीं था। वहां इतना तेज पानी कैसे घुसा? इसी सवाल के गर्भ में तमाम भ्रष्टाचार और कदाचार निहित हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पास मुखर्जी नगर की वह घटना आज भी याद आती है, जब आग से बचने के लिए युवा छात्रों ने खिड़कियों से ही छलांग लगा दी थी अथवा किसी रस्सी के सहारे, जलते हुए कमरे से, बाहर कूद पाए थे। कुछ मौतें भी हुई थीं। वहां भी आईएएस, आईपीएस बनने का सपना पाले युवा छात्र पढ़ते हैं। वहां भी बंद प्राय कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। राजेंद्र नगर के दुखद हादसे 4-5 दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में एक युवा करंट की चपेट में आकर मारा गया। वह भी आईएएस की तैयारी कर रहा था।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आईएएस कोचिंग सरीखे 550 से अधिक केंद्र दिल्ली में चल रहे हैं, जिनमें से 60-65 ही पूरी तरह 'वैध' हैं। अधिकतर इमारतों में अग्नि-सुरक्षा के न तो बंदोबस्त हैं और न ही प्रमाणपत्र हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मामला सेट है। इन हादसों के बाद अब प्रशासन ने इमारतों के ऑडिट करने का फैसला लिया है। उससे भी क्या होगा, क्योंकि प्रशासन ने ही आंखें मूंदी हुई हैं, कान भी बंद कर रखे हैं, संज्ञान पर सन्नाटा छाया है। दिल्ली में हादसे के बाद देश के अन्य राज्यों में भी कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी और कानून कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण 107 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें 20 अवैध बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को सील कर दिया गया। लखनऊ में अवैध बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी पर कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि, शहर में

करीब 2000 अवैध बेसमेंट वाली इमारतों पर कार्रवाई कब होगी, यह सवाल अब भी बना हुआ है। एलडीए के मुताबिक, नक्शा स्वीकृत कराए बिना और पास कराए नक्शे के सापेक्ष निर्माण न करना अवैध की श्रेणी में आता है। हजरतगंज, अमीनाबाद, तेलीबाग, चौक, आलमबाग और गोमती नगर की इन अवैध इमारतों में पार्किंग की जगह बेसमेंट बनाकर कमाई की जा रही है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा व अन्य नगरों में भी अवैध तरीके से बेसमेंट में चल रही कोचिंग को सील किया गया है।

राजस्थान की कोचिंग मंडी कहे जाने वाले कोटा में प्रशासन सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी कोचिंग एरिया में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। कोटा के स्थानीय प्रशासन ने बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद करने का आदेश दिल्ली की घटना के बाद दिया है। साथ ही लाइब्रेरी मालिकों को हिदायत दी गई है कि अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो लाइब्रेरी को सील कर दिया जाएगा।

दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में भी ग्रेटर निगम और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने गुलाबी नगरी जयपुर शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों को सख्त निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते दिनों जयपुर में 438 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों का पुलिस द्वारा निरीक्षण कर जांच की गई। जांच में 65 संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनियमितता पाई गई, जिसमें 31 संस्थानों को नोटिस देने एवं 38 संस्थानों के सील की कार्रवाई की गई।

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की सरकार ने भी कोचिंग सेंटर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। कमोबेश हर राज्य ने दिल्ली की घटना के बाद छात्रों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। असल बात यह है कि ये संवेदनशीलता किसी घटना के घट जाने के बाद ही नहीं, हमेशा दिखाने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन को समय-समय पर कोचिंग संस्थानों की जांच करती करते रहना चाहिए। दिल्ली में घटी घटना या फिर अन्य प्रदेशों में कोचिंग सेंटर में घटी ऐसी ही दुखद घटनाओं में कोचिंग संचालकों के साथ ही साथ व्यवस्था में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए, वहीं ऐसे लापरवाह, कानून के पालन में कोताही बरतने वाले और असंवेदनशील अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ उचित कानून एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी रहती है। लेकिन कोचिंग संचालकों की ऊंची पहुंच और भ्रष्ट व्यवस्था के चलते अवैध गतिविधियां धड़ल्ले से जारी रहती हैं और किसी घटना के बाद प्रशासन गहरी नींद से जागता है।

दिल्ली में हुए हादसे के बारे में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार, दोनों को इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं न होना, उसके लिए जरूरी उपाय और निर्णय करने होंगे। छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना सरकार और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए कारगर व्यवस्था करनी होगी। आखिरकार यहां सवाल देश के भविष्य का है।

ग्लेशियर पिघलने से बदल जाएगा बहुत कुछ

मेलबर्न, (द कन्वरसेशन): जैसे-जैसे वैश्विक तापमान साल-दर-साल बढ़ रहा है, दुनिया के ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। बर्फ की ये नदियाँ और यहां तक कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को ढकने वाली बड़ी बर्फ की चादरें पिघल रही हैं और पिघलने की गति तेज हो रही है।

केवल कुछ ही प्रजातियां होती हैं जो ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में रह सकती हैं, बर्फ के कीड़ों से लेकर बर्फ के पिस्सू और बर्फ के शैवाल तक। जब बर्फ पिघलती है तो इन प्रजातियों को उसके साथ पीछे हटना पड़ता है। लेकिन उन क्षेत्रों का क्या होता है जो ग्लेशियर पीछे छोड़ जाते हैं? क्या जीवन आगे बढ़ता है?

शोधकर्ताओं की हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पिछला दशक इस बात की जांच में बिताया है कि जब ग्लेशियर पर्वत शृंखलाओं की ओर पीछे हटते हैं तो नई खुली जमीन का क्या होता है। हमने ट्रैक किया कि 46 पीछे हटने वाले ग्लेशियरों पर क्या हो रहा है, हिमालय से लेकर एंडीज़ तक, स्वालबार्ड के आर्कटिक द्वीपसमूह से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक, और यहां तक कि मैक्सिको में उष्णकटिबंधीय ग्लेशियरों तक।

हमारे नए शोध से पता चला है कि जीवन इन नए आवासों में सूक्ष्मजीवों से लेकर हार्डी लाइकेन और काई तक, घास जैसी अग्रणी प्रजातियों तक तेजी से बसने के लिए आगे बढ़ता है। अधिक पौधे आते हैं और फिर, उनका अनुसरण करते हुए, जानवर आते हैं। समय के साथ, हमने देखा है कि नए पारिस्थितिकी तंत्र उभर कर सामने आए हैं। जब कोई ग्लेशियर पिघलता है, तो पीछे जो बचता है वह चट्टान और तलछट का बंजर परिदृश्य होता है। समय के साथ, ये क्षेत्र धीरे-धीरे एक जटिल और विविध हिमनदोत्तर पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाते हैं। हम यह जानना चाहते थे कि यह कैसे होता है, इसमें कितना समय लगता है, और जीवन नए निवास स्थान को कैसे बसाता है।

लगभग 14वीं और 19वीं शताब्दी के बीच, दुनिया 'लघु हिमयुग' की चपेट में थी, मध्यम शीतलन की अवधि जो बड़े पैमाने पर उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित कर रही थी। इस अवधि के दौरान, इस गोलार्ध में कई ग्लेशियरों का विस्तार हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन को नियमित रूप से जलाना, अधिक गर्मी को फंसाना और ग्रह को गर्म करना शुरू कर दिया, पहले धीरे-धीरे लेकिन अब तेज हो रहा है।

हमने अपने हिमनद परिदृश्यों को सावधानी से चुना, केवल उन ग्लेशियरों का चयन किया जहां हम स्थलाकृतिक मानचित्र, क्षेत्र माप, तस्वीरें, पेंटिंग, रिमोट इमेजिंग और फ़ील्ड डेटा सहित डेटा स्रोतों की एक शृंखला का उपयोग करके बर्फ के पीछे हटने की शुरुआत की सटीक तारीख बता सकते हैं। हमारी टीम ने दुनिया के कई हिस्सों को कवर किया, लेकिन हमने ध्रुवीय क्षेत्रों में कम सैंपलिंग की।

हमने अपने 46 ग्लेशियरों में 1,200 से अधिक भूखंडों से मिट्टी के नमूने एकत्र किए और प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी प्रजाति कब आई। हमने मिट्टी के गुणों और पोषक तत्वों

और पौधों द्वारा कार्बन कैप्चर के साक्ष्य का विश्लेषण करके पारिस्थितिकी तंत्र के गठन पर नज़र रखी। हमने स्थानीय जैव विविधता का आकलन करने के लिए पशु प्रजातियों द्वारा छोड़े गए डीएनए निशानों को पकड़ने के लिए पर्यावरणीय डीएनए नमूनाकरण तकनीकों का भी उपयोग किया।

हम तब प्रजातियों के आगमन को क्रॉस-रेफरेंस कर सकते हैं जब प्रत्येक ग्लेशियर पीछे हटना शुरू कर देता है। पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण का आश्चर्यजनक रूप से व्यापक पैटर्न। सबसे पहले आने वाले जीवनरूप सबसे छोटे थे। बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव जमीन पर निवास करते हैं। ये छोटे जीवनरूप अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध समुदाय बना सकते हैं। बड़ी प्रजातियों के आने से पहले सूक्ष्मजीवों द्वारा अपनी बस्तियां बसाने में लगभग एक दशक का समय लगता है। कुछ सूक्ष्मजीव चट्टानों में खनिजों को अन्य प्रजातियों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं।

इसके बाद कठोर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम लाइकेन, मॉस और घास जैसी साहसी अग्रणी प्रजातियां आती हैं। भले ही बर्फ हट गई हो, ये क्षेत्र अभी भी हवा और ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। अग्रणी प्रजातियां बढ़ने और मरने के बाद, वे अपने पीछे कार्बनिक पदार्थ छोड़ जाती हैं। यह धीरे-धीरे पतली मिट्टी को समृद्ध करता है। जब पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ होता है, तो अधिक जटिल पौधे जड़ पकड़ सकते हैं। बड़े जानवर सबसे बाद में आते हैं, क्योंकि शाकाहारी जानवरों को जीवित रहने के लिए संपन्न पौधा समुदायों की आवश्यकता होती है और शिकारियों को खाने के लिए शिकार जानवरों की आवश्यकता होती है।

पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सरल से लेकर अत्यधिक जटिल तक हो सकते हैं। जैसा कि हमारे शोध से पता चलता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रजातियों की संख्या के बजाय समय है। जैसे-जैसे समय बीतता है, अधिक नई प्रजातियों के इन हिमनदों के बाद के परिदृश्यों में बसने की संभावना है। लेकिन यह जीवों के बीच की अंत:क्रिया है जो पारिस्थितिक तंत्र को कार्यशील बनाती है।

सूक्ष्मजीव अक्सर उपजाऊ मिट्टी के विकास में तेजी लाकर अग्रणी पौधों की मदद करते हैं। कैसे? बैक्टीरिया और कवक मृत पौधों से कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया ह्यूमस बनाती है, जो मिट्टी का एक समृद्ध, उपजाऊ घटक है जो इसकी संरचना और पोषक तत्व सामग्री में सुधार करता है। बदले में, पौधे जानवरों के लिए नए आवास और भोजन स्रोत बनाते हैं। आर्कटिक लोमड़ियों और खरगोशों जैसे शिकारी-शिकार संबंधों के माध्यम से, या केंचुए जैसे 'पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियरों' के माध्यम से जानवर एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

Newspaper Paid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अपने देश का मिलकर बढ़ाइए आकर्षण

पड़ोस से सबक

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सराहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है, वह अनुकरणीय है। विपक्ष के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी ने बैठक में भाग लिया और अपनी-अपनी बात रखी। किसी भी विवादित विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का वही गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को ऐसी स्थिति में कतई नहीं फंसना चाहिए, जहां सियासी पार्टियों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जाएं कि फौज दखल देने को मजबूर हो जाए। वाकई अगर बांग्लादेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी-अपनी सीमाओं का अंदाजा होता, तो यह नौबत नहीं आती। अब ऐसी नौबत आ ही गई है, तो कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम खूनखराबा न हो। बहुत अफसोस की बात है कि शेख हसीना के देश से पलायन के बावजूद वहां हिंसा थमी नहीं है और कथित रूप से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

यह एक बड़ा सवाल है कि वहां छात्रों को अब क्या नाराजगी है? क्या बांग्लादेश में छात्रों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने फिर फन फैला लिया है? भारत ने ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी स्पष्ट कहा है कि हिंसा तत्काल रुकनी चाहिए और जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। सरकार का एक व्यवस्थित ढांचा जब सामने आएगा, तभी उपद्रवियों पर लगाम लगेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया है कि कई जगहों पर अल्पसंख्यकों के व्यवसायों और मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि, अफवाहों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे अनेक तत्व होंगे, जो इस प्रकरण को सांप्रदायिक रूप देना चाहेंगे। जैसे, एक अफवाह उड़ी थी कि वहां की क्रिकेट टीम के सदस्य लिटन दास के घर पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया है। वास्तव में, बांग्लादेश से आ रही खबरों को दो-तीन बार परख लेने की जरूरत है। अनेक स्थानों पर बांग्लादेशी नागरिक ही अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों की पहल का स्वागत किया है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश को ऐसी स्थिति में कतई नहीं फंसना चाहिए, जहां सियासी दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जाएं कि फौज दखल देने को मजबूर हो जाए।

बेशक, भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बता दिया है कि भारत ने शेख हसीना को संयम बरतने की सलाह बार-बार दी थी और आग्रह किया था कि हालात को बातचीत से सुलझा लें। अफसोस, हसीना ने सलाह पर गौर नहीं किया और अब यूरोप में शरण खोज रही हैं। यूरोपीय देश भी शरण देने से पहले चिंतित हैं, क्योंकि अब उनके यहां भी कट्टरता पैठ गई है। शेख हसीना का पतन वास्तव में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। जो लोकतंत्र और चुनाव की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिवेश न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाफ हो जाएं, तो समय रहते सत्ता से अलग हो जाना ही बड़प्पन की निशानी है। ऐसे बड़प्पन से ही लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 अगस्त, 1949

मध्यम वर्ग

सन् १९४५-४६ में केन्द्रीय सरकार का ध्यान मध्यम वर्ग की ओर गया और उसने उनकी अवस्था की जांच कराई। सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में इस सम्बन्ध में ५००० मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारी परिवारों के आय-व्यय के हिसाब मंगाये और उनसे परिणाम निकालकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो तीन वर्ष में, जब स्थितियां पहले से बहुत कुछ बदल गई हैं, हमारे हाथों में पहुंची हैं। अगस्त १९३९ के भावों को सौ का सत्तर मानकर जून १९४६ के जो भावांक २५२ थे, वे जून १९४९ में ३७८ अर्थात् ड्योढ़े हो गये थे। बम्बई में... रहन-सहन का व्यय लगभग ३० प्रतिशत बढ़ गया था। नये भावों और व्यय की तुलना में सरकार के मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में सरकारी वेतन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो वृद्धि हुई, वह नगण्य है। अतः रिपोर्ट को इस स्थिति के प्रकाश में ही देखना और उस पर उनकी वर्तमान अवस्था का अनुमान किया जाना चाहिए।

जांच में ७ प्रान्तों और ४ नगरों के चुने हुए नमूने के परिवार सम्मिलित किये गये, जिनके वेतन ३० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक थे। इनको मध्यम वर्ग में गिना गया। ३० रुपये पाने वाले कर्मचारी को मध्यम वर्ग में गिनने से मध्यमवर्गीय परिवार की आय का औसत स्तर बहुत नीचे निकला। मद्रास में औसत आय १६० रुपये मासिक से कम थी। अधिकतम औसत आय राजधानी दिल्ली में पाई गई और वह है २८६ रुपये।

बचत के बजट बहुत कम पाये गये। बम्बई और मद्रास प्रान्त में बचत के बजट से चौगुने, मद्रास नगर में पांच गुने, युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, पंजाब, बिहार और उड़ीसा में छः या सात गुने घाटे के बजट थे। केवल राजधानी में बचत के बजट से ड्योढ़े घाटे के बजट थे। वस्तुतः यह अवस्था शोचनीय थी। दिल्ली में प्रति घर १५ रुपये मासिक का घाटा न्यूनतम था और पंजाब में ५१ रुपये अधिकतम। खर्च में से प्रोविडेंट फंड की कटौती और बीमे की किस्त की रकमें नहीं निकाली गईं। उन्हें बचत मानकर घाटे में से काटने पर भी मासिक घाटा रहता है। इसका अर्थ यह है कि यह वर्ग अपनी पिछली बचत को भी इस युद्धोत्तर महंगाई में खा गया होगा।... दिल्ली में ऋणी परिवारों की संख्या ४० प्रतिशत और पंजाब में ३७ प्रतिशत (न्यूनतम) मिली।

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

यह मिथक है कि सिर्फ रोजगार की तलाश में लोग देश से बाहर जाते हैं। एक आशंका यह भी है कि साल 2024 में 4,300 अरबपति भारत की नागरिकता छोड़ देंगे।

पिछले दिनों अखबारों में छपी एक खबर ने बरबस ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रतिवर्ष लगभग 2.25 लाख भारतीय देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं और यह पूरी दुनिया में किसी एक देश से प्रवसन या पलायन करने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रवसन का अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 और 2022 में विकसित देशों की ओर होने वाले पलायन का सबसे बड़ा स्रोत भारत था। यह मिथक ही है कि सिर्फ रोजगार की तलाश में गरीब या मध्यवर्ग के लोग ही देश छोड़कर बाहर गए। बाहर पूंजी लगाने के लिए प्रवसन का अध्ययन करने वाले थिंक टैंक हेनले ऐंड पार्टनर्स के एक अध्ययन के अनुसार, संभावना है कि 2024 में ही 4,300 अरबपति भारत की नागरिकता छोड़ेंगे और यह इस श्रेणी में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। चीन (15,200) इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रोजगार के लिए बाहर जाने वालों में से काफी संख्या में लोग लौट आते हैं, पर अरबपति तो जाते ही हैं, अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करके। भिन्न देशों की नागरिकता उन्हें लगभग खरीदनी पड़ती है। अर्थात वे वहां एक बड़ी राशि का निवेश या उसका वायदा करते हैं। इस तरह उनके जाने से देश उनके अनुभव के अलावा एक बड़ी धनराशि के निवेश से भी वंचित हो जाता है।

आज जब दावा किया जा रहा है कि भारत विकासशील देशों में सबसे तेज बढ़ती और विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है, क्योंकर ऐसा है कि हर समर्थ व्यक्ति अगर उसे मौका मिले, तो देश छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठा है? विकास के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की मजबूरी तो समझ में आती है, जो रोजगार की तलाश में देश के अंदर ही मारा-मारा फिरता है और अपना गांव-दुवार छोड़कर महानगरों में कई बार नारकीय जीवन भी चुन लेता है। यह वह तबका है, जो रूस की सेना में निश्चित मृत्यु का जोखिम उठाकर भी भर्ती हो रहा है या हाल में युद्ध के दहाने पर बैठे इजरायल में इमारती कारीगर बनने चला गया। इजरायल जाने वाले एक मजदूर की मजबूरी इस वाक्य से समझी जा सकती है कि वहां से पैसे भेजकर वह कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर ही सकेगा। इस तरह का गरीब मजदूर अपनी नागरिकता नहीं छोड़ता, बल्कि हर महीने कुछ न कुछ विदेशी मुद्रा भेजकर देश की मदद ही करता है। गए वित्तीय वर्ष में भारतीय नौकरीपेशा लोगों ने बाहर से 107 अरब डॉलर भेजे और हमारे विदेशी मुद्राकोष को बढ़ाने में सहायक हुए।

यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से भरपूर लाभ उठाने वाले अरबपतियों में देश छोड़ने की होड़ क्यों लगी हुई है? उनमें से एक छोटा सा तबका तो वह है, जो किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने और कानून की पकड़ से बचने के लिए बाहर भाग जाता है, पर ज्यादातर स्वेच्छा से और कानूनी तरीकों से अपने पासपोर्ट का रंग बदलते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें दो तथ्य मद्देनजर रखने होंगे।

चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना बड़ी है और अगले कुछ दशकों में जो अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उसे छोड़कर जाने वाले अरबपति भारत के मुकाबले तीन गुने से अधिक हैं। फिर क्यों वे चीन से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को चुन रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में छिपा है कि भारतीय और चीनी अरबपति जा कहां रहे हैं? वे उन देशों में जा रहे हैं, जहां पिछली कुछ शताब्दियों में लोकतंत्र फला-फूला है और जिन्होंने नागरिक अधिकारों को इस हद तक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है कि उसके चलते वे दुनिया की दो पुरानी सभ्यताओं- भारत और चीन को पछाड़कर इस सोपान पर दोनों से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। लोकतंत्र उनके जीवन का अंग बन गया है।

मुझे यह देखकर बड़ा दिलचस्प लगता है कि पश्चिम विरोधी दुनिया के दो बड़े दर्शनों- मार्क्सवाद और इस्लाम की छत्रछाया में रहने वालों के मन के भी किसी कोने में किसी भी तरह अमेरिका या यूरोपीय संघ के देशों में बस जाने की इच्छा छिपी रहती है। चीन और इस्लामी मुल्कों में जहां इस पलायन के लिए लोकतंत्र का अभाव जिम्मेदार है, भारत में इसके साथ गवर्नेंस की अनुपस्थिति भी एक बड़ा कारण है। धीरे-धीरे बढ़ रही शहरीकरण की प्रक्रिया में अनुपस्थित शासन साफ दिखता है। दूर न जाकर इस प्रक्रिया में विकसित हो रही सबसे बड़ी शहरी बसावट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को देखकर ही हम गवर्नेंस का अंदाज लगा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बरसात अब किसी कोमल अनुभूति के साथ नहीं आती, नागरिक इस दौरान दहशत से गुजरते हैं। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी आधे दर्जन से अधिक नागरिक जलभराव और इमारतों के गिरने से मरे, सड़कें चलने लायक नहीं रहीं और इस साल भी भ्रष्ट म्यूनिसिपल अधिकारियों की बांछें खिली रहीं। एनसीआर की एक महत्वपूर्ण बसावट नोएडा की सड़कों पर सांड़ और गायें घूमती रहती हैं। दूसरी बड़ी बसावट गुरुग्राम में हल्की बारिश भी नागरिकों को शहर में बाढ़ का मजा चखाती रहती है। एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर टूटी सड़कें, बंद नालियां, उखड़े अतिक्रमित फुटपाथ और सड़कों पर घूमते लावारिस पशु आपका स्वागत करेंगे। उस पर तुर्रा यह कि अगले बीस-पच्चीस वर्षों में विकसित होने का सपना देखने वाले देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था निरंतर व्यावसायिक होते जाने से आम नागरिकों की पहुंच से दूर होती जा रही है।

यह एक खुला सच है कि किसी समाज के सभ्य और अपने नागरिकों के बीच लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा आधार वहां मौजूद रूल ऑफ लॉ या कानून कायदों को निष्पक्ष ढंग से लागू करने में राज्य की इच्छाशक्ति और सामर्थ्य होता है। हमें बाहर भागने वालों को कोसने के पहले यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने नागरिकों को रूल ऑफ लॉ दे पा रहे हैं? चीन या इस्लामी देशों की स्थिति तो समझी जा सकती है कि सारी समृद्धि के बावजूद लोकतंत्र का अभाव उनके नागरिकों को पश्चिम की तरफ खींचता है, पर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? अवसरों की कमी की वजह से गरीब या मध्यवर्ग का पलायन तो स्वाभाविक लगता है, पर अरबपतियों के देश छोड़ने को समझने के लिए हमें देश में मौजूद नागरिक सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रही गिरावट या गवर्नेंस की कमी के साथ-साथ निरंतर घट रहे लोकतंत्र पर भी नजरें डालनी पड़ेंगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आगजनी, लूटपाट और हत्या के बेकाबू भंवर में बांग्लादेश

यहां स्कैन करें

सुबीर भौमिक | वरिष्ठ पत्रकार

बांग्लादेश अराजकता के एक ऐसे भंवर में फंस चुका है, जिसे बेकाबू बनाकर शेख हसीना मुल्क छोड़कर निकल चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने बांग्लादेश का भविष्य फौज के हाथों में सौंप दिया। उन्हें तो राष्ट्र के नाम अंतिम संबोधन के लिए भी समय नहीं दिया गया और उनके घर को लूटपाट के लिए खुला छोड़ दिया गया। जीत का जश्न मना रही भीड़ ने उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा तक को तोड़ डाली। कट्टरपंथी उन्मादी जमात का उत्पात बदस्तूर जारी है, जिसे रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा। भीड़ के निशाने पर पुलिस, अवामी लीग के नेतागण, अल्पसंख्यक समुदाय और धर्मनिरपेक्ष चेहरे हैं।

सोमवार को खून-खराबे और तबाही का जो तूफान आया, वह मंगलवार को भी जारी रहा। आकलन है कि सोमवार को महज एक दिन में 786 लोगों की मौत हुई, 76 पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी गई और वहां पर रखे हुए हथियार लूट लिए गए, बैंकों की 14 शाखाएं लूटकर आग के हवाले कर दी गईं, अवामी लीग नेताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के 30,000 घर जला दिए गए, टीवी चैनलों सहित 11,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई, 37 पावर ग्रिड स्टेशनों, ट्रेन के 39 डिब्बे, 29 पेट्रोल पंप आदि सभी स्वाहा कर दिए गए हैं, 23 मंदिरों और गिरिजाघरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। उन्मादी आमतौर पर अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों, विशेषकर पुलिस को निशाना बना रहे हैं। हालांकि, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां ने शांति बहाल करने और नई सरकार के गठन की 'पूरी जिम्मेदारी' ली है, पर पिछले दो दिनों की हिंसक घटनाओं और सेना की प्रतिक्रिया ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। यह समझा जा सकता है कि कोई पेशेवर सेना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे निहत्थे छात्रों पर गोली चलाना पसंद नहीं करती, लेकिन लूटपाट में शामिल तत्वों या पुलिस स्टेशनों और वर्दीधारियों पर हमले करने वाले कट्टरपंथियों को खुली छूट देना, किसी भी तरह से उचित रवैया नहीं है।

भीड़ के निशाने पर आमतौर पर पुलिस, अवामी लीग के नेतागण, अल्पसंख्यक समुदाय और धर्मनिरपेक्ष चेहरे दिख रहे हैं।

बहरहाल, शेख हसीना का यूं सत्ता से बाहर होना हमारी चिंता का भी एक बड़ा कारण है। जिस आरक्षण-विरोधी आंदोलन की शिकार बांग्लादेश सरकार बनी है, उसमें भारत-विरोधी भावना प्रबल थी। यह भावना अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शेख हसीना नई दिल्ली आ चुकी हैं। इसलिए अब वहां जो भी नई सरकार बनेगी, चाहे वह सेना समर्थित अंतरिम सरकार हो या कोई निर्वाचित हुकूमत, उसका भारत के प्रति लगाव कम हो सकता है। इसकी पूर्वपीठिका बनती हुई दिख रही है, क्योंकि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का यह बयान आया है कि 'जब भारत कहता है कि बांग्लादेश में हिंसा उसका आंतरिक मामला है, तो हमें दुख होता है।' जाहिर है, द्विपक्षीय रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती अब हमारे सामने है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की मुखिया खालिदा जिया खुलेआम कह रही हैं कि अवामी लीग के समय भारत के साथ जितने समझौते हुए थे, उन सभी की जांच और समीक्षा की जाएगी। लिहाजा, वहां की परियोजनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। हो सकता है कि इनको खत्म न किया जाए, लेकिन नई सरकार में इनकी रफ्तार जरूर धीमी की जा सकती है। इसी तरह, वहां के अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेशियों की सुरक्षा भी एक गंभीर मसला है, जिसका तत्काल समाधान आवश्यक है। इनमें से ज्यादातर सीमा पार करके शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ढाका में व्यवस्था अनुकूल नहीं बन पाती, तो इसका किस तरह हल निकाला जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। वैसे, कुछ इसी तरह की चिंता उन कट्टरपंथी जमातों व जातीय अलगाववादियों को लेकर भी होगी, जिनसे हसीना सरकार के समय सख्ती से निपटा गया था, पर अब जिन्हें बांग्लादेश में खाद-पानी मिलने की आशंका प्रबल है।

बहरहाल, बांग्लादेश-प्रकरण का एक सबक तो स्पष्ट है। जब तक आम लोगों की धारणा अनुकूल न हो, द्विपक्षीय रिश्ते स्थिर नहीं हो सकते, फिर चाहे सरकारों का आपस में भले ही कितना अच्छा संबंध क्यों न हो?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शरीर एकमात्र उपहार

किसी व्यक्ति के भौतिक सृजन का सबसे अभिन्न अंग उसका अपना शरीर ही होता है। यही वह पहला उपहार है, जिसका एहसास उसे सबसे पहले होता है। हालांकि, शरीर पहला ही नहीं, बल्कि एकमात्र उपहार है। योग विज्ञान में मन या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। स्थूल से सूक्ष्म तक, सब कुछ विभिन्न आयामों में उसी शरीर की अभिव्यक्तियां हैं।

शरीर के पांच आवरण या आयाम होते हैं। इनके बारे में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल हम भौतिक शरीर की बात करेंगे। इसे ऐसे बनाया गया है कि यह आपकी भागीदारी के बिना भी काम करता रहता है। आपको हृदय धड़काना नहीं पड़ता। लिवर की सारी जटिल रासायनिक क्रियाएं चलानी नहीं पड़तीं या सांस लेने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। आपके भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सब खुद-ब-खुद ही होता रहता है।

भौतिक शरीर एक संपूर्ण यंत्र है, जो आत्मनिर्भर होता है। यदि आपको मशीनों से बहुत लगाव है, तो आपके लिए इससे अधिक दिलचस्प मशीन कोई और नहीं है। इस शरीर के विषय में आप जिन छोटी-मोटी बातों को जानते हैं, वे बहुत अविश्वसनीय होती हैं। इस धरती पर मानव शरीर सबसे जटिल किस्म का यंत्र है। यह उस यांत्रिकी का चरम स्तर है, जिसकी आपने शायद ही कभी कल्पना की होगी। यह उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सर्वोत्कृष्ट रूप है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा न होगा। यह ऐसे विद्युतीय संपर्क का सर्वश्रेष्ठ स्तर है, जो आपने सपने में भी संभवतः नहीं सोचा होगा। यह हिसाब करने की क्षमता का सर्वोत्तम रूप है, जिसका विचार कभी आपके मन में शायद ही आया होगा।

चलिए मान लेते हैं कि आपने दोपहर में एक केला खाया। शाम तक, यह केला आपका रूप ले लेता है। डार्विन ने आपको बताया था कि एक बंदर को इंसान बनने में लाखों साल लग गए, लेकिन आपने कुछ ही घंटे में एक केले को इंसान बना दिया! यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि का वह स्रोत आपके अंदर लगातार कार्य कर रहा है।

आपको हृदय धड़काना नहीं पड़ता, सांस लेने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। आपके भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सब खुद-ब-खुद ही होता रहता है।

आपके अंदर एक खास स्तर की बुद्धि और क्षमता है। यह आपके अंदर है। यह आपकी तर्कशक्ति से भी परे होती है, जो एक केले को एक ऐसी वस्तु में बदल देती है। यह तकनीक के हिसाब से श्रेष्ठ है। यही तो योग है- उस आयाम, उस बुद्धि, उस क्षमता तक पहुंच पाना, जो एक केले को कुछ ही घंटे में एक इंसान में बदल दे। अगर आप उस रूपांतरण को अचेतन के बजाय चेतन रूप में प्राप्त कर लेते हैं, यदि अपने दैनिक जीवन में उस बुद्धि का एक छोटा-सा अंश भी ले आते हैं, तो आपका जीवन दुख-दर्द भरा नहीं, बल्कि चमत्कारिक बन सकता है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

भारतीय प्रवासियों ने लगभग हरेक देश में अपनी छाप छोड़ी है, फिजी में अनेक कठिनाइयों के बीच अग्रणी पीढ़ियों द्वारा दिखाया गया दृढ़ संकल्प, उनका संघर्ष व बलिदान और फिर उनकी सफलता, एक अद्भुत विरासत है।

अनुलोम-विलोम
बांग्लादेश तख्तापलट

पड़ोसी देशों की साजिश का नतीजा

आखिरकार वही हुआ, जिसका अंदेशा था। लंबे समय से चल रहे हिंसक छात्र आंदोलन और अराजकता के भंवर में हिचकोले खाती हसीना की सरकार का तख्तापलट हो गया। फिलहाल कमान सेना के हाथों में है। वहां से आई तस्वीरें खौफनाक हैं। अराजक बनी भीड़ और आतताइयों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास को घेर लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री आवास में बिस्तर पर लेटे उपद्रवियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। ऐसी विस्फोटक स्थिति में प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर जैसे-तैसे जान बचाकर भागीं। यह पूरा प्रकरण 21वीं सदी में परिपक्व होते लोकतंत्र पर करारा तमाचा है कि किस प्रकार हुड़दंगियों और बाहरी ताकतों द्वारा लोकतंत्रात्मक ढंग से चलती सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाता है। उपद्रवियों की हरकत से स्पष्ट है कि इस तख्तापलट की साजिश पड़ोसी देश में रची गई है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि जिस बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश को जन्म दिया, आज उन्हीं की प्रतिमाओं पर हथोड़े चलाए जा रहे हैं और उनके मेमोरियल को आग के हवाले किया जा रहा है। साफ है, शक की सुई पाकिस्तान और चीन की तरफ ही उठती है। बहरहाल, जो होना था, वह हो गया। वक्त का अब यही तकाजा है कि वहां किसी तरह से लोकतंत्र को बहाल किया जाए। इसमें अगर कहीं हमारी मदद की जरूरत होगी, तो हमारी सरकार शायद ही मना करेगी।

हर्ष वर्द्धन, टिप्पणीकार

चिंतनीय घटनाक्रम

आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में लोगों के धैर्य का बांध टूट ही गया। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और फिर संसद। विशेषज्ञ यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हिंसक प्रदर्शन के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। यह दूसरा मौका है, जब प्रधानमंत्री आवास पर इस तरह प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। इससे पहले श्रीलंका में हम यह दृश्य देख चुके हैं। सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? असल में, नई दिल्ली ने बांग्लादेश में काफी निवेश कर रखा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लोट रहा था। चूंकि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चीन की मदद से यह पूरा षड्यंत्र रचा। सवाल यह भी है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान रोकथाम के लिए कहीं सेना मौजूद नहीं थी। ऐसे में, भारत ने स्वाभाविक ही पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए रखी है। वहां के हालात वाकई चिंताजनक हैं।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

हसीना सरकार ने स्थिति खुद बिगाड़ी

कहने वाले भले यह कहते रहें कि दूसरे देशों की साजिश का शिकार शेख हसीना बनी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। शेख हसीना ऐसे चुनाव से चुनकर आई थीं, जिसमें विपक्ष ने भागीदारी ही नहीं की थी। जाहिर है, जो भी वोट मिला, (हालांकि उसमें लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया) सब उन्हीं के खाते में गया और वह प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गईं। मगर बाद में उन्होंने जो फैसले लिए, वे जनता के खिलाफ ही माने जाएंगे। आरक्षण का ही यह मामला देखिए। होना तो यह चाहिए कि अब मुक्तियोद्धाओं को दी जा रही विशेष रियायत खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन उनके पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ देने की बात हुई। चूंकि मुक्ति योद्धा आमतौर पर अवामी लीग के ही समर्थक हैं, इसलिए यदि हसीना सरकार का यह फैसला अपने वोट-बैंक को मजबूत करने वाला माना गया, तो यह गलत नहीं लगता।

इस आरोप को बल मिलता है सरकार के रवैये से। देश में भाई-भतीजावाद भी खूब किया गया और भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। इन सबने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं, लेकिन सरकार मानो बेफिक्र होकर अपने में मस्त रही। यहां तक कि जब मानवाधिकारों के उल्लंघन और तानाशाही के आरोप हसीना सरकार पर लगे, तब भी प्रधानमंत्री ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, उदासीन बनी रहीं। इसने जनता के मन में उनके प्रति जबर्दस्त नाराजगी पैदा की। यह नाराजगी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की खबर आई, तो आक्रोशित आंदोलनकारियों ने शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति तक तोड़ डाली। शेख मुजीबुर्रहमान वही नेता हैं, जिनको बांग्लादेश बनाने का श्रेय दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेशियों ने अपने राष्ट्र-निर्माता का भी अपमान किया, क्योंकि वह शेख हसीना के पिता हैं।

जाहिर है, अगर किसी पार्टी को सत्ता मिलती है, तो वह खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूल न करे। श्रीलंका की घटना के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से तख्तापलट किया गया है, उसका संदेश यही है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार का मुख्य दायित्व लोकतंत्र की रक्षा करना है। इसके लिए उसे जनता की मुश्किलों का समाधान करना होता और उसके दुख-सुख को समझना पड़ता है। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं चल सकती। यह बात हर लोकतांत्रिक देश को समझ लेना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो यह जनता, जो उसे सिर चढ़ाती है, उतरना भी जानती है।

विकास कुमार, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण

सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है

भारत की बढ़ती चुनौतियां

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलायन के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे। शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थीं, लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है। ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने को तैयार नहीं और अमेरिका ने तो न केवल उनका वीजा रद कर दिया, बल्कि वहां की सेना को यह जानते हुए भी सलाम किया कि वह अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी तत्वों की भागीदारी के लिए भी तैयार है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि बांग्लादेश में सेना के वर्चस्व वाली अंतरिम सरकार का भारत के प्रति मित्रवत रवैया होगा। इस सरकार में घोर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के शामिल होने के साथ ही विपक्षी नेता एवं उन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भी भागीदारी हो सकती है, जिनसे भारत के संबंध कभी सहज नहीं रहे। यदि इस अंतरिम सरकार में उन तत्वों की भागीदारी बढ़ी, जो शेख हसीना को नई दिल्ली की कठपुतली बताते थे, तो भारत की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी।

बांग्लादेश में भारत के नजरिये से असहमत पश्चिमी देशों के साथ चीन का भी दखल बढ़ने का अंदेशा है। चीन पहले से ही मालदीव एवं नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा है। वह श्रीलंका में भी अपना दबदबा बढ़ाने की ताक में है। एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार भी अस्थिरता से जूझ रहा है और वहां भी चीन का दखल साफ दिख रहा है। भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए? आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटपुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी शामत ही आ गई है। बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें न आ रही हों। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, वे फिलहाल असहाय-निरुपाय दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही, जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के प्रकरण का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है उससे अब यह आशंका और बलवती होती दिख रही है कि फर्जीवाड़े के पीछे की मंशा केवल चंद पैसों के लिए सरकारी कर्मचारी के आत्मा बेचने भर की नहीं रही, बल्कि वास्तविक लक्ष्य कुछ और है। यह आशंका शुरू से ही व्यक्त की जा रही है कि जितनी बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए उसके पीछे का मकसद जनसांख्यिकी संरचना में बदलाव लगता है। मामला तब प्रकाश में आया था जब रायबरेली के सलोन कस्बे में इसकी कुल जनसंख्या से अधिक जन्म प्रमाणपत्र केवल दो साल में ही बना दिए गए। संदेह होने पर की गई प्राथमिक जांच में पाया गया कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी ने जनसेवा केंद्र संचालक जीशान, सुहैल और रियाज को अपनी आइडी दे रखी थी। इसी के बाद ग्राम विकास अधिकारी विजय सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) की फील्ड यूनिटों एवं स्थानीय पुलिस की सहायता से जो गिरफ्तारियां हुईं उनमें दो बातें प्रमुखता से सामने आई हैं। पहली यह कि प्रकरण सिर्फ रायबरेली के एक कस्बे तक सीमित नहीं है। गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर, बलिया, सोनभद्र, बहराइच, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मुरादाबाद से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और सिर्फ एक नहीं, कई अधिकारियों की आइडी का दुरुपयोग किया गया। दूसरी यह कि नेटवर्क संगठित रूप से वाट्सएप ग्रुप बनाकर संचालित किया जा रहा था, जिसमें अलग-अलग जिलों के दलाल शामिल थे। वे ग्रुप पर ही आइडी भी शेयर करते थे। यही बात सर्वाधिक रूप से शंका उत्पन्न करती और गहरी साजिश का संकेत करती है। इसके माध्यम से बांग्लादेशी अथवा रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की मंशा से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब जरूरी है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए।

अराजकता में डूबा बांग्लादेश

दिव्य कुमार सोती

अस्थिरता से बुरी तरह घिरे बांग्लादेश में अवामी लीग के साथ हिंदुओं का भी भविष्य खतरे में है

अवधेश राजपूत

बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का जो नंगा-नाच चल रहा था और बांग्लादेशी फौज में इन प्रदर्शनकारियों को लेकर जैसी सहानुभूति दिखाई दे रही थी, उसे देखते हुए शेख हसीना के पास अधिक विकल्प नहीं बचे थे। अगर वह सही समय पर देश नहीं छोड़तीं तो संभवतः उनका हाल उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान जैसा होता, जिनकी उनके अधिकांश परिवारजनों के साथ बांग्लादेश निर्माण के चार साल के भीतर ही फौजी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह भी अच्छा रहा कि शेख हसीना ने अपने ही रिश्तेदार को सेना प्रमुख नियुक्त किया था। संभवतः इस कारण भी उन्हें देश से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल सका। बांग्लादेश में जो हुआ, वह देर-सबेर होना ही था। करीब 15 वर्षों से शासन कर रहीं शेख हसीना देश को पंथनिरपेक्ष बनाने का प्रयास कर रही थीं। एक समय वह इसमें कुछ सफल होती भी दिख रही थीं। अपने शासन में वह बांग्लाभाषी मुसलमानों और अल्पसंख्यक हिंदुओं का पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर नरसंहार करने वाले जमात-ए-इस्लामी के रजाकार नेताओं को फांसी की सजा दिलाने में सफल रहीं। उनकी इस मुहिम के विरोध में विपक्षी और इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों से गहरे संबंध रखने वाली खालिदा जिया की बीएनपी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकी थी।

बांग्लादेश में पिछले एक साल में हालात बहुत तेजी से बदले। शेख हसीना ने अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं में मोहरा बनने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा भी कि एक पश्चिमी देश उनसे बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन भी किया कि उस पश्चिमी देश की योजना बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के ईसाई बाहुल्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को एकीकृत कर पूर्वी तिमोर की भांति एक अलग ईसाई देश बनाने की है। उनका इशारा भारत के मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार के चिन प्रदेश और बांग्लादेश के एक छोटे से क्षेत्र को मिलाकर कुकीलैंड या जालेनगाम बनाने के लिए चल रहे सशस्त्र आंदोलन की तरफ था। इस सबके चलते वह नागरिक विरोध-प्रदर्शनों के नाम पर 'रंगीन क्रांतियां' कराकर सरकारों का तख्तापलट कराने में माहिर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गई थीं, क्योंकि यह सच है कि अकेले इस्लामिक तत्व उनका तख्तापलट करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। यही कारण रहा कि उनके विरोध में अलग-अलग मुद्दों को छेड़कर नागरिक विरोध-प्रदर्शनों का स्वरूप दिया गया। इस कड़ी में कई महीनों तक बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए जिनमें भारत के बहिष्कार का आह्वान किया गया। शेख हसीना को भारत का मोहरा बताया गया। इसके बाद छात्रों के माध्यम से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को मिलने वाले आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन शुरू किए गए। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में सेक्युलर प्रवृत्ति रखने वाले शेख मुजीब समर्थकों की संख्या को घटाना था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण पिछले पांच दशकों से दिया जा रहा था, परंतु इसके विरोध में प्रदर्शन तभी शुरू हुए जब शेख हसीना ने अमेरिका के इशारों पर काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने चीन के इशारे पर भी चलने से इन्कार किया। चीन ने इस्लामाबाद के जरिये ढाका में पाकिस्तानपरस्त तत्वों की मदद की हो तो कोई हैरानी की बात नहीं।

आरक्षण विरोध वास्तव में आरक्षण को लेकर नहीं था। इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर दो प्रतिशत करने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रुके। कोर्ट द्वारा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बावजूद प्रदर्शन और उग्र हो गए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन प्रदर्शनों के दौरान ही हिंदू अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों और घरों पर व्यापक हमले भी शुरू हो गए। बड़ी बात नहीं कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी एजेंसियों और इस्लामी कट्टरपंथियों का गठजोड़ भी काम कर रहा हो और जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार का तख्तापलट करना हो। यह इससे लगता है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीब से जुड़े स्मृति चिह्नों को निशाना बनाना शुरू किया।

शेख हसीना सरकार अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश घोर हिंसा और अराजकता में डूब गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी अवामी लीग के नेताओं-समर्थकों और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। वहां से विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश जब 1971 में बना था, तब वहां हिंदू जनसंख्या 22 प्रतिशत थी जो आज घटकर 7-8 प्रतिशत के बीच रह गई है। आज भी बांग्लादेश में 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। शेख हसीना के जाने के बाद भी सेना ने हिंदुओं की हत्याओं को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। वह उन्हीं तत्वों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुला रही है, जो हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में उनके सत्ता में आने पर हिंदुओं की सुरक्षा को और खतरा बढ़ाना तय समझिए। ऊपर से बीएनपी और जमात इस फिराक में हैं कि अवामी लीग का कोई नामोनिशान बांग्लादेश में न बचे। अगर यह हिंसा का दौरा लंबा चलता है तो भारत सरकार हिंदुओं एवं भारत समर्थक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के 1970-71 सरीखे नरसंहार में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। फिलहाल बांग्लादेश सेना हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हिंदुओं और लीग समर्थकों को वहां से निकाल कर राहत शिविरों में लाए।

बांग्लादेश के भयावह दिख रहे भविष्य को देखते हुए वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की दूरगामी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारत के निकट उनके घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाएं। इस मामले में हमें रूस से सीखना चाहिए, जिसने यूक्रेन के डोनस्क और लुहांस्क को रूसी भाषियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बना दिया। अगर हम यह नहीं कर सके तो बांग्लादेश में घटती हिंदुओं की संख्या को विलुप्त होते देखेंगे। संभवतः उनकी सुरक्षा में हमारे समूचे पूर्वोत्तर के भविष्य की सुरक्षा भी निहित है।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

कौआ कान ले गया वाला रवैया

राजीव सचान

वक्फ अधिनियम में बदलाव की पहल का विरोध अंधविरोध की राजनीति का नया प्रमाण ही है

वक्फ एक्ट में बदलाव से सहमत मजहबी नेता। फाइल

लोकतांत्रिक देशों में सुधार की कोई पहल या नई नीति का निर्माण अथवा नया काम शुरू करना आसान नहीं होता। भारत भी इसका अपवाद नहीं। 1853 में जब अंग्रेजों ने देश में पहली बार रेल चलाई थी तो उसका यह कहकर विरोध हुआ था कि लोहे पर लोहा चलाना अपशकुन को निमंत्रण देना है। स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ। इसी विरोध के चलते उस पर अमल में देरी हुई। हाल का इतिहास देखें तो पाएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और तीन कृषि कानूनों का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमलों को देखते हुए तो अब यह आवश्यक हो गया है कि नागरिकता कानून को और अधिक उदार बनाया जाए, ताकि 2014 के बाद भी भारत आए तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से शरण एवं नागरिकता दी जा सके। ऐसा करते हुए पीड़ित और आक्रांता में भेद किया ही जाना चाहिए।

यह किसी से छिपा नहीं कि तीन तलाक खत्म करने की पहल पर किस तरह आसमान सिर पर उठा लिया गया था। इस पहल का विरोध यह कहते हुए किया जा रहा था कि यह प्रथा गलत तो है, लेकिन इसे खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट या सरकार को नहीं करना चाहिए। जब भी समान नागरिक संहिता की चर्चा छिड़ती है, कई मुस्लिम नेता और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल तत्व उसका आंख मूंदकर विरोध करना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने-समझे कि इस संहिता के क्या प्रविधान होंगे? यह कौआ कान ले गया वाला रवैया है। इसी रवैये का परिचय वक्फ अधिनियम में सुधार के मामले में दिया जा रहा है। विरोध करने वाले वही जाने-पहचाने ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता और नकली सेक्युलर, लिबरल और बौक तत्व हैं। कुछ मुस्लिम नेता सुधार के पक्ष में भी हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समाज उनकी सुनेगा? अभी तक सभी सूत्रों के हवाले से इतना भर पता चला है कि वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन होंगे और इसके तहत वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार खत्म किए जाएंगे। सरकार के अलावा शायद ही किसी को पता हो कि इसके अलावा अन्य संशोधन क्या होंगे, लेकिन विरोध करने वालों को जानकारी के इस अभाव से कोई फर्क नहीं। वे कुतर्क देने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा कुतर्क यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। इस कुतर्क के आगे कोई भी तर्क रखना बेकार है, क्योंकि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। शक करने वालों की तरह अंधविरोध से ग्रस्त लोगों का भी कोई इलाज नहीं।

किसी भी सरकार के फैसलों और उसकी नीतियों का विरोध या समर्थन उनके गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अपने देश की राजनीति में ऐसा नहीं होता। विरोध के लिए विरोध हमारे सभी दलों की प्रिय नीति है। कई विपक्षी दल इसी नीति का परिचय वक्फ अधिनियम में बदलाव पर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए उचित यही है कि वह वक्फ अधिनियम में जो भी संशोधन करने जा रही है, उन पर संसद में व्यापक बहस कराए, ताकि विपक्षी नेताओं को यह कहने का बहाना नहीं मिले कि सरकार ने बिना बहस आनन-फानन संशोधन विधेयक पारित करा लिया। व्यापक बहस का एक परिणाम यह भी होगा कि आम जनता और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में भ्रांतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकार मिले हुए हैं। आवश्यकता इसलिए भी है ताकि वक्फ संपत्तियों का निर्धन मुस्लिम समाज की भलाई के लिए सदुपयोग हो और इन संपत्तियों का दुरुपयोग एवं उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। कट्टरपंथी नेता कुछ भी कहें, खुद वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी यह मानते हैं कि उनकी छवि जमीन हड़पने वालों की बन गई है। इस छवि के लिए वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार है। वे किस मनमाने तरीके से काम करते हैं, इसका उदाहरण पिछले सप्ताह ही जबलपुर हाई कोर्ट के उस आदेश से मिला, जिसमें उसने शाहजहां की बहू के मकबरे समेत तीन अन्य मुगलकालीन संपत्तियों पर उसका दावा इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि ये संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में होनी चाहिए थीं। वक्फ बोर्डों को कैसे मनमाने अधिकार हासिल हैं, इसका प्रमाण तमिलनाडु का वह गांव भी है, जिसके मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जबकि यह मंदिर 1500 साल पुराना यानी इस्लाम के उदय के पहले का है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आमतौर पर सियासी और मजहबी रसूख वाले नेता काबिज रहते हैं। वे उसकी संपत्तियों का दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि उन पर कब्जे कराने के साथ उन्हें बेचते भी हैं। प्रयागराज में वक्फ की 50 करोड़ से अधिक की जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। 2023 में योगी सरकार ने उसे खाली कराया और अब वहां वक्फ बोर्ड की ओर से एक क्लीनिक का संचालन हो रहा है। कुछ वर्ष पहले कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से वक्फ की करोड़ों की संपत्ति बेच दी गई। इस रिपोर्ट पर न तो कोई जांच हुई और न ही कार्रवाई। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के एक पदाधिकारी को इस आरोप में हटाया गया कि उसने वक्फ की संपत्तियां बिल्डरों को बेच दी थीं। देश भर के करीब 30 वक्फ बोर्डों के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्तियां हैं, लेकिन किसी को और कम से कम गरीब मुसलमानों को नहीं पता कि उनसे उन्हें क्या लाभ मिल पा रहा है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मज्ञान

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हमारा यह शरीर नश्वर है, परंतु इस शरीर को चलायमान रखने वाला आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा चैतन्य है। यह परमात्मा का ही अंश है। सर्वव्यापी चेतना है। अजर और अमर है। छांदोग्य उपनिषद में 'तत्त्वमसि' के माध्यम से ब्रह्म और जीव का संबंध समझाया है। तत्त्वमसि से आशय है 'तुम वही ब्रह्म हो' अर्थात तुम (जीव) परमात्मा का अंश हो। इसी प्रकार, प्रत्येक चेतन वस्तु परमात्मा का अंश है। यदि संसार के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश है तब फिर विभेद कहां है? फिर सभी समान हुए। एक छोटे से कीट पतंगे से लेकर सिंह या मनुष्य तक सभी एकसमान हुए, यही अद्वैतवाद की अवधारणा है।

शुद्ध मन, सात्विक आचरण तथा निरंतर अभ्यास द्वारा इच्छाओं एवं भौतिक सुख को तिरोहित कर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान की उपलब्धि के पश्चात हम संसार के समस्त तत्वों में परमात्मा का निवास अनुभव कर सकते हैं। जब हमें अद्वैत की अनुभूति हो जाए तो यह आत्मज्ञान की परम अवस्था है। इस प्रकार, आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य होनी चाहिए। इसके उपरांत हम सभी जीवों में परमात्मा के अंश को पहचानते हैं और सर्वत्र एकत्व का अनुभव करते हैं। एकत्व का अनुभव हो जाए तो मन में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार नहीं रह जाता। इस अहंकार भाव से मुक्ति मोक्ष की ओर उन्मुख करती है। आत्मज्ञान की राह में मन की चंचलता और अस्थिरता एक बड़ा अवरोध बनती हैं। ये अवरोध हमें आत्मा के सत्य से साक्षात्कार नहीं करने देते। इन अवरोधों से पार पाने के लिए निरंतर अभ्यास और सात्विक आचरण के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए। जब मन शुद्ध और अनुशासित होता है तब ध्यान और साधना के द्वारा बुद्धि को एकाग्र कर आत्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है।

सोमा सुर

आत्मनिर्भरता का प्रतीक स्वदेशी आंदोलन

सुधीर कुमार

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सात अगस्त का विशेष महत्व है। वर्ष 1905 की इसी तिथि को कलकत्ता के टाउन हाल में आयोजित एक विशाल सभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना था। यह दिन स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना को जगाने का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन का प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं था, अपितु इसका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ा।

स्वदेशी आंदोलन ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई में एकजुट किया। सात अगस्त की बैठक में ऐतिहासिक 'बहिष्कार प्रस्ताव' पारित होने के पश्चात सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अनेक नरमपंथी नेता भी देश-यात्रा पर निकल गए और लोगों से मैनचेस्टर के बने कपड़े और लीवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील करने लगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाना इस आंदोलन का एक प्रमुख और प्रतीकात्मक कार्य था। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी कपड़ों के ढेर लगाकर उन्हें जलाते थे। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहनना और विदेशी बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इससे न केवल घर-घर में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी, बल्कि यह भी साबित हुआ कि महिलाएं भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। 16 अक्टूबर को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसे भारतीयों ने 'राष्ट्रीय शोक दिवस' के रूप में मनाया। शोक के प्रतीक के रूप में घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा दी तथा लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई में एकजुट किया। आंदोलन के दौरान स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का प्रचार-प्रसार हुआ, जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को प्रबल किया।

सात अगस्त, 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई में एकजुट किया

स्वदेशी आंदोलन ने सही मायनों में आत्मनिर्भरता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी शिक्षा के लिए 1906 में 'बंगाल नेशनल कालेज' और 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' की स्थापना हुई। उस दौर में जगदीश चंद्र बोस और पीसी राय ने विज्ञान, रवींद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और नंदलाल बोस ने कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन से ही प्रेरित होकर मोदी सरकार ने 2014 में 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू किया और 2015 में इस तिथि को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' घोषित किया। बहरहाल स्वदेशी अपनाकर हम भी देश की मजबूती में अहम हिस्सेदार बन सकते हैं।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

जल निकासी की हो समुचित व्यवस्था

'जल निकासी में असहाय शहर' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस कड़ी में कुछ बिंदु जोड़ना चाहता हूं। जैसे कि हमें जल निकासी से संबंधित अवसरंचना को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। शहरों में जलजमाव की बहुत चिंता की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र भी इस समस्या से दो-चार होते हैं, जिसकी तपिश मुख्य रूप से किसानों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम पूरे राष्ट्र को एक इकाई मानकर जलापूर्ति और जल निकासी तंत्र के बारे में विचार करें। वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। ड्रेनेज के क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले नीदरलैंड और जल संरक्षण में इजरायल के अनुभव का सहयोग लेकर निवेश करना उपयोगी हो सकता है। जल निकासी की समस्या का निदान समेकित हो न कि शहरी और गैर-शहरी क्षेत्र को अलग रखकर। दीर्घकालिक योजनाओं से ही टिकाऊ समाधान संभव है। जैसे हर घर को नल से जल और हर खेत को जल सुनिश्चित किया जा रहा है वैसे ही हर घर और खेत से समुचित जल निकासी का सोच विकसित करना होगा। तभी स्थितियां सुधरेंगी।

प्रो. मान सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक-आइसीएआर, नई दिल्ली

जल भराव के लिए जिम्मेदार नागरिक

अगर शहरों को रहने योग्य बनाना है तो शहरों की योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण पर जुड़े उपायों को प्राथमिकता की सूची में रखना होगा। सोचने वाली बात यह है कि थोड़ी सी बारिश में भी शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? पूरे देश के नगरों, महानगरों में प्राधिकरण और नगर निगम हैं और वह हर साल नाले नालियों की सफाई के नाम पर हजारों, लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हैं। उसके बाद भी थोड़ी बारिश में ही पानी सड़कों पर बहने लगता है। और बाढ़ जैसे हालात क्यों बन जाते हैं? इस सबके लिए हम सिर्फ शासन प्रशासन को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। असल में देखा जाए तो इस सबके लिए ज्यादा जिम्मेदार देश की जनता और व्यापारी वर्ग है, जो सड़कों के दोनों ओर नालों, नालियों को ढक देते हैं। और दुकानों से निकलने वाला पुरा कूड़ा नाले नालियों में भर देते हैं। वास्तव में सभी छोटे बड़े शहरों के नालों पर जाल लगने चाहिए। और हर 10 मीटर की दूरी पर नालों के बीच में ऐसे जाल लगें जिससे कि मोटा कूड़ा उनसे न जा सके। सिर्फ पानी ही जाए। और उन नालों के जाल के साथ जो कूड़ा जमा हो जाता है उसको निकालने की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के अतिक्रमण के कारण नालियों पर सफाई कर्मियों को उनकी सफाई करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। सरकार के साथ-साथ देश के नागरिकों का भी यह दायित्व है कि वे भी नाले में कूड़ा न भरें। उन पर अतिक्रमण न करें जिससे कि उनकी सफाई कर्मचारी कर सकें।

अतिवीर जैन 'पराग', पूर्व उपनिदेशक, रक्षा मंत्रालय, बरेली

देश विरोधी ताकतों के उभरने की आशंका

बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार के दुर्भाग्यपूर्ण कत्ल से भारत ने अपना सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र और शुभचिंतक खो दिया है। पाकपरस्त कट्टरपंथियों ने छात्र आंदोलन की ओट में जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचा, वह न केवल विस्मयकारी है अपितु भारत को सावधान करने वाला भी है। बांग्लादेश के तख्तापलट से भारत विरोधी ताकतों में जो स्वाभाविक उभार आएगा उसका असर शेख हसीना के लंबे शासन-काल में मजबूत हुए भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश के अफसोसजनक ताजा हालातों के पीछे पाकिस्तान की आइएसआइ की साजिश से इन्कार नहीं किया जा सकता। आइएसआइ एक अर्से से बांग्लादेश में अपने कट्टरपंथी गुर्गों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार के रहते उसके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे थे।

pandeyvp1960@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

भारत की बढ़ती चुनौतियां

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलायन के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे। शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थीं, लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है। ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने को तैयार नहीं और अमेरिका ने तो न केवल उनका वीजा रद कर दिया, बल्कि वहां की सेना को यह जानते हुए भी सलाम किया कि वह अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी तत्वों की भागीदारी के लिए भी तैयार है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि बांग्लादेश में सेना के वर्चस्व वाली अंतरिम सरकार का भारत के प्रति मित्रवत रवैया होगा। इस सरकार में घोर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के शामिल होने के साथ ही विपक्षी नेता एवं उन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भी भागीदारी हो सकती है, जिनसे भारत के संबंध कभी सहज नहीं रहे। यदि इस अंतरिम सरकार में उन तत्वों की भागीदारी बढ़ी, जो शेख हसीना को नई दिल्ली की कठपुतली बताते थे, तो भारत की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। बांग्लादेश में भारत के नजरिये से असहमत पश्चिमी देशों के साथ चीन का भी दखल बढ़ने का अंदेशा है। चीन पहले से ही मालदीव एवं नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा है। वह श्रीलंका में भी अपना दबदबा बढ़ाने की ताक में है। एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार भी अस्थिरता से जूझ रहा है और वहां भी चीन का दखल साफ दिख रहा है। भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए? आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटपुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी शामत ही आ गई है। बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें न आ रही हों। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, वे फिलहाल असहाय-निरुपाय दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही, जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है।

बच सकेंगी जानें

दुर्घटना में घायल को पहुंचाने वाले व्यक्ति से अस्पताल किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस आशय का निर्देश राज्य के सभी सिविल सर्जन, निजी और सरकारी अस्पतालों को भेजा गया है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है और निश्चित तौर पर इससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम किए जाने में मदद मिलेगी। अभी बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। यहां सड़क हादसों के 78 प्रतिशत मामलों में घायलों की जान चली जाती है। मिजोरम के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है, जहां इतनी ज्यादा जनहानि होती है। इन मौतों में तभी कमी लाई जा सकती है जब घायलों को समय पर उपचार मिल जाए। अभी अस्पताल ले जाने के बाद तमाम औपचारिकताओं में वक्त जाया होता है। ज्यादातर अस्पताल मरीज की तीमारदारी शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि इलाज का पैसा कौन देगा। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद अस्पताल बिना वक्त बर्बाद किए घायलों का उपचार करेंगे और कई परिवारों को जिंदगी भर मिलने वाले दर्द से दूर रखने में कामयाब होंगे। इस आदेश का ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि घायलों की मदद कर अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना होगा। पैसे के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। लोगों को तो यह भी नहीं पता कि घायलों को मदद पहुंचाने वालों को सम्मानित तक किया जाता है। जाहिर तौर पर इसका प्रचार प्रसार होगा तो घायलों को मदद पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य में ट्रामा सेंटर व एंबुलेंस की व्यवस्था को भी और सघन किए जाने की जरूरत है।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई शुल्क न लेने का आदेश सराहनीय है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश का घटनाक्रम भारत की चिंता बढ़ाने वाला है?

आज का सवाल

क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए?

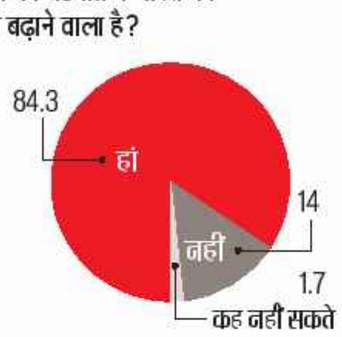

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अराजकता में डूबा बांग्लादेश

दिव्य कुमार सोती

अस्थिरता से बुरी तरह घिरे बांग्लादेश में अवामी लीग के साथ हिंदुओं का भी भविष्य खतरे में है

बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का जो नंगा-नाच चल रहा था और बांग्लादेशी फौज में इन प्रदर्शनकारियों को लेकर जैसी सहानुभूति दिखाई दे रही थी, उसे देखते हुए शेख हसीना के पास अधिक विकल्प नहीं बचे थे। अगर वह सही समय पर देश नहीं छोड़तीं तो संभवतः उनका हाल उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान जैसा होता, जिनकी उनके अधिकांश परिवारजनों के साथ बांग्लादेश निर्माण के चार साल के भीतर ही फौजी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह भी अच्छा रहा कि शेख हसीना ने अपने ही रिश्तेदार को सेना प्रमुख नियुक्त किया था। संभवतः इस कारण भी उन्हें देश से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल सका। बांग्लादेश में जो हुआ, वह देर-सबेर होना ही था। करीब 15 वर्षों से शासन कर रहीं शेख हसीना देश को पंथनिरपेक्ष बनाने का प्रयास कर रही थीं। एक समय वह इसमें कुछ सफल होती भी दिख रही थीं। अपने शासन में वह बांग्लाभाषी मुसलमानों और अल्पसंख्यक हिंदुओं का पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर नरसंहार करने वाले जमात-ए-इस्लामी के रजाकार नेताओं को फांसी की सजा दिलाने में सफल रहीं। उनकी इस मुहिम के विरोध में विपक्षी और इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों से गहरे संबंध रखने वाली खालिदा जिया की बीएनपी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकी थी।

बांग्लादेश में पिछले एक साल में हालात बहुत तेजी से बदले। शेख हसीना ने अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं में मोहरा बनने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा भी कि एक पश्चिमी देश उनसे बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन भी किया कि उस पश्चिमी देश की योजना बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के ईसाई बाहुल्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को एकीकृत कर पूर्वी तिमोर की भांति एक अलग ईसाई देश बनाने की है। उनका इशारा भारत के मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार के चिन प्रदेश और बांग्लादेश के एक छोटे से क्षेत्र को मिलाकर कुकीलैंड या जालेनगाम बनाने के लिए चल रहे सशस्त्र आंदोलन की तरफ था। इस सबके चलते वह नागरिक विरोध-प्रदर्शनों के नाम पर 'रंगीन क्रांतियां' कराकर सरकारों का तख्तापलट कराने में माहिर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गई थीं, क्योंकि यह सच है कि अकेले इस्लामिक तत्व उनका तख्तापलट करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। यही कारण रहा कि उनके विरोध में अलग-अलग मुद्दों को छेड़कर नागरिक विरोध-प्रदर्शनों का स्वरूप दिया गया। इस कड़ी में कई महीनों तक बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए जिनमें भारत के बहिष्कार का आह्वान किया गया। शेख हसीना को भारत का मोहरा बताया गया। इसके बाद छात्रों के माध्यम से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को मिलने वाले आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन शुरू किए गए। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में सेक्युलर प्रवृत्ति रखने वाले शेख मुजीब समर्थकों की संख्या को घटाना था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण पिछले पांच दशकों से दिया जा रहा था, परंतु इसके विरोध में प्रदर्शन तभी शुरू हुए जब शेख हसीना ने अमेरिका के इशारों पर काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने चीन के इशारे पर भी चलने से इन्कार किया। चीन ने इस्लामाबाद के जरिये ढाका में पाकिस्तानपरस्त तत्वों की मदद की हो तो कोई हैरानी की बात नहीं।

अवधेश राजपूत

आरक्षण विरोध वास्तव में आरक्षण को लेकर नहीं था। इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर दो प्रतिशत करने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रुके। कोर्ट द्वारा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बावजूद प्रदर्शन और उग्र हो गए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन प्रदर्शनों के दौरान ही हिंदू अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों और घरों पर व्यापक हमले भी शुरू हो गए। बड़ी बात नहीं कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी एजेंसियों और इस्लामी कट्टरपंथियों का गठजोड़ भी काम कर रहा हो और जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार का तख्तापलट करना हो। यह इससे लगता है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीब से जुड़े स्मृति चिह्नों को निशाना बनाना शुरू किया।

शेख हसीना सरकार अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश घोर हिंसा और अराजकता में डूब गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी अवामी लीग के नेताओं-समर्थकों और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। वहां से विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश जब 1971 में बना था, तब वहां हिंदू जनसंख्या 22 प्रतिशत थी जो आज घटकर 7-8 प्रतिशत के बीच रह गई है। आज भी बांग्लादेश में 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। शेख हसीना के जाने के बाद भी सेना ने हिंदुओं की हत्याओं को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। वह उन्हीं तत्वों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुला रही है, जो हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में उनके सत्ता में आने पर हिंदुओं की सुरक्षा को और खतरा बढ़ाना तय समझिए। ऊपर से बीएनपी और जमात इस फिराक में हैं कि अवामी लीग का कोई नामोनिशान बांग्लादेश में न बचे। अगर यह हिंसा का दौरा लंबा चलता है तो भारत सरकार हिंदुओं एवं भारत समर्थक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के 1970-71 सरीखे नरसंहार में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। फिलहाल यही आवश्यक है कि बांग्लादेश सेना पर दबाव बनाया जाए कि वह हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हिंदुओं और लीग समर्थकों को वहां से निकाल कर भारतीय सीमा के निकट बांग्लादेशी भूमि पर ही राहत शिविरों में लाए ताकि किसी बड़ी हिंसा की सूरत में उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके।

बांग्लादेश के भयावह दिख रहे भविष्य को देखते हुए वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की दूरगामी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारत के निकट उनके घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाएं। इस मामले में हमें रूस से सीखना चाहिए, जिसने यूक्रेन के डोनस्क और लुहांस्क को रूसी भाषियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बना दिया। अगर हम यह नहीं कर सके तो बांग्लादेश में घटती हिंदुओं की संख्या को विलुप्त होते देखेंगे। संभवतः उनकी सुरक्षा में हमारे समूचे पूर्वोत्तर के भविष्य की सुरक्षा भी निहित है।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

कौआ कान ले गया वाला रवैया

राजीव सचान

वक्फ अधिनियम में बदलाव की पहल का विरोध अंधविरोध की राजनीति का नया प्रमाण ही है

वक्फ एक्ट में बदलाव से सहमत मजहबी नेता ● फाइल

लोकतांत्रिक देशों में सुधार की कोई पहल या नई नीति का निर्माण अथवा नया काम शुरू करना आसान नहीं होता। भारत भी इसका अपवाद नहीं। 1853 में जब अंग्रेजों ने देश में पहली बार रेल चलाई थी तो उसका यह कहकर विरोध हुआ था कि लोहे पर लोहा चलाना अपशकुन को निमंत्रण देना है। स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ। इसी विरोध के चलते उस पर अमल में देरी हुई। हाल के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और तीन कृषि कानूनों का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमलों को देखते हुए तो अब यह आवश्यक हो गया है कि नागरिकता कानून को और अधिक उदार बनाया जाए, ताकि 2014 के बाद भी भारत आए तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से शरण एवं नागरिकता दी जा सके। ऐसा करते हुए पीड़ित और आक्रांता में भेद किया ही जाना चाहिए।

यह किसी से छिपा नहीं कि तीन तलाक खत्म करने की पहल पर किस तरह आसमान सिर पर उठा लिया गया था। इस पहल का विरोध यह कहते हुए किया जा रहा था कि यह प्रथा गलत तो है, लेकिन इसे खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट या सरकार को नहीं करना चाहिए। जब भी समान नागरिक संहिता की चर्चा छिड़ती है, कई मुस्लिम नेता और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल तत्व उसका आंख मूंदकर विरोध करना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने-समझे कि इस संहिता के क्या प्रविधान होंगे? यह कौआ कान ले गया वाला रवैया है। इसी रवैये का परिचय वक्फ अधिनियम में सुधार के मामले में दिया जा रहा है। विरोध करने वाले वही जाने-पहचाने ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता और नकली सेक्युलर, लिबरल और वोक तत्व हैं। कुछ मुस्लिम नेता सुधार के पक्ष में भी हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समाज उनकी सुनेगा? अभी तक सभी सूत्रों के हवाले से इतना भर पता चला है कि वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन होंगे और इसके तहत वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार खत्म किए जाएंगे। सरकार के अलावा शायद ही किसी को पता हो कि इसके अलावा अन्य संशोधन क्या होंगे, लेकिन विरोध करने वालों को जानकारी के इस अभाव से कोई फर्क नहीं। वे तरह-तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा कुतर्क यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। इस कुतर्क के आगे कोई भी तर्क रखना बेकार है, क्योंकि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। शक करने वालों की तरह अंधविरोध से ग्रस्त लोगों का भी कोई इलाज नहीं।

किसी भी सरकार के फैसलों और उसकी नीतियों का विरोध या समर्थन उनके गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अपने देश की राजनीति में ऐसा नहीं होता। विरोध के लिए विरोध हमारे सभी दलों की प्रिय नीति है। कई विपक्षी दल इसी नीति का परिचय वक्फ अधिनियम में बदलाव पर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए उचित यही है कि वह वक्फ अधिनियम में जो भी संशोधन करने जा रही है, उन पर संसद में व्यापक बहस कराए, ताकि विपक्षी नेताओं को यह कहने का बहाना नहीं मिले कि सरकार ने बिना बहस आनन-फानन संशोधन विधेयक पारित करा लिया। व्यापक बहस का एक परिणाम यह भी होगा कि आम जनता और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में भ्रांतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकार मिले हुए हैं। आवश्यकता इसलिए भी है ताकि वक्फ संपत्तियों का निर्धन मुस्लिम समाज की भलाई के लिए सदुपयोग हो और इन संपत्तियों का दुरुपयोग एवं उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। कट्टरपंथी नेता कुछ भी कहें, खुद वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी यह मानते हैं कि उनकी छवि जमीन हड़पने वालों की बन गई है। इस छवि के लिए वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार है। वे किस मनमाने तरीके से काम करते हैं, इसका उदाहरण पिछले सप्ताह ही जबलपुर हाई कोर्ट के उस आदेश से मिला, जिसमें उसने शाहजहां की बहू के मकबरे समेत तीन अन्य मुगलकालीन संपत्तियों पर उसका दावा इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि ये संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में होनी चाहिए थीं। वक्फ बोर्डों को कैसे मनमाने अधिकार हासिल हैं, इसका प्रमाण तमिलनाडु का वह गांव भी है, जिसके मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जबकि यह मंदिर 1500 साल पुराना यानी इस्लाम के उदय के पहले का है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आमतौर पर सियासी और मजहबी रसूख वाले नेता काबिज रहते हैं। वे उसकी संपत्तियों का दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि उन पर कब्जे कराने के साथ उन्हें बेचते भी हैं। प्रयागराज में वक्फ की 50 करोड़ से अधिक की जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। 2023 में योगी सरकार ने उसे खाली कराया और अब वहां वक्फ बोर्ड की ओर से एक क्लीनिक का संचालन हो रहा है। कुछ वर्ष पहले कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से वक्फ की करोड़ों की संपत्ति बेच दी गई। इस रिपोर्ट पर न तो कोई जांच हुई और न ही कार्रवाई। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के एक पदाधिकारी को इस आरोप में हटाया गया कि उसने वक्फ की संपत्तियां बिल्डरों को बेच दी थीं। देश भर के करीब 30 वक्फ बोर्डों के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्तियां हैं, लेकिन किसी को और कम से कम गरीब मुसलमानों को नहीं पता कि उनसे उन्हें क्या लाभ मिल पा रहा है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPdf

ऊर्जा

आत्मज्ञान

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हमारा यह शरीर नश्वर है, परंतु इस शरीर को चलायमान रखने वाला आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा चैतन्य है। यह परमात्मा का ही अंश है। सर्वव्यापी चेतना है। अजर और अमर है। छांदोग्य उपनिषद में 'तत्त्वमसि' के माध्यम से ब्रह्म और जीव का संबंध समझाया है। तत्त्वमसि से आशय है 'तुम वही ब्रह्म हो' अर्थात तुम (जीव) परमात्मा का अंश हो। इसी प्रकार, प्रत्येक चेतन वस्तु परमात्मा का अंश है। यदि संसार के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश है तब फिर विभेद कहां है? फिर सभी समान हुए। एक छोटे से कीट पतंगे से लेकर सिंह या मनुष्य तक सभी एकसमान हुए, यही अद्वैतवाद की अवधारणा है।

शुद्ध मन, सात्विक आचरण तथा निरंतर अभ्यास द्वारा इच्छाओं एवं भौतिक सुख को तिरोहित कर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान की उपलब्धि के पश्चात हम संसार के समस्त तत्वों में परमात्मा का निवास अनुभव कर सकते हैं। जब हमें अद्वैत की अनुभूति हो जाए तो यह आत्मज्ञान की परम अवस्था है। इस प्रकार, आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य होनी चाहिए। इसके उपरांत हम सभी जीवों में परमात्मा के अंश को पहचानते हैं और सर्वत्र एकत्व का अनुभव करते हैं। एकत्व का अनुभव हो जाए तो मन में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार नहीं रह जाता। इस अहंकार भाव से मुक्ति मोक्ष की ओर उन्मुख करती है।

आत्मज्ञान की राह में मन की चंचलता और अस्थिरता एक बड़ा अवरोध बनती हैं। ये अवरोध हमें आत्मा के सत्य से साक्षात्कार नहीं करने देते। इन अवरोधों से पार पाने के लिए निरंतर अभ्यास और सात्विक आचरण के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए। जब मन शुद्ध और अनुशासित होता है तब ध्यान और साधना के द्वारा बुद्धि को एकाग्र कर आत्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है। यही आनंद का एकमात्र उपाय और जीवन को सार्थक बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है।

सोमा सुर

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

जल निकासी की हो समुचित व्यवस्था

'जल निकासी में असहाय शहर' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस कड़ी में कुछ बिंदु जोड़ना चाहता हूं। जैसे कि हमें जल निकासी से संबंधित अवसरंचना को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। शहरों में जलजमाव की बहुत चिंता की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र भी इस समस्या से दो-चार होते हैं, जिसकी तपिश मुख्य रूप से किसानों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम पूरे राष्ट्र को एक इकाई मानकर जलापूर्ति और जल निकासी तंत्र के बारे में विचार करें। वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। ड्रेनेज के क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले नीदरलैंड और जल संरक्षण में इजरायल के अनुभव का सहयोग लेकर निवेश करना उपयोगी हो सकता है। जल निकासी की समस्या का निदान समेकित हो न कि शहरी और गैर-शहरी क्षेत्र को अलग रखकर। दीर्घकालिक योजनाओं से ही टिकाऊ समाधान संभव है। जैसे हर घर को नल से जल और हर खेत को जल सुनिश्चित किया जा रहा है वैसे ही हर घर और खेत से समुचित जल निकासी का सोच विकसित करना होगा। तभी स्थितियां सुधरेंगी।

प्रो. मान सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक-आइसीएआर, नई दिल्ली

लोकतंत्र व आमजन की मनः स्थिति

अधिकांश देशों ने औपनिवेशिक चंगुल से मुक्ति पाने के बाद लोकतंत्र को तो अपनाया, परंतु वहां के आमजन की मनः स्थिति कट्टरता से ओतप्रोत रह गई तो वहां लोकतंत्र का बुरा हश्र होना ही था। आज बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया। कल यही स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका की भी थी। दुर्भाग्यवश भारत के तमाम पड़ोसी देशों में लोकतंत्र अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं है। इसके पीछे मूल कारण यही है कि लोकतंत्र के अनुरूप वहां के आमजन की मनःस्थिति नहीं है। ऐसे में सरकारों का कर्तव्य बनता था कि लोगों की मनःस्थिति बदलने में सहयोग करें, परंतु उन देशों की सरकारों ने ऐसा किया नहीं। नतीजा सामने है। भारत में लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में है, परंतु देश के चारों ओर अलोकतांत्रिक या यूं कहें कि अर्ध-लोकतांत्रिक सरकारें चुनौती हैं।

मुकेश कुमार मन्नन, पटना

गुलाम कश्मीर को अंग बनाए भारत

कैप्टन आर. विक्रम सिंह द्वारा लिखित आलेख 'पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय' पढ़ा। जम्मू-कश्मीर में बदलाव की धारा बह रही है। लोकसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। पांच वर्ष पूर्व केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलत जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए से मुक्ति मिली। इसके बाद आतंकी घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आई। कश्मीर में यह बदलाव पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। वह नए सिरे से जम्मू-कश्मीर में आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पूर्व की सरकारों की भूल की वजह से आज तक कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के अधीन है। गुलाम कश्मीर की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जब तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा।

ई हिमांशु शेखर, कैसपा, गया

सभी परीक्षाओं पर लागू हो विधेयक

सुरेंद्र किशोर का आलेख 'सुनिश्चित हो परीक्षाओं की शुचिता' पढ़ा। वर्तमान समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए आठ राज्य सरकारों ने एक कानून लागू किया है। बिहार सरकार ने भी बिहार लोक परीक्षा विधेयक लागू किया है। यह विधेयक केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामान्य परीक्षाओं में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में दिवंगत प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद शर्मा की पुस्तक 'इंटर काउंसिलः एक हकीकत' का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को एक लाभ कमाने वाले उद्योग के रूप में चित्रित किया है। उनकी पुस्तक में शिक्षा प्रणाली की गहराई से की गई समीक्षा आज भी प्रासंगिक है और शिक्षा प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाती है। बिहार और अन्य उत्तरी राज्यों में शिक्षा का पतन 1995 से शुरू हुआ। हालांकि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण 1996 में निष्पक्ष परीक्षा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पटना जिले में केवल 15 प्रतिशत छात्र इंटर साइंस और 16 प्रतिशत छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके थे। इसके बाद शिक्षा माफिया ने निष्पक्ष परीक्षा में बाधा डालकर केवल भ्रष्टाचार ही फैलाया। हमें निष्पक्ष परीक्षाओं की स्थिति को पुनः स्थापित करना होगा। इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। यथा, प्रश्नपत्र लीक करने वालों को सख्त सजा देना और परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

डा. पवन कुमार, जनकपुर, गया

पोस्ट

जिन बंगबंधु मुजीब ने बांग्लादेश निर्माण में अहम भूमिका निभाई वहां उन्हीं की मूर्ति तोड़ दी गई। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, वह एंबुलेंस में पड़े-पड़े सड़क पर ही मर गए थे। अनुपम सिंह@anupamnawada

शेख हसीना से विरोध था तो चलो उन्हें हटा दिया। यह ठीक है, लेकिन आखिर लगभग आधे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और आगजनी क्यों हो रही है? अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

कुछ समय पहले रफाह में लोगों की स्थिति को लेकर अभियान चलाने वाले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर मुखर नहीं दिख रहे। उनकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी या फिर किसी ने स्क्रिप्ट नहीं थमाई? रुबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

शेख हसीना पर सबसे बड़ा आरोप निरंकुशता का है, पर वहां आंदोलन की दूसरी लहर ने यह साबित किया कि इस आंदोलन के पीछे छात्रों को ढाल बनाकर दूसरों ने अपना उल्लू सीधा किया। प्रमोद जोशी@pjoshi23

अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत भारत में हिंदू-मुसलमानों को लड़ाया और अब उन्हें खुद अपने देश में मुस्लिम अराजकता से जूझना पड़ रहा है। सब कर्मों का खेल है। प्रकाश सिंह@singh_prakash

जनपथ

जारी है अंतर्कलह जलता बंगलादेश,
पर हिंदू समुदाय हित बेमतलब का क्लेश।
बेमतलब का क्लेश द्वेष में जाते मारे,
ज्यों दांतों बिच जीभ फंसे बैठे बेचारे।
जहां रहे इस्लाम वहां पर बारी-बारी,
हिंदू जन पर जुल्म हमेशा रहता जारी।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिछा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 117

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 7 अगस्त 2024

प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष अक्सर भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से होते हैं।
-रॉबर्ट कैगन

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हाल ही में दुनिया भर के शेयर बाजारों में जिस तरह से उथल-पुथल दिखाई दी और भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों को करीब पंद्रह लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, उससे अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई दुनिया अमेरिकी मंदी का शिकार होने वाली है?

मंदी आने को है?

अमेरिका में मंदी और ईरान-इस्राइल के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच हाल ही में दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल-पुथल देखी गई, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशकों को एक ही सत्र में करीब पंद्रह लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, उससे अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका में मंदी आने वाली है। यह भी देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी मंदी की आशंका का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार के कमजोर परिदृश्य और जापान में ब्याज दर बढ़ाए जाने से येन में कैरी ट्रेड के बंद होने से भी अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों-नैस्डैक, एसएंडपी 500 और डॉउजोंस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों और भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों-सेंसेक्स और निफ्टी50 में भी घबराहट देखी गई। दरअसल, अमेरिका में बेरोजगारी दर के पिछले तीन साल के उच्चतम स्तर पर रहने की वजह से मंदी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम कहते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगातार दो तिमाहियों तक नकारात्मक रहता है, तो उसे मंदी का सामना करना पड़ता है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ढाई फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ी है। लिहाजा अमेरिका में मंदी के संकेत बेशक दिख रहे हों, पर वहां मंदी आ चुकी है, यह कहना अतिशय ही होगा। भारत में बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पंजीकरण पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बीस लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा घटा है, जो चिंताजनक है। मगर राहत की बात है कि यह गिरावट जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई बाजारों और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम रही। उल्लेखनीय है कि 2008 की अमेरिकी मंदी, जिससे पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई थी, के समय

भी भारत काफी हद तक अप्रभावित रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार पर निर्भर करता है। यही वजह है कि वैश्विक झटकों का भारत पर उतना असर नहीं पड़ता। चूंकि केंद्र सरकार सतत रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, ऐसे में रोजगार का बढ़ना तय है। भारतीय शेयर बाजार इन सबसे कुछ दबाव में आने के बावजूद मजबूत बने हुए हैं, तो यह अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर आश्वस्त ही करता है। लेकिन बाजार की अनिश्चितताओं को मापने वाले सूचकांक इंडिया वीआईएक्स के 42 फीसदी बढ़ने से आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। ऐसे में, देखना होगा कि आगामी दिनों में बाजार कैसा प्रदर्शन करते हैं।

अब कट्टरपंथियों के हवाले

बांग्लादेश में अगर लोग शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ रहे हैं और खुद को मुक्ति योद्धाओं से अलग देखते हुए अराजकता फैला रहे हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि कौन-सी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं। ऐसे में भारत को अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है।

इसी महीने 15 अगस्त को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके बीस करीबी रिश्तेदारों की हत्या की 49वीं वर्षगांठ है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग ने उस दिन 'राष्ट्रीय शोक दिवस' मनाना तय किया था। लेकिन बाद में 'सूचित' किया गया कि वह 'कार्यक्रम अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया' है। ढाका में अचानक हुए सियासी बदलाव को बताने के लिए इससे ज्यादा मार्मिक और कुछ नहीं हो सकता।

हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाना, 1971 में मुक्ति युद्ध से जन्मे बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए सबसे नया सियासी घटनाक्रम है। 53 वर्ष पहले मुजीब के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी परिणति एक और सैन्य तख्तापलट के रूप में हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा उस सैन्य जनरल ने किया है, जो शेख हसीना का दूर का रिश्तेदार है, और जिस पर वह भरोसा करती थीं। 15 वर्षों तक सैन्य शासन के बाद, जिसे शेख हसीना ने आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता से रोका था, बांग्लादेश अब फिर सेना के अधीन है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले सैन्य तख्तापलट की तरह सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने अंतरिम सरकार का वादा किया है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इसमें उनकी या सेना की कोई भूमिका होगी या नहीं। मगर इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि फैसले कौन लेगा। उन्होंने 'न्याय' का भी वादा किया है। सबसे पहले रिहा होने वालों में शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया भी हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। पिछली सदी के अंत में खालिदा जिया और उनके इस्लामी सहयोगी पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए भी चिंता का कारण बन गए थे, जब बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था। ये ताकतें भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है, वह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्या बांग्लादेश फिर से आतंकवादियों का प्रमुख केंद्र

बन जाएगा? शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षित बनाने में भारी योगदान दिया। बांग्लादेश की धरती से संचालित होने वाले आतंकी शिविरों को उखाड़ फेंका गया। भारत को अब फिर से बांग्लादेश द्वारा कबायली चरमपंथ को बढ़ावा दिए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब नगा, उल्फा एवं अन्य चरमपंथी गुटों के साथ केंद्र सरकार के शांति समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ढाका के उथल-पुथल में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा सामाजिक रूप से ताकतवर इस्लामी संगठनों के साथ पाकिस्तान-समर्थक जमात-ए-इस्लामी की संलिप्तता है, जिसे हसीना प्रतिबंधित करना चाहती थीं, लेकिन नहीं कर पाईं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कबायली आबादी के अलावा बढ़ते व्यवसायी वर्ग एवं मदरसों के माध्यम से इस उथल-पुथल को हवा दी। पाकिस्तान में 'मुजीब युग' के अंत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत पर अपने पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा पर निगरानी बढ़ाने का दबाव कई गुना बढ़ गया है।

भारत को कूटनीतिक विवादों को जन्म दिए बिना हसीना शासन के दौरान दी गई सभी आर्थिक मदद, व्यापार रियायतों और परियोजनाओं को संशोधित करना होगा। पाकिस्तान की तरह चीन भी ढाका में हुए बदलाव पर खुश है। बीजिंग इस बात से नाराज था कि हसीना ने भारत से ऐसी परियोजनाएं हासिल कीं, जिन्हें वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव फैलाने के लिए चाहता है। रिपोर्ट बताती हैं कि हसीना को चीनी नेतृत्व ने तवज्जो नहीं दिया था। आर्थिक रिश्तों और सीमा प्रबंधन के अलावा, जो किसी भी दो पड़ोसी देशों के लिए ज्यादा मायने रखता है, भारत को गंगा जल संधि पर कूटनीतिक विवाद के लिए तैयार रहना होगा, जिसका नवीनीकरण होना है। अतीत में खालिदा जिया सरकार ने 1990 के दशक में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया था। एक अन्य विवादास्पद मुद्दा तीस्ता जल बंटवारे और उसके बेसिन के विकास का है, जो उत्तर बंगाल में 23 किलोमीटर लंबे संकरे 'चिकेन नेक' के पास है।

भारत ने हसीना सरकार को आश्वस्त किया था कि वह चीन को इससे दूर रखेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का विरोध किया। ढाका की नई सरकार अब चीन को इसमें शामिल कर सकती है, जो धन और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए तैयार है। इससे भारत के क्षेत्रीय और नदी संबंधी हित खतरे में पड़ सकते हैं। इस्लामी और कबायली चरमपंथियों के अलावा, भारत को बांग्लादेश के हिंदू एवं बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए भी चिंता करनी होगी, जिनके ऊपर वहां अक्सर हमले होते रहते हैं। बांग्लादेश अब भारत को रेडिमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में विरोधी के रूप में देखेगा, जहां दोनों विश्व बाजार में एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। बांग्लादेश के साथ भारत 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सबसे लंबी सीमा है। इन सीमा रेखाओं से पशुओं, मनुष्यों और नशीले पदार्थ की तस्करी रिश्तों को खराब कर सकती हैं, जिसे अब तक दोनों पक्षों ने कम महत्व दिया था। बांग्लादेश अब गरीब नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति वाला मुल्क है और अब वह भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। विश्व समुदाय छोटे से बांग्लादेश के साथ सहानुभूति रख सकता है। कूटनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि लोगों के बीच आपसी संबंधों का एक नया युग शुरू होने वाला है।

हसीना के नेतृत्व में भारत ने 'पड़ोसी पहले' की अपनी नीति के तहत बांग्लादेश को दोस्ताना पड़ोसी बताया था। कूटनीतिक व सुरक्षा कारणों से भारत न तो अपने छोटे पड़ोसियों से लड़ सकता है और न ही उनकी अनदेखी कर सकता है। बांग्लादेश उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हो गया है, जो लगातार सत्ता परिवर्तन से गुजरते हैं, जैसे नेपाल, अशांत श्रीलंका और मालदीव, जहां सत्ता में परिवर्तन को इस आधार पर देखा जाता है कि कौन भारत समर्थक है और कौन चीन समर्थक। बांग्लादेश तख्तापलट इस क्षेत्र की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत की तरह पश्चिम को भी दक्षिण एशिया में बढ़ती चीनी भूमिका से निपटना होगा, क्योंकि चीन को 'रोकने' के लिए अमेरिका दक्षिण एशिया को एक 'धुरी' बनाना चाहता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

निकोला टेस्ला

हम सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी हम अविभाज्य संबंधों के साथ आकाश में तारों की तरह एक साथ बंधे हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं।

अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं

आज दुनिया के सबसे सभ्य देश अपनी आय का अधिकतम हिस्सा युद्ध पर और न्यूनतम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। युद्ध के मैदान में मरने के बजाय अज्ञानता के विरुद्ध लड़ना अधिक गौरवपूर्ण होगा। इसके लिए एक नई दुनिया का जन्म होना चाहिए। एक ऐसी दुनिया, जो मानवता द्वारा किए गए बलिदानों को उचित ठहराएगी। यह नई दुनिया ऐसी दुनिया होनी चाहिए, जिसमें ताकतवर द्वारा कमजोरों का शोषण न हो, बुराई द्वारा अच्छे लोगों का शोषण न हो, जहां अमीरों की हिंसा से गरीबों का अपमान न हो, जहां बुद्धि, विज्ञान और कला के उत्पाद समाज की बेहतरी और जीवन को सुंदर बनाने के काम आएं, न कि व्यक्तियों द्वारा धन कमाने के लिए।

यह नई दुनिया शोषितों और अपमानित लोगों की दुनिया नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र लोगों और स्वतंत्र राष्ट्रों की दुनिया होगी। जब हम मनुष्य की बात करते हैं, तो हमारे पास समग्र रूप से मानवता की अवधारणा होती है, और उसके आंदोलन की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने से पहले हमें इसे एक भौतिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या आज कोई इस बात पर संदेह कर सकता है कि लाखों प्रकार के व्यक्ति एक इकाई का निर्माण करते हैं? यद्यपि हम सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी हम अविभाज्य संबंधों के साथ आकाश में तारों की तरह एक साथ बंधे हुए हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। सदियों से धर्म की अत्यंत बुद्धिमानी भरी शिक्षाओं में इस विचार की घोषणा की गई है, शायद केवल मनुष्यों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक गहन सत्य के रूप में। सभी धर्म के लोग इसे अलग-अलग तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, हम सब एक हैं। हालांकि, आध्यात्मिक प्रमाण ही एकमात्र ऐसे प्रमाण नहीं हैं, जिन्हें हम इस विचार के समर्थन में प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञान भी अलग-अलग व्यक्तियों की इस संबद्धता को पहचानता है, हालांकि बिल्कुल उसी अर्थ में नहीं, जिस तरह से यह स्वीकार करता है कि एक नक्षत्र के सूर्य, ग्रह और चंद्रमा एक शरीर हैं। यदि हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचना होगा। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन होते हैं कि वे अपने भीतर क्या चल रहा है, उससे पूरी तरह बेखबर हो जाते हैं। लेकिन बचपन से ही हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें शुरू में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारे भविष्य के लिए यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह काम आता है, क्योंकि इससे हमें जीवन के संरक्षण में आत्मनिरीक्षण के अमूल्य मूल्य की सराहना करने के साथ ही जीवन में उपलब्धि का एक साधन भी मिलता है। जीवन में उपलब्धि पाने के लिए हमें अकेले रहना होगा, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं।

निराशा का अंतिम रूप खुशी

सूत्र

अगर हमारे जीवन में निराशा आ जाए, तो याद रखें इसका आखिरी रूप खुशी ही होगी। हमें अतीत में देखना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी महान था, उसका अक्सर उपहास किया गया, उसकी निंदा की गई, उसका दमन किया गया, लेकिन वह संघर्ष से शक्तिशाली और अधिक विजयी होकर उभरा है।

दूसरा पहलू

मार्गरिट ए मुइर जहाज 1893 में एक तूफान के दौरान डूब गया था। वैज्ञानिकों को यह विस्कॉन्सिन बंदरगाह के मुहाने पर मिला है।

डूबने के 130 साल बाद मिला जहाज

मार्गरिट ए मुइर जहाज 30 सितंबर, 1893 को नमक लेकर मिशिगन झील से शिकागो के बंदरगाह की ओर जाते हुए मैकिनैक के संकीर्ण जलडमरूमध्य को पार कर गया था। जैसे ही चालक दल ने मिशिगन का चक्कर लगाया और दक्षिण की ओर बढ़ा, जहाज को 50 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे मुइर ने तेज हवाओं व ऊंची लहरों का सामना किया, जो जहाज के डेक को तोड़ गईं। कैप्टन डेविड क्लो और उनके चालक दल के छह सदस्य बमुश्किल जीवित बचे।

सारा रुबर्ग

मुइर में कैप्टन के वफादार कुत्ते की मौत हो गई। इससे दुखी कैप्टन क्लो, जिनके पहले तीन जहाज डूबने से बच गए थे, ने जहाज नहीं चलाने की शपथ ली।

मुइर में कैप्टन के वफादार कुत्ते की मौत हो गई। इससे दुखी 71 वर्षीय कैप्टन क्लो, जिनके पहले तीन जहाज डूबने से बच गए थे, ने जहाज नहीं चलाने की शपथ ली। साथ ही कहा कि उन्हें पानी पसंद नहीं। इस तरह मुइर 19वीं सदी में ग्रेट लेक्स के तूफानी पानी में फंसे अन्य हजारों जहाजों में शामिल हो गया। अब खो जाने के 130 साल बाद मुइर मिल गया है। 12 मई को विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन के तीन वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का उपयोग करके जहाज के अवशेष खोज लिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष और टीम के सदस्य ब्रेंडन बैलोद ने कहा कि मुइर की खोज पर जाने से पहले उन्होंने पुराने मानचित्रों और जहाजों के डूबने की समाचारपत्रों की खबरों के आधार पर पांच वर्ग मील का नक्शा तैयार किया था।

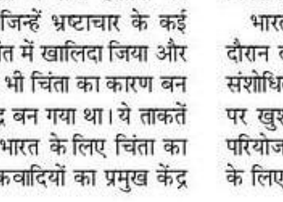

विस्कॉन्सिन अंडरवाटर आर्कियोलॉजी एसोसिएशन के तीन वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का उपयोग कर जहाज के अवशेष खोज निकाले।

इसके बाद वह और उनके साथी रॉबर्ट और केविन मई में एक दिन मुइर की खोज पर निकले। सूरज डूबने वाला था, लेकिन उनकी सोनार तकनीक झील के तल में मुइर का पता नहीं लगा सकी। वह अपना सामान समेटने वाले ही थे कि स्क्रीन पर एक बड़ी वस्तु रेंगती हुई दिखी। बैलोद ने कहा, 'उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह मुइर है।' इतिहासकारों के मुताबिक मुइर ग्रेट लेक्स के अवशेष वाले 8,000 जहाजों में से एक है। मुइर 130 फुट लंबा, तीन खंभों वाला स्कूनर था, जिसे अनाज व्यापार के लिए बनाया गया था। इसे 1872 में कैप्टन डेविड मुइर के लिए बनाया गया था, जिन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था। जहाज ने अपने 21 साल के सफर के दौरान सभी पांच महान (ग्रेट लेक्स) झीलों में माल पहुंचाया। कैप्टन क्लो ने अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मिलकर जहाज बनाए थे और दशकों तक उन्हें चलाया। बैलोद कहते हैं कि ऐसे जहाज बनाने के लिए अब 50 लोगों का दल लगेगा। बैलोद ने बताया कि जहाजों के अवशेषों से वह झीलों के किनारे लुप्त हुई संस्कृतियों की कहानी बताने के लिए करते हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

बांग्लादेश सीमा

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमारेखा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पश्चिम बंगाल	2,216.7
त्रिपुरा	856.0
मेघालय	443.0
मिजोरम	318.0
असम	263.0

भारत के राज्यों से लगती बांग्लादेश की सीमारेखा के आंकड़े किमी में। | स्रोत : MEA

आज हरियाली तीज है। मान्यता है कि श्रावणी शुक्ल पक्ष की तीज के दिन भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था।

पूरी हुई माता पार्वती की मनोकामना

एक बार महादेव ने देवी पार्वती को पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहा कि हे पार्वती! तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। एक बार नारद मुनि आपके पिता जी के पास पहुंचे और कहा, 'भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे अपना पति मान चुकी थीं।'

शिव जी ने पार्वती को बताया, 'इसके बाद तुम अपनी सखी के कहने पर घने जंगल में एक गुफा में शिवलिंग बनाकर तप करने लगी थीं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर दर्शन देकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता जी से कहा कि, मैं आपके साथ तभी चलूंगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे।' शिव जी ने कहा, 'हे पार्वती तुम्हारे तप और हठ के आगे पिता ने तुम्हारा विवाह मुझसे कराने की सहमति दे दी।' मान्यता है कि जो भी महिला हरियाली तीज पर विधि-विधान के साथ व्रत रखती है, तो उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित संकट दूर हो जाते हैं। इससे शिव-पार्वती प्रसन्न होते हैं।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 मार्च, 1957

फौजी गठबंधनों से अलग रहेंगे अरब देश

अरबदेश फौजीगठ-
बंधनों से अलग रहेंगे
मिस्र को युद्ध हर्जाना दिया जाय
काहिरा वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित
भारत के चुनाव
स्वतंत्र व निष्पक्ष

मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया और जॉर्डन की सरकारों के अध्यक्षों ने वार्ता के बाद संयुक्त घोषणा में कहा कि वे ऐसे कदम उठाएंगे, जिससे मिस्र की भूमि से इस्राइल को तत्काल हटाया जा सके। साथ ही अरब देश फौजी गठबंधनों से अलग रहेंगे।

भुला दी गई नदियां मचा रहीं तबाही

वायनाड भूस्खलन में सबसे बड़ी भूमिका उन नदियों की है, जिनको गैर-जरूरी मानकर कभी इन्सान ने समाप्त करने का प्रयास किया था।

पंकज चतुर्वेदी — आपदा

वायनाड-नीलगिरी पर्वतमाला के ऊंचे पहाड़ों से होकर कभी एक नदी बहती थी। तेज गति वाली नदी गर्मी में उदास रहती थी, लेकिन बरसात के छह महीने तेज वेग में नीचे जाकर पश्चिमी घाट की नदियों में मिल जाती। सन 1876 में इंग्लिश और स्कॉटिश कॉर्पोरेटिव सोसायटी ने यहां के पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा क्यारियां बनाकर असम और चीन की चाय की संकर नस्ल की खेती शुरू की। वहां कई छोटी-छोटी जल सरिताएं थीं। अंग्रेज बागान मालिक ने उन सरिताओं पर मिट्टी डलवा दी और उस पर मजदूरों के लिए बस्ती बसा दी।

वायनाड में आई भयावह तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान वेल्लारीमाला पर्वतमाला के नीचे मुंदक्कई और चूरलमाला में हुआ है। असल में इन दोनों जगहों पर घर और इमारतें भुला दी गई नदी के ऊपर बने हुए थे। वेल्लारमाला स्कूल की विशाल इमारत भी उस नदी के बहाव मार्ग पर बनी थी, जो कुछ साल पहले अपना रास्ता तो बदल चुकी थी, लेकिन शायद उसे भूली नहीं

थी। विदित हो कि वेल्लारीमाला पर्वतमाला कोझिकोड जिले में थिरुवंबाडी पंचायत से वायनाड जिले में मेप्पाडी पंचायत तक फैली हुई है। वायनाड के ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर जब मलप्पुरम जिले की तरफ आते हैं, तो शायद दुनिया का एकमात्र सागवान की लकड़ी का संग्रहालय नीलांबुर में मिलता है। इस छोटे से कस्बे की सुंदरता और जैव विविधता जिस चलियार नदी के कारण है, वह इन्सानों की लाशों से पट गई। यह नदी वायनाड जिले में इलमपिलेरी पहाड़ियों से निकलती है।

वायनाड से लगभग 90 किलोमीटर दूर इन्सानों के शव के टुकड़े मिलना बताते हैं कि वायनाड भूस्खलन से हुई तबाही में सबसे बड़ी भूमिका उन नदियों की है, जिनको गैर-जरूरी मानकर कभी इन्सान ने समाप्त करने का प्रयास किया था। विकास के नक्शे बनाने वाले यह भूल गए कि सभी नदियां जीवित जीव की तरह होती हैं और उनकी याददाश्त 200 साल की होती है।

इस तबाही के मूल में वेल्लारीमाला पर्वतमाला का भूस्खलन है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन के साथ मानवीय दखल जिम्मेदार है, लेकिन मलबे के तेजी से बहने के पीछे लुप्त नदी का अचानक जीवंत होना भी बड़ा कारण है। वर्ष 2020 में केरल में घटित जलवायु परिवर्तन, खासकर तापमान में वृद्धि की घटनाओं को समूचे तंत्र ने नजरअंदाज किया। उस वर्ष केरल में भयंकर जल प्लावन के बाद जैव विविधता के लिए जगजाहिर वायनाड में अचानक केंचुए और कई प्रकृति प्रेमी कीट गायब हो गए थे। कई शोध बताते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी से पश्चिमी घाट के आसपास के इलाकों में अचानक भारी बरसात होगी ही और जब ऐसे में प्रकृति पर मानवीय दखल बढ़ा, जंगल कम होने से मिट्टी की पकड़ ढीली हुई, तो भारत के इतिहास के सर्वाधिक भयावह भूस्खलन में से एक वायनाड में घटित हो गया।

वेल्लारीमाला पर्वतमाला घने जंगल और छोटी-बड़ी जलनिधियों से संपन्न ऊंट की पीठ के आकार की पर्वतमाला है। बार-बार इसे विशेष क्षेत्र घोषित कर सभी तरह के निर्माण रोकने की मांग होती रही, लेकिन पहाड़ खोद कर कोझिकोड राजमार्ग को चौड़ा करना जारी रहा। वेल्लारीमाला का भूस्खलन एक सैडल (ऊंची जमीन के दो क्षेत्रों के बीच एक निचला बिंदु) से उत्पन्न हुआ है। सैडल दो तरह से बन सकते हैं, या तो दरारों द्वारा या फिर कटाव से। आमतौर पर कटाव वाले सैडल चूना पत्थर में होते हैं, जो यहां है नहीं। स्पष्ट है कि वेल्लारीमाला का भूस्खलन दरारों के कारण हुआ था। जब इस तरह की दरारों में लंबे समय तक पानी जमा होता है और मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ती जाती है, तो यह अचानक फट पड़ता है। कोई 100 मीटर सीधी ऊंचाई से ढेर सारा मलबा नीचे आना और फिर उससे लुप्त हो गई नदी के बहाव का जुड़ जाना कल्पना से परे है कि मानव निर्मित कोई संरचना इस वेग में खड़ी रह सकती थी। फिर दो घंटे में 37 सेंटीमीटर बारिश का प्रकोप, तो था ही।

एक बात और जिस स्थान पर सबसे अधिक तबाही हुई, उसमें से एक है चूरलमाला। चूरल अर्थात बांस और माला अर्थात पहाड़। कभी यहां बांस का घना जंगल था और वह यहां के जमीन के कटाव को रोके रखता था। यह स्थापित तथ्य है कि नदी से हो रहे भ-कटाव और मिट्टी के कमजोर होने से रोकने में बांस की बड़ी भूमिका रही है। कुछ साल पहले यहां लोगों ने अधिक भूमि के लोभ में बांस के झुरमुटों को उजाड़ दिया था। अब किसान समझ गए कि यदि नदी को अपने खेत में आने से रोकना है, तो इसका एकमात्र इलाज बांस लगाना है। दुर्भाग्य से चूरलमाला में लगे-लगाए बांस को बेपरवाही से उजाड़ा गया। आज वायनाड में पुनर्वास का काम चल रहा है। कम से कम तीन कस्बे फिर से बसाने होंगे। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि अब किसी भूली बिसराई नदी के सुप्त हो गए बहाव पर बस्ती नहीं बसाई जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में बांस लगाए जाएं।

परिवर्तन का रहस्य यह है कि आप पुरानी चीजों से लड़ना छोड़कर नई चीजों के निर्माण में पूरी तरह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें।

– सुकरात

जिम्मेदारी के बजाय

मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के एक वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी इसके रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। थोड़े अंतराल के बाद संबंधित संगठनों के बीच बातचीत या समझौते की कोई खबर आती है और कुछ ही दिनों बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। सवाल है कि इतने समय से सरकार किस दिशा में क्या काम कर रही हैं कि एक छोटे से राज्य में इतने लंबे वक्त से टकराव और हिंसा कायम है। विचित्र हकीकत यह है कि राज्य सरकार आधिकारिक रूप से यह स्वीकार करती है कि हालात अच्छे नहीं हैं, मगर इसमें सुधार के लिए या तो उसे ठोस पहल करना जरूरी नहीं लगता या फिर उसके पास दूरदर्शिता का घोर अभाव है। वरना राज्य सरकार की तमाम एजंसियों, केंद्र सरकार के प्रयासों, सेना की दखल के बावजूद आज भी हिंसा का दौर जारी है, लोग बेघर हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है?

विचित्र यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जहां इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि राज्य में लगातार हिंसा को रोक पाने में उनकी सरकार नाकाम रही है, वहां वे राज्य में इस जातीय हिंसा की वजह से हुई तबाही के सिर्फ आंकड़े पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक सवाल के जवाब में सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह बताया कि राज्य में हुई हिंसा में अब तक करीब साठ हजार लोग विस्थापित हुए हैं और इस दौरान हुई आगजनी में ग्यारह हजार से ज्यादा घर जल कर खाक हो गए। यह समझना मुश्किल है कि एक वर्ष से ज्यादा से जारी हिंसा के पीड़ितों का आंकड़ा पेश करते हुए उन्हें इसका अहसास था या नहीं कि हिंसा को पूरी तरह रोकना उनका दायित्व है। मगर पिछले वर्ष जब एक अदालती निर्देश के तहत मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा देने का मसला उठा तभी जातीय हिंसा शुरू हुई। तब भी उनकी सरकार के पास इसे वहीं थाम लेने की दूरदर्शिता नहीं दिखी और न आज वह कुछ ऐसा ठोस कर पा रही है, जिससे राज्य के आम लोग इस आग से बाहर निकल सकें।

यह जगजाहिर तथ्य है कि मणिपुर में आज कुकी-जो और मैतेई सहित अलग-अलग समुदायों के बीच अविश्वास का स्तर इतना गहरा हो चुका है कि संवाद की गुंजाइश बेहद सिमट या खत्म हो गई है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिन पहले राज्य के जिरीबाम जिले में शांति बहाल करने के लिए हमार और मैतेई प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मगर सिर्फ चौबीस घंटे के भीतर वह समझौता टूट गया और इसके साथ ही फिर से हिंसा शुरू हो गई। इस पहले राज्य और केंद्र की सरकारों की ओर से सुरक्षा बलों को उतारने से लेकर शांति समितियां बनाने जैसी पहलकदमियों की घोषणाएं हो चुकी हैं। मगर यह एक अफसोसनाक हकीकत है कि किसी भी सरकारी कवायद का अब तक कोई सकारात्मक हासिल सामने नहीं दिख रहा है। आज भी वहां हिंसा की वही आग जारी है, जो एक नीतिगत अदूरदर्शिता की वजह से भड़की थी। हैरानी की बात यह है कि इस बीच सरकार के रवैए में कोई बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं दिख रहा, ताकि नए सिरे से हिंसा थमने या समस्या का कोई हल निकलने की उम्मीद जगे। तबाही के आंकड़े पेश करने के समांतर यह जरूरी है कि इस हालत के लिए अपनी नाकामी को भी स्वीकार किया जाए और कम से कम अब भी राज्य में उलझ चुकी इस जटिल समस्या का हल निकाला जाए।

मनमानी के केंद्र

कोचिंग केंद्रों की पारस्परिक स्पर्धा, भ्रामक विज्ञापनों, अनावश्यक जांच परीक्षाओं, मनमानी फीस वसूली, कक्षाओं में जरूरी सुविधाओं का ध्यान न रखने आदि को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं। मगर जबसे दिल्ली के एक कोचिंग केंद्र के तलघर में चल रहे पुस्तकालय में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत का मामला सामने आया है, कोचिंग केंद्रों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस संबंध में कड़ी टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा है कि कोचिंग केंद्र मौत का कुआं बन चुके हैं। ये अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक इनमें भवन सुरक्षा संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं होता, तब तक इन्हें अपनी कक्षाएं आनलाइन चलानी पड़ेंगी। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि इस संबंध में उन्होंने क्या उपाय किए हैं।

कोचिंग केंद्रों में मनमानी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोटा के कोचिंग केंद्रों पर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। वहां छात्रों की खुदकुशी को लेकर लगातार विरोध के स्वर उभरते रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ नियम-कायदे जरूर जारी किए, मगर उसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई भरोसेमंद उपाय नजर नहीं आता। दिल्ली मामले के बाद जब तलघर में कक्षाएं, पुस्तकालय आदि चलाने को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो नगर निगम और पुलिस ने ऐसे कोचिंग केंद्रों पर तालाबंदी जरूर कर दी, मगर कोचिंग केंद्रों की दलील थी कि तलघर के उपयोग को लेकर दिल्ली में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जो नियम हैं, उनमें काफी विरोधाभास है। हर घटना के बाद इस तरह के तर्क और दलीलें दी ही जाती हैं, मगर यह स्पष्ट है कि न केवल कोचिंग केंद्रों, बल्कि सरकार और संबंधित महकमों को विद्यार्थियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। यह स्पष्ट है कि कोचिंग केंद्र एक समांतर शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, जिसके लिए कोई स्पष्ट कानून और नियम-कायदे अभी तक नहीं बने हैं। जब तक इसके लिए कोई नियामक व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई भरोसा नहीं पैदा हो सकता।

अर्थव्यवस्था में पिछड़ती ग्रामीण महिलाएं

सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों और शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है।

अमित बैजनाथ गर्ग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा (करीब 48 फीसद) होने के बावजूद महिलाएं सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18 फीसद का योगदान देती हैं। इस अंतर को ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सांस्कृतिक बाधाएं, सीमित अवसर, शिक्षा की कमी और ऋण तक सीमित पहुंच शामिल है। एक रपट के अनुसार इस लैंगिक अंतर को पाटने से 2025 तक भारत की जीडीपी में 18 फीसद की वृद्धि हो सकती है। यह एक सक्षम वातावरण बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है। उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी पहलों से इस अंतर को पाटने और ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन भी ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। असल में ग्रामीण महिलाएं अक्सर दुनिया के गरीब तबकों में होती हैं और अपनी रोजी-रोटी के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर रहती हैं। इस परिवर्तन से पेयजल, भोजन और ईंधन की सुरक्षा पर असर पड़ता है, जिनके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। सूखे और बारिश में अनियमितता की वजह से महिलाओं को पानी और ईंधन इकट्ठा करने में अधिक समय लगाना पड़ता है। इससे फसलों और पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ता है, जिससे महिलाओं को कम भोजन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों और शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है। इससे उनकी पढ़ाई और नौकरी पाने के अवसर सीमित हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व दिया जा सकता है। उनका कौशल और क्षमता विकास किया जा सकती है। जेंडर-केंद्रित सार्वजनिक नीतियां बनाई जा सकती हैं। पिछले एक दशक में ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रमों ने उनके समुदायों में असाधारण योगदान दिया है। ग्रामीण महिलाओं के अथक प्रयासों को मान्यता देना दूसरों को प्रेरित करता है। इससे अधिक टिकाऊ आजीविका वाले भविष्य की दिशा में बहुत जरूरी बदलाव होता है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन आम आदमी के सामाजिक सरोकारों के बिना लक्ष्यों तक पहुंच पाना आसान नहीं है।

महिलाओं को अधिक समतापूर्ण समाज के लिए सशक्त बनाने के अलावा उनकी आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी विचार होना चाहिए। अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं, बढ़ता तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न तेजी से परिदृश्य को बदल रहे हैं, जो एक बड़े खतरे की ओर संकेत करते हैं। 'सीओपी 28' सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसमें कहा गया है कि आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखने के लिए ग्रामीण भारत की ओर रुख करना होगा। महाराष्ट्र में आजीविका कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है और वहां बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी आजीविका कार्यक्रमों के अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब भी

प्रयासों में और तेजी लाने की दरकार है, जिसके लिए कदम उठाने होंगे।

इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लड़ाई है बदलती जलवायु के सामने महिलाओं की आजीविका बनाए रखने की। यह कहीं अधिक कठिन चुनौती भरा काम है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की एक रपट के मुताबिक महिला प्रधान ग्रामीण परिवार जलवायु परिवर्तन के झटकों से असामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। एक डिग्री तापमान बढ़ने का अर्थ है पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में उनकी आय में 34 फीसद की भारी गिरावट। इससे एक महत्त्वपूर्ण सवाल है कि इस वैश्विक परिवर्तन को देखते हुए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में अक्सर इन सबसे अधिक जोखिम वाले समुदायों का समर्थन करने के लिए ठोस कार्रवाई की कमी क्यों होती है? जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण में महिलाओं का अक्सर कम प्रतिनिधित्व क्यों होता है?

> **ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की संसाधनों, सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सीमित है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कठिन हो सकता है। औसतन, गर्मी के कारण वे धनी परिवारों की तुलना में पांच फीसद अधिक आय खो देते तथा बाढ़ के कारण चार फीसद से अधिक आमदनी गवां देते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो और अधिक बुरा असर पड़ता है। पुरुषों द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग आठ फीसद अधिक तथा बाढ़ के कारण तीन फीसद अधिक नुकसान होता है।**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एफएओ की रपट के मुताबिक ग्रामीण लोगों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों का समाधान करने में विफलता संपन्न और निर्धन लोगों तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच पहले से मौजूद बड़े अंतर को और अधिक बढ़ा देगी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण तथा महिला-प्रधान परिवारों को आपदा आने पर पुरुषों की तुलना में पहले से ही अधिक वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है। अगर वेतन में इन महत्त्वपूर्ण मौजूदा अंतरों को दूर नहीं किया गया, तो यह अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान वैश्विक तापमान सन 1800 के अंत की तुलना में कुल मिलाकर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जिसके कारण बाढ़, तूफान और गर्म लहरों जैसे विनाशकारी मौसम में लगातार वृद्धि हो रही है। एफएओ ने कहा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि सामाजिक संरचनाएं तथा भेदभावपूर्ण मानदंड बहुत गहरे जड़ें जमा चुके हैं। इनसे लड़ पाना आसान नहीं है।

असल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की संसाधनों, सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सीमित है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कठिन हो सकता है। औसतन, गर्मी के कारण वे धनी परिवारों की तुलना में पांच फीसद अधिक आय खो देते तथा बाढ़ के कारण चार फीसद से अधिक आमदनी गवां देते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो और अधिक बुरा असर पड़ता है। पुरुषों द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग आठ फीसद अधिक तथा बाढ़ के कारण तीन फीसद अधिक नुकसान होता है। यह रपट यह सोचने को मजबूर करती है कि आखिर हम जलवायु परिवर्तन से ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या हम सुरक्षा कर भी पाएंगे या नहीं? अगर नहीं कर पाए तो इन महिलाओं का भविष्य क्या होगा? हमारे समाज और देश पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी बहुपक्षीय संस्थानों, राज्यों, नागरिक समाज और व्यापार समुदाय पर है। इनमें से हर हितधारक को अपने-अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करना चाहिए और महिलाओं की जरूरतों और अनुभवों के प्रति संवेदनशील प्रयासों के माध्यम से साझीदारी बनाने और सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करना चाहिए। उनकी क्षमताओं और संभावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों के बीच अधिक संपर्क आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह पहचानना भी महत्त्वपूर्ण है कि महिलाओं की मात्र उपस्थिति इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके अनुभव और नेतृत्व को जलवायु परिवर्तन नीतियों में एकीकृत किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर महिलाओं का अधिक समावेश आवश्यक है। उनको राष्ट्रीय और ग्रामीण स्तर पर भी नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण और पहल को भी शहरी महिलाओं की तरह सामने लाने की दरकार है।

सौहार्द का पाठ

सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

मूल्य शिक्षा का महत्त्व न केवल हमारे समाज में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह वह आधार है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आज के युग में जब नैतिकता और मानवीय मूल्य तेजी से लुप्त हो रहे हैं, मूल्य शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। मूल्य शिक्षा का अर्थ है ऐसे गुणों और सिद्धांतों की शिक्षा देना, जो व्यक्ति के चरित्र को सुदृढ़ बनाते हैं। यह शिक्षा न केवल स्कूलों और कालेजों में दी जानी चाहिए, बल्कि घर और समाज में भी इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। मूल्य शिक्षा हमें सहानुभूति, करुणा, ईमानदारी, सहनशीलता और आदर जैसे महत्त्वपूर्ण गुण सिखाती है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं।

मूल्य शिक्षा के कई महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख सहानुभूति और करुणा हैं। ये गुण हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। ईमानदारी भी एक अहम गुण है, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह गुण हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अहम भूमिका निभाता है। सहनशीलता वह गुण है जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा हमें सहनशीलता से मिलती है। आदर दूसरों की भावनाओं, विचारों और अधिकारों का सम्मान करने का गुण है, जो हमें समाज में सभी के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। इन सभी गुणों का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि वे हमें एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारा समाज और अधिक संवेदनशील, ईमानदार, सहनशील और सम्मानपूर्ण बन सकता है।

जीवन मूल्यों की शिक्षा दरअसल नैतिकता और मानवीय मूल्य सिखाकर हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम एक सहानुभूतिपूर्ण, करुणामयी और ईमानदार समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मूल्य शिक्षा, नैतिकता और आदर्शों की समझ देकर समाज को सुदृढ़ और समृद्ध बनाती है।

स्कूल बच्चों का चरित्र निर्माण करने का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहां उन्हें शैक्षणिक ज्ञान के साथ नैतिक और मानवीय मूल्य भी सिखाए जाते हैं। स्कूलों में मूल्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों को नैतिकता, सहानुभूति, ईमानदारी और आदर जैसे महत्त्वपूर्ण गुण सिखाने का उद्देश्य रखता है। यह कार्यक्रम उन्हें न केवल एक अच्छे विद्यार्थी, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इन गुणों के माध्यम से बच्चे समाज में सकारात्मक योगदान देने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं।

समाज वह स्थान है, जहां हम अपनी अधिकतर जिंदगी बिताते हैं और यहां हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना और उनके साथ सामंजस्य बनाना होता है। मूल्य शिक्षा लोगों को सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ देती है, जिससे वे अपने कार्यों और निर्णयों में नैतिकता का पालन कर सकें। जब समाज में मूल्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाता है, तो इससे न केवल व्यक्तियों का नैतिक विकास होता है, बल्कि यह पूरे समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। नैतिक मूल्यों से लैस व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार और दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील होते हैं। इससे आपसी सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम ईमानदारी, सद्भावना, सहिष्णुता और न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण गुणों को समाज में स्थापित कर सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण के लिए भी अपरिहार्य है।

मूल्य शिक्षा व्यक्ति के चरित्र को सुदृढ़ बनाती है। सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम एक नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति को आत्म-संयम, सहनशीलता और आत्म-सम्मान जैसे महत्त्वपूर्ण गुण सिखाती है, जो हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और आदर का भाव रखने की प्रेरणा देती है, जिससे समाज में सौहार्द और सहयोग का माहौल बनता है। इससे हम सभी एकजुट होकर एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। मूल्य शिक्षा के ये गुण हमें एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाते हैं, जो समाज की प्रगति और एकता में योगदान देते हैं। यह हमें न केवल एक अच्छे इंसान, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। इसके माध्यम से हम अपने समाज को एक नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण स्थान बना सकते हैं, जहां सभी लोग एक-दूसरे का आदर और सम्मान करें।

दुनिया मेरे आगे

> **समाज वह स्थान है, जहां हम अपनी अधिकतर जिंदगी बिताते हैं और यहां हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना और उनके साथ सामंजस्य बनाना होता है। मूल्य शिक्षा लोगों को सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ देती है, जिससे वे अपने कार्यों और निर्णयों में नैतिकता का पालन कर सकें।**

सफलता की सीढ़ियां

आज की नजर, अर्जुन-सा निशाना और भारतीय निशानेबाजी का शानदार फसाना। मनु भाकर ने छोटी-सी उम्र में इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस अद्वितीय उपलब्धि ने मनु को आजादी के बाद एक ही संस्करण में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय, निशानेबाजी में देश की इकलौती खिलाड़ी और पीवी सिंधु और सुशील कुमार के बाद दोहरी ओलंपिक पदक विजेता बना दिया है। मनु के ये अभूतपूर्व कारनामे तक की यात्रा इतनी आसान नहीं, बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण थी। तोक्यो 2020 में बंदूक के विश्वासघात की टीस उनके दिमाग में जरूर रही होगी, हालांकि पेरिस में मिली शानदार विजय ने उन भूलने लायक पलों को पीछे छोड़ दिया और उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाया। मनु ने अपने आलोचकों को चुप किया साथ ही वे युवा एथलीटों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गई हैं। बारह वर्षों में देश के लिए एक से भले दो पदक लाने के दबाव पर काबू पाने से उनके मजबूत मनोबल और सटीक एकाग्रता का पता चलता है। मनु की कहानी कड़े तप और धैर्य का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाती है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां मात्र हैं।

– महाजन रोहन, जम्मू

युद्ध के बादल

ईरान और इजराइल में चल रहे तनाव और टकराव को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे कदम भी अब ठिठक गए हैं, क्योंकि उनकी आशंका है कि दोनों देश अब युद्ध के नए दौर के मुहाने पर अडिग खड़े हो गए हैं। यों तो युद्ध किसी मसले का कोई हल नहीं, बल्कि युद्ध खुद एक मसला है, लेकिन हमास के इस्माइल हानिये और हिजबुल्ला के फुआद शुकर की मौत को ईरान पचा नहीं पा रहा है। इसीलिए वह बार-बार दोहरा रहा है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है... वह इजराइल से बदला लेकर रहेगा। तीन महीने पहले अप्रैल में भी ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई के दौरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों एवं ड्रोन द्वारा खूब बमबारी की गई थी, लेकिन उस दौरान मामले को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया गया था। मगर अब वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध की विभीषिका को झेल रही दुनिया एक और युद्ध को झेलनी की स्थिति में नहीं है।

– मामचंद, रजोकरी, दिल्ली

बाधाओं के बीच

हरियाणा के झज्जर जिले से ताल्लुक रखने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक खेलों में शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देश का मान बढ़ाया है। यह उपलब्धि कुछ मायने में खास हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, झज्जर बालिका लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक प्रभावित रहा। वहां से असामान्य प्रतिभा का निकलना और यों वैश्विक पटल पर छा जाना विशेष है। इसका मतलब यह भी है कि महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों के बीच भी कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जो अपनी बेटियों को आसमान की ऊंचाई में उड़ने का हौसला देते हैं। आज महिलाएं विज्ञान, खेल, उद्योग, प्रबंधन लगभग हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। मनु भाकर का तमाम बाधाओं के बीच अपने जज्बे को बनाए रखना यह साबित करता है कि हौसला बरकरार हो तो विपरीत हालात में भी कामयाबी खुद अपनी राह बनाती है।

– जोगिंदर भारद्वाज, नरेला, दिल्ली

असंतोष की आग

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। इससे पूर्व ऐसी स्थिति श्रीलंका में पैदा हुई थी। अब स्वाभाविक ही भारत ने बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या कर उनकी सरकार छीन ली गई थी। शेख हसीना पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। पिछले साल आम चुनाव में केवल अवामी लीग ही चुनाव लड़ी थी, बाकी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर किचेन का सारा सामान और शेख हसीना के कपड़े लूट लिए। पूरे प्रदर्शन के दौरान रोकथाम के लिए कहीं भी सेना और पुलिस नहीं थी। भारत के यह जरूरी है कि वह बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

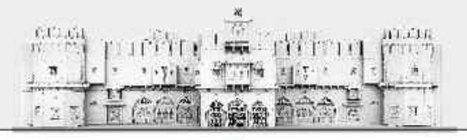

अनिश्चितता-अस्थिरता के साए में बांग्लादेश

बांग्लादेश एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। सात महीने पहले हुए आम चुनाव में तीन चौथाई बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली शेख हसीना को भारी हिंसा के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति ने आंदोलनकारी छात्रों के दबाव में आकर मंगलवार को संसद भंग कर दी। बेशक इसे आंदोलन की जीत मान लिया जाए लेकिन 53 साल पुराने देश के सामने असली चुनौतियां अब आने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब देश को चलाएगा कौन? क्या सेना सरकार चलाएगी? या फिर सभी दलों की भागीदारी से अंतरिम सरकार बनेगी? या फिर आठ महीने के भीतर देश एक और जनमत संग्रह देखेगा? अनेक सवालों के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर एक चुनी हुई सरकार गिरी क्यों और प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा?

बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता के लिए भले ही ठीकरा छात्रों के सिर पर फोड़ दिया जाए लेकिन इसके पीछे अनेक दिमाग काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे से अमरीका अपनी चालें चल रहा था तो चीन और पाकिस्तान अपने तरीके से षड्यंत्र का ताना-बाना बुन रहे थे। कट्टरपंथी ताकतें भी अपना खेल खेल रही थीं। बांग्लादेश किस रास्ते पर जाएगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ये देश अब पाकिस्तान की तरह अस्थिरता के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। आने वाली सरकार से तय होगा कि इसके भारत के साथ संबंध कैसे रहते हैं। यदि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार आती है तो उसमें कौन-से दल होंगे? कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी जैसे दल सरकार में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश भी तालिबान राज की तरफ जा सकता है। इससे भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चिंता वहां रहने वाले आठ फीसदी हिंदुओं की भी है। सत्रह करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश में सवा करोड़ हिंदू जनसंख्या है। वहां के माहौल से हिंदुओं में भय है। 1975 में वहां हुए सैन्य तख्ता पलट के समय भी ऐसा ही माहौल था। तब भी शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी।

पड़ोसी देश में हुआ यह राजनीतिक घटनाक्रम भले ही बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो लेकिन यह हर हाल में भारत और भारतीय लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए भारत सरकार और यहां के राजनीतिक दलों को पूरी संवेदनशीलता दिखाने के साथ-साथ सतर्कता भी बरतनी होगी। राजनीतिक फायदे के लिए राजनेताओं को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ें। भारत ने पहले भी समझदारी दिखाई है और अब भी हर फैसला सोच-समझ कर लेगा।

बांग्लादेश: हसीना का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए कई मोर्चों पर झटका है, खासतौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं

सियासी उलटफेर भारत के लिए चिंताजनक

शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने की घटना पर समूचे विश्व की नजर है। जहां तक भारत का मामला है, तो इससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग चार हजार किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है। वहां पर किसी भी तरह की अस्थिरता से भारत का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए बांग्लादेश के हालात पर निरंतर नजर रखनी होगी।

बढ़ गया है घुसपैठ का खतरा, चौकसी जरूरी

बांग्लादेश का घटनाक्रम चौंकाने वाला है। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ दिया। भारत से उन्होंने अनुरोध किया था जिस पर उन्हें 'सुरक्षित मार्ग' की पेशकश की गई। आने वाले दिनों में वे लंदन या अन्य किसी देश में शरण मांग सकती हैं। अमरीका में रह रहे उनके पुत्र सजीब वाजेद जॉय कहते हैं कि उनकी मां ने देश की काया पलट दी। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब यह देश विफल राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। आज यह देश एशिया की उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है।' सजीब वाजेद जॉय ने यह भी कहा कि वे अब फिर कभी राजनीति में नहीं आएंगी।

मनिष दाभाडे
थिंकटैंक द इंडियन फ्यूचर के संस्थापक, जेएनयू में कूटनीति के एसोसिएट प्रोफेसर
@patrika.com

दूसरी ओर, बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सत्ता संभाल ली है और उन्होंने जल्द ही अंतरिम सरकार गठित किए जाने की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खालिदा घर में नजरबंद हैं। किसी को जरा भी यह आभास नहीं था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की एकमात्र उत्तराधिकारी 76 वर्षीय हसीना अपने पिता की स्टैच्यू को तोड़े जाने की गवाह बनेंगी।

इस साल जनवरी में शेख हसीना ने अवामी लीग के लिए रेकॉर्ड 5वीं और लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा गया। विशेषकर दुनिया में गारमेंट्स के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में। उनके कार्यकाल में पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर तीन गुना हो गई। हसीना को सैन्य शासन के खिलाफ कट्टर लोकतंत्र समर्थक और धर्मनिरपेक्षता की प्राचीर का निर्माण करने वाले के रूप में देखा गया। उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। भारत में उन्हें विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार और विकास में सहयोगी माना जाता था।

दरअसल, विपक्ष को दबाने के लिए हसीना ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की रणनीति अपनाई। यह भी आरोप हैं कि उन्होंने देश को एक पार्टी तंत्र में बदल दिया और सरकारी नौकरियों में अंधाधुंध तरीके से पार्टी सदस्यों को पदस्थापित करा दिया। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। पुलिस राज और उससे जुड़ी ज्यादतियों का बढ़ना आम बात थी। उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर 18 फीसदी के आसपास रहने और कोविड से उबरने के बाद की चुनौतियों ने हसीना के प्रति नाराजगी बढ़ गई। एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हसीना को बांग्लादेश में भारत समर्थक और पीएम मोदी की प्रबल समर्थक के रूप में देखा जाने लगा। उन पर बांग्लादेश में रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों पर नरम रुख अपनाने का भी आरोप लगा।

हसीना का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए कई मोर्चों पर झटका है। सबसे महत्त्वपूर्ण है दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदार को खोना। अस्थिरता और हिंसा से भरा बांग्लादेश भारत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिरदर्द बढ़ा देगा। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान को रक्षा आपूर्ति करता है। आइएसआइ निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी और गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेगी जो भारतीय हितों के खिलाफ है। इस राजनीतिक हिंसा और आर्थिक अनिश्चितता से भारत में घुसपैठ बड़ी चुनौती बन सकती है।

चुनौती का एक और मोर्चा!

पाकिस्तान की साजिशें तो उसके अस्तित्व में आने के बाद से ही अलगाववाद और आंतकवाद के रूप में भारत झेल रहा है। चीन की साजिशें भी किसी से छिपी नहीं हैं। नेपाल में भी चीन और पाकिस्तान मिल कर भारत विरोधी कुचक्र रचते ही रहते हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश में भी भारत विरोधी ताकतों को अपना नया मोर्चा खोलने का मौका हमारी चुनौतियां बढ़ाएगा ही।

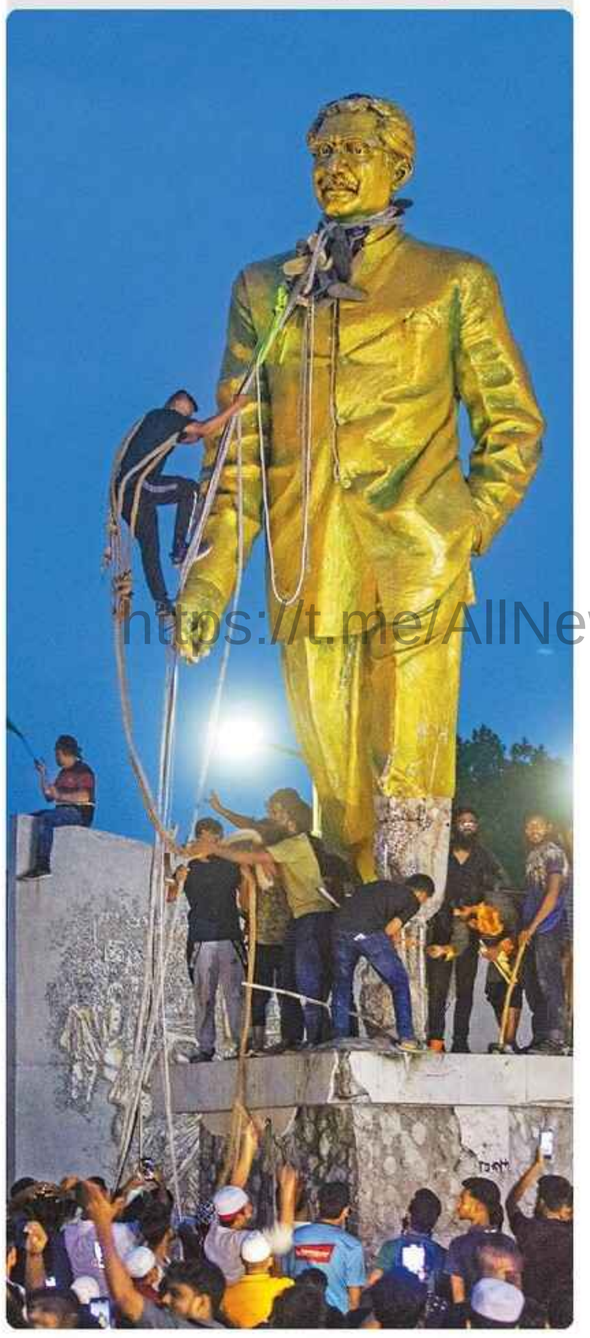

https://t.me/AllNewsPaperPdf

क्या पटरी पर आ पाएंगी आर्थिक गतिविधियां

बांग्लादेश में शेख हसीना का राज खत्म हो गया। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से शुरू हुआ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने इसी साल चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। 2009 से उनकी सरकार का यह लगातार चौथा कार्यकाल था। दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नए देश के रूप में उभरने के बाद से वह सबसे लम्बे समय तक हुकुमत करने वाली नेता रही हैं। पिछले 2018 के चुनाव में, उन्होंने एकतरफा जीत हासिल करते हुए संसद की 300 सीटों में से 288 सीटों पर अपना परचम लहराया था।

शेख हसीना के पिछले तीन कार्यकाल में असाधारण आर्थिक विकास हुआ। विश्व बैंक ने भी कहा कि 2026 तक बांग्लादेश 'सबसे कम विकसित देश' के वर्ग से बाहर निकल जाएगा। इस आशातीत सफलता का मूल उसका रेडिमेड गारमेंट्स का निर्यात है जिसमें यह भारत से आगे निकलते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। रेडिमेड गारमेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग (आरएमजी) की निर्यात में प्रमुख हिस्सेदारी है, जीडीपी में हिस्सेदारी 11 फीसदी है। यह क्षेत्र 2.5 मिलियन महिलाओं को रोजगार देता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। अब यह सब आर्थिक विकास देशव्यापी दंगों के कारण आई मंदी के चलते रसातल में पहुंच गया है। देश उच्च महंगाई दर का सामना कर रहा है। व्यापार घाटा बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और कर्ज भुगतान में तनाव बढ़ा है। आय और सम्पत्ति की असमानता अप्रत्याशित स्तर पर पहुंची है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष शेख हसीना की पार्टी की जीत मुख्य विपक्षी दल के चुनाव बहिष्कार के बीच हुई थी और मतदान भी बमुश्किल 40 फीसदी हुआ था जबकि 2018 में मतदान प्रतिशत 80 था। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी अशांति सरकार-विरोधी अभियान में बदल गई। पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर हिंसा भड़काने व आतंकवाद फैलाने का भी आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है।

मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों की मूल वजह सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के रिश्तेदारों और वंशजों के लिए आरक्षण है। 2018 में आरक्षण प्रणाली खत्म कर दी गई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। जून में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी दंगे भड़क उठे, विशेषकर युवा और छात्र इसमें शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित निर्णय लेते हुए इस फैसले को पलट दिया।

अजीत रानाडे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री, विचारक और राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

बांग्लादेश की इस अराजकता से कई सबक भी हैं। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी मानते हैं कि आरक्षण के कारण मेधावी युवाओं को अवसरों से वंचित किया जा रहा है। मुक्ति योद्धाओं के परिवारों को मिली रियायत के लिए फर्जी प्रमाणपत्र के मामले सामने आए हैं। भारत में भी वंचित वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था है। इसका लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र के मामले उजागर हुए हैं। उच्च बेरोजगारी दर, नियंत्रण से परे जाती महंगाई, विदेशी मुद्रा की बिगड़ती स्थिति से बढ़ती ईंधन कीमतें और बढ़ती असमानता आदि से तनावपूर्ण हालात तो थे ही, आरक्षण की चिंगारी भी इसमें शामिल हो गई। चरमपंथी विचारधारा ने भी युवाओं में असंतोष को बढ़ाया। एक स्थिर और समृद्ध पड़ोसी का होना भारत के हित में है।

'गरीबों के बैंकर' यूनुस की हो सकती है अहम भूमिका

'गरीबी मेरे चारों ओर थी, और मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। मुझे विश्वविद्यालय की कक्षा में अर्थशास्त्र के सुरुचिपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाना मुश्किल लगता था। मैं अपने आसपास के वंचित लोगों की मदद के लिए तत्काल कुछ करना चाहता था।' यह कथन है एक संपन्न परिवार में जन्मे नोबेल पुरस्कार प्राप्त मुहम्मद यूनुस का, जो आजकल फिर से बांग्लादेश में चर्चा में हैं। उन्हें आंदोलनकारी और सेना के साथ-साथ अन्य लोग भी पसंद करते हैं।

यूनुस ने अपने जीवन में गरीबों की पीड़ा को अनुभव किया तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के बजाय चिंतन, शोध और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलवाया तथा उनकी गरीबी दूर की। मुहम्मद यूनुस ने अर्थशास्त्र में चटगांव विश्वविद्यालय से स्नातक, अमरीका के कोलोराडो विश्वविद्यालय से मास्टर्स और वैंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय 'बांग्लादेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था' था। यूनुस ने सीधे सामाजिक सरोकारों से जुड़ने से पहले कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, जिनमें मिडल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी, टेनेसी विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय शामिल हैं। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के तुरंत बाद वह वापस लौट आए। जब वह वापस लौटे, तो उन्हें चटगांव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का प्रमुख चुना गया, पर तब बांग्लादेश भीषण अकाल से जूझ रहा था और उन्हें लगा कि यह समय गरीबी उन्मूलन के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करने का है।

वेद माथुर
लेखक पूर्व बैंकर और आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों के जानकार हैं
@patrika.com

मुहम्मद यूनुस ने गरीबों के लिए माइक्रोक्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा शुरू की और बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन बदलने में सफल हुए। बांग्लादेश में उचित गारंटी या प्रतिभूति के अभाव में पारंपरिक बैंक ऋण नहीं मिल पाता था। लोगों को ऋण प्रदान करने के तरीकों पर कई वर्षों तक प्रयोग करने के बाद, उन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। कहा जाता है कि इसके बाद बांग्लादेश में गरीबी दर में काफी कमी आई। यूनुस निरंतर सरकार पर गरीबों-वंचितों की उपेक्षा व पूंजीपतियों की मददगार नीतियां बनाने का आरोप लगाते रहे। यूनुस का कहना था कि शेख हसीना की नीतियों से बांग्लादेश का समग्र जीडीपी भले ही बढ़ जाए पर इसका लाभ कम आय वाले आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। शेख हसीना सरकार ने यूनुस पर टैक्स चोरी से लेकर श्रम कानून के उल्लंघन तक के दर्जनों मुकदमे दर्ज किए। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें 2011 में ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से इस आधार पर बाहर कर दिया कि वह 60 वर्ष की कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके थे। यूनुस ने इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी पर बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने इसे बरकरार रखा।

अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत दुनिया की 170 से अधिक शख्सियतों ने बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार को पत्र लिखकर प्रो. यूनुस के 'लगातार हो रहे न्यायिक उत्पीड़न' को रोकने की मांग भी की थी। 84 वर्षीय यूनुस, जिन्हें 'सबसे गरीब लोगों के बैंकर' के रूप में जाना जाता है, को जब वर्ष 2006 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब उन्होंने नोबेल व्याख्यान के दौरान कहा था कि मनुष्य का जन्म भूख और गरीबी का दुख झेलने के लिए नहीं हुआ है। हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी चाहिए, जिसमें गरीबी और अभाव इतिहास के संग्रहालयों तक ही सीमित हो। अब यह तय माना जा रहा है कि शेख हसीना के पद से हटने के बाद अंतरिम सरकार में मुहम्मद यूनुस की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

पड़ोस में भारत-विरोधी ताकतों की बढ़त, परीक्षा की घड़ी

राज कुमार सिंह
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं
@patrika.com

एकतरफा चुनाव के कारण शेख हसीना और आवामी लीग की साख पर गंभीर सवाल उठे, पर तख्तापलट की भूमिका लिखी गई आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन से, जिसमें बाद में तमाम विरोधी ताकतें भी शामिल हो गईं। पुलिस व सेना की कार्रवाई में हिंसा और भी भड़की। शेख हसीना आंदोलन को समझ ही नहीं पाईं।

भारतीय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी तो की थी 5 अगस्त को इजरायल और ईरान के बीच टकराव से महायुद्ध के आगाज की, लेकिन तख्तापलट बांग्लादेश में हो गया। एक महीने से भी ज्यादा समय से बांग्लादेश में जारी आरक्षण विरोधी छात्र हिंसा ने ऐसा रूप लिया कि 5 अगस्त को एक नाटकीय घटनाक्रम में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे कर देश से पलायन करने वाली शेख हसीना और बांग्लादेश में हिंसा के निशाने पर आ गई उनकी आवामी लीग पार्टी की आगे क्या भूमिका होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन 5 अगस्त के घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया में शांति और शक्ति संतुलन से जुड़े कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम और प्रभाव होंगे। लगभग 20 साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहने वाली शेख हसीना ने इसी साल जिन चुनावों के जरिए 5वीं बार सत्ता संभाली थी, उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था और विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार किया था, पर पाकिस्तान व बांग्लादेश में तो अक्सर ही ऐसा होता रहा है।

जिस तरह एकतरफा चुनाव हुए, उससे शेख हसीना और आवामी लीग की साख पर गंभीर सवाल उठे, पर तख्तापलट की भूमिका लिखी गई आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन से, जिसमें बाद में तमाम विरोधी ताकतें भी शामिल हो गईं। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के मुक्ति के संग्राम की अगुवा रही मुक्ति वाहिनी के सदस्यों के परिजनों के लिए 2024 में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर शेख हसीना सरकार के विरुद्ध यह छात्र आंदोलन भड़का। आरक्षण 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया था, जिसका छात्र, घटती सरकारी नौकरियों और बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर विरोध कर रहे थे। पुलिस और सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मारे भी गए, जिससे हिंसा और भी भड़की। शेख हसीना इस छात्र आंदोलन को सही ढंग से समझ ही नहीं पाईं। कभी आंदोलनकारियों को गद्दार करार दिया तो कभी बातचीत का न्योता भेजा। जाहिर है, इससे विरोधी ताकतों को छात्र आंदोलन के राजनीतिक इस्तेमाल का मौका मिल गया। बेशक 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के स्वतंत्रता सेनानी रहे लोगों के परिजनों को 53 साल बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण को तर्कसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। शेख हसीना अपने वोट बैंक को मजबूत करने की ही कवायद कर रही थीं, जो अंततः उन्हें इतनी भारी पड़ी कि सत्ता छोड़ कर विदेश में शरण की नौबत आ गई।

दरअसल, कोरोना काल से ही डगमगाई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को आधार बना कर शेख हसीना विरोधी ताकतों, जो असल में भारत विरोधी ताकतें भी हैं, ने सत्ता विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बेलगाम महंगाई इसमें मददगार बनी। आम चुनाव के जरिए जब मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे, तो मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान की आइएसआइ और चीनी षड्यंत्रकारियों से मिल कर तख्तापलट की साजिश रची, जिसे अंजाम देने का मौका खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण के अतार्किक दांव और विरोध में हुए छात्र आंदोलन से निपटने के गलत ढंग के जरिए उपलब्ध करवा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पाकिस्तानपरस्त और भारत विरोधी छवि किसी से छिपी नहीं है। खबरें हैं कि उनके बेटे और पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले तारिक रहमान ने पिछले दिनों अपने चीनी मित्रों और आइएसआइ के असरदार लोगों से विदेश में मुलाकातें की थीं। कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी भी पाकिस्तानपरस्त और भारत विरोधी हैं। दोनों ही शेख हसीना को भारत की कठपुतली बताते और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाते रहे हैं। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि पाकिस्तान के दमन से पूर्वी पाकिस्तान को मुक्ति दिलवा कर बांग्लादेश को पृथक देश बनवाने में भारत की निर्णायक भूमिका रही, जिसका बदला लेने की हसरत हर पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की सेना का जनरल पाले रहता है। सच यह भी है कि दोनों देशों के बीच गहरे दोस्ताना और व्यापारिक रिश्ते भी हैं। आपसी विश्वास पर टिके ये रिश्ते दोनों ही देशों के लिए परस्पर लाभप्रद रहे हैं।

आंदोलनकारियों की घेराबंदी के बाद बांग्लादेश की सेना ने भी शेख हसीना को इस्तीफा दे कर देश छोड़ने की सलाह दी। हसीना के पलायन के कुछ ही घंटे बाद वैसे ही दृश्य नजर आए, जैसे कुछ समय पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में नजर आए थे। सुखद संकेत है कि सेना ने खुद सत्ता पर काबिज होने के लोभ से बचते हुए अंतरिम सरकार के गठन का विकल्प चुना है, पर आंदोलनकारियों ने जिस तरह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाएं तोड़ी हैं, वह आंदोलन के पीछे गहरी साजिश का जीता-जागता सबूत है। बंग बंधु के संबोधन से चर्चित मुजीब भारत को सच्चा मित्र मानते थे। पर अब माहौल बता रहा है कि जब भी चुनाव होंगे, चीन और पाकिस्तान की सरपरस्ती में भारत विरोधी ताकतों का पलड़ा भारी रहने की आशंका है। यह भारत के लिए कड़ी कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी होगी।

सीमा पर सतर्कता जरूरी

बांग्लादेश का सियासी उलटफेर निश्चित रूप से भारत के लिए चिंताजनक है। अब सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करनी होगी। बांग्लादेश में भारत सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं, जो सत्ता परिवर्तन होने पर प्रभावित हो सकती हैं। चीन और पाकिस्तान से भी सावधान रहना होगा।

-ईश्वर जैन, उदयपुर

आपकी बात

कट्टरपंथियों का उभार

बांग्लादेश में हुई अशांति से भारत के आर्थिक और सामरिक हित प्रभावित होंगे। शेख हसीना ने कट्टरपंथियों पर लगाम लगा रखी थी। अब फिर से इनका उभार भारत के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हमले बढ़ सकते हैं। भारत को वहां के घटनाक्रम पर निगाह रखनी होगी।

-नीता टहिलियानी, जयपुर

भारत के हित में नहीं

शेख हसीना के भारत के साथ संबंध काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं , जो चीन और पाकिस्तान को नागवार लग रहे थे। अब यदि सेना के प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी तो हो सकता है उस पर चीन का प्रभाव रहे, जो भारत के लिए हितकर नहीं होगा। बांग्लादेश में रह रहे हिन्दुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

-संजय डागा, इन्दौर

आज का सवाल

क्या बांग्लादेश का सियासी तूफान विपक्ष के दमन का नतीजा है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'बांग्लादेश के घटनाक्रम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?' कई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

इसे स्कैन करें

https://rb.gy/8l50h4

चिंतन

बांग्लादेश में अराजकता भारत की प्रमुख चिंता

शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद त्याग कर देश छोड़ देने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अराजकता के हालात बन गए हैं। उग्र भीड़ हिंसा में लिप्त है, चुनचुन कर आवामी लीग से जुड़े नेताओं का संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है, प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट जारी है। मंदिरों व हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों के संघर्ष में एक दिन में ही करीब सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। आरक्षण को लेकर हिंसा की आग से समूचा बांग्लादेश झुलस गया है। बंग सेना ने जरूर ऐलान किया है कि वह अंतरिम सरकार का गठन करेगी, लेकिन इस दिशा में उसने कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। सेना ने बीएनपी नेता बेगम खालिदा जिया को रिहा कर दिया है, इससे प्रतीत होता है कि सेना खालिदा जिया के ईर्द-गिर्द अंतरिम सरकार का स्वरूप सोच सही है। सेना ने व्यापक फिरबदल भी किया है। हालांकि इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के मसलाहकार के तौर पर नोबेल विजेता व ग्रामीण बैंक के प्रमुख मोहम्मद युनूस का नाम आगे बढ़ाया है, उन्होंने इसे स्वीकार भी लिया है। अमेरिका ने अपील की है कि हसीना के बाद बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अंतरिम सरकार बनाई जानी चाहिए। ऐसे में सेना पर नई सरकार के गठन को लेकर दबाव बन गया है। हसीना अभी भी दिल्ली में ही हैं, नए ठिकाने मिलने तक उन्हें भारत में रहना पड़ सकता है। बांग्लादेश के हालात पर भारत में चिंता है, पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विपक्ष ने सरकार के हर फैसले के साथ होने की बात की है। यह एक अच्छा मूव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूचित किया है कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्हें भविष्य की रणनीति तय करने के लिए समय दिया है। कूटनीतिक, सामरिक व ट्रेड के लिहाज से बांग्लादेश भारत के लिए अहम है। करीब दस हजार भारतीय छात्र वहां है। भारत का करीबी मित्र देश बांग्लादेश है, दोनों मुल्कों में काफी ट्रेड होते हैं, जो अशांति एवं अस्थिरता की वजह से ठप हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत बांग्लादेश को मुख्य रूप से सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, चीनी, कन्फेक्शनरी, रिफाइंड पेट्रोलियम तेल, रसायन, कपास, लोहा और इस्पात तथा वाहनों का निर्यात करता है जबकि प्रमुख आयात मछली, प्लास्टिक, चमड़ा और परिधान हैं। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टर इस्लामी राजनीतिक पार्टी जमीयत-ए-इस्लामी की छात्र इकाई ने हालात पैदा किए हैं और अब उसकी पसंद की नई सरकार बनने की संभावना जगी है, इसमें पाकिस्तान, चीन व अमेरिका की रुचि है, ऐसे में बांग्लादेश में भारत विरोधी इस्लामिक शक्तियां नई चुनौती बनकर उभरेंगी। भारत में घुसपैठ बढ़ने का खतरा है, आतंकवादी का नया ठिकाना बांग्लादेश बन सकता है और वहां से पाक प्रायोजित आतंकवाद सक्रिय हो सकता है। तीस्ता समेत करीब दस से अधिक समझौते भारत के साथ हैं, इसकी रक्षा की चुनौती भी होगी। चीन की नजर भी तीस्ता समझौते पर है। शेख हसीना बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को कुचलती रही थीं, अब चीन के करीबी माने जाने वाले सेना प्रमुख की कमान में अंतरिम सरकार भारत का सामने चुनौतियां पेश कर सकती हैं। भारत को बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए व कूटनीतिक डायलॉग के साथ सामरिक सुरक्षा के दरवाजे खुले रखने चाहिए।

बांग्लादेश के हालात पर नजर जरूरी

पड़ोस
डॉ. एन.के. सोमानी

हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा काफी हद तक खत्म कर दिया। केवल पांच फीसदी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए व दो फीसदी अल्पसंख्यकों व दिव्यागों के लिए आरक्षित होंगी। शेष पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर होगी। एक बारगी लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीएनपी पाक समर्थित पार्टी है जिसको अमेरिका का समर्थन हासिल है। अगर ऐसे समूह सत्ता में आते हैं तो दोनों देशों के संबंधों के समक्ष एक चुनौती पैदा हो सकती है। यही वजह है कि बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत नजर रखे हुए हैं।

सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रा सेनानियों के परिवारों को आरक्षण दिए जाने का बांग्लादेश उच्च न्यायालय का फैसला अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना व उनकी सरकार के लिए संकट का सबब बन गया है। आरक्षण के विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय में आग लगा दी है। इतना ही नहीं बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुर्जीबुर्रहमान की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की सत्ता सेना के पास आ गई है। हालांकि, सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने जल्द से जल्द अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी शांति की अपील करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि हिंसा में मारे गए लोगों के साथ न्याय होगा। बांग्लादेश में सारा उपद्रव जुलाई में उस वक्त शुरू हुआ जब बांग्लादेश उच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट का एक अंग) ने 2018 में सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले को पलट दिया था जिसमें सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए दिए जाने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त किया गया था।

कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि, हसीना सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया। बांग्लादेश की आजादी के एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था। 2018 में जब इसे खत्म किया गया, उस वक्त सरकारी नौकरियों में अलग-अलग वर्गों के लिए 56 प्रतिशत आरक्षण था। हालांकि, हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा काफी हद तक खत्म कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब केवल पांच फीसदी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए व दो फीसदी नौकरियां अल्पसंख्यकों व दिव्यागों के लिए आरक्षित होंगी। शेष पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर होगी। न्यायालय के निर्णय के बाद 93 फीसदी भर्तियां अनारक्षित कोटे से होना तय था। एक बारगी लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी व छात्र संगठन प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वालों को न्याय दिये जाने की मांग पर अड़ गए। वे इस बात से भी क्षुब्ध थे कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों पर विचार करने के बजाए उन्हें रजाकारों (गद्दारों) का वंशज तथा आतंकवादी कह रही है। हसीना के बयान पर छात्र भड़क गए और विरोध तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच झड़प में 14 पुलिस अधिकारियों सहित 94 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शन शुरू होने के बाद एक ही दिन में मरने वालों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते

हसीना के पद छोड़ने की मांग पर कैसे केंद्रित हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में राष्ट्र विरोधी तत्वों को खेलने का अवसर मिल गया हो। जिस तरह बंगबंधु मुर्जीबुर्रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया है, उसे देखते हुए साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जो सवाल सबसे अधिक परेशान कर रहा है वह यह है कि क्या बांग्लादेश की सत्ता सेना के हाथों में आ जाएगी। हालांकि सेना ने कहा कि एक-दो दिन में अंतरिम सरकार चुन ली जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश या तमाम वे मुल्क जहां जब-तब लोकतंत्र को फौज के बूटों तले कुचला गया, वहां के अनुभव यह बताते हैं कि सेना के सत्ता में आने के बाद उसका वापस बैरक में लौटना मुश्किल होता है।

दूसरा देश की प्रमख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया (80) स्वास्थ्य के चलते लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति से गायब है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। एक अहम सवाल यह भी है कि साझा सरकार में अवामी लीग की क्या भूमिका होगी। अगर उसे सरकार में शामिल नहीं किया जाता है तो क्या देश के भीतर स्थिरता बहाल हो पाएगी? अगर यह मान भी लिया जाए कि अवामी लीग को साझा सरकार में शामिल किया जा सकता है तो क्या देश की नाराज अवाम को यह स्वीकार होगा। इसके अलावा नए चुनावों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अंगुलियां अमेरिका की तरफ भी उठती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से शेख हसीना के शासनकाल में रूस व चीन ने बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाया है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं। सितंबर में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की ढाका यात्रा के बाद से बांग्लादेश के प्रति अमेरिका और अधिक संजीदा हो गया है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर था जब रूस के किसी विदेशमंत्री का ढाका दौरा हुआ है। अमेरिका-बांग्लादेश तनाव के बीच थोड़े समय पहले रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का एक युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। पिछले पांच दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब इस प्रकार के स्कवाड्रन ने बांग्लादेश के किसी बंदरगाह पर लंगर डाला हो। इन सब घटनाओं से अमेरिका की चिंता बढ़नी ही थी।

चीन के साथ भी बांग्लादेश के आर्थिक रिश्ते मजबुत हुए हैं। बांग्लादेश चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। दूसरी ओर अमेरिका मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर हसीना सरकार की आलोचना कर रहा है। वह बांग्लादेश पर अपनी इंडोपैसिफिक नीति में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन विदेश नीति में संतुलन बनाकर चलने वाली शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। शेख हसीना अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप भी लगा चुकी हैं। भारत के बांग्लादेश के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में यह संबंध और मजबूत हुए हैं। 1996 से 2001 तक और फिर 2009 से लगातार भारत को बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग मिला है। भारत ने अपनी जी-20 की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को सदस्य न होने के बावजूद उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया। हसीना सरकार ने भी देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं। यही वजह है कि भारत हसीना सरकार के साथ है। बीएनपी पाक समर्थित पार्टी है जिसको अमेरिका का समर्थन हासिल है। अगर ऐसे समूह सत्ता में आते हैं तो दोनों देशों के संबंधों के समक्ष एक चुनौती पैदा हो सकती है। यही वजह है कि बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत नजर रखे हुए हैं।

(लेखक विदेशी मामलों के जानकार हैं,, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

कुरनूल जिले के पूर्वी घाटों में स्थित, अहोबिलम मंदिर, आंध्रप्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। 108 दिव्य देसमों में से एक होने के कारण, इस मंदिर को वह स्थान माना जाता है जहां हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया था। पवित्र अहोबिलम मंदिर का निर्माण भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के पदचिह्न पर किया गया था, जिसकी माप 5 फीट 3 इंच थी।

एकनिष्ठ भक्ति

संकलित
दर्शन

अनेक महापुरुष हैं, अनेक देवी-देवता हैं, अनेक मार्ग हैं, किंतु एकनिष्ठता आवश्यक है। इसी कारण इष्ट देवता की अवधारणा है। घर की बहू सास, ससुर, जेठ, जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती। सबकी सेवा करती है, किंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, जबकि अन्य देवी-देवताओं का सम्मान करो, सबके प्रति श्रद्धा रखो। सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं। किंतु किसी एक के प्रति एकनिष्ठ रहो। चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चलें तो उन्हें कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी लक्ष्य के पास पहुंचकर पकते-पकते भी कट जा सकती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु अथवा इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता, यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है। एक बार किसी यात्री ने एक आदमी से कोलकाता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने और एक जन से रास्ता पूछा। उसने दूसरा रास्ता बताया। इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता तो पहले वाले का रास्ता छोड़ उस पर चल देता। ऐसा करते हुए वह रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया। उसे किसी ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछना चाहिए था, जिस पर विश्वास हो कि वह सही मार्ग जानता है।

अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र

संकलित
प्रेरणा

एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे धर्मराज उनके कर्मों का लेखा-जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। धर्मराज ने दोनों से कहा: मैं अवसर देता हूं, कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराजः मैंने जीवन भर पापकर्म किए जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे आप जो दंड दें, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला महाराजः मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी फिर डाकू से कहा: तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा: महाराज! इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ वह क्षुब्ध होकर बोलेः निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मर कर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, और तप को पूर्ण करो।

श्रावणी तीज

डॉ. मोनिका शर्मा

समाज-परिवार के जुड़ाव को पोसता लोकपर्व तीज

भारत के सामाजिक-पारिवारिक परिवेश की बुनियाद को मजबूती देने में महिलाओं की अहम भूमिका है। बहू-बेटियों के दायित्वबोध के चलते ही वैश्विक बिखराव के इस दौर में भी हमारे देश में पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों का जुड़ाव कायम है। आधी आबादी की यह रेखांकित योग्य भाव-भूमि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक ही नहीं, मानवीय पहलुओं को भी सींचने वाली है। विचारणीय यह है कि मन-जीवन से जुड़े इस भावनात्मक पक्ष को हमारी परम्पराएं पोषण देती हैं। श्रावणी तीज का उत्सव लोक पर्वों की सूची में शामिल ऐसे ही सुंदर परंपरागत उत्सव का उदाहरण है। जड़ों से जोड़ने वाला यह त्योहार न केवल भारत की समृद्ध परम्पराओं का उदाहरण है बल्कि बेटियों के सम्मान और बहू का मान करने की सीख लिए हुए है। बहू-बेटियों के मान-मनुहार की रीत वाले देश में भ्रूण-हत्या और दहेज की मांग वाली विकृति जाने क्यों और कैसे जड़ें जमा सकी? लौकिक रिवाजों में भी स्त्री जीवन से जुड़े उत्सवीय रंगों की छटा के बिना मन-जीवन की आभा को अधूरा ही माना गया है ।महिलाएं सदा से ही परिवार की धुरी मानी गई हैं। सामाजिकता को पोसने का दायित्व निभाती आई हैं। श्रावणी तीज का पर्व मेलजोल का ही एक सुंदर उत्सव है। प्रकृति से बढ़ती दूरी, अकेलापन और समाज में जड़ें जमाते एकाकीपन के इस दौर में ऐसे उत्सव मन को खुशी देते हैं। जीवन से जोड़ने वाली इन परम्पराओं को केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि मानवीय भाव-चाव से जोड़कर देखना जरूरी है। अब तो सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी आपसी मेलजोल को बढ़ाने की बात कहने लगे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान पर्व-त्योहारों को मन का स्वास्थ्य सहेजने का अवसर बताने लगे हैं, क्योंकि ऐसे पर्वों के साथ सद्भावना और सामाजिकता की सोच जुड़ी है। निस्संदेह, रीति-रिवाज के प्रेमपगे भाव और पर्यावरण के जुड़ाव का संदेश देते ऐसे पर्वों की अहमियत और बढ़ गई है। ध्यातव्य है कि उत्तर और पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हरियाली तीज का पर्व बड़े उत्साह और पारम्परिक अंदाज में मनाया जाता है। इस पर्व को उत्तर प्रदेश में कजली तीज और राजस्थान में श्रावणी तीज कहा जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। दरअसल, आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे त्योहारों में समाहित कुशलकामना का भाव हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद रहा है। तभी तो तीज मनाने के लिए विवाहित बेटियों को मायके आने के न्योते भेजे जाते हैं। बहुओं की मनुहार की जाती है। रीति-रिवाज की कड़ियों को जोड़ते हुए मन को उल्लास की सौगात देने वाला तीज पर्व हर राज्य में अलग अंदाज़ में मनाया जाता है। महिलाएं लोकगीत गाती हुई टोलियों में झूला झूलती हैं। सुखद है कि तीज के त्योहार का चाव आज भी कायम है। स्नेहिल दाम्पत्य के मनोभावों से जुड़े तीज जैसे उत्सव सार्थक प्रतीत होते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार, स्तंभकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

हिरोशिमा परमाणु बम के सबक

छह अगस्त 1945 का वो काला दिन जब अमरीकी वायुसेना ने हिरोशिमा, जोकि जापान में है, पर परमाणु बम गिराकर हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, उसके जख्मों को अभी भी दुनिया नहीं भुला पाई है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रुमैन उस समय हुए युद्ध के दौरान जापान की युद्ध क्षमता को चौपट करना चाहते थे, इसलिए भी अमरीका ने परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले किए थे। इस हमले की कोई भी वजह रही हो, लेकिन ऐसे युद्धों और हमलों को बढ़ावा देना बहुत ही गलत है। इसमें प्राणी जाति के विनाश के बीज हैं। युद्ध हमेशा हानिकारक ही सिद्ध हुए हैं। मुट्ठीभर सत्ताधारियों के अहम ने जब भी कोई युद्ध छेड़ा है तो इसमें बेकसूर लोग ही मारे गए हैं। हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए।

- मोहन जोशी, कोरबा

करंट अफेयर

मस्क का ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर

मशहूर उद्यमी एलन मस्क ने सोमवार को 'ओपनएआई' और इसके दो संस्थापकों-सैम ऑल्टमैन तथा ग्रेग ब्रॉकमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'चैटजीपीटी' निर्माता ने मुनाफा कमाने के बजाय जनता की भलाई के लिए काम करने के अपने मूल उद्देश्यों से विश्वासघात किया है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में मस्क के मामले को 'परोपकारिता बनाम लालच' बताया गया है। शिकायत के अनुसार, मुकदमे में नामित ऑल्टमैन और अन्य लोगों ने 'जानबूझकर मस्क को धोखा दिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों के बारे में मस्क की मानवीय चिंताओं को दरकिनार किया।' मस्क ने 2015 में ओपनएआई की स्थापना होने पर सबसे पहले इसमें निवेश किया था और वह ऑल्टमैन के साथ इसके बोर्ड के सह-अध्यक्ष हैं। मुकदमे में मस्क ने कहा कि उन्होंने लाखों रुपये निवेश किए और ओपनएआई के लिए शीर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान वैज्ञानिकों की भर्ती की। मस्क ने 2018 की शुरुआत में इसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

ऑफ बीट

सनस्क्रीन समुद्री पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह

सनस्क्रीन जटिल अवयवों की एक श्रृंखला से बने होते हैं, जिनमें यूवी फिल्टर भी शामिल हैं, जिन्हें या तो यूवी किरणों को अवरुद्ध करने या अवशोषित करने के लिए इसमें शामिल किया जाता है, साथ ही इसमें सुगंध, स्टेबलाइजर्स, पैराबेंस (मिथाइलपरबेन या ई128 जैसे संरक्षकों का एक परिवार) और अक्सर वॉटरप्रूफिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ (पीएफएएस) या हमेशा बने रहने वाले रसायन का समावेश होता है। यूवी फिल्टर रासायनिक या खनिज आधारित हो सकते हैं। रासायनिक यूवी फिल्टर में ऑक्सीबेनज़ोन और ऑक्टोक्रिलीन जैसे सिंथेटिक यौगिक शामिल होते हैं जो यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं - अधिकांश मुख्यधारा के सनस्क्रीन इनका उपयोग करते हैं। खनिज यूवी फिल्टर में जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल होता है जो यूवी किरणों को प्रतिबिंबित और बिखेरता है। बाद वाले को आमतौर पर नैनोकणों के रूप में जोड़ा जाता है - ये बेहद छोटे खनिज कण त्वचा पर एक पतली परत प्रदान करते हैं, उनके भारी समकक्षों के विपरीत जो मोटे और चिपचिपे दिखाई दे सकते हैं।

ट्रेंड

राष्ट्रपति जी को बधाई

फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति जी को बधाई। यह हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों से जुड़ाव को भी मान्यता है। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी

फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मेरी हार्दिक बधाई। यह सम्मान न केवल विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

-अमित शाह, गृहमंत्री

बसपा केंद्र के फैसलों के साथ

पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेज़ी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनज़र आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित व ज़रूरी। बीएसपी भी इस मामले में केन्द्र सरकार के फैसलों के साथ है।

-मायावती, बसपा सुप्रीमो

उद्योग कम मांग से जूझ रहा

प्रतिकूल परिस्थितियों से कॉरपोरेट मुनाफे को जो अस्थायी बढ़ावा मिला था, वह अब कम हो रहा है और उद्योग जगत कमजोर उपभोक्ता मांग वृद्धि की वास्तविकता से जूझ रहा है। यह सबसे बुनियादी आर्थिक चुनौती है। **-जयराम रमेश, कांग्रेस नेता**

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Or you can tap on this link:

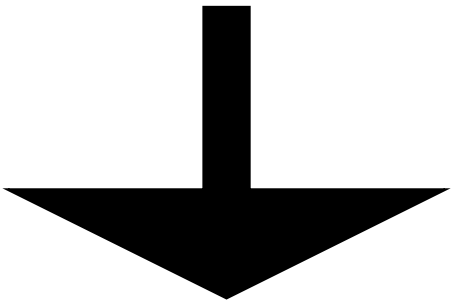

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid